ISSN 0974-1100

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

PŪRVADEVĀ - A Social Science Research Journal

Peer Reviewed Bilingual International Research Journal
The Journal indexed in the UGC-CARE list.

वर्ष 30 * अंक : 119

अक्टूबर-दिसम्बर, 2024

प्रधान सम्पादक

डॉ. हरिमोहन धवन

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

PŪRVADEVĀ **A Research Journal of Social Sciences**

Peer Revied Bilingual International Research Journal
This Journal is included in the UGC-Consortium for Academic and Research Ethics

वर्ष 30, अंक 119 **अक्टूबर–दिसम्बर 2024**

❐

प्रधान सम्पादक

डॉ. हरिमोहन धवन

❐

प्रकाशक

पी.सी. बैरवा

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी

बाण भट्टमार्ग, सेन्ट्रल स्कूल के सामने, उज्जैन (म.प्र) 456010

दूरभाष (0734) 2518737

E-mail : mpdsaujn@gmail.com Website : www.mpdsa.org

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

परामर्श मण्डल

डॉ. प्रकाश बरतुनिया

पूर्व कुलाधिपति– बाबा साहेब अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉ. अनिल दत्त मिश्रा

प्रतिष्ठित गांधीवादी विद्वान व वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुलभ अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन, नईदिल्ली

डॉ. रामगोपाल सिंह

पूर्व आचार्य, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू (म.प्र.)

डॉ. जयप्रकाश कर्दम

वरिष्ठ साहित्यकार एवं सम्पादक, दलित साहित्य वार्षिकी, नईदिल्ली

डॉ. रमेशचन्द्र जाटवा

पूर्व अतिरिक्त संचालक, उज्जैन संभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

डॉ. डी. डी. बेदिया

आचार्य एवं निदेशक, व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

सम्पादक मण्डल

डॉ. ज्ञानचन्द्र खिमेसरा

पूर्व आचार्य अर्थशास्त्र व प्राचार्य, शास.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर

डॉ. प्रभा श्रीनिवासुलु

पूर्व आचार्य इतिहास व प्राचार्य, शास. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)

डॉ. शैलेन्द्र पाराशर

पूर्व आचार्य समाजशास्त्र व अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

डॉ. प्रेमलता चुटैल

पूर्व आचार्य, हिन्दी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

डॉ. अरूण कुमार

प्राध्यापक,राजनीति विज्ञान, शासकीय तिलक महाविद्यालय, कटनी (म.प्र.)

प्रधान सम्पादक

डॉ. हरिमोहन धवन

आचार्य, राजनीति विज्ञान व पूर्व प्राचार्य, उच्च शिक्षा विभाग, (म.प्र.)

प्रकाशक : पी. सी. बैरवा

© स्वात्वाधिकारी : मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी,

बाणभट्ट मार्ग, सेन्ट्रल स्कूल के सामने, उज्जैन (म.प्र.)

इस अंक का मूल्य रूपये 150/–

वित्तीय सहयोग

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नईदिल्ली

सम्पादन व प्रकाशन सर्वथा अवैतनिक एवं अव्यवसायिक

वर्ष 30, **अंक** 119 **अक्टूबर–दिसम्बर, 2024**

पूर्वदेवा

सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

वर्ष 30 अंक 119 अक्टूबर–दिसम्बर, 2024

❐ अनुक्रम ❐

1. उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता और भेदभाव का होना –अरूण कुमार 1

2. महिला हिंसा एवं महिला अधिकारों के सरंक्षण में मानवाधिकार की आवश्यकता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन –डॉ. प्रीति सिंह 9

3. सीमांतीकरण के संदर्भ में दिव्यांग अनाथ बालिकाएँ –डॉ. सोमी अली 19

4. स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण परिवेश का बदलता परिदृश्य एक समाजशास्त्रीय दृष्टि –मोनिका वर्मा 28

5. गढ़वाल हिमालय की मूर्तिकला में शिव का नटराज स्वरुप –डॉ. श्वेता कुमारी 40

6. हरियाणा में शिक्षा की स्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (1920–47 ई) महिला साक्षरता के विशेष संदर्भ में –निखिल कुमार 48

7. आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के काव्य में प्रकृति चित्रण –सुमन सैनी 58

8. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत महिला तथा पुरूष शिक्षक–प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द का उनके कार्य प्रेरणा के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन –श्रीकान्त सिंह 63

9. समावेशी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक समीक्षात्मक अध्ययन –डॉ. आर. पुष्पा नामदेव 72

10. आपदा से अवसर : अम्बेडकर की प्रासंगिकता –डॉ. विमल कुमार लहरी 79

11. उत्तर प्रदेश की राजनीति का बदलता परिदृश्य एवं उसके निहितार्थ –कुमारी पूजा भारती 85

12 औपनिवेशिक काल में दक्षिणी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में शिक्षा का स्वरूप –मिहिर बोराना, नारायणसिंह 95

13 राष्ट्र निर्माण और आर्थिक उन्नति के संदर्भ में दत्तोपंत ठेगडी के विचारों का अध्ययन –मनोज कुमार, डॉ. राघवेन्द्र 104

14. Socio-Economic and Spatail Marginalization of Muslims in India 112
-Akhilesh Maurya.

15. Resurgence of Adivasi Identity : Pathalgadi Movement and 125
Politics of Indigeneity in Jharkhand -Alok Mishra

16. Emergence of Kanshiram and the Organisational Development in 142
Dalit Politics -Babli

17. Social and Economical Impact of Post Liberalization 155
Reforms of the Civil Aviation Sector of India
-Dr. Lalee Sharma, Dr. Smita Barge

18. A Study on Crimes against Scheduled Castes in 169
Southern States of India -Dr. Sukanta Sarkar

19. Electoral Candidate Selection in India and the USA Party 181
Nominations Versus Primaries
-Dr. Sunil Devi Kharb; Shivani Deshwal

20. Understanding the Role of Information, Education and 192
Communication Activities in Swachh Bharat Mission
-Neelesh Vigyanvratam

21. Assessment ot Healthcare Expenditure and Accessibility 202
A Case Study on Kannur District of Kerala
-Dr. Manohar V. Serrao, Dr. Alwyn Stephen, Misquith Janvi P. V.

22. Political Violence and Targeted Killings A Study of 218
Jmmu & Kashmir -Sunil Kumar, Dr. Pravat Ranjan Sethi

23. An Analysis of China's Cultural Incursion in Nepal and 225
Its Implications for India -Krishn Kumar

'पूर्वदेवा' में प्रकाशित लेख एवं उनमें व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार है.
सम्पादक व प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 1–8

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता और भेदभाव का होना

अरूण कुमार
शोधार्थी ऐतिहासिक अध्ययन और पुरातत्व विभाग,
दक्षिण बिहार केंन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया (बिहार)
E-mail: arunkumarmonto1@gmail.com Mob. 7011766176.

सारांश

उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में, विशेषज्ञता और विभेदीकरण उन तरीकों को अभिव्यक्त करता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थान विशिष्ट पहचान और विशेषज्ञता के क्षेत्र बनाकर खुद को एक दुसरे से अलग करते हैं। विशेष विषयों या अध्ययन के क्षेत्रों में अधिक ज्ञान और शोध के अवसर प्रदान करना ही विशेषज्ञता का अर्थ है। दूसरी ओर, विभेदीकरण विशिष्ट शैक्षिक अनुभव विकसित करने के लिये अधिक व्यापक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है, जिसमें व्यवसायों या समुदायों के साथ–साथ विशेष पाठ्यक्रम, निर्देशात्मक तकनीक और परिसर संस्कृतियाँ सम्मिलित हो सकती है। छात्रों कि विभिन्न रुचियों और भविष्य के आकांक्षाओं से मेल खानें वाले विशेष शैक्षिक मार्गों कि बढ़ती आवश्यकता को इस प्रवृति द्वारा सम्बोधित किया जाता है। यह विशेषतः छात्र जनसंख्या को आकर्षित करने, वित्तपोषण प्राप्त करने और शैक्षणिक संस्थानों कि स्थिति में सुधार करने में भी सहायता करता है। वैसे, इन रणनीतियों में कमियां भी है, जैसे कि शैक्षिक दृष्टिकोण को सीमित करने कि क्षमता और विशेष कार्यक्रमों को बनाने और संचालित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वितीय व्यय। सभी बातों पर विचार करने पर, विशेषज्ञता और विभेदीकरण उच्च शिक्षा के बदलते स्वरुप के लिये आवश्यक है, क्योंकि वे शैक्षणिक परीस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।

भारत में, माध्यमिक स्तर से आगे की शिक्षा को उच्च शिक्षा कहा जाता है। ''उच्च शिक्षा'' शब्द का तात्पर्य उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन, प्रशिक्षण या शोध के किसी भी रूप से है, जो विश्वविद्यालयों या अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिन्हें संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा उच्च शिक्षा प्रतिष्ठानों के रूप में मान्यता दी जाती है। इन संस्थानों का उपयोग विशेष रूप से अनुसंधान या तकनीकी और सामान्य शिक्षा के लिये किया जाता है। कोई

भी राष्ट्र पर्याप्त उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के बिना सच्चे स्वदेशी और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, इससे कुशल और शिक्षित व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण समूह तैयार होता है। विकासशील और गरीब देश, विशेष रूप से, प्रौद्योगिकी के मामले में अधिक विकसित देशों से स्वयं को अलग करने वाले अंतर को पाटने में उच्च शिक्षा के अभाव के कारण ही असमर्थ होते है।

आधुनिक समाज की ज्ञान–आधारित प्रकृति के कारण, शिक्षा और अनुसंधान सभी स्तरों पर लोगों, समुदायों और देशों के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा से ही किसी भी सांस्कृतिक, सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय विविधता को पहचना जा सकता है। ''यदि हम शिक्षा पर कोई भी ऐसा समझौता या संधि करते है जो जन–कल्याण से परे हो तो, इससे किसी भी देश की सामाजिक–आर्थिक प्रगति खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली ही है जो विकास को आगे बढ़ाती है।''[1] यदि हम अपने सार्वजनिक जीवन, व्यवसायों और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में उच्च नैतिक मानकों और नैतिक मूल्यों को बनाये रखने की आशा करते है, तो हमें शिक्षा प्रणाली पर तेज़ी से बदलते सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य के लिए इसकी प्रासंगिकता के मद्देनजर गंभीरता से दोबारा विचार करना चाहिए।

शिक्षा को एक ऐसे समाज के निर्माण का साधन भी होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से समृद्ध होने के साथ–साथ बहुलवादी और लोकतांत्रिक वातावरण में भी विकास कर सके। ''शिक्षा मानवाधिकारों, लोकतंत्र, सतत विकास, शांति और न्यायपूर्ण तथा समतापूर्ण समाज का एक बुनियादी स्तंभ है।''[2] अब हमारे सामने दो मुख्य समस्याएं है कि– कैसे उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय विकास की आवश्यकताओं के लिए अधिक प्रासंगिक बनाया जाये? क्योंकि यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में प्रवेश कर रहा है और दूसरें कि, इसे कैसे हमारे समाज के सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से हाशिये पर पड़े वर्गों के लिये उच्च शिक्षा तक पहुँच बढाई जाये ?

उच्च शिक्षा कि प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञता पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा अमीर लोगों के लिए अधिक सुलभ है और इसलिए विभिन्न कारणों से यह गरीबों की पहुँच से बाहर है। अगर विशेषज्ञता को प्राथमिकता प्रदान नहीं किया गया तो इसके अभाव में यह और भी बदतर हो जाएगा। उच्च शिक्षा को व्यापक बनाने और इसे समाज के वंचित और दलित वर्गों के लिए सुलभ बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए सार्थक पहल किया जाना चाहियें। इस अध्ययन का उद्देश्य है, विशेषज्ञताओं की प्रकृति और कमी को तथा भेदभाव की उत्पत्ति और सीमा का विश्लेषण करना तथा इस समस्यों के समाधान के तरीकों की रूपरेखा तैयार करना है।

उच्च शिक्षा में विशेषज्ञताः

हाल के वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और संचार के विधियों में हुये प्रगति के कारण ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि छह साल के भीतर ज्ञान का भंडार दोगुना हो जाता है। ''एक व्यक्ति को अपने द्वारा चुने गये और रुचिकर लगने वाले विषयों पर लगातार बढ़ती जानकारी के साथ अद्यतित रहना मुश्किल लगता है। नतीजतन, उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता को किसी दिये गये विषय के एक क्षेत्र या शाखा पर ध्यान केंद्रित करने

और जितना संभव हो सके, इसके बारे में अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आज दुनिया एक वैश्विक गाँव के रूप में संस्थापित हो चूकी है।''[3] वही आज प्रत्येक अर्थव्यवस्था और समाज परस्पर जुड़ते जा रहे है।

परिवर्तन न केवल उत्पादन और वितरण के तरीकों में हो रहे है, बल्कि सामाजिक–राजनीतिक संबंधों की व्यवस्था और गतिशीलता में भी हो रहे है। इसलिए समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव के रास्ते बंद हो गये तो समाज खतरे में पड़ जाएगा। विशेषज्ञताओं का कार्य–काल कभी भी समाप्त नहीं होता है, लेकिन यह बात अब व्यापक रूप से स्वीकार की जा रही है कि ज्ञान को अलग–अलग विषयों की सीमाओं तक सीमित भी नहीं किया जा सकता है। समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए, विकास के समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले छात्र को, विकास के अर्थशास्त्र को भी समझना होगा।

साहित्य का छात्र सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकता है। नतीजतन, हमें अपने विद्यार्थियों को किसी मुद्दे में रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र विकसित करने के लिए स्वतंत्र करना चाहिए। वे किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय समस्यां –आधारित विशेषज्ञता विकसित करें, जो उनके लिए महत्त्वपूर्ण और रुचिकर होना चाहिए।

अब विशेषज्ञताएँ इस प्रकार शैक्षणिक मानकों को स्थायी बनाये रख सकेगी, जो समाज की लगातार बदलती आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है और अकादमिक दुनिया में उत्कृष्टता के बराबर है। उत्पाद की रोजगार क्षमता बढ़ाने से विशेषज्ञता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। ''एक तरफ, हम इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार नहीं चाहते तो वही दूसरी तरफ, हमारे पास ऐसी नौकरियाँ है जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। इसलिए, स्नातक शिक्षा को शिक्षा सुधार से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। यूजीसी द्वारा विकास प्रक्रिया में पहले चरण के रूप में 35 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पहचान की गई थी। 1994–1995 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी।''[4] ये पाठ्यक्रम– जैसे कि कंप्यूटर अनुप्रयोग, बिक्री और विज्ञापन, तथा सचिवीय तकनीक आदि। इस पाठ्यक्रम को वर्ष 1995 और 1996 के बीच 381 कॉलेजों और 26 विश्वविद्यालयों में प्रारंभ किया गया था।

वैसे, प्रारंभ में इसमें 5 प्रतिशत से भी कम संस्थानों को ही सम्मिलित किया गया था। ''स्नातक डिग्री कार्यक्रम के तीन साल इसके एकीकरण के कारण व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए समर्पित था। ऐसे पाठ्यक्रमों की बहुत मांग थी और वे तेज़ी से भरे भी जा रहें थे।''[5] ये कार्यस्थल के लिए प्रासंगिक क्षमताओं का विकास करने का कार्य भी किये है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश पाठ्यक्रम औद्योगिक प्रबंधन में उपयोग के लिये होते थे। इस कारण से, हमें ऐसे पाठ्यक्रम भी बनाने चाहिए, जो ग्रामीण और अर्ध–ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ अविकसित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और देश के दूरदराज के क्षेत्रों में हमारे विश्वविद्यालयों के स्थानों के लिए बेहद अनुकूल हो।

व्यावसायिक शिक्षा भारत में कभी भी बहुत लोकप्रिय नहीं रही है, क्योंकि इसे हमेशा एक मृत–अंत कार्यक्रम के रूप में देखा गया है। ''परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों से स्नातक पास अधिक रोजगार योग्य हुये और बेरोजगार भीं हुये। हालाँकि, उच्च शिक्षा के लिए अपर्याप्त

योजना और इसके अप्रत्याशित विस्तार के कारण, अब बहुत सारी अव्यवहारिक प्रणालियाँ है और एक ऐसी प्रणाली है, जो तेज़ी से विकसित हो रहे सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य से मेल नहीं खाती है।''[6] इसके अलावा, शिक्षा को एक ऐसे समाज के निर्माण का साधन भी होना चाहिए, जो आर्थिक रूप से सफल हो और बहुलवादी और लोकतांत्रिक वातावरण को विकसित करने में भी सक्षम हो। शिक्षा मानवाधिकारों, लोकतंत्र, विकास, शांति और न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज का एक मूलभूत स्तंभ है।

इसलिए समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा को बदलना होगा। बदलाव के दरवाजे बंद करने से सभ्यता खतरे में पड़ जाएगी। वैसे, विशेषज्ञता का अपना विशेष महत्व है, लेकिन यह अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि, ज्ञान को विभिन्न विषयों की सीमाओं के भीतर नहीं रखा जा सकता है। ''समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए, विकास के समाजशास्त्र का अध्ययन करने वाले छात्र को विकास के अर्थशास्त्र या हाल ही में उदारीकरण की नीतियों को भी समझना होगा। साहित्य का छात्र सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिला ले सकता है। परिणामस्वरूप, हमें अपने विद्यार्थियों को रुचि के क्षेत्र में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए स्वतंत्र करना होगा।''[7]

उत्पाद के लिए, उच्च रोजगार दर का उपयोग विशेषज्ञता का समर्थन करने के लिए किया जाना चाहिए। ''एक तरफ, हम इतनी बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार नहीं देखना चाहते है और वही दूसरी तरफ, हमारे पास ऐसी नौकरियां है, जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध भी नहीं है। इसलिए, कॉलेज शिक्षा को इसके निरंतर प्रासंगिकता पर सबसे अधिक प्रभाव डालने की आवश्यकता है।''[8]

गुजरात विश्वविद्यालय ने 35 व्यावसायिक पाठ्यक्रम बनाकर एक कार्यक्रम शुरू किया था। यह कार्यक्रम 1994 और 1995 के बीच शुरू हुआ था। इसके पाठ्यक्रम में कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिक्री, विज्ञापन और सचिवीय कौशल आदि को भी सम्मिलित किया गया था। पाठ्यक्रम के तीन वर्ष एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम से मिलकर बने थे, जो स्नातक डिग्री कार्यक्रम के साथ एकीकृत थे। इस तरह के पाठ्यक्रम की बहुत मांग थी और इसका तेजी से विस्तार भी हो चूका था। कामकाजी दुनिया के लिए कौशल विकसित किये जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त, एक औद्योगिक प्रक्रम अधिकांश पाठ्यक्रमों के डिजाइन के केंद्र में हमेशा रहता था। चूंकि, ये कॉलेज अविकसित क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, अर्ध–ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों और देश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित होते है, इसलिए ऐसे पाठ्यक्रमों को बनाना चाहिए, जो उनके लिए अधिक उपयुक्त हों। देखा जाये तो, भारत कभी भी व्यावसायिक शिक्षा का एक मजबूत उपयोगकर्ता के रूप में नहीं रहा है, क्योंकि यह पूर्व के दशकों में एक पराधीन राष्ट्र के रूप में रहा है, जिसके कारण भारत के संसाधनों का अधिक दोहन हुआ है। वही विश्वविद्यालयों से जो छात्र स्नातक उत्तीर्ण होते जा रहें है वो सर्वाधिक बेरोजगार भी हुये है। ''1996 में, उच्च शिक्षा के लिए अपर्याप्त योजना और इसके अप्रत्याशित विकास के कारण 8,210 संबद्ध कॉलेजों में से लगभग 40 प्रतिशत यूजीसी सहायता के लिए पात्र नहीं थे। ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि ये कॉलेज शिक्षकों और बुनियादी ढांचे के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं करते थे। योजनाकारों और नीति निर्माताओं को इस बारे में बेहद चिंतित होना चाहिए, क्योंकि

अव्यवहारिक संस्थान स्नातक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को स्वीकार करने और पर्याप्त रूप से संचालित करने में असमर्थ हैं।''[9]

उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता के लिए हमारे मौजूदा क्षेत्रों को संशोधित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सैद्धांतिक आधार के अलावा नये पाठ्यक्रमों को जोड़ने के अलावा अभिविन्यास को भी शामिल किया जा सके। भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बागवानी या पुष्प–कृषि, औद्योगिक रसायन विज्ञान, तथा कई अन्य विषयों को विज्ञान पाठ्यक्रमों में उद्योग और कृषि से संबंधित अनुप्रयोगों में बदला जा सकता है। ''अनुप्रयोग–उन्मुख विषय–वस्तु के माध्यम से, हमें विज्ञान के शिक्षण में क्रांति लाने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान और मानविकी भी इसी तरह इसे पूरा कर सकते हैं।

योग्यता और प्रतिभा के आधार पर छात्रों को चुनने की हमारी क्षमता उच्च शिक्षा विशेषज्ञता के लिए आवश्यक हो सकती है।''[10] किसी प्रकार का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना भी आवश्यक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च शिक्षा प्रणाली को अलग तरीके से प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें महत्वपूर्ण वित्त पोषण और रचनात्मक योजना की आवश्यकता होगी।

उच्च शिक्षा में भेदभावः

स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में उच्च शिक्षा कि पहुंच और सामान्य रूप से आधुनिक शिक्षा तक सीमित थी। चूँकि उच्च शिक्षा ऐतिहासिक रूप से समाज के कुछ वर्गों की तुलना में अधिक महंगी रही है, इसलिए यह हमेशा अभिजात्य वर्ग की रही है, जिसमें स्वतंत्रता के बाद भी कई कारणों से गरीबों की तुलना में अमीरों को प्राथमिकता दी गई है। ज्ञान और कौशल के क्षेत्रों में भेदभाव का परिणाम यह हुआ कि समाज के गरीब हिस्से उच्च शिक्षा में प्रवेश करने में असमर्थ थे। बुद्धि और विशेषज्ञता पर समाज के शक्तिशाली और धनी वर्गों का एकाधिकार था। ''ज्ञान व्यक्तिगत और सामाजिक प्रगति दोनों की कुंजी होती है और ज्ञान अन्य सभी विषयों का आधार होता है।''[11]

स्पष्ट कारणों से, वर्ग और जाति व्यवस्थाएँ हमारी संस्कृति में लंबे समय से सह–अस्तित्व में रही है। इस वजह से, कुछ ही व्यक्तियों का समाज के अधिकांश संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो पाती है और साथ ही उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता दिखाने का मौका भी मिलता है तथा महिलाओं को उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता में भेदभाव के कारण ऐतिहासिक रूप से इन अवसरों और संसाधनों से वंचित रहना पडता है। ये असमानताएँ पूरे देश को नुकसान पहुँचाती है। यह अपने अधिकांश लोगों के कौशल और योग्यताओं को समाप्त कर देता है, लेकिन जब यह कुछ ही लोगों के पास एकाधिकार में होता है, तो यह ठहराव, पतन, शोषण और विकृति को भी जन्म देने का कार्य करता है।

शैक्षणिक संस्थानों के असमान वितरण के परिणामस्वरूप शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति पूर्वाग्रह होता है। ''एजुकेशन फॉर ऑल NIEPA नई दिल्ली 1993 के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 73.02 प्रतिशत लोग और ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 44.69 प्रतिशत लोग

क्रमशः साक्षर थे। उत्तरार्द्ध की तुलना में, जहाँ महिला साक्षरता 64 प्रतिशत थी, पूर्व में केवल 30 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थीं। सर्वेक्षण (सितंबर 1990) के निष्कर्शों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 5.7 प्रतिशत पुरुष माध्यमिक स्तर तक साक्षर थे, जबकि महानगरीय क्षेत्रों में 15.9 प्रतिशत पुरुष साक्षर थे। पूर्व में से सात स्नातक बाद में थे, जबकि पूर्व में 1.2 थे।

माध्यमिक और स्नातक स्तर पर शिक्षित आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी क्रमशः 1. 9 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 10.2 और शहरी क्षेत्रों में 3.8 प्रतिशत थी। ग्रामीण भारत में बहुसंख्यकों को जिस तरह की सामान्य शिक्षा उपलब्ध है, वह सर्वविदित है। इन दिनों, वे उन शैक्षणिक संस्थानों से मिलते जुलते है, जहाँ धनी भारतीय माता–पिता अपने बच्चों को भेज सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से अविकसित उत्तर भारतीय राज्यों में अभी भी लाखों नागरिक ऐसे है, जिनकी शिक्षा तक पहुँच नहीं है।''[12] समाज के कमजोर वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े लोग संसाधनों के इस असमान वितरण के कारण सामान्य रूप से शिक्षा और विशे ा रूप से उच्च शिक्षा से वंचित है। ये समूह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है, लेकिन वर्तमान में यहाँ भी परिवर्तन देखा जा रहा है।

सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंडों और वित्तीय चिंताओं के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाता रहा है। यद्यपि तकनीकी शिक्षा में महिलाओं का नामांकन अपेक्षाकृ त कम है, लेकिन हाल के वर्षों में कुछ राज्यों में यह दर तेज़ी से बढ़ी है। ऐसे में, हमें परिस्थिति के अनुसार जागरूक होना चाहिए और लिंग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह धारणा कि भारत उच्च शिक्षा पर अत्यधिक राशि खर्च करता है और प्राथमिक शिक्षा के लिए बहुत कम धन छोड़ता है, पूरी तरह से मनगढ़ंत है। वास्तव में, हमारी सरकारे उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों में बहुत ही कम निवेश करती है, अपेक्षाकृत विकसित देशों कि तुलना में। ''एशियाई विकास बैंक का दावा है कि 1994 में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद, व्यय–अनुपात दक्षिण कोरिया के तुलना में सातवाँ, मलेशिया के दसवें हिस्से से भी कम और श्रीलंका के छठे हिस्से के बराबर था।''[13] इस प्रकार से उच्च शिक्षा में असमानता बढ़ रही है। यानी इसके कारण, निजीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और बहुत अधिक अध्यापन शुल्क होने के कारण कम सुविधा प्राप्त पृष्ठभूमि वाले लोगों को उच्च शिक्षा तक पहुँच से वंचित होना पड़ सकता है और इसका परिणाम यह होगा कि भविष्य में ज्ञान और कौशल पहले से कहीं अधिक ध्रुवीकृत हो जाएँगे।

सुधारात्मक पहल

संविधान के संस्थापकों ने न केवल सभी के लिये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक निष्पक्षता और समानता का आह्वान किया था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज के अपंग पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये साधन भी उपलब्ध कराये थे। उपर्युक्त विचारशील उपायों में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों, जैसे कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान शामिल है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अवसरों तक समान पहुँच मिले, जिससे कि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सकें और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। ''हमारे संविधान में ये धाराएँ केवल इस वास्तविकता को

स्वीकार करती है कि, ऐसे मामलों में जब आर्थिक असमानता के साथ–साथ सामाजिक असमानता भी मौजूद हो, तो केवल वित्तीय सहायता और समर्थन समाज के वंचित वर्गों को बहुसंख्यकों के स्तर तक नहीं पहुँचा सकती है।''[14] इस प्रक्रियां को अमेरिका में भी अपनाया जाता है, जहाँ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जैसे, काले लोगों के लिये इसी तरह के विशेष प्रावधान स्थापित किये गये है।

वैसे, ये प्रावधान केवल एक सकारात्मक कदम का ही प्रतिनिधित्व करते है। केवल सीटें आरक्षित करके और चुनिंदा आधार पर छात्रव त्ति और मुफ़्त छात्रव त्ति देकर इस मुद्दे को नहीं बदला जा सकता है। उच्च शिक्षा में भेदभाव को खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक और साहसी उपायों की भी आवश्यकता है, क्योंकि गरीबी और अभाव बहुत व्यापक है, और लैंगिक भेदभाव एक ऐसी स्वीकार्य सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथा बन चूकी है, जिसको कि नकारा नहीं जा सकता है। ''महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों और सबसे वंचित समूहों के सदस्यों के लिए निर्वाह भत्ते, पुस्तक अनुदान, छात्रावास लागत और अन्य लाभ जैसी सहायता प्रणालियाँ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उनके नामांकन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देंगी। अन्य छात्रों को भी उनके साधनों और योग्यताओं के आधार पर छात्रवृत्ति और ऋण के लिए विचार किया जाना चाहिए, साथ ही उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता और भेदभाव के आधार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। ये सिफारिशें बहुत महंगी हो सकती हैं।''[15]

उच्च शिक्षा में भेदभाव की सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने के लिए सही रास्ते पर चलना होगा, अगर शिक्षा के महत्व को सही संदर्भ में देखा जाये, तो निर्वाह भत्ते, पुस्तक, अनुदान, छात्रावास लागत और महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों और सबसे वंचित समूहों के सदस्यों के लिए अन्य लाभ जैसी सहायता प्रणालियाँ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उनके नामांकन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देकर ही समाप्त किया जा सकता है, अन्य छात्रों को भी उनके साधनों और योग्यताओं के आधार पर छात्रवृत्ति और ऋण के लिए विचार किया जाना चाहिए, साथ ही उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता और भेदभाव के आधार पर भी ध्यान दिया जाना चाहियें। ये सिफारिशें भी बहुत महंगी हो सकती है, किन्तु इससे समाज के प्रत्येक वर्ग का भला होना सुनिश्चित है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा में विशेषज्ञता पर जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक वातावरण में प्रवेश कर रहे है। यह राष्ट्रीय विकास की विभिन्न आवश्यकताओं के लिये उच्च शिक्षा के महत्व को और मजबूत करता है। इसे प्राप्त करने वालों को अधिक लागत उठानी पड़ती है और अधिक निवेश की आवश्यकता भी होती है। वैसे, भारत में उच्च शिक्षा हमेशा से ही अभिजात्य वर्ग की ओर झुकाव रखती रही है। उच्च शिक्षा तक पहुँच की कमी के कारण, समाज के गरीब तबके के पास सूचना और कौशल की कमी बनी हुई है। उच्च शिक्षा के परिणामस्वरूप समाज अधिक भेदभावपूर्ण हो गया है। जैसे–जैसे उच्च शिक्षा अधिक विशिष्ट होती जाएगी, भेदभाव और भी कम होता जाएगा। इससे धनी और शक्तिशाली वर्ग के मध्य सूचना और कौशल का एकाधिकार और अधिक हो जाएगा। संभावनाओं के अभाव के परिणामस्वरूप आबादी के गरीब और हाशिये पर पड़े गरीब तबका केवल जीवन ही जीते रहेंगे।

परिणामस्वरूप, राज्य को रचनात्मक नियोजन, महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता, प्रभावी प्रशासन और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों के लिए विशेषकर उच्च शिक्षा तक पहुंच का प्रस्ताव करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए सगठनात्मक रूप से सार्वजनिक जागरूकता कि आवश्यकता है और अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, संसदों और मीडिया, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों, छात्रों के साथ–साथ संस्थानों, परिवारों और उच्च शिक्षा से जुड़े सभी सामाजिक क्षेत्रों की भागीदारी पर विचार करने कि आवश्यकता है, इक्कीसवीं सदी के लिए उच्च शिक्षा पर मसौदा विश्व घोषणा द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार किया जाना चाहिए ।

❒

सन्दर्भ –

1. *चब्बर, वी. (2010)। संगठित हित, विकास रणनीतियाँ और सामाजिक नीतियाँ। गरीबी पर न्छत्पैं की प्रमुख रिपोर्ट मेंः गरीबी कम करने की परियोजना और नीति व्यवस्था, भारत (पृ.163–181)। न्यूयॉर्कः संयुक्त राष्ट्र।*
2. *डीम, आर. (1998)। 'न्यू मैनेजरियलिज्म' और उच्च शिक्षाः यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन और संस्कृतियों का प्रबंधन। शिक्षा के समाजशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, 8(1), 47–70*
3. *अल्टबैक, पी. जी. (2005) वि ववविद्यालयः पारिवारिक भौली। अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, 39 पृ. 10–12*
4. *जयराम, एन. (2006) राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यः भारत। जेम्स जे. एफ. फॉरेस्ट और फिलिप जी. अल्टबैक (संपादक), उच्च शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय पुस्तिका। डोड्रेच्ट, नीदरलैंडरू स्प्रिंगर, पृ. 747–767।*
5. *तिलक, जे.बी.जी. (2005) त्रिशंकु में उच्च शिक्षा। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 10 सितंबर, पृ. 4029–4037।*
6. *अल्टबैक, पी. जी. 1993. भारतीय उच्च शिक्षा में परिवर्तन की दुविधा। उच्च शिक्षा में, 26. पृ. 3–20.*
7. *वही पृ. 3–20.*
8. *अल्टेकर, ए.एस.1944. प्राचीन भारत में शिक्षा, दूसरा संस्करण, नंद किशोर एंड ब्रदर्स, बनारस।*
9. *आनंदकृ णन, एम.2004, क्षेत्रीय विकास में उच्च शिक्षारूकुछ मुख्य बिंदु, यूजीसी द्वारा आयोजित क्षेत्रीय विकास पर भारत–यूके संगोष्ठी।*
10. *आनंदकृष्णन, एम. 2006, उच्च शिक्षा का निजीकरणः अवसर और विसंगतियाँ, 2 मई, 2006 को नई दिल्ली में NIEPA द्वारा आयोजित उच्च शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत शोधपत्र, माइमियो।*
11. *बासु, अपर्णा 1991. मूनिस रजा (संपादक) में औपनिवेशिक भारत में उच्च शिक्षा।*
12. *अल्टबैक, पी. जी., और टेचलर, यू. (2001)। एक वैश्वीकृत विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीयकरण और आदान–प्रदान। जर्नल ऑफ स्टडीज इन इंटरनेशनल एजुकेशन, 5(1), 5–25.*
13. *गैलेगो, एफ.(2010). स्कूली शिक्षा की ऐतिहासिक उत्पत्तिः लोकतंत्र और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की भूमिका। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी की समीक्षा, 92(2), 228–243.*
14. *शेंकमैन, ए. (1954), भारत में उच्च शिक्षा, सुदूर पूर्वी सर्वेक्षण, 23(2), 24–28.*
15. *कोहली, ए.(1997).क्या लोकतंत्र जातीय राष्ट्रवाद को समायोजित कर सकते हैं? भारत में आत्मनिर्णय आंदोलनों का उदय और पतन। जर्नल ऑफ एशियन स्टडीज, 56(2), 325–344*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 9–18

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

महिला हिंसा एवं महिला अधिकारों के सरंक्षण में मानवाधिकार की आवश्यकता एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. प्रीति सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर (उ.प्र.)
Email Id: pritinet5@gmail.com Mob. 6393064624

सारांश

किसी भी देश के नागरिकों की जब चर्चा की जाती है तो शब्द से उभय रूप में महिला और पुरूष दोनों का बोध होता है। किसी समाज की प्राथमिक इकाई परिवार मानी जाती है और परिवार को चलाने में महिला और पुरूष की भूमिका बराबर की होती है, वे गाड़ी के उस दो पहिए के समान होते है जिसके बराबर न होने पर गाड़ी सीधी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकती, बात जब मानव अधिकारों की, कि जाती है तो बर्बस ही महिला व पुरूष समान अधिकार प्राप्त माने जाते है, लेकिन जब बात भारत वर्ष की कि जाती है तब महिलाओं की तरफ ध्यान एक शक्ति, देवीतुल्य, पूज्य तथा अधिकार प्राप्त नारी का एक चेहरा उभरकर सामने आता है वजह साफ है, मनुस्मृति में भारतीय नारी को शक्ति का स्वरूप समझा जाता था। वर्तमान समय में भी नवरात्रि के समय कन्या पूजन इसी तरफ संकेत करता है, मनुस्मृति में एक स्थान पर उल्लेख भी आया है–"यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः" अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है।

मुख्य शब्द– महिला शोषण, मानवाधिकार, सामाजिक आदर्श, पितृसत्तात्मक परिवार, समाज की वर्चस्ववादी प्रवृत्ति।

प्रस्तावना

भारतीय समाज व्यवस्था में अतीत काल में उसे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान व प्रस्थिति प्रदान की गयी थी। इसकी स्थिति पर ही समाज का संगठन और विघटन दोनों निर्भर करता है व समाज में विभिन्न सम्बन्धों का निर्वहन करती है जिस समाज में महिलाओं को उच्च स्थिति प्रदान की गयी है वह समाज अत्यन्त विकसित माना गया है। कुल्लुक ने मनुस्मृति पर टीका करते हुए वाजसनेयी से एक अंश उद्धित किया है, पुरूष अपना केवल वह भाग है जब तक उसे पत्नी प्राप्त नहीं होती वह अपूर्ण रहता है। वह इसलिए पत्नी प्राप्त करता है और पूर्ण बनता

है। नर परस्पर अपने कृत्यों को करते हुए पुरूषोपयोगी कार्य करता है और स्त्री स्त्रीयोचित कार्य को करती है। दोनों अपने–अपने कृत्यों को करते हुए भी अपूर्ण रहते है और मिलकर पूर्ण हो जाते है। एक धारणा है कि पति–पत्नी एक दूसरे के सर्वोत्तम मित्र होते है, मित्रता जो सब सम्बन्धों का सार है, यहां तक कि स्वयं जीवन भी इस प्रकार पति–पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए एक आदर्श पत्नी अपनी सरस, सुकुमार एवं मनोजयी मुस्कान और अच्छे साहचर्य द्वारा पुरूष के लिए अत्यन्त तृप्ति का साधन होती है।

राधाकृष्णन के अनुसार, ''हिन्दू समाज में स्त्रियों का सम्मान व आदर प्राचीन काल से आदर्शात्मक व मर्यादायुक्त रहा है। उसके प्रति स्वभाविक निष्ठा व श्रद्धा रही है और समुदाय में उनके द्वारा किये जाने वाले योगदान का महत्व और गौरव रहा है। नारी सर्वशक्तिमान मानी गयी है, विद्या यश, शक्ति और सम्पत्ति का प्रतीक समझी गयी। नारी मानव जाति की जननी और धात्री है व जीवन का स्रोत और सामाजिक व्यवस्था (जीवन) की धुरी है।''[1]

प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक को कई बड़े परिवर्तनों का इतिहास कहा जा सकता है उसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है– महिला की भूमिका और स्थिति में दुनिया भर में आये और आ रहे बदलाव। इस बदलाव ने महिला के जीवन और समाज में उसके दोयम दर्जे की बातों को पूरी तरह से बदल दिया है। महिला की आजादी की राह इतिहास की एक असिद्ध थ्योरी को सिद्ध करती प्रतीत होती है। इतिहास अपने आपको दोहराता है। ऋग्वेद के करीब वह स्वतंत्रता के बेहद करीब थी। छठीं सदी ईसा पूर्व से उसका वास्तविक संघर्ष प्रारम्भ हुआ और अब फिर ऋग्वैदिक भूमि की ओर तेजी से अग्रसर रही। ऐसी अनेक महिलाएं हैं, जिन्होंने अपनी योग्यता से प्रसिद्धि को प्राप्त किया उसमें गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा, अहिल्या आदि प्रमुख हैं। उद्विकास की यात्रा महिलाओं को सामाजिक मां का दर्जा देती है जो किसी दूसरे मादा जीव की तरह ही अपने परिवार (समूह) की रक्षा करती है। महिलाएं अपनी भूमिका में शक्ति का रूप समझी जाती है फिर भी वे प्रत्येक क्षेत्र में हिंसा की शिकार है, शास्त्रों में कहां गया है कि– *'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरायसी'* अर्थात् जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है।[2]

महिलाओं को इतना उच्च स्थान भारतीय शास्त्रों एवं उपनिषदो में इसलिए दिया गया है कि महिला का अर्थ ही होता है, महान शक्तिशाली, बहुत बड़ी ताकतवाली इस शब्द से ही स्पष्ट है कि भारत में महिलाओं का क्या स्थान है ? परन्तु दूसरी तरफ उनके लिए अबला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ ही होता है दुर्बल, कम ताकतवाली, जिसकी रक्षा दूसरों को करनी होगी। ये दो शब्द एक तरफ महिला तो दूसरी तरफ अबला के नाम से जाना जाता है। यह नाम केवल महिला मुद्दा न बनकर एक मानवीय मुद्दा बनकर सामने आये महिला आदर्शों से अधिक महिला शक्ति के यथार्थ को समझा जा सके।

विभिन्न भारतीय ग्रंथों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाकाव्यों आदि में महिलाओं को एक तरफ देवी का स्थान प्राप्त है तो दूसरी तरफ सामाजिक उत्पीड़न एवं अत्याचार को सहती महिलाओं को भी देखा गया है। महिलाओं का जीवन रामायण, महाभारत में भी हिंसा प्रधान था, इसी काल में, सीता, द्रोपदी, अहिल्या आदि के साथ घोर अत्याचार किया गया। समस्त धार्मिक ग्रन्थों में यही बात देखी गयी है कि मां के आंचल में जगत का ममत्व समाया हुआ है, इसके विपरीत स्मृति कालीन धर्म शास्त्रों में महिलाओं को दासी अथवा वस्तु के रूप में दिया गया है।

ईसा के लगभग छः सौ वर्ष पहले महिलाओं को सम्पत्ति से वंचित कर दिया गया, तीसरी शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और सती प्रथा का आरम्भ हुआ इसी समय बालिका हिंसा बहुपत्नी वाद, पर्दा प्रथा भी मौजूद रहा। उन्नीसवीं शताब्दी से दहेज प्रथा का भी प्रचलन हो गया जिसके कारण लड़कियों को भार के रूप में समझा जाने लगा यही वह समय था जब महिला हिंसा एवं घरेलू हिंसा की नींव पड़ती चली गयी। भारतीय हिन्दू धर्म में जहां महिलाओं को सम्पत्ति ज्ञान और शक्ति का प्रतीक मानकर उन्हें लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में मान्यता दी गयी। वही वर्तमान समय में महिलाओं का जीवन भयंकर अव्यवस्थित हो गया है। ग्यारवीं शताब्दी से अठारवीं शताब्दी के बीच सम्भवतः महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी दयनीय हो गयी थी। इस अवधि में विधवा, पुनर्विवाह निषेद्य, पर्दा प्रथा एवं बाल विवाह तथा सती प्रथा आदि अनेक सामाजिक बुराईयों ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को काफी गिरा दिया था। यह क्रम सदियों से चला आ रहा है और आज भी वे हिंसा के ही दौर से गुजर रही है।[3]

लैंगिक विषमताएं

लिंग पर आधारित अन्तर और अस्वीकार्य असमानताएं देश में जारी है महिलाएं समान अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। महिलाओं के साथ भेद–भाव हाशिये पर कर दिये जाने का कार्य बड़ी दक्षता और सम्मानजनक तरीके से किया जाता है। जबकि मानवाधिकारों का सरोकार प्राचीन काल से ही रहा है, हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम का आराधक रहा है, हमारे देश ने विश्व को *जियो और जीने दो* का आदर्श दिया है, लेकिन समय के साथ मानव स्वभाव और सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आया है। अब लोगों में सद्भाव और सहिष्णुता समाप्त होती जा रही है और जिसकी वजह से समाज में विषमताएं व शोषण की घटनाएं बढ़ रही हैं। महिलाएं शोषण के इस कृत्य में जकड़ी हुई हैं। महिलाओं के साथ हिंसा अपने चरम पर है हिंसा तो प्रत्येक महिला पुरूष के साथ होता है पर कुछ ही क्षेत्रों में पुरूष इसके शिकार है परन्तु महिलाएं उस प्रत्येक क्षेत्र में हिंसा की शिकार है, जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि में वे प्रवेश करती है। महिलाओं के साथ हिंसा कोई नैसर्गिक कारण नहीं है, बल्कि यह तो मानव निर्मित समस्या है जो वर्तमान में भी विभिन्न रूपों में विद्यमान है चाहे वह मादा भ्रूण हत्या हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, बाल विवाह, महिला व्यापार, दहेज का लेन–देन या शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो आदि। इन रूपों में महिलाएं हमेशा दुखि रहती हैं।

मानवाधिकार एवं महिला

मानव अधिकार के क्षेत्र में महिला एक ऐसी दुर्बल वर्ग है जो अब भी उपयुक्त रूप से सुरक्षित नहीं है क्योंकि इनके सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, जिसे स्वतंत्रतापूर्वक जीने का अधिकार कह सकते है, को उनसे छिना जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में यह एक आन्दोलन के रूप में उभरकर सामने आया, यह आन्दोलन पूर्ण एवं प्रभावी तभी होगा जब महिलाओं को सुरक्षित एवं हिंसा मुक्त रखा जायेगा। महिला मानवाधिकार की रक्षा हमारे देश एवं विश्व समुदाय के लिए एक चुनौती है। समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनसे गठित होता है, इनके अधिकारों की रक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि कोई भी आर्थिक और सामाजिक विकास मानव अधिकरों के लिए सम्मान की आधार रेखा के बिना कायम नहीं रह सकती है।

समूचा विश्व लिंग सम्बन्धी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने के कारण गैर–बराबरी को पोषित करता है । भारत सभी राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं की बराबरी की वकालत करता रहा है । भारत की यह स्पष्ट न्यता है कि महिलाओं की उपेक्षा करके विकास की बात करना असम्भव है क्योंकि महिलाएं न केवल उस जनसंख्या का आधा हिस्सा है बल्कि उस केन्द्र बिन्दु का भी सूचक है जिसके इर्द–गिर्द ही सार्थक सामाजिक परिवर्तन का ताना–बाना बुना जा सकता है । विकास के स्थान पर जनमानस की भागीदारी आर्थिक विकास से मानव विकास तथा धर्मार्थ सेवाओं के स्थान पर सबलीकरण सम्बन्धी बदलाव विकास के प्रतिमानों को प्रस्तावित करते है। भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु यह परिवर्तन एक कारगर एवं स्थायी गारंटी है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की महिलाओं के लिए आधी आबादी कहकर पुकारा है। आज भी ये आधी आबादी देश के किसी कोने में सुरक्षित नहीं हैं। एक तरफ महिलाएं अत्याचार और शोषण की चक्की में पिसती नजर आ रहीं हैं तो दूसरी तरफ सामाजिक उत्पीड़न एवं अत्याचार के षड़यंत्र में फंसी हैं इसके बावजूद भी वर्तमान सदी का प्रथम वर्ष महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। निश्चय ही महिलाओं की स्थिति में कुछ सकारात्मक बदलाव आया है, महिलाएं अपने अस्तित्व व भविष्य को लेकर जागरूक हुई हैं। महिलाएं आज राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शिखर पर पहुंची हैं और आने वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इसके विपरीत इक्कीसवीं सदीं का यह नग्न सत्य है कि पितृसत्तात्मक परिवार या समाज की वर्चस्ववादी प्रवृत्ति उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, यहीं कारण है कि महिला दहेज के लिए जलाकर मारी जाती है, छत से ढकेली जाती है, गला दबाकर हत्या की जाती है, बलात्कार तो सामान्य सी बात हो गयी है। आनर किलिंग की घटनाएं हर रोज हो रही हैं । अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सौ साल पूरे हो गये है और इन सौ सालों में महिलाओं की दुनियां कितनी बदली है। सौ साल की स्थिति की बस यही कहानी है कि महिलाएं आज तमाम प्रगति करने पर भी हिंसा की शिकार हैं। महिलाओं की ऐसी स्थिति के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि–

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में है पानी।

अपनी तमाम स्थितियों के बावजूद भी आज महिलाएं हर दहलीज को पार कर अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं और आगे बढ़ रही हैं लैंगिक समानता अब केन्द्रीय स्थिति में हैं, जहां महिलाएं प्रत्येक बंदिश को तोड़कर बाहर आ रही हैं जिसमें इन्दिरा नूई, हिलेरी क्लिंटन, सुनीता विलियम्स, सानियां मिर्जा, प्रतिभा पाटिल, सुमित्रा महाजन, इन्दिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, ऐनी बेसेन्ट, शीला दीक्षित, मीरा कुमार, जयललिता, साइना नेहवाल जैसी महिलाओं के उदाहरण हैं। इन तमाम स्थितियों एवं तरक्कियों के बावजूद भी महिलाओं को अभी पुरूषों के बराबर समानता पानी है जिसमें स्वयं महिलाएं ही कदम बढ़ा सकती हैं इस संदर्भ में मजाज लखनवी लिखते है कि,

तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन,
तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।[4]

आज महिलाओं की राजनीति, शिक्षा, नौकरी, ग्राम पंचायत आदि में सहभागिता बढ़ी है। महिलाओं ने देश की राजनीतिक में प्रवेश कर, अनेक उच्च पदों को प्राप्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री, सांसद आदि पदों पर निर्वाचित होकर महिलाएं कार्य कर रही हैं। शक्ति सम्पन्न और नेतृत्व प्रदान करने वाली महिलाएं हमारे देश को गौरव प्रदान करती हैं। इन सबके बावजूद भी वर्चस्व और सशक्तिकरण के मामले में पुरूषों से काफी पीछे हैं। इसकी वजह हिंसा और घरेलू हिंसा की घटना उनकी प्रतिभा, निर्णयशक्ति, महिलाओं की क्षमताओं को प्रभावित कर रहा है, जिससे महिलाओं का विकास अवरूद्ध होता है। महिला सशक्तिकरण हिंसा और असमानता से लड़ने के लिए अस्तित्व में आया है महिलाएं अनेक संघर्षों एवं अनुभवों को लेकर सामने आयी हैं। वह अपने मान–सम्मान एवं अधिकार के लिए आगे बढ़ी हैं जिससे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रही हैं।

महिला एवं हिंसा सामाजिक विकास के लिए दो विपरीत शब्द हैं, जहां महिला समस्त मानव जाति का निर्माण करती हैं, वहीं हिंसा उसकी विनाश में लगी रहती है। महिलाएं हिंसा मुक्त जीवन यापन करें यह उसका मानवाधिकार है। किसी भी प्रकार की लिंग प्रजाति, जाति, वर्ग, धर्म और सभी प्रकार की सामाजिक विभिन्नताओं के होते हुए भी महिलाओं के लिए मानवाधिकार समान है।

यदि महिलाओं के संदर्भ में देखा जाय तो आज भी तमाम महिलाएं, युवतियां प्रतिदिन लैंगिक हिंसा से जूझ रही हैं। वर्तमान युग में लोगों के विचारों, तौर–तरीकों में परिवर्तन आया है परन्तु यह परिवर्तन महिलाओं का शोषण एवं उनके दमन और शासन करने सम्बन्धी विचारों में पूर्ण रूप से नहीं आ सका है। परन्तु महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के तरीकों में बदलाव अवश्य आया है। भेदभाव की यह वैश्विक संस्कृति महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार को दिन–प्रतिदिन बढ़ावा देती रही है। यह इतना ज्यादा परवान पर है कि आज तीन साल की बच्ची से लेकर अस्सी साल की बूढ़ी मां के साथ बलात्कार, निर्मम हत्या आदि घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं का गर्भपात करा देना, दहेज के लिए उसे जला देना, घर से बाहर निकाल देना, दुर्व्यवहार, बदतमीजी आदि ऐसी घटनाएं हैं जो यह दर्शाती है कि, संविधान में एक समान अधिकार रखने पर भी महिलाएं पीड़ित रहती हैं ।

आज हमारे समाज में लड़की की बजाय लड़का पाने की जो परम्परागत प्रवृत्ति है वह समाज में कमजोर होने के बजाय पुष्ट हो गयी है। इसी प्रवृत्ति के कारण आज महिलाओं का लिंगानुपात बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है जैसे–जैसे समाज का विकास होता गया वैसे–वैसे इस कुप्रथा का भी विकास होता गया समाज में यह प्रथा तो अति प्राचीन है, परन्तु इस प्रथा का कोई लिखित प्रमाण हमारे समक्ष नहीं है। आजादी के समय कुछ जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा के तहत उसे हर सम्भव मारने का प्रयत्न किया जाता था। असफल रहने पर ऐसे अमानवीय कृत्य किये जाते थे जिससे पूरी मानव जाति शर्मशार हो जाती। भारत में पुरूषों का उच्च स्तरीय लिंगानुपात कन्या शिशु हत्या और लिंग परीक्षण सम्बन्धी गर्भपातों के लिए बेटे की चाह रखने वाले परिवार द्वारा कन्या को जन्म से पहले इस दुनियां में आने से रोक दिया जाता है। सभी चिकित्सकीय परीक्षणों पर भारत में प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों में कमी नहीं आयी है ।

भारत को आजाद हुए लगभग 75 साल से अधिक हो गये है, आजादी की आधी सदीं बीत जाने के बाद भी आज महिलाएं पूरी तरह से आजाद और बराबरी का दर्जा हासिल नहीं कर पायी हैं। भारत में घरेलू हिंसा की घटना उतनी ही प्राचीन है जितना कि यह समाज। यह एक सार्वभौमिक घटना है। विकसित राष्ट्र हो या विकासशील विश्व भर में ऐसा कोई देश नहीं है जहां महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार न होती हो। भारत की बात की जाय तो स्थिति और भी खराब है। देश का कोई तबका इससे अछूता नहीं है हर वर्ग आयु एवं जाति की महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है। ऐसी कोई महिला नहीं जिस पर सामाजिक कुरीतियों, परम्पराओं एवं परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर किसी प्रकार की हिंसा का प्रहार न किया गया हो। सदियों से चली आ रही इस मानसिकता को, कि स्त्री जीवन के किसी भी पड़ाव पर स्वतंत्र होने योग्य नहीं है। आज भी समाज किसी कीमत पर इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। महिला के प्रति इसी रूढ़िवादी सोच के कारण महात्मा गांधी कहते भी हैं कि, जल में तैराना अच्छा है, लेकिन इसमें डूबना आत्महत्या है।

यदि महिलाओं के संदर्भ में मानवाधिकारों की बात की जाये तो 21वीं सदी में भी महिलाओं को उनके जीने के अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे भी छीना जाता है। बरसों से चली आ रही पितृसत्तात्मक समाज में आधी दुनिया के मानवाधिकारों का इस प्रकार हनन हो रहा है कि, शिक्षा, स्वास्थ्य तो दूर की बात है भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और बलात्कार जैसी दानवों से घिरी आधी दुनिया मानवाधिकारों की जरूरत को रेखांकित करते–करते अक्सर थक सी जाती है। आज घरेलू हिंसा एक सामाजिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि महिलाओं के प्रति हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गयी है कि आज महिलाएं अपने नागरिक अधिकारों एवं मानवाधिकारों के हक से वंचित होती जा रही है जिससे देश में महिलाओं की उन्नति नहीं हो रही है। इस संदर्भ में अरस्तु ने ठीक ही कहा है कि, महिलाओं की उन्नति और अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति निर्भर करती है।[5]

आज हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा किया जाता है। पुलिस रिकार्ड में महिलाओं के खिलाफ भारत में घरेलू हिंसा का उच्च स्तर दिखाई देता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों ने माना है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की विकास दर जनसंख्या वृद्धि से कहीं ज्यादा बढ़ रही है। दहेज की परम्परा की विद्यमानता के कारण दहेज की समस्या विद्यमान है जिसके कारण महिलाओं का जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। दहेज परम्परा का दुरूपयोग लिंग चयनात्मक गर्भपातों और कन्या शिशु हत्याओं के लिए मुख्य कारणों में से एक रहा है।

घरेलू हिंसा हमारे समाज (भारत) में काफी प्रचलित रही है जहां हमारे देश की अबलाएं चुपचाप पुरुष सत्तात्मक वातावरण के तहत बेरहम पुरूषों के अत्याचार सहने को विवश हैं। घरेलू हिंसा की घटनाएं निम्न स्तरीय सामाजिक, आर्थिक वर्गों में अधिक होती है कई मामलों में तो दहेज प्रथा भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। जहां आज के आधुनिक युग में भी हमारी बेटियां या हमारे समाज की औरतें चुपचाप इतने अत्याचार सहने को विवश हैं तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हमारे देश की आधुनिक महिलाएं स्वतंत्र हैं।[6]

महिला के ही परिवार में महिला का इतना अपमान होता है कि आज के शैक्षिक युग में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ उनके ही परिवार में पशुओं के जैसा व्यवहार किया जाता है, उसको अपमानित करना एक सामान्य सी घटना हो गयी है जिसकी वह आदि हो चुकी है। उनके चरित्र पर दोषारोपण करना, कन्या होने पर उसे अपमानित करना, कार्य करने वाली महिलाओं का वेतन छीन लेना, घर से निकाल देना आदि। इसके अलावा भी शराबी पतियों के द्वारा घर में खाना कम होने से उन्हें मारना ऐसे घरों में पति ही अपनी पत्नी को अपमानित करता है, यातनाएं देता है यही वह पितृसत्तात्मक परिवार या समाज है जिसमें महिलाएं एक अपाहिज की तरह अपनी जिन्दगी जीती हैं, कहीं–कहीं महिला ही महिला का शोषण करती है तो कहीं पुरूष महिला का शोषण करता है, भले ही उसके व्यवहार करने का ढंग अलग–अलग हो। इनके पशुवत व्यवहार से महिलाएं हमेशा से शोषित ही हैं।

आधुनिक काल के विचारकों द्वारा महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने हेतु किये गये कार्य एवं विचार–

राजाराम मोहन राय–

राजाराम मोहन राय ने महिला शोषण के विरूद्ध अनेक प्रसंशनीय कार्य किये, उन्होंने समाज में व्याप्त रूढ़ियों परम्पराओं का विरोध किया जो महिलाओं को पशुओं की तरह जीने को मजबूर कर दिया था। पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया गया, क्योंकि इस समय महिलाओं की स्थिति को दयनीय बनाने में धर्म और अंधविश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। इस समय सती प्रथा एक कलंक के रूप में भारतीय समाज में व्याप्त थी, महिलाओं के साथ क्रूरता एवं पशुता जैसा व्यवहार किया जाता था। इस समय विवाह में वर की आयु वधु की आयु से दोगुना–तीगुना होता था जिससे महिलाएं जल्दी ही विधवा हो जाती थी। सती प्रथा की शुरूआत धार्मिक ठेकेदारों ने कर दी। इसी समय बहुपत्नी प्रथा का चलन प्रारम्भ हो गया। इस समय राजा, जमींदार, तालुकदार आदि के पास जब तक एक से अधिक पत्नियां नहीं रहती थी उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी। इस समय महिलाएं केवल उपभोग की वस्तु समझी जाती थी। राजा राममोहन राय ने महिलाओं को उपर्युक्त बुराईयों से बचाने के लिए महिला शिक्षा पर बल दिया और कहा कि शिक्षित महिलाएं ही स्वयं का, परिवार का और समाज का विकास कर सकती है। शिक्षा के माध्यम से ही वह इस बुराई से बच सकती है। सन् 1822 में इन्होंने एक किताब प्रकाशित करवायी, जिसमें महिलाओं के अधिकारों की विस्तृत विवेचना की गयी है। वे चाहते थे कि महिलाएं स्वतंत्र रहें, वे महिला पुरूष में किसी प्रकार का भेद नहीं करते थे, वे कहते है कि, जब तक महिलाओं पर अत्याचार होगा तब तक समाज प्रगति नहीं कर सकेगा। उन्होंने विधवा महिला को उसकी सम्पत्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20 अगस्त 1928 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसमें विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया और बाल विवाह का विरोध किया गया उन्होंने अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए 1892 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पास कराया। उन्होंने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तीकरण की नींव रख दी।

स्वामी दयानन्द सरस्वती–

इनके समय में महिलाओं को धर्म ग्रंथ पढ़ने नहीं दिया जाता था। इस समय बाल विवाह, बहुविवाह था जिसका इन्होंने विरोध किया। स्वामी जी ने 5 से 8 वर्ष की आयु के लड़के–लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय में पढ़ने को कहा। वे लड़कियों को पढ़ाने के लिए अलग महिला अध्यापक की बात करते थे। वे महिला शिक्षा के लिए जाति और वर्ण को नकारते है एवं महिला पुनर्विवाह के समर्थक थे। उन्होंने ब्राह्मण विधवाओ के बारे सोचा। वे कहते है कि, यदि कोई महिला निःसंतान है तो स्वयं की जाति के बच्चे को गोद ले सकती है। विधवा ब्राह्मण महिला के पुनर्विवाह को लचीला बनाया।

स्वामी जी ने महिला व्रतों का खण्डन किया जिससे महिलाएं अन्धविश्वास से बाहर निकल सकें। आर्य समाज ने बाल विवाह एवं वृद्ध विवाह का खुलकर विरोध किया। इन्होंने एक एक्ट लाया जिसका नाम शारदा एक्ट था। इन्होंने कहां कि, जब पुरुषों को पुनर्विवाह करने की आज्ञा दी जाती है तब महिलाओं को दूसरे विवाह से क्यों रोका जाय। ब्राह्मण विधवाओं के सम्बन्ध में वे कहते है कि यदि ब्रह्मचर्यपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें तो अच्छा है। स्वामी जी ने महिलाओं को अन्ध विश्वासों से उबरने की प्रेरणा दी वे व्रतों का खण्डन करते है कहते है कि यह महिलाओं में अन्धविश्वास को जन्म देता है यदि महिला उस व्रत को नहीं करती है तो अपशगुन की कल्पना करने लगती है। आर्य समाजी महिलाओं का इनमें विश्वास नहीं है। इन्होंने महिलाओं को ऊच–नीच, शूद्र, पवित्र के भेदभाव को खत्म करके इनकों समान अधिकार दिलाया। इन्होंने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकला। शारदा एक्ट के तहत बाल विवाह को प्रतिबन्धित किया।

स्वामी विवेकानन्द का महिलाओं के सम्बन्ध में विचार–

स्वामी विवेकानन्द महिलाओं के आध्यात्मिक आदर्श को श्रेष्ठ मानते है। प्राचीन मनीषियों ने भारतीय महिलाओं के लिए जो मर्यादाएं स्थापित की ये उसका समर्थन करते है, महिलाओं के लिए विवाह सम्बन्ध में जो कानून बनाये गये थे, उसके समर्थक थे। वे महिलाओं को सचेत करते है कि, वे पाश्चात्य महिलाओं का अनुसरण न करें । स्वामी जी महिला पुरूष की समानता का समर्थन करते हुए कहते है कि, ''जब आत्मा में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तो महिला पुरूष को लिंग भेद के आधार पर बांटना उचित नहीं है। दोनों में बाहरी भेद होने के बावजूद कोई भेद नहीं है। समाज को प्रेरित करते हुए कहते है कि, वर्तमान दशा में महिलाओं का प्रथम उद्धार करना होगा। सर्वसाधारण को उठाना होगा, तभी तो भारत में कल्याण होगा। मनुष्य युद्ध तथा कठिन शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, इसलिए वे समझते है कि वे अधिक श्रेष्ठ है और इसके साथ स्त्री जाति की शारीरिक दुर्बलता तथा युद्धपराड़मुखता की तुलना करते है, पर यह अन्याय है। महिला भी उतनी ही साहसी होती है, जितना की पुरूष अपने–अपने ढंग से दोनों ही अच्छे है। यह सम्पूर्ण विश्व सन्तुलित है।''[7] स्वामी जी उन शास्त्रों की आलोचना करते है, जो महिलाओं को ज्ञान, भक्ति की अधिकारिणी नहीं मानता। ये मानते है कि, महिलाओं को योग्य, सक्षम और कामकाजी बनाना आवश्यक है। इन्होंने महिला शिक्षा के प्रचार–प्रसार पर बल दिया वे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने पर जोर देते है लेकिन नाटक व उपन्यास को छोड़कर। वे देश के विकास के लिए ब्रह्मचारियों की नियुक्ति करके, कुमारियों को शिक्षा देने का समर्थन

किया। वे पुरूषों को फटकारते है कि, तुमने उसे (महिलाओं) को पतित बनाया और गुलाम बनाकर घर में बच्चों के पालन–पोषण के लिए रखा। इसलिए पुरूषों का यह कर्त्तव्य है कि वह नारी जाति को सुशिक्षित करें। शिक्षा के द्वारा ही बाल विवाह और विधवा विवाह को खत्म किया जा सकता है। महिलाओं को स्वयं की आत्मरक्षा के तरीके सीखने होगें। विवेकानन्द जी कहते है कि, सती प्रथा एवं जौहर से महिलाएं अपने आपको खत्म कर रही है। विधवा को बलपूर्वक सती करवाने में किस प्रकार के सतीत्व का विकास का दिखाई पड़ता है ? कुसंस्कारों की शिक्षा देकर लोगों से पुण्य कर्म क्यों करवाते हो ? मैं कहता हूँ मुक्त करों, जहां तक हो सकें लोगों के बन्धन खोल दिये जाय।

स्वामी जी कहते है कि यदि महिलाओं को उच्च शिक्षा दी गयी होती तो आज महिलाएं स्वावलम्बी होती और नारी उत्थान के लिए कार्य करती जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास होता। बंगाल के बाल विवाह से दुःखी थे और कहते थे कि महिलाओं को इतनी शिक्षा दी जाय कि वे अपने जीवन का निर्माण कर सके। शिक्षा ही उनमें आत्मबल एवं आत्म सम्मान उत्पन्न कर सकती।

महात्मा ज्योतिबा फुले के दर्शन में महिलाओं की स्थिति–

ज्योतिबा फुले ने महिला उत्थान के अनेक प्रयास किये उन्होंने दलित, पिछड़ी, अनुसूचित जाति, दबी–कुचली महिलाओं को शिक्षित करने का संकल्प लिया उनके समय में महिलाओं को वस्तु की तरह घर की चहारदीवारी में रखा जाता था। उसके सिर्फ कर्त्तव्य थे, अधिकार तो थे ही नहीं वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था की बन्दी बनकर रह गयी थी। इन्होंने शिक्षा को महत्व दिया, कहा कि जब तक दलितों, महिलाओं में शिक्षा का प्रचार–प्रसार नहीं होगा तब तक ये जातियां ऊपर नहीं उठ सकती और इनका अपमान होता रहेगा। वे महिला शिक्षा को लेकर चिन्तित थे, भावी पीढ़ी के लिए इनका शिक्षित होना आवश्यक है। मनुष्य के मूल अधिकारों की स्थापना के लिए उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की जहां वे नारी शिक्षा पर जोर दे रहे थे। वहां वे नारी समानता पर जोर देने लगे। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया बाल विवाह का विरोध किया। उस समय अधिकांश विधवाएं ब्राह्मण जाति की होती थी इन विधवाओं के बारे में फुले ने लिखा कि, शिशु जन्म या शिशु पालन में पूर्ण सुरक्षा एवं गोपनीयता बरती जायेगी। इस प्रयत्न ने महिला मुक्ति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, नये विचारों को जन्म दिया, नई परम्पराएं स्थापित की। सावित्रीबाई ने महिला सेवामण्डल की स्थापना की इसे भारतवर्ष की प्रथम महिला संगठन होने का श्रेय प्राप्त है।

निष्कर्ष–

महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा को रोकथाम हेतु आवश्यकता इस बात की है महिला शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयंसेवी संगठनों एवं महिला उत्थान से संबंधित संचालित विभिन्न संगठनों द्वारा महिलाओं के स्वावलंबन एवं नारी उत्थान के कार्य को प्रबलतापूर्वक आगे बढ़ना होगा जिससे महिलाओं में आर्थिक एवं सामाजिक आत्मनिर्भरता विकसित होगी। इसके साथ ही साथ महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत करने की आवश्यकता है। राज्य को महिलाओं की भागीदारी

को प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे सकारात्मक कदम उठाकर कार्यबल में लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करना, एक सक्षमता सुनिश्चित करना और सामाजिक सहायता सेवाओं जैसा समावेशी वातावरण एवं मातृत्व लाभ प्रदान करना। जहां भी आवश्यकता हो, महिलाओं को आरक्षण प्रदान करके महिला श्रम बल की भागीदारी में सुधार किया जाए। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता विकसित होगी एवं समाज में पितृ सत्तात्मक विचारधारा के प्रति बदलाव आएगा। महिला भी एक नागरिक के तौर पर स्वतंत्र, आत्मनिर्भर एवं पुरुषों के समान जीवन जीने की हकदार बनेगी।

❒

सन्दर्भ –

1. *सरोजनी पाण्डे (2003) भारतीय धर्म, समाज और नारी, ग्रन्थम पब्लिकेशन, कानपुर पृ. 48*
2. *बेनी प्रसाद, उद्धृत (2010) ऋग्वेद संहिता भाग 2, सूक्त 22៥219, मनोज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 25*
3. *देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय (2005) लोकनायक, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ. 112 ।*
4. *बेनी प्रसाद, उद्धृत (2010) ऋग्वेद 1:117:1:179:5:28:6:10:2:8:9, मनोज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 50*
5. *जोसुआ ड्रेसलर (2002) इनसाइक्लोपीडिया ऑफ क्राइम एण्ड जस्टिस, न्यूयार्क मैकमीलन रिफ्रेन्स यू०एस०ए० द्वितीय संस्करण ।*
6. *Lupri, Eugene; Grandin, Elaine (2004) Intimate partner abuse against men (PDF). National Clearinghouse on Family Violence. Archived from the original (PDF) on January 4, 2009. Retrieved on March 10, 2024.*
7. *रेखा मोदी (स०) (1999) एक्यूस्ट फॉर रूट्स, स्त्री शक्ति, स्त्री पब्लिकेशन्स, कोलकाता, पृ. 32 ।*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 19–27

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

सीमांतीकरण के संदर्भ में दिव्यांग अनाथ बालिकाएँ

डॉ. सोमी अली
पोस्ट डॉक्टोरल स्कालर (आई.सी.एस.एस.आर.),
समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
E-mail: somialibhu@gmail.com Mob.+91 7379592408

सारांश

सीमांतीकरण, जिसे सामाजिक बहिष्कार भी कहा जाता है, तब होता है जब लोगों के कुछ समूहों को सामाजिक सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। लिंग, अक्षमता की स्थिति, सामाजिक–आर्थिक स्तर और आयु इत्यादि इनके वंचित रहने का कारण होता है। ऐसे ही वंचित समूहों में से एक समूह अनाथ बच्चों का होता है जिनका कोई सहारा नहीं होता है। बच्चों के अनाथ होने के बहुत से कारण होते है उनमें से एक प्रमुख कारण नवजात का लड़की होना है। परित्याग किए बच्चों में ज्यादा प्रतिशत लड़कियों का होता हैं। यदि लड़की शारीरिक रूप से दिव्यांग हो तो उसके परित्याग की सम्भावना अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियों को लिंग और दिव्यांगता के आधार पर समाज में भेदभाव व बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। सामान्य अर्थ में दिव्यांगता ऐसी शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता है जिसके कारण कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तरह किसी कार्य को करने में अक्षम होता है। प्रस्तुत प्रपत्र का उद्देश्य अनाथ लड़कियों को समाज में किस प्रकार की उपेक्षा व भेदभाव का सामना करना पड़ रहा, को जानना और सरकार द्वारा उनको समाज की मुख्यध ारा से जोड़ने हेतु किन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, इसका विवरणात्मक शोध पद्धति द्वारा विवेचन किया गया है।

मुख्य शब्द– अनाथ लड़की, दिव्यांगता, सीमांतीकरण, भेदभाव, परित्याग।

प्रस्तावना

सीमान्तीकरण परिवर्तन और विकास का अकार्यात्मक पक्ष है। जब विकास के प्रयत्नों के बाद भी नीतियों के दोषपूर्ण होने या स्वयं कमजोर समूहों की अपनी असमर्थताओं के कारण विभिन्न समूह विकास का लाभ पाने की जगह एक अभावपूर्ण और तिरस्कृत जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब इसी दशा को हम सीमान्तीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, इसके अन्तर्गत एक समूह को समाज से बाहर कर दिया जाता है। व्यक्तियों को उनके अधिकारों, अवसरों तथा संसाधनों तक

पहुंच से वंचित कर दिया जाता है। इस कारण वह समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भाग लेने से वंचित रह जाता है।[1]

सीमांतीकरण को सीमांत व्यक्ति के अर्थ के सन्दर्भ में सरलता से समझा जा सकता है।

सीमान्त व्यक्ति–

दो भिन्न एवं विशिष्ट सांस्कृतिक समूहों में सहभागिक होने के कारण द्विधा, असमंजस्यता तथा मानसिक संघर्ष की स्थिति से ग्रस्त व्यक्ति को सीमान्त व्यक्ति की संज्ञा दी गई है। **एम. शेरीफ** ने व्यक्ति की सीमान्तता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि एक सीमान्त व्यक्ति वह है जो अपने समूह के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए भी पराए समूह के मूल्यों को आन्तरिक रूप में स्वीकार करता है। यही द्वन्द्वात्मक स्थिति उसकी सीमान्तता की द्योतक है। दो विरोधी सन्दर्भ–समूहों के बीच पड़ जाने की स्थिति भी सीमान्तता को प्रकट करती है। सीमान्त व्यक्ति की अवधारणा का सामाजिक विज्ञानों में सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय **स्टोनाक्विष्ट** और बाद में **रॉबर्ट ई. पार्क** को जाता है।[2]

रॉबर्ट पार्क ने सीमान्त व्यक्ति के विषय में लिखा है कि 'विभिन्न प्रजातियों के बीच आपसी संबंध से जो नई प्रजाति अथवा पीढ़ी विकसित होती है, वह संक्रमण के दौर से गुजरती है तथा धीरे– धीरे वह अपने समाज में हाशिए पर चली जाती है।'[3]

अक्षमता की स्थिति, लिंग, सामाजिक–आर्थिक स्तर और आयु इत्यादि इनके वंचित रहने का कारण होता है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहुधार्मिक जनसंख्या वाले देश में, सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित समूहों की समस्याएं बहुत बड़ी है। वरिष्ठ नागरिकों, औसत से कम बुद्धि वाले लोग, श्रवण, नेत्रहीन व भाारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, गम्भीर और स्थायी मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति, गरीबी में रहने वाले व्यक्ति, बेघर इत्यादि सीमांत समूहों का उदाहरण है।

इन्हीं समूहों में एक समूह **अनाथ बच्चों** का होता है। बच्चों के अनाथ होने के बहुत से कारण होते है। उनमें से एक प्रमुख कारण गरीबी है। अत्यधिक गरीबी में रहने वाले परिवारों का परिणाम यह होता है कि परिवार अपने बच्चों को खाना खिलाने, शिक्षा देने, चिकित्सा देखभाल प्रदान करने या यहां तक की उनकी देखभाल करने में भी असमर्थ होते है और इसके कारण अक्सर उन्हें छोड़ दिया जाता है। दिव्यांगता या एचआईवी जैसी बीमारियों के साथ पैदा हुए बच्चों को अतिरिक्त देखभाल और चिकित्सा उपचार की आवश्यकता होती है, जिसे गरीब परिवार वहन नहीं कर सकते। इसलिए इन बच्चों को अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ दिया जाता है।

इसके अलावा, जब अत्यधिक गरीबी के इस स्तर को सामाजिक पूर्वाग्रहों के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि दहेज प्रथा और अन्य रीति–रिवाजों के कारण लडकियों को भ्रूण के रूप में छोड़ दिया जाता है या यहां तक की उनकी हत्या भी कर दी जाती है। वही लड़की का अनाथ व दिव्यांग होना आज के समय में कोई आसान बात नहीं हैं। दोनों के रूप में दोहरे भेदभाव से निपटना एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। लड़कियां सबसे अधिक असुरक्षित है। वही लिंग और दिव्यांगता का मिलन अनोखी बाधएं उत्पन्न करता है। दिव्यांग लड़कियों के साथ हिंसा

की सम्भावना उन लड़कियों की तुलना में अधिक होती है जो दिव्यांग नहीं है। **संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोश** अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि दिव्यांगता वाली 40–60 प्रतिशत युवा महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले यौन हिंसा का अनुभव करती है।[4]

आज के समय में लड़कियों को बचाना सिर्फ जीवन बचाने से कही ज्यादा है। यह लैंगिक समानता का माहौल बनाने के बारे में है, खासकर तब जब देश की लगभग आधी आबादी चिंताजनक लिंग श्रेणी से सम्बन्धित है। यह लगभग आधा आंकड़ा भारत की कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत है। यह आंकड़ा 1960 के दशक से लगातार घट रहा है, सम्भवतः उससे भी पहले। आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 20 वर्षों में भारत में लगभग 10 मिलियन लड़कियों को जन्म से पहले या तुरन्त बाद उनके माता–पिता ने मार दिया है। लिंग अनुपात पर आगे के आंकड़े बताते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 1,000 लड़कों पर केवल 927 लड़कियां है। विश्व में सबसे असंतुलित अनुपात और एक आंकड़ा जो अभी भी घट रहा है।[5]

अध्ययन की आवश्यकता

मानव समाज के किसी भी सदस्य का अनाथ होना अपने आप में एक मानवीय त्रासदी है। भारत में ऐसे बच्चों की जनसंख्या विश्व के अन्य देशों की सबसे अधिक है। इन अनाथ बच्चों में एक बड़ी संख्या अनाथ लड़कियों की है। अनाथ लड़कियों को स्थानीय समाज में बोझ समझा जाता है। **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** के अनुसार, 2013 में 11 मिलियन से ज्यादा भारतीय बच्चों को छोड़ दिया गया, जिनमें से 90 प्रतिशत लड़कियाँ थी। बाल अधिकार एनजीओ **बचपन बचाओ आंदोलन** ने बताया कि भारत में लापता होने वाले बच्चों में 65 प्रतिशत लड़कियाँ होती हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि बाल तस्कर गरीब परिवारों से लड़कियों का अपहरण करते हैं और उन्हें वैश्यावृत्ति, भिक्षाावृत्ति, घरेलू नौकरों या कैदियों के रूप में कार्य करवाया जाता है।[6] बड़ी संख्या में होने के बावजूद भारत में इन परित्यक्त लड़कियों की सुरक्षा, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के बजाय, सरकार इनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। यद्यपि बहुत सी सरकारी व गैर–सरकारी संस्थाएं इनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इसलिए यह जानने की विशेष आवश्यकता है कि अनाथ लड़कियों को समाज में किस प्रकार की उपेक्षा व भेदभाव का सामना करना पड़ रहा और सरकार द्वारा उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु किन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अनाथ लड़कियों को समाज में किस प्रकार की उपेक्षा व भेदभाव का सामना करना पड़ रहा और सरकार द्वारा उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु किन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, को जानना है।

अध्ययन की पद्वति

प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक शोध पद्वति पर आधारित है। तथ्यों के संकलन के लिए द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

भारत में दिव्यांग अनाथ लड़कियों की समस्याएं

हेल्प इंडिया किड्स के **जोनाथन बोलबैक** ने कहा कि भारत में लड़कियों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता तो हम कल्पना कर सकते है कि जो लड़की जो किसी भी तरह की शारीरिक व मानसिक दिव्यांग हो उसकी क्या स्थिति होगी।[7]

भारत में दिव्यांग अनाथ लड़कियों की समस्याओं को निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते है–

- **दिव्यांग लड़कियों का गरीब परिवार में कोई महत्व नहीं**

भारत में परिवारों द्वारा बच्चों का परित्याग करना कोई असामान्य बात नहीं है क्योंकि वे उनका पालन–पोशण करने में असमर्थ हैं। दुर्भाग्य से ऐसा लड़कियों के साथ ज्यादा होता है। परित्याग किए गए बच्चे ड्रग्स, गिरोह व सेक्स व्यापार के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। परिवार के नजर में दिव्यांग बच्चे काम नहीं कर सकते और इसलिए वे पैसे नहीं कमा पाएंगे। इस कारण उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और समाज में चुनौतियों का सामना अकेले ही करना पड़ता है।

- **अनाथालयों में उचित देखभाल हेतु अपर्याप्त संसाधन**

लिंग आधारित सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और आर्थिक दबावों के कारण, भारत में अनाथ बच्चों में से अधिकांश लड़कियाँ है। **यूनिसेफ** के अनुसार, भारत में 31 मिलियन अनाथ बच्चे है। **टाइम्स ऑफ इंडिया** की रिपोर्ट के अनुसार, 10 में से 9 परित्यक्त बच्चे लड़कियाँ है। परित्यक्त लड़कियाँ अनाथालयों में डाल दिया जाता है। अनाथ लड़कियों की बड़ी संख्या के कारण, अनाथालयों में अक्सर लड़कियों की उचित देखभाल करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं।[8]

- **लिंग आधारित भेदभाव**

हमारे समाज में लड़कों की तुलना में लड़कियों को परित्याग करने की घटनाएं ज्यादा होती है, ऐसा हमारे समाज की संरचना के कारण है। बीबीसी गुजराती ने सूचना के अधिकार के द्वारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी से जानकारी जुटाई और पाया कि देशभर के अनाथालयों में 1032 लड़कों की तुलना में 1432 लड़कियां गोद लेने के लिए उपलब्ध है। इसे अगर प्रतिशत के आधार पर देखे तो लडकिया लड़कों की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है।[9]

- **दुर्व्यवहार का सामना**

भारत में अनाथ बच्चों के सामने सबसे ज्यादा प्रचलित मुद्दों में से एक है बाल शोषण। देश भर में लड़के और लड़कियां दोनों ही इसके शिकार है। भारत में लगभग 30 मिलियन अनाथ बच्चों में से आधे मिलियन से भी कम बच्चों को आश्रय या अनाथालय में रहने की सुविधा प्राप्त है। आज भी भारत की ज्यादातर अनाथ आबादी सड़कों पर है, जहां वे तस्करी के साथ–साथ बाल शोषण और कई अन्य खतरों के शिकार हैं।[10]

अनाथ बच्चों के लिए चलाए जा रही विभिन्न योजनाएं

केन्द्र सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए चलाए जा रही विभिन्न योजनाएं :–

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम

भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को बच्चों के लिए इस स्कीम की शुरूआत हुई। इसका उद्देश्य उन बच्चों को सहयोग करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू हूई कोविड–19

महामारी की अवधि के दौरान माता–पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता–पिता दोनों को खो दिया है। इसमें निरन्तर तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण को सक्षम बनाना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना और 23 वर्ष की आयु तक उन्हें वित्तीय सहयोग के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है।

स्पांसर योजना (2024)

अनाथ, बेघर, परिवार से परित्यक्त आदि बच्चों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पात्र बच्चों को प्रत्येक माह 4 हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मिशन वात्सल्य योजना–

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए **मिशन वात्यल्य** शुरू किया गया है। वर्ष 2009 से पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने योजनाएं लागू की–

- देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों एवं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए किशोर न्याय कार्यक्रम।
- सड़कों पर रहने वाले बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम।
- बाल गृहों की सहायता हेतु योजना।

वर्ष **2010** में इन कार्यक्रमों का विलय **एकीकृत बाल संरक्षण योजना** में कर दिया गया। वर्ष **2017** में **बाल संरक्षण योजना** का नाम परिवर्तित किया गया। वर्ष **2021–22** में **मिशन वात्यल्य** के रूप में प्रस्तुत किया गया।

मिशन वात्सल्य के घटकों में शामिल है–

- वैधानिक निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार करना।
- सेवा वितरण सरचनाओं को सुदृढ़ बनाना।
- संस्थागत देखभाल और सेवाओं को उन्नत बनाना।
- गैर–संस्थागत समुदाय–आधारित देखभाल को प्रोत्याहित करना।
- आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।

विभिन्न राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए चलाए जा रही विभिन्न योजनाएं

राज्य	योजना	उद्देश्य
उत्तर प्रदेश	मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना	अनाथ/निराश्रित बचचों की देखरेख हेतु 4000 रू. की प्रतिमाह वित्तीय सहायता करेगी।
उत्तराखण्ड	मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना	इसके तहत कोविड–19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों को प्रतिमाह 3 हजार रू. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश	**मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना**	बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग देकर समाज में पुर्नस्थापित करना एवं 18 वर्ष तक की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने सम्बन्धियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अन्य कोविड 19 महावारी के कारण मृत माता–पिता की अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता।
झारखण्ड	**फोस्टर केयर योजना**	ऐसे बच्चों को संरक्षण प्रदान करना है, जो पारिवारिक देखभाल मिलने की सम्भावना न के बराबर है। जिसमें गैर परिवार के लोग जिनके द्वारा किसी अनाथ बच्चे की देखभाल की जा रही है को सरकार द्वारा 2000 रू. की राशि प्रति माह उनके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा।
राजस्थान	**पालनहार योजना**	अनाथ बच्चों के पालन पोशण एवं शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसमें 5 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों को 500 रू0 की आर्थिक सहायता एवं स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 रू0 प्रतिमाह प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त 2000रू0 प्रतिवर्ष बच्चों को प्रदान की जाती है जिससे वह वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खरीद सके।
	राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता योजना	जिनके माता–पिता दोनों की या एक की भी मृत्यु कोरोना के कारण हुईं है तो ऐसे अनाथ बच्चों को तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख रू0 का अनुदान व 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रू0 की सहायता तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रू0 की सहायता।
	वात्सल्य (फोस्टर केयर) अभियान और बाल अधिकार ई–बाक्स	वात्सल्य अभियान 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पारिवारिक माहौल में बढ़ने का एक अवसर है। पारिवारिक देखभाल से वंचित एवं बाल देखभाल संस्थाओं में रह रहे बच्चों को पारिवारिक देखभाल एवं स्नेह एवं दुलार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार बाल अधिकारिता विभाग के माध्यम से **वात्सल्य योजना** चला रही है। इसमें बच्चों को 4000 रू0 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
		किसी भी प्रकार की हिंसा, अपराध या शोषण के शिकार बच्चे **बाल अधिकार ई–बॉक्स** के माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन करके या ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या भेजकर बाल अधिकारिता विभाग से तत्काल राहत प्राप्त कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़	**महतारी दुलार योजना**	कोरोना के कारण ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता–पिता को खो दिया है, उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही उन्हें पहली से आठवीं तक के ऐसे बच्चों को 500

		रू0 प्रतिमाह और 9 वीं सं 12 वीं तक के बच्चों को 1000 रू0 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी।
हरियाणा	**हरिहर योजना**	राज्य के बाल देखभाल संस्थानों से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को रोजगार, शैक्षिक और वित्तीय लाभ प्रदान करना है।
ओड़िसा	**आर्शीवाद योजना**	इस योजना के तहत सरकार उन अनाथ बच्चों को हर महीने 2,500 रू0 देगी जिसने अपने माता–पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है। आर्थिक सहायता के तौर पर दी जाने वाली ये धनराशि लाभार्थियों की देखभाल करने वाले के बैंक अकाउंट में तब तक भेजी जाएगी, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते। इसके अलावा अगर देखभाल करने वाले किसी व्यक्ति के न होने पर ऐसे बच्चों को बाल गृह भेजा जाता है तो उन्हें हर महीने 1,000 रू0 दिए जाएंगे। वही कोरोना माहवारी से जिन बच्चों के माता–पिता में से कमाने वाले सदस्य की मौत हो गई है तो उन्हें 1,500 रू0 दिए जाएंगे।
हिमाचल	**सुख आश्रय योजना**	इसके अन्तर्गत अनाथ बच्चों को हर महीने जेब खर्च के लिए 4 हजार रू0 मिल रहे है।
मणिपुर	**प्रोजेक्ट असिस्ट**	सांम्प्रदायिक, जातिगत, जातीय या आतंकवादी हिंसा के कारण अनाथ या बेसहारा हुए बच्चों को उनकी देखरेख, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
त्रिपुरा	**मुख्यमंत्री बाल सेवा प्रकल्प**	सरकार उन बच्चों को 3,500 रू0 प्रतिमाह प्रदान करेगी जो महामारी से अनाथ हो गए हैं और 18 वर्ष की आयु तक अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ रह रहे है। अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के समय 50,000 रू0 भी देगी।
असम	**मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना**	जिन बच्चों ने अपने माता–पिता दोनों को खो दिया है और जिनकी देखरेख उनके परिवार के सदस्य कर रहे हैं, वे प्रति माह 3,500 रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बिहार	**परवरिश योजना**	इसके अन्तर्गत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 1000 रू0 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
गोवा	**देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के कल्याण हेतु योजना**	इस योजना का उद्देश्य उन स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करना है जो 18 वर्ष की आयु तक के निराश्रित और अनाथ बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

गुजरात	**मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना**	इसके अन्तर्गत अपने माता–पिता को खो चुके बच्चों को 4,000रू0 मासिक वजीफा मिलेगा।
नागालैण्ड	**वात्सल्य योजना**	अनाथ बच्चों को शिक्षा और पालन–पोषण के अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर चाइल्डकेयर संस्थान छोड़ने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता।
तमिलनाडु	**थायुमानवर योजना**	इस योजना में निराश्रित, अकेले रहने वाले बुजुर्ग, एकल अभिभावक परिवार, अनाथ बच्चे, मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति और विशेष सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों वाले परिवार शामिल हैं। इस योजना के तहत उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त शिक्षा, रोजगाार के अवसर, कौशल विकास और आवास की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
तेलंगाना	–	तेलंगाना के मंत्री केटी रामा राव ने घोषणा की कि सरकार 'अनाथ नीति' पेश करेगी। जिसके तहत वह राज्य में अनाथ बच्चों को गोद लेने और उन्हें मानवीय आधार पर सभी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय। इन्हें 'राज्य के बच्चे' कहा जाएगा।
महाराष्ट्र	**बाल संगोपन योजना**	बेघर, अनाथ और कमजोर बच्चे इस योजना के अन्तर्गत लाभ के पात्र है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता 1125 रू0 प्रतिमाह प्रदान की जाती हैं जिसे बढ़ाकर 2500 रू0 किया जा सकता है।
	–	महाराष्ट्र सरकार ने 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले माता–पिता दोनों को खो चुके अनाथ बच्चों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में एक फीसदी का आरक्षण देने का निर्णय किया है।
दिल्ली	–	कोविड–19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 25 वर्ष की आयु तक इन्हें 2,500 रू0 की राशि प्रदान की जाएगी।
केरल	–	जिन बच्चों ने कोविड–19 के कारण अपने माता–पिता को खो दिया है, उन्हें तत्काल राहत के रूप में 3,00,000 रू0 दिए जाएंगे और 18 वर्ष की आयु तक 2,000 रू0 की मासिक राशि जारी की जाएगी।

निष्कर्ष

इस प्रकार हम देखते है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों को छोड़ने की घटनाएं ज्यादा होती है। यह मुख्य रूप से हमारी समाज की संरचना के कारण है। भारतीय समाज में आज

भी लड़कों को परिवार का वारिस माना जाता है, जबकि लड़कियों को बोझ माना जाता है। इस कारण समाज और सरकार का दायित्व है कि इनके कल्याण व विकास में अग्रणी भूमिका निभाए। बहुत से सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों द्वारा इनके कल्याण में सहयोग कर रहे है साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार भी विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करके इनके सर्वागींण विकास हेतु अग्रसर है। परन्तु आज भी इनके प्रति हो रही हिंसात्मक घटनाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सरकार को इन घटनाओं का गहनता से अवलोकन कर इन घटनाओं के घटित होने का कारण पता कर उसके आधार पर इनके कल्याण व विकास के कार्य करने चाहिए।

❐

सन्दर्भ –

1. *Makwana Gautam & Elizabeth, H (2023). Challenges for Children from the Marginalized India Communities' 'Vidya – A JOURNAL OF GUJARAT UNIVERSITY, Vol.15 No. 4.*
2. *रावत, हरिकृष्ण (2011) उच्चत्तर समाजशास्त्र विश्वकोश, रावत पब्लिकेशन्स।*
3. *पाण्डेय, वन्दना (2018) हाशिए का समाज : अवधारणा एवं स्वरूप, International Journal of Scientific & Innovative Research Studies, ISSN : 2347-7660.*
4. *Cushen, Christina ¼2023½. Navigating the unique challenges faced by Girls with Disabilities*
5. *https://www. ghrh.org/blog/navigating-the-unique-challenges-faced-by-girls-with-disabilities*
6. *https://www.theguardian.com/world/2008/jun/19/india-children*
7. *Soni, Sonya (2019). The Structural Violence Inflicted on Girls in India,s Orphanages. Published in AMPLIFY.*
8. *Bourdon, Julie ¼2016½. Girls with disabilities face hardship in India https://www.mnnonline.org/news/girls-disabilities-face-hardship-india/*
9. *Neelakandan, Laya ¼2021½. How Poverity Affects Girls'Orphanages in India*
10. *परमार, अर्जुन (2021) बाल दिवस : देश के अनाथालयों में लड़को से 38 फीसदी अधिक लड़कियां https:// www.bbc.com/hindi/india-59280126*
11. *Orphan Life Foundation ¼2023½. 5 Problems Faced By Orphan Children In India https://orphanlifefoundation.org/5-problems-faced-by-orphan-children-in-india/*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 28–39

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

स्वयं सहायता समूह एवं ग्रामीण परिवेश का बदलता परिदृश्य एक समाजशास्त्रीय दृष्टि

मोनिका वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा (उ.प्र.)
E-mail: monikaverma2020786@gmail.com

सारांश

ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों अर्थात महिलाओं, छोटे और सीमान्त किसानों को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, ऋण, बचत और आय सृजन की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे है। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह को, विकास की क्रियाओं को करने वाले एक सशक्त माध्यम के रूप में देखा जा रहा है जिसके लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी निकायों व स्वयं सेवी संस्थानों द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। हरदोई जिले में कई स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहें है। प्रस्तुत शोध पत्र में 20 स्वयं सहायता समूह की 100 महिलाओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनकी सफलता एवं असफलता के पीछे कारकों को देखा गया है। शोध में यह पाया गया कि समूह द्वारा महिलाओं का न केवल आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है बल्कि महिलाओं में सामुदायिक एवं पारिवारिक कार्यों के महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने एवं नियन्त्रण की क्षमता में भी वृद्धि हुई है।

मुख्य शब्दः– स्वयं सहयता समूह, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना

भारत एक विकासशील देश है। दुनिया के अधिकांश देशों में भारत की स्थिति को महत्वपूर्ण माना जा सकता है।[1] स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षो के उपरान्त ही भारत की अर्थव्यवस्था ने तीव्र गति से विकास किया है लेकिन आज भी कुछ क्षेत्रों में भारत की स्थिति संतोषजनक नही है।[2] भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ आज भी कई प्रकार की समस्यायें मौजूद है जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, कुपोषण, मातृत्व मृत्यु दर आदि। सरकार द्वारा समस्याओं के निदान के लिए समय–समय पर विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते रहे है जैसे कि गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में सामाजिक एवं

वित्तीय निवेश किये गये है जिसमें अधिकांश कार्यक्रम टाप–डाउन दृष्टिकोण पर आधारित थे और जो सभी व्यक्तियों की जरूरतों पर समान रूप से विचार नही करते थे।

2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 68.8 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है।[3] तथा देश की इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज करके देश का विकास नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है जिसके मूल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषकर मानव संसाधनों का विकास सम्मलित है। मानव सांसधन, विकास में समाज के कमजोर वर्गो की जीवन दशाओं में सुधार करने के प्रयास के रूप में निर्धनता निवारण, विपणन, साख (ऋण) तथा मुख्य रूप से नारी साक्षरता, महिला सशक्तिकरण आदि शामिल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद तक ग्रामीण क्षेत्रों में महाजन और व्यापारी, ऋण और बहुत ऊँची दरों में ब्याज वसूलने के प्रयास में सफल रहे है। भारत सरकार द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त करने हेतु 1969 में सामाजिक बैकिंग व्यवस्था प्रारम्भ की गई तथा सन 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.) का आरम्भ किया। इस दिशा में बांग्लादेश के प्रमुख अर्थशास्त्री मुहम्मद युनुस का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने 1970 से ही लघु वित्त आन्दोलन की शुरूआत की थी जिसके तहत गरीबों विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गयी।[4] इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की जिसकी मूल युक्ति–'**गांव बढ़ें तो देश बढ़ें' (नाबार्ड)** की संकल्पना निहित है। वर्ष 1999 में इस दिशा में बडा प्रयास किया गया जब (आई. आर. डी. पी.) को स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के (एस. जी. एस. वाई.) के रूप में रूपान्तरित किया गया। यह कार्यक्रम समूह विकास पर आधारित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम (एन. आर. एल. एम.) था, जहाँ ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया।[5] समाज का समग्र विकास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य का चेहरा बदलने के लिए महिला–सशक्तिकरण आवश्यक है। जिसके लिये अधिकांश मात्रा में महिला स्वयं सहायता समूह संगठित करने का लक्ष्य रखा गया है। किसी भी देश का विकास महिलाओं को हाशिएं पर रखकर संभव नही है। महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित कर के ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास की संकल्पना की जा सकती है। भारत की कुल आबादी की आधी आबादी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त किए बिना सुदृढ़ भारत का सपना नहीं पूरा किया जा सकता है।[6]

वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह को महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।[7] स्वयं सहायता समूह का गठन कई कारणों से किया जाता है फिर भी उनका प्राथमिक उद्देश्य पूँजी तक पहुँच बनाने के लिए बैंक लिंकेज एवं ऋण के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है।[8] स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों मे संगठित छोटे कार्यात्मक समूह है, जो सदस्यों के संसाधनो को आपस में मितव्ययिता एवं ऋण के माध्यम से आगे बढ़ाते है। महिला स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य अधिकांश मात्रा में महिलाओं को समूह में संगठित करना है। समूह में संगठित महिलायें आर्थिक रूप से सशक्त होती है तथा महिलाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य, पारम्परिक और आधुनिक कृषि, सूक्ष्म ऋण, पशु चिकित्सा पद्धतियों, जल संसाधन प्रबंधन, और अन्य मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की नयी भूमिका का विकास हुआ हैं। समूहों की संख्या मे वृद्धि से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए नये द्वार खुले हैं। लेन–देन पर आधारित स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण विकास की प्रगति की राह पर एक नया विचार उभर कर सामने आया है। भारत में बैकों के राष्ट्रीयकरण के बावजूद यह व्यवस्था गरीबों के लेन–देन के स्तर तक कार्य नहीं कर रही थी। लेकिन स्वयं सहायता समूह के गठन एवं इसके विकास ने ग्रामीणों को बैंकों से जोड़ने का कार्य किया है।[9] इस नयी व्यवस्था में महिलाओ और गरीबों की प्रभुत्वशाली भूमिका है। स्वाभाविक रूप से गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और ऐसी अन्य एजेंसियां जिसके द्वारा महिलाओं को नये कार्यबल के रूप मे संभव बनाया गया है।[10] ये संगठन सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बैकों के द्वारा ऋण प्रदान करने तक विस्तृत करती है। योजना में निश्चितता एवं शीघ्रता के लिए समूह के मार्गदर्शन मे दुग्धशाला, मुर्गीपालन, जैविक खाद, बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता, सब्जी लगाना आदि विशिष्ट रूप से ग्रामीण प्रोजेक्ट में संलग्न है। भारत में नयी गठित पंचायते ऐसे सामूहिक गतिविधियों के उत्प्रेरक के रूप मे उपयोगी साबित हुईं है तथा पंचायते, सहकारी संघ एवं समूह एक दूसरे को सहयोग करते हुए ग्रामीण विकास की योजनाओं में विभिन्न प्रकार से स्वस्थ्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकते है

संबंधित साहित्य की समीक्षा

सालगांवकर एवं सालगांवकर (2009)[11] अपने लेख **"पंचायत एण्ड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप : अण्डर स्टैंडिंग द सिम्बायोसिस"** में लिखते है कि ग्राम पंचायत विकेन्द्रीकरण भाासन की प्रमुख इकाई है जिससे सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं एवं नीतियों का क्रियान्यवयन एवं मूल्याकंन किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाएं न केवल विभिन्न रोजगार के अवसर प्राप्त कर रही है बल्कि वे विभिन्न प्रकार के नेतृत्व वाले कार्यों जैसे ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों के कार्य–कारणी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है।

गलब एण्ड रॉव (2003)[12] अपने भाोधपत्र **"वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप पॉवर्टी एलिवेशन एण्ड एम्पावरमेंट"** में आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबी का निवारण करने एवं महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों–डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एण्ड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज (डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए.), साउथ एशिया पॉवर्ट्री एलीवेशन प्रोग्राम (एस. ए. पी. ए. पी.) तथा आन्ध्रप्रदेश रूरल पॉवर्ट्री प्रोजेक्ट तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों का मूल्याकंन आधारित शोधपत्र है। आन्ध्रप्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन तथा महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी योजनाओं में स्वयं सहायता समूह के गठन एवं विकास के लिए बड़ा स्थान प्रदान किया है। यह शोध पत्र गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण आधारित तीन स्वयं सहायता समूह मॉडल, आन्ध्रप्रदेश में कैसे कार्य कर रहे हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं तथा उनके दृष्टिकोण आपस में कैसे भिन्न हैं तथा इनके योगदान की पड़ताल करता हैं। कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्याकंन करने से स्पष्ट होता है कि महिलाएं गैर पारंपरिक कार्यों जैसे कृषि, विपणन लघु उघोग कार्य कर रही है। छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से वे अपनी आय पर नियन्त्रण करना सीख रही है।

श्रीरामुलु एवं खान (2008)[13] अपने भाोध अध्ययन **"पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप : ए स्टडी इन आन्ध्र प्रदेश"** में यह बताया है कि भारत दुनिया

के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है तथा सभी को स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का आकड़ा न्यूनाधिक है तथा इसके कारण, धार्मिक सामाजिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक हो सकते है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की सशक्त करने की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है तथा भारत की सरकार महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है जिसमें विशेष रूप से नौवीं और दसवीं पंचवर्षीय तथा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एण्ड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज (डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए.) प्रमुख हैं। यह शोध पत्र महिलाओं के विशेष रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण पर केन्द्रित है। शोध में अध्ययन क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश के अनन्त पुर जिला को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछडें होने के कारण चयनित किया गया है तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं के राजनीतिक विकास से सम्बन्धित आकड़े एकत्रित कर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि महिलाओं में समूह की मदद से राजनीतिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

राज एवं वैश (2023)[14] शोधपत्र **"एस. एच. जी. फॉर वुमेन्स कन्ट्रीव्यूशन टू एकोनॉमिक डेवलेपमेंट"** में लिखते है कि राष्ट्र का विकास महिला सशक्तीकरण पर निर्भर करता है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए इस बात पर केन्द्रित है। स्वयं सहायता समूह समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु काम करता है। यह शोध उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चॉका ब्लॉक पर केन्द्रित है तथा शोध पत्र में यह बताया गया कि एस. एच. जी. से जुड़ने के बाद महिलाओं की आय सुधार आया है तथा वे परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने में भी सक्षम हुई है।

रॉय एवं दास (2014)[15] ने अपने शोध पत्र **"इवेलुएटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप ए विलेज लेबल एनालिसिस"**, बीरभूम जिले के दो ग्राम सुरूल एवं माहिदापुर पर आधारित है। सुरूल ग्राम में विभिन्न जातियों के लोग थे तथा मोहिदापुर ग्राम में मुस्लिम परिवारों की संख्या अधिक थी। अध्ययन में समूह की कार्य प्रणाली तथा समूह द्वारा महिलाओं के हुए सम्भावित सामाजिक बदलाव पर चर्चा की है। सूक्ष्म वित्तीय व्यस्था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों में एक सशक्त कारण है जिससे सामाजिक पूँजी का निर्माण एवं ऋण लेने की व्यस्था विकसित होती है। अध्ययन में विभिन्न चरों जैसे– प्रारम्भिक औपचारिक शिक्षा तथा समूह का कार्य निष्पादन क्या एक दूसरे से स्वतंत्र है या एक दूसरे को प्रभावित करते है का मूल्याकंन किया गया है तथा यह निष्कर्ष निकला है कि दोनो चर एक दूसरें से स्वतंत्र है तथा इसी प्रकार अन्य चरों का एक दूसरें से सम्बन्ध और प्रभावों की जॉच की गयी है।

शोध का उद्देश्य

- महिलाओं द्वारा समूह में सम्मिलित होने के कारणों को जानना।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार की संभावनाओं का अवसर का विश्लेषण करना।
- समूह सदस्यता ग्रहण करने के उपरान्त महिलाओं की परिवर्तित सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।

अध्ययन पद्धति

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तथा प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, मातृ मृत्युदर, लैंगिक भेदभाव जैसी समस्यायें मौजूद है। अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के द्वारा अध्ययन क्षेत्र के रूप में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बहेन्दर ब्लॉक का चयन किया गया है तथा प्रतिदर्श चयन के माध्यम से चार ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित चार ग्राम पंचायतों में से 20 महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया है और प्राथमिक तथ्यों के संग्रह हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं समूह साक्षात्कार का प्रयोग किया गया है, जिसके लिये 100 महिलाओं का प्रतिदर्श निदर्शन के माध्यम से चयन करके सारणी एवं ग्राफ के माध्यम से उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

ग्रामीण समाज का अवधारणात्मक परिचय

ग्रामीण समाज, जहां पर व्यक्ति सामूहिक हित से सम्बन्धित होते है, वे सामान उद्देश्य साझा करते है, प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते है तथा इन सब के अतिरिक्त भारतीय समाज जाति आधारित पेशे पर निर्भर रहता है। समाजशास्त्रीय विचारक ईमाइल दर्खाइम ने ग्रामीण समाज को यान्त्रिक समाज की संज्ञा दी है। आपके अनुसार यान्त्रिक समाज में व्यक्ति सामूहिक चेतना एवं समान विश्वास से साझा करते है। टॉनीज के अनुसार जैमिनशॉफ्ट जहां व्यक्ति सामान रक्त सम्बन्धी एवं समान मान्यताओं पर आधारित भावनाओं पर आधारित होते है, ग्रामीण समाज है **(रिट्जर, 1992)[16]।** भारत की आधी आबादी से अधिक जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीब परिवारों को सामाजिक पूंजी बनाने में मदद करता है तथा महिलाओं की आर्थिक निवेश में भागीदारी को भी बढ़ाता है। पितृसत्तात्मक समाज, वह स्थिति है जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीजिक क्षेत्रों में पुरूषों को महिलाओं से श्रेष्ठ समझा जाता है तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया से उन्हें बाहर रखा जाता है इस प्रकार समाज में महिलाएं हाशिए पर रहती है। एक ओर महिलाओं को पत्नी, गृहिणी, कामगार इत्यादि की भूमिका निभानी पड़ती है वही दूसरी तरफ ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवरोध है, जो महिलाओं को कामगार नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करने में सहायता नही करते है।[17] परियोजना के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट ग्रामीण परिवारों में से अधिक से अधिक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में शामिल करना आवश्यक है। मिशन में ऐसी कार्यनीतियां तैयार की जाती है, जिसमें गरीब समुदाय अपनी गरीबी से उबरने का प्रयास करते है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए गए प्रयास सदस्यों को नाएला कबीर, की सशक्तिकरण परिभाषा के अनुसाार सार्थक जीवन के विकल्प चुनने में सक्षम बना सकता है तथा समूह के सदस्य अपने बचत और खर्च करने पैटर्न को भी बदल सकते है जिससे अन्ततः आर्थिक सामाजिक राजनैतिक मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण का उदय हो सकता है।[18]

गॉधीवादी दर्शन के अनुसार, आदर्श ग्राम का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्वरोजगार एवं आर्थिक विकास है और यह सब सभी के लिये (ऑल फॉर ऑल) के सिद्धान्त पर कार्य करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परियोजना के अन्तर्गत अधिकांश मात्रा में ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर संसाधनो तक उनकी पँहुच को सुनिश्चित कराना है। नीति निर्माताओं एवं

सहायता कर्मियों ने यह माना कि समूह इस प्रकार की नीतियों के निर्माण में सहायक है जिससे सामाजिक पूंजी का निर्माण विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आय निर्माण, जोखिम में कमी एवं सार्वजनिक सेवा प्रावधान के साधन के रूप देखा जा सकता है।[19]

महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले संगठन

महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज भी समाज पुरूष–प्रधान मानसिकता से ग्रसित है। जहाँ एक तरफ शहरों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है वही दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की स्थिति को आज भी अच्छा नही कहा जा सकता है। वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन करने के उद्देश्य से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन. आर. एल. एम.) तथा रॉजीव गॉधी विकास परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य ग्रमीण आजीविका मिशन (यू. पी. एस. आर. एल. एम.) के संयुक्त प्रयास द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में समूहों के संगठित करने में गैर सरकारी संगठनों के प्रयास भी सराहनीय है।

तालिका क्रमांक : 1

महिलाओं को समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने वाले कारक

क्रं.	प्रोत्साहित करने वाले साधन	संख्या	प्रतिशत
1	सरकारी समूह की महिलाएं (सरकार द्वारा चयनित)	44	44
2	दूसरे समूह की महिलाएं	16	16
3	गैर सरकारी संगठन	27	27
4	अन्य तरीके	13	13
	कुल	**100**	**100**

तालिका क्रमांक : 1 महिलाओं को समूह की सदस्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करने वाले कारकों के आधार पर वितरण से सम्बन्धित है। जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा समूह को बनवाने के चयनित महिलाओं द्वारा प्रोत्साहित होकर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 44 सबसे अधिक है, गैर सरकारी संगठन द्वारा प्रोत्साहित होकर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 27, दूसरे समूह की महिलाओं द्वारा प्रोत्साहित होकर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 16 है तथा अन्य तरीको से सूचना प्राप्त कर समूह बनाने वाली महिलाओं का प्रतिशत 13 है। विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा समूह बनवाने के लिये समूह की जिन महिलाओ को चयनित किया गया है उनके द्वारा अपनी जिम्मेदारी का पालन उचित रूप से किया जा रहा है।

समूह की समयावधि

स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है। समूह की समयावधि से यह स्पष्ट होता है कि समूह कितना पुराना है अर्थात प्रदेश में सरकार कितने वर्षो से महिलाओ के विकास की ओर ध्यान दे रही है तथा कौन–कौन से अन्य संगठन है जो समूह

के संगठन एवं विकास के लिए कार्य कर रहे है। समूह की समयावधि से समूह की संचित पूजीं का भी निर्धारण किया जाता है तथा बैंक द्वारा लोन भी समूह नियमितता एवं उनके ऋण वापस करने की अवधि के अनुसार दिया जाता है।

तालिका क्रमांक : 2

समूह की समयावधि

क्रं.	समूह की समयावधि	संख्या	प्रतिशत
1	1–2 वर्ष	10	10
2	2–3 वर्ष	35	35
3	3–4 वर्ष	30	30
4	4 वर्ष से अधिक	25	25
	कुल	100	100

उपरोक्त तालिका क्रमांक : 2 के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि समूह 2–3 वर्ष की अवधि में गठित होने वाले समूहों का प्रतिशत सबसे अधिक है तथा इसके बाद 3–4 वर्ष की अवधि में गठित होने वाले समूह का प्रतिशत 30 है जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश समूह का गठ़न 3–4 वर्ष के अवधि पहले हुआ है।

महिलाओं के समूह की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य कारण

महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक बचत एवं समय पर ऋण उपलब्ध होना है। समूह के माध्यम से महिलायें छोटी–छोटी बचत करना सीखती है तथा बचत एवं समूह निधि का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करती है। आर्थिक रूप से सशक्त महिलायें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उचित पहल कर उसे कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

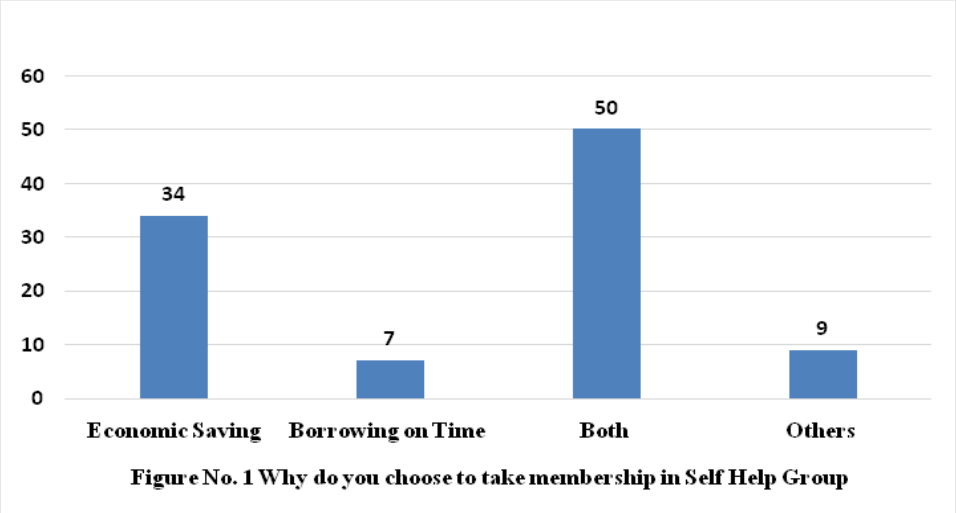

Figure No. 1 Why do you choose to take membership in Self Help Group

चित्र संख्या 1 : महिलाओं के समूह की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य कारण

चित्र संख्या : 1 में आर्थिक बचत एवं ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से सबसे अधिक 50 प्रतिशत महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण की है। केवल आर्थिक बचत के उद्देश्य से 34 प्रतिशत

महिलाओ ने, समय पर ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से 7 प्रतिशत महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण की है और अन्य कारणों जैसे (***हम कुछ करना चाहते थे, समूह में कोई पढ़ा लिखा सदस्य नही था***) से समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलाओं की संख्या 9 प्रतिशत है। नायर एवं मनोहरन (2012)[20] ने पाया कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्राप्त करने का मुख्य कारण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती है समूह के माध्यम से वे छोट–छोटी बचत करना सीखती है तथा ऋण एवं साख, महिलाओं की आय बढ़ाने, निवेश, संम्पति सृजन तथा व्यसाय संचालन की प्रक्रिया में मदद करते है

समूह में शामिल विभिन्न वर्गो की महिलायें

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की स्थिति दयनीय है, फिर भी जनतान्त्रिक माहौल व स्त्रियों की भागीदारी के चलते स्थिति में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया है। वर्तमान समय में स्वयं सहायता समूह की सदस्यता समाज के सभी वर्गों की महिलाओ ने ग्रहण की है। **चित्र संख्या : 2** में जाति श्रेणी के अनुसार महिलाओं के वितरण का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न जातियों (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) की मिश्रित जातीय संरचना है। चित्र संख्या : 2 से स्पष्ट है कि कुल 100 महिलाओं मे से सबसे अधिक, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं का है, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का 23 प्रतिशत है, सामान्य वर्ग की महिलाओं का 17 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का 15 प्रतिशत है।

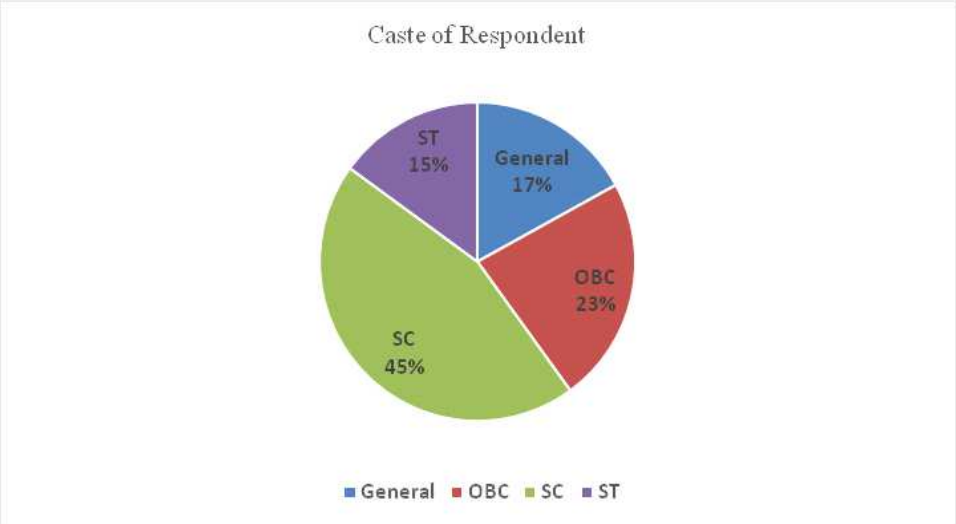

चित्र संख्या 2 : समूह में भाामिल विभिन्न वर्गो की महिलायें

समूह की महिलाओं द्वारा समूह से लिये गये ऋण का प्रयोग

ग्रामीण गरीब महिलाओं को अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये गॉव के जमीदारों एवं साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। जिसके लिये साहूकार कभी–कभी मनचाहा ब्यॉज भी वसूलते थे। समूहों के निर्माण से महिलाएं अब अपनी विभिन्न आवश्यक

कार्यों को समूह से ऋण लेकर करने लगी है तथा उन्हें अब ऋण के लिये किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नही करना पडता है।

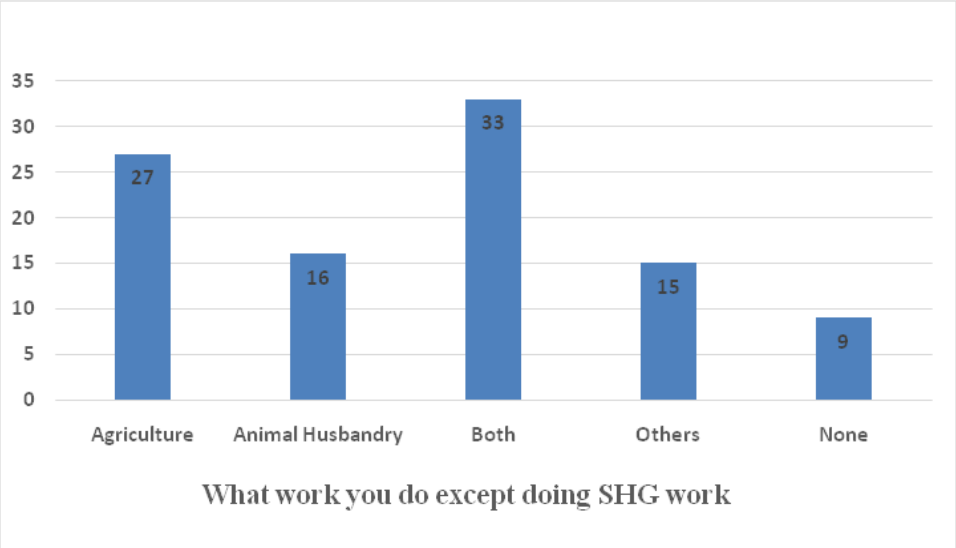

चित्र संख्या 3 : समूह की महिलाओं द्वारा समूह से लिये गये ऋण का प्रयोग

चित्र संख्या : 3 के वितरण से स्पश्ट है कि समूह की सबसे अधिक 33 प्रतिशत महिलाएं समूह से लिये गये ऋण का उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं जैसे–पशुपालन, बच्चों की शिक्षा तथा कृषि कार्यों को करने में, 27 प्रतिशत महिलायें कृषि, 16 प्रतिशत महिलायें पशुपालन, 15 प्रतिशत महिलायें अन्य, 9 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ना ही ऋण लिया गया और ना ही ऋण उपयोग किया गया। उपरोक्त वितरण से स्पश्ट है कि समूह की अधिकांश महिलाऐं ने लिये गये ऋण के द्वारा अपनी विभिन्न आवश्यकताओं (पशुपालन, बच्चों की शिक्षा तथा कृषि कार्यों) की पूर्ति करती है। दहल (2014)[21] समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं ने पैसे संम्भानले की सशक्ता को महसूस किया है। कई महिलाओं ने समूह की सदस्यता लेने से पहले समान की खरीद बिक्री में कभी भाग नहीं लिया था और उन्हें समूह की सदस्यता के पहले कभी भी घरेलू लेखाकंन करने के अनुमति नहीं दी गयी थी तथा सदस्यता के बाद कई महिलाओं ने अपने घरेलू वित्तीय प्रबंधन की बढ़ती भागीदारी को बताया है।

आर्थिक सुदृढता एवं महिला सशक्तीकरण

सशक्तिकरण से हमारा क्या तात्पर्य है? क्या इसे हम जीवन जीने की दशा में सुधार कह सकते है? नोबेल पुरश्कार विजेता अमर्त्य सेन (2003)[22] बताते है कि स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की जीवन जीने की दशाओं में परिलक्षित होती है तथा किसी व्यक्ति की क्षमता उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं, सामाजिक विशेषताओं जैसे कारकों पर निर्भर करती है। विकास के उद्देश्यों की माप के लिए कुछ सार्वभौमिक रूप से मूल्यवान कार्यप्रणाली पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो अस्तित्व और कल्याण के बुनियादी सिद्धान्तों से सम्बन्धित हों। सेन, उचित पोषण, अच्छा स्वस्थ्य और आश्रय का सहारा लेते हुए कहते है कि यदि इन बहुत ही बुनियादी कार्यकाजी उपलब्धियों में लिंग अंतर है तो उन्हें अन्तर्निहित क्षमताओं में असमानताओं के प्रमाण के रूप में

लिया जा सकता है। देश की आधी आबादी, महिलाओं के समुचित विकास के बिना हम देश के प्रगति की कल्पना नही कर सकते है। महिलाओं के समुचित विकास के लिये उनका आर्थिक रूप से सशक्त होना आवश्यक है। क्योंकि सदियों से महिलाओं को आर्थिक निर्णयन की प्रक्रिया से अलग रखा गया है। विकास की प्रक्रिया महिलााओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने से वे न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होगी बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक जिम्मेदारियों को निभाने में भी सक्षम होगी। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं में अन्य की तुलना में अधिक आत्मविश्वास होता है। जिससे वे स्वयं सामाजिक सुरक्षा एवं अपने अधिकारों के लिये प्रयास कर सकती है। महिलाएं समूह द्वारा अर्जित किए हुये धनराशि या किसी अन्य स्त्रोत से मिले पैसों का उपयोग बच्चों का भरण–पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में करती है।

तालिका क्रमांक : 3

आर्थिक सुदृढता की महिलाओं के सशक्तीकरण मे भूमिका के आधार पर वितरण

क्र.	आर्थिक सुदृढता एवं सशक्तीकरण	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	28	28
2	अधिकाशतः	34	34
3	थोड़ा बहुत	33	33
4	नही	05	05
	कुल	100	100

तलिका क्रमांक : 3 के वितरण से स्पष्ट होता है कि निदर्शन में शामिल कुल 100 महिलाओं मे से 28 प्रतिशत महिलाएं मानती है कि आर्थिक सुदृढता महिलाओं के सशक्तिकरण में पूणर्तः भूमिका निभाती है, 34 प्रतिशत मानती है कि अधिकाशतः तथा 33 प्रतिशत महिलाए मानती है कि थोड़ा बहुत भूमिका निभाती है। केवल 5 प्रतिशत महिलाएं ये मानती है कि आर्थिक सुदृढता महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका नही निभाती है। (पेरियोडी, 2006)[23] अपने अध्ययन में बताते है कि समूह के समर्थन से महिलाएं सार्थक निर्णय लेने एवं अपने जीवन में साकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हुयी है महिलाओं ने अपने गांवों में आत्मविश्वास से चलने और एक समूह में अधिकारियों के पास तथा विभिन्न हित धारकों के साथ काम करने में अधिक सहजता महसूस की है, जबकि समूह की सदस्यता से पहले महिलाएं स्वयं को असमर्थ समझती थी। अतः उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आर्थिक सुदृढता महिलाओं के सशक्तीकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मूल्यांकन

देश के विकास का सबसे प्रभावी तरीका महिलाओं का विकास है। आर्थिक क्षेत्र में देश की प्रगति की गवाही तो दुनिया भर के अर्थशास्त्री दे रहे है। लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति में वांछित परिवर्तन नही आया है। जहाँ महानगरों की महिलाएं सशक्त हो रही है वही दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के ओर रूख करते ही हालात एकदम उल्टा दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूह सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि तथा एक समान महिलाओं को संगठित करने का माध्यम बना। **यह महिलाओं का महिलाओं के लिये तथा महिलाओं के**

द्वारा भासन, के आधार पर कार्य करता है। ग्रामीण महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण के लिये आवश्यक है कि महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं–आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक का प्रभावी सम्मिलन हो। स्वयं सहायता समूह की सदस्यता प्राप्त करने वाली महिलाएं समूह के माध्यम से न केवल विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे–मुर्गी पालन, बकरी पालन, कृषि, जैविक खाद, दुग्ध उत्पादन, सिलाई–बुनाई जैसी विभिन्न कार्यों को करती है, बल्कि राजनीति में भी वे अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दर्ज कराती है। समूह के माध्यम से महिलायें विभिन्न संगठनो (कमेटियों) की सदस्य बनती है। जिससे उन्हें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, बैंक, और रोजगार जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विशयों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है। समूह के माध्यम से समाज की सभी वर्गों की महिलाओं की स्थिति में वांछित परिवर्तन हो रहे है। जिसके लिये सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन दोनो प्रयासरत हैं। वर्तमान में महिलाओं के परिवार के सदस्यों द्वारा समूह की महत्ता को समझा जाने लगा है। वे महिलाओं को समूह की मीटिंग में आने से नही रोकते है तथा जरूरत पड़ने पर वे महिलाओं की मदद भी करते है। राष्ट्र के विकास के लिये महिला सशक्तीकरण से अधिक प्रभावशाली तरीका कुछ भी नही है। भारत की अधिकांश आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूहों का निर्माण विशेषकर महिलाओं के विकास के लिये मील का पत्थर साबित होते दिखाई पड़ रहें है। ❒

सन्दर्भ –

1- *TELLIS,J.T., "INDIA AS A LEADING POWER"CARNEGIE ENDOWMENT FOR INTERNA TIONAL PEACE 2016 PP. 3-7*

2- *आर्थिक समीक्षा 2020 https:pib.gov.in/PressRelease.aspx?PRID=1693268*

3- *सेंससऑफ इण्डिया 2011 https://censusindia.gov.in/website/data/population-finder*

4- *श्रीवास्तव ए एम.ए मुहम्मद युनुस का योगदान योजना 2008 पृ. 18*

5- *Mitra, S., Kande, N., "Institution Building and Capacity Building in NRLM", South Asia Agricul ture and Rural Growth Discussion Note World Bank Series March*

6- *"शर्मा, डी. शशांन्ति मैत्री मिशन संस्थान मरूस्थलीय ग्रामीण विकास का पुरोधा कुरूक्षेत्र जुलाई 2013*

7- *Jakimov, T. Kibly, P., "Empowering women: A Critique of the Blueprint for Self Help Group in India", Indian Journal of Gender Studies 2006 pp. 375-400*

8- *Gugerty, M. K., Biscaye, P., Anderson, C., "Delivering Development? Evidence on Self Help Group as Development Intermediaries in South Asia and Africa", Development policy Review 2019 pp. 129-151*

9- *Rutherford,S., "The Poor and Their Money", Delhi Oxford University Press Singh 2000*

10- *Rogaly, B., "Microfinance Evangelism Destitute Women and the Hard Selling of a New Anti – Poverty Formula", Development in Practice 1996 pp. 100-112*

11- *Salgaonkar, S., Salgaonkar, B., "Panchayat and Women Self Help Group: Understanding the Symbiosis Indian Political Science Association", April- June 2009 pp. 481-494*

12- *Galab, S Chandrashekhar Rao N., "Women's Self-Help Group, Poverty Alleviation and Empow erment Economic and Political Weekly", 22 March - 4 April, 2003. pp. 1274-1283*

13- *Shreemulu, G. And Hushenkhan, P., "Political Empowerment of Women Through Self Help Group (SHG's): A Study in Andra Pradesh", Indian Political Science Association (July-Sep 2008) pp. 609-617.*

14- *Raj, A. and Vaish. A, "SHG for Women Contribution to Economic Development", International Journal of Innovation Research in Engineering and Management" April 2023 pp. 32-37.*

15- *Roy, P. and Das, R., "Evaluating Self Help Group a Village Level Analysis", International Journal of Science Volume March 2014*

16- *Ritzer, G., "Sociological Theory, Third Edition, New York Mac Graw Hill,1992*
17- *Omvet, G., "The Origin of Patriarchy, the Creation OF Patriarchy by Gerda Lerner", Oxford University Press New York 1986 pp. 368*
18- *Kabeer, N., "Between Affiliation and Autonomy navigating Pathways of Women's Empower ment and Gender Justice in Rular Bangladesh", Development and Change 2011. pp. 499-528*
19- *Pandolfelli, L., Ruth, M., "Gender and Collective Action; Motivation, Effectiveness and Impact", Journal of International Development 2008*
20- *Nair, K., Manoharan, "Self Help Group; A New Paradigm Shift for Women Empowerment", International Journal of Research in Commerce Economics and Management`, March 2012 pp. 81-84*
21- *Dahal, S., "A Study of Women's Self-Help Group and Impact of SHG Participation on Women Empowerment and Livelihood in Lamachur Village of Nepal", Department of International Envi ronment and Development Studies, Norwegian University of Life Science Norway, 2014*
22- *Sen, A.K., "Gender and Co-Operative Conflict in I Tinker Persistent Inequalities", New Delhi Oxford Press1990*
23- *Mathwrani, V. and Periodi, V., "The Sangha Mane the Translation of an Internal Need in to a Physical Space", Indian Journal of Gender Studies 2006 pp. 317-349*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 40–47

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

गढवाल हिमालय की मूर्तिकला में शिव का नटराज स्वरुप

डॉ. श्वेता कुमारी
सहायक प्रोफेसर, पायलट बाबा इन्स्टीटयूट, हरिद्वार (उत्तराखंड)–249408
E-mail: skmishra19797@gmail.com Mob. 9917418478

भारत की आध्यात्मिक संस्कृति में आदि योगी शिव के विविध लीला स्वरूप की पुष्कल व्याख्या प्राप्त होती है। इन बहुविध स्वरूपों में आरण्यक देव शिव अपने नृत्यनिमग्न छवि में नटराज नाम से अभिहित किए गए हैं। शिव के नटराज स्वरूप का विशिष्ट अर्थ नटराज के शाब्दिक अर्थ में निहित है। नटराज शब्द दो शब्दों से बना है 'नट' और 'राज' जिसका अभिप्राय है नट अर्थात् नर्त्तक और राज अर्थात् स्वामी। इस प्रकार नटराज स्वरूप में शिव नृतधिपति के रूप में एक उत्तम नर्त्तक है।

भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नर्त्तन कला को दो वर्गों में विभक्त किया है। ये दो वर्ग नतः और नृत्य हैं। नृत्तः में भावविहीन रूप में लय और ताल के अनुरूप अंगों का संचालन किया जाता है वहीं नृत्य में भाव युक्त अभिव्यंजना के साथ अंगों का संचालन किया जाता है।[1] नटराज स्वरूप में शिव का नृत्तः नर्त्तन का मूल रूप है। शिव नृतः के इस बहुआयामी स्वरूप में सृष्टि का सम्पूर्ण लौकिक एवं अलौकिक ज्ञान समाहित है। योगीश्वर शिव के इस विहंगम नटराज स्वरूप में सृष्टि की कारक और संहारक दोनों शक्तियाँ निहित हगै।

आनंद वेंकटेश कुमारस्वामी ने शिव के इस नृत्यनिमग्न छवि को सृष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव तथा अनुग्रह आदि पंचक्रियाओं का प्रतिनिधि स्वरूप कहा है।[2] इन पंचक्रियाओं में सृष्टि से तात्पर्य सृजन या उद्भव से है, स्थिति से शिव के संरक्षणकर्त्ता के गुणों का पता चलता है, प्रलय शिव के संहारक गुणों का संकेतक है, तिरोभाव इस शक्ति में आत्मा से सत्य को अप्रकट रखने का संकेत प्राप्त होता है। अनुग्रह का तात्पर्य ज्ञान प्रदान करके आत्मा को बंधनमुक्त करना है।

भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में शिव को प्रथम नर्त्तक कहा गया है।[3] पाणिनि कृत अष्टाध्यायी के 'महेश्वरसूत्र' की उत्पत्ति शिव के नटराज स्वरूप से ही मानी गई है। इस सूत्र में यह वर्णन प्राप्त होता है कि नाटराज शिव नृत्त के अवसान पर ऋषियों की सिद्धि और मुक्ति के लिए चौदह बार डमरू का वादन करते हैं, जिसकी प्रत्येक ध्वनि से एक वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। इस

प्रकार 14 बार डमरू की ध्वनि से 14 वर्णमाला उत्पन्न हुई जो भाषा के मूल रूप व्याकरण में विद्यमान है।

इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के इस वर्णन में शिव को लेखन कला के जनक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।[4]

नटराज शिव का नृत्त ताडंव के नाम से प्रसिद्ध है। शिव नृत्त का तांडव संबोधन शिव के प्रिय शिष्य तण्डु से संबद्ध है, जिन्होंने शिव से नृत्त की शिक्षा ग्रहण करके इसमें गायन और वादन का समायोजन किया तथा इसकी शिक्षा नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि को प्रदान किए। इसी कारण शिव का नृत्त तण्डु मुनि के नाम पर ताण्डव नाम से प्रसिद्ध हुआ।

शिव के इस तांडव नृत्त के दो रूप हैं। शिव जब आनंद विभोर होकर नृत्त करते हैं, तो उसे आनंद तांडव कहा जाता है जबकि शिव जब उग्र भाव में नृत्त करते हैं, तो उसे रौद्र तांडव कहा जाता है।[5]

शिव के नटराज स्वरूप के आध्यात्मिक पक्ष में वैज्ञानिक तथ्य निहित हैं जिसके अन्वेषणोपरांत भौतिक विज्ञानी फ्रित्जॉफ कापरा ने अपनी पुस्तक 'द ताओं ऑव फिजिक्स' में इस तथ्य को स्वीकारा है और लिखा है कि 'शिव का नृत्त सभी अस्तित्व का आधार है। शिव का नृत्त स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वह सब मौलिक नहीं है, वरन यह भ्रम है, जो हमेशा परिवर्तित होते रहता है। शिव नृत्त की भाँति ही प्रत्येक सबएटॉमिकक कण सिर्फ ऊर्जा का प्रवाह ही नहीं वरन् ऊर्जा का नृत्त भी है, जिसमें सृजन और विलय की प्रक्रिया निहित है।[6] जेनेवा के सर्न नामक परमाणु केन्द्र पर स्थापित शिव की नटराज प्रतिमा इस मान्यता का ज्वलंत उदाहरण है।

पुराणों में शिव के नटराज स्वरूप से संबंधित विविध कथानकों का वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में शिव के नटराज स्वरूप से सम्बंधित विविध कथानकों का वर्णन प्राप्त होता है लिंग पुराण में वर्णित कथानक के अनुसार दारूक नामक असुर ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या करके अपार शक्ति का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में प्राप्त इस अपार शक्ति के अहंकार में दारूक देवगणों, ऋषिगणों एवं ब्राह्मणों को अपने आतंक और अत्याचार से पीड़ित करने लगा। असुर दारूक के इस प्रताड़ना से त्रस्त होकर ब्रह्मा सहित सभी देवगण विष्णु की शरण में जाकर दारूक के आतंक की व्यथा बताए। देवगणों से असुर दारूक के आतंक का वृतांत सुनकर विष्णु ने अपनी शरण मे आए देवगणों को असुर दारूक के अंत का रहस्य बताये जिसके अनुसार दारूक की मृत्यु किसी स्त्री–शक्ति के द्वारा ही संभव था। विष्णु द्वारा बताए असुर दारूक के मृत्यु के रहस्य पर विचार करके देवगण स्त्रीवेश धारण कर दारूक असुर से युद्ध प्रारम्भ किए। असुर दारूक ने इस युद्ध में स्त्रीवेशधारी देवताओं को अपनी अपार शक्ति से परास्त कर दिया। असुर दारूक से परास्त होने के बाद सभी देवगण निराश होकर शिव की शरण में गए। अपने शरण में आए देवगणों से दारूक असुर के आतंक की बात सुनकर शिव अपनी वामांगिनी शक्ति स्वरूपा पार्वती से दारूक असुर का अंत कर देवगणों को उसके आतंक से मुक्त करने की प्राप्त किए। शिव की प्रार्थना पर पार्वती अपने एक अंश के साथ शिव के शरीर में प्रविष्ट की तथा शिव के कंठ में स्थित विष से संयोग कर अतिशक्तिशाली देवी का स्वरूप धारण कर शिव के

तीसरे नेत्र से बाहर प्रकट हुई। देवी के इस वीभत्स स्वरूप को देखकर देवता भी भयातुर हो गए। दिव्यवस्त्राभूषणों से सुसज्जित, त्रिनेत्रधारी देवी अपने हस्त में धारण त्रिशूल से असुर दारूक पर प्रहार कर उसका अंत कर दी। परन्तु दारूक के अंत के बाद भी देवी की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई। देवी के इस क्रोधाग्नि से सम्पूर्ण सृष्टि तप्त होने लगी तब देवी के क्रोधाग्नि से सृष्टि की रक्षा के लिए शिव एक बालक का रूप धारण करके देवी के समक्ष रूदन करने लगे। बालक को रूदन करते देखकर देवी का ममत्व जागृत हो उठा और देवी रूदन करते बालक को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। तब शिव रूपी बालक दुग्धपान के साथ ही देवी के क्रोधाग्नि का भी पान कर लिए। क्रोधाग्नि का अंत होते ही देवी मूर्च्छित हो गई। देवी के मूर्च्छित होने पर शिव उन्हें चेतनावस्था में लाने के लिए दिव्य नर्त्तक स्वरूप धारण कर अति मनोमुग्धकारी नृत्य करने लगे। शिव के इस विहंगम नृत्त का पान कर देवी चेतनावस्था प्राप्त कर स्वयं भी नृत्यनिमग्न हो गई। इस प्रकार देवी को चेतन अवस्था में लाने के लिए शिव द्वारा धारण अलौकिक नर्त्तक स्वरूप नटराज नाम से लोकप्रिय हुआ।[7] शिव पुराण में इससे भिन्न कथानक का वर्णन प्राप्त होता है जिसके अनुसार हिमालय तनया पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से अपने पितृ गृह का त्याग कर वन में कठोर तपस्या करने चली गई। पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के तपःस्थली में प्रकट हुए तथा पार्वती से वरदान माँगने को कहा। शिव का दर्शन प्राप्त कर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई तथा शिव से आग्रहपूर्वक बोली कि हे देव यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरे माता–पिता से मुझे आग्रहपूर्वक माँगकर मुझे अपनी वामांगिनी के रूप में वरण करें। पार्वती के इस अनुरागपूर्ण आग्रह को पूर्ण करने का वचन देकर शिव पार्वती से उनके पितृ गृह लौटने की विनती किए। शिव की आज्ञा से पार्वती अपने पिता हिमवान् के महल में लौट गई। पार्वती के घर लौटने पर राजा हिमवान् और माता मैना ने उत्सव का आयोजन किया तथा राजा हिमवान इस शुभ बेला में गंगा स्नान के लिए गए। इसी अवसर पर शिव अपने दिए वचनानुसार हिमवान के महल में नट का वेश धारण कर उपस्थित हुए तथा अपने मनमोहक नृत्तः से सबका मन मोह लिया नट रूपी शिव के नृत्तः से आनंद विभोर होकर मैना उन्हें दक्षिणा के रूप में मोती–माणिक्य से भरा हुआ थाल भेंट करने के लिए ले आई। परन्तु नट रूप धारण किए शिव इस भेंट को अस्वीकार कर दिए तथा महारानी मैना से बोले कि यदि आप मेरे नृत्त से आनंदित होकर भेंट देना चाहती हैं तो अपनी पुत्री पार्वती को मुझे प्रदान करे। नट रूपी शिव का यह वचन सुनकर मैना कुपित हो गई। उसी समय हिमवान् भी आ गए और पूरी घटना से अवगत होकर अपने सेवकों से नट को महल से बाहर निकालने की आज्ञा दिए। बहुत प्रयत्न करके भी कोई नट रूपी शिव को निकालने में सफल नहीं हुआ। इसी समय हिमवान को अपने विविध लीला रूपों का दर्शन कराये, जिसमें पहले विष्णु, तब ब्रह्मा तब सूर्य और अंत में पार्वती सहित रूद्र रूप का। शिव का यह वास्तविक स्वरूप देखने के बाद हिमवान और मैना शिव के हाथो में अपनी कन्या पार्वती को समर्पित किए। इस प्रकार पार्वती को प्राप्त करने के लिए शिव ने नर्तक रूप धारण किया।[8]

प्रतिमा लक्षण

पुराणों एवं प्रतिमाशास्त्रीय ग्रंथों में नटराज स्वरूप के प्रतिमालक्षणों का वर्णन प्राप्त होता है। मत्स्यपुराण[9] में वर्णित लक्षणों के अनुसार नटराज स्वरूप की प्रतिमा में शिव को दसभुजी

रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। इस स्वरूप की प्रतिमा में शिव को गजचर्मधारी प्रदर्शित करना चाहिए। इस स्वरूप की प्रतिमा में शिव को विशाखस्थान युक्त यानि दोनों पैरों के मध्य एक हस्त की दूरी के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। नटराज शिव प्रतिमा में पार्श्व देव के रूप में गणेश, पार्वती तथा उनके गणों को प्रदर्शित करना चाहिए। शिव को नटराज स्वरूप प्रतिमा में चार, आठ, दस और सोलह भुजाओं के साथ प्रदर्शित करना चाहिए। इस स्वरूप में देवता कि अपनी भुजाओं में खड्ग, खेटक, त्रिशूल, दण्ड, कपाल, सर्प, अक्षमाला, खट्वांग, परशु, धनुष, बाण, शंख, चक्र, गदा आदि धारण किए हुए प्रदर्शित करना चाहिए। इस प्रतिमा में शिव के दो या दो से अधिक हस्त नृत्य मुद्रा में तथा एक अभय मुद्रा में प्रदर्शित होना चाहिए। इस प्रकार प्रतिमाशास्त्रीय लक्षणों का अध्ययन करके हम देखते हैं कि शिव का नटराज स्वरूप सृष्टि की संरचना और उसकी क्रियाओं की मूक अभिव्यंजना है, जिसका विश्लेषण करके हम सृष्टि के गूढ़ रहस्यों का उद्‌भेदन कर सकते हैं।

शिव के इस स्वरूप के प्रतिमाशास्त्रीय लक्षणों का अध्ययन करके हम देखते हैं कि शिव का नटराज स्वरूप सृष्टि की संरचना और उसकी क्रियाओं की मूक अभिव्यंजना है, जिसका विश्लेषण करके हम सृष्टि की गति के गूढ रहस्यों का उद्‌भेदन कर सकते हैं।

शिव के इस स्वरूप के विश्लेषण क्रम में शिव के हाथ में धारण डमरू सृजन का प्रतीक है, क्योंकि डमरू से उत्पन्न ध्वनि ज्ञान का संकेताक्षर है। ध्वनि से ही अक्षर की उत्पत्ति होती है और इसी अक्षर से ज्ञान अर्थात् बुद्धि उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ नृत्तरत शिव के हस्त में धारण अग्नि विनाश का प्रतीक है, जो इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि सृष्टि की सभी वस्तुओं का विनाश होता है। परन्तु यह नश्वरता नव–निर्माण का प्रतीक है। अभय मुद्रा धारण शिव का एक हस्त भयमुक्त जीवन का संदेश देता है, क्योंकि भयमुक्त जीवन में ही सृजन और चिंतन की असीम शक्ति होती है। इस प्रकार शिव अभय मुद्रा धारण कर भयमुक्त होकर अपने कर्त्तव्य पथ पर अग्रसर रहने का संदेश देते हैं। नृत्तरत शिव का एक हस्त उनके भूमि से थोड़ा ऊपर उठे हुए पैर की ओर संकेत करता है, जो इस बात का प्रतीक है कि स्वतंत्र होकर कर्मपथ पर अग्रसर रहना चाहिए। अर्थात् कर्मपथ में प्रतिरोध के बंधन से स्वतंत्र हो जाना। नृत्तरत शिव के पैर के नीचे अपस्मार पुरुष का अंकन अज्ञानता रूपी अंधकार पर ज्ञान के विजय का प्रतीक है। इस स्वरूप में शिव के एक हस्त में सर्पवलय का अंकन शरीर के अंदर विद्यमान कुण्डलिनी शक्ति का प्रतीक है। शिव की लहराती जटाएँ सृष्टि में प्रवाहित आनंद का प्रतीक है। वहीं शिव के एक कर्ण में धारण मकर कुंडल पुरुष का और एक कर्ण में धारण पत्रकुंडल स्त्रीबोधक है, जो कि पुरुष और प्रकृति के एकत्व या एकाकार स्वरूप का प्रतीक है, जो समस्त ब्रह्माण्डीय ऊर्जा की गतिशीलता का कारक है। नृत्तरत शिव के चारों तरफ अग्नि–वलय का अंकन जो कि सामान्यतः दक्षिण भारतीय नटराज शिव के शिल्पांकन में दृष्टिगोचर होता है। यह अग्नि–वलय सृष्टि चक्र का द्योतक है तथा इस चक्र में शिव का लयबद्ध नृत्त सृष्टि की निरंतरता को दर्शाता है। इस प्रकार नटराज शिव के स्वरूप के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिव का नटराज स्वरूप सृष्टि के निरंतरता और गतिशीलता की प्रेरक शक्तियों का उद्‌भेदन करता है।[10]

भारतीय मूर्त्तिकला में नटराज शिव प्रतिमाएँ – शिव के विविध स्वरूपों का अंकन भारतीय मूर्त्तिकला की महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विषय–वस्तु रही है। इन विविध स्वरूपों में भारतीय दर्शन

का प्रतिनिधित्व करता शिव के नटराज स्वरूप का प्रारम्भिक अंकन शुंगकालीन शिव की वीणाधर दक्षिणा प्रतिमा में द्रष्टव्य होता है, जो वर्तमान में गोपी कृष्ण कनौरिया संग्रह में संग्रहित है। काल क्रमिक विकास के क्रम में शिव की नटराज स्वरूप प्रतिमाओं का प्रतिमा लाक्षणिक ग्रंथों पर आधारित स्पष्ट शिल्पांकन गुप्तकालीन मूर्त्तिकला में दृष्टिगोचर होने लगती है। गुप्तकाल से उत्तरगुप्त काल की समयावधि में शिव के नृत्यरत स्वरूप का शिल्पांकन प्रभूत संख्या में किया गया है। एलौरा, भुवनेश्वर, एलिफेंटा, ओसियाँ, खजुराहों, मोढेरा, तंजौर, बादामी आदि प्रमुख कला केन्द्रों से इस स्वरूप की उत्कृष्ट प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं।

इस प्रकार नटराज स्वरूप प्रतिमाओं के शिल्पांकन काल के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस स्वरूप की प्रतिमाओं का प्रारम्भिक शिल्पांकन उत्तर भारतीय मूर्त्तिकला में की गई, परन्तु इसका समृद्धतम शिल्पांकन स्वरूप दक्षिण भारतीय मूर्त्तिकला में दृष्टव्य है। इस स्वरूप का शिल्पांकन दक्षिण भारतीय मूर्त्तिकला में 7वीं सदी अर्थात् पल्लव काल से मिलनी प्रारम्भ हो जाती है। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत की नटराज प्रतिमाओं में तुलनात्मक रूप से शिल्पगत विविधताएँ दृष्टिगोचर होती है। उत्तर भारतीय मूर्त्तिकला में नटराज शिव का अंकन एक पीठिका के ऊपर किए जाने की परम्परा प्रचलित रही है। साथ ही नृत्यरत शिव के साथ नंदी की प्रतिमा के शिल्पांकन की परम्परा प्रचलित रही है। उत्तर भारतीय कला में शिव की नृत्तःरत प्रतिमा को 'नटेश' नाम से अभिहित किया गया है। शिव की नटेश प्रतिमा का अंकन शैव अथवा वैष्णव मंदिरों में प्रस्तर शिल्प के रूप में प्राप्त होती है।[11]

गढ़वाल हिमालय की मूर्तिकला में नटराज शिव–उत्तर भारतीय मूर्त्तिकला में नटराज स्वरूप प्रतिमाओं के अंकन में गढ़वाल हिमालय की मूर्त्तिकला का भी अपना गौरवपूर्ण स्थान है। आदिकाल से शिव की विविध लीलाओं के आनन गढ़वाल हिमालय में शिव स्वरूपों का मूर्त्तन यहाँ की लोकसंस्कृति की स्वाभाविक प्रकृति रही है। शिव के विविध स्वरूपों में से नटराज स्वरूप का मूर्त्तन गढ़वाल–हिमालय की प्रकृति प्रदत्त कला प्रतीत होती है। शिव के नटराज स्वरूप का सम्पूर्ण सारगर्भ देवराज हिमालय की उत्पत्ति संबंधी वैज्ञानिकता में सन्निहित है। शिव के नटराज स्वरूप और हिमालय की उत्पत्ति की सादृश्यता अध्यात्म और विज्ञान के मध्य शून्य विरोधाभास की साक्षी है। अतः प्रकृति के इस मनोहारी आनन में शिव के नृत्तः स्वरूप का मूर्त्तन कलाकार की स्वाभाविक प्रवृत्ति का उत्कृष्ट प्रमाण है। गढ़वाल हिमालय की पर्वतीय भूमि में पाषाण द्रव्यों की सुलभता के कारण नटराज प्रतिमाओं का मूर्त्तन प्रस्तर शिल्प में प्राप्त होता है। गढ़वाल की मूर्त्तिकला में निर्मित शिव की नटराज स्वरूप प्रतिमाएँ स्वतंत्र एवं चैत्य गवाक्षों के मध्य शिल्पांकित की गई है।[12]

गढ़वाल हिमालय से प्राप्त नटराज प्रतिमाओं का विवरण निम्न प्रकार से है– इस स्वरूप की पहली प्रतिमा (चित्र संख्या–1) देहरादून जिले के लाखामण्डल स्थित लाक्षेश्वर शिव मंदिर के संग्रहालय से प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा में त्रिनेत्रधारी देवता को भूमि के ऊपर ललित मुद्रा में नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया गया है। प्रतिमा में देवता का दायाँ पैर कुंचित मुद्रा में है जबकि बायाँ पैर भूमि पर स्थित प्रदर्शित है। अष्टभुजी देवता के दो मुख्य हाथों में बायाँ हाथ पताकाहस्त मुद्रा में पद्ममुकुल धारण किए हुए तथा दायाँ हाथ गजहस्त मुद्रा में प्रदर्शित हैं। देवता को अपने दो उर्ध्व हाथों में विषभुजंग धारण किए हुए जिसका फण दायीं ओर है प्रदर्शित किया गया है।

देवता दायें दो हाथों में से एक हाथ में डमरू धारण किए हुए तथा दूसरा हाथ देवता के दाएँ पार्श्व में पीठिका पर आसीन पार्वती के हनु का स्पर्श करते हुए प्रदर्शित है। प्रतिमा में देवता के शेष दो बायें हाथों में से एक हाथ में त्रिशूल तथा दूसरा हाथ अपने जंघे पर स्थित प्रदर्शित है। इस प्रतिमा में शिव जटामुकुट, रत्नकुंडल, हार सर्पकटिबंध, बाजूबंध, कंगन और घुटने तक लटकती हुई वनमाला तथा धोती (परिधान) से सुसज्जित प्रदर्शित किए गए हैं। प्रतिमा में दाएँ पार्श्व में आसीन पार्वती नृत्य को ताल देने के लिए वीणा वादन करते हुए प्रदर्शित है। साथ ही पार्वती शिव शंभू की ओर मुखाभिमुख होकर उनके नृत्य की मनमोहक छवि से आनंदविभोर होते हुए प्रदर्शित हैं। जिन्हें देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि वे गिरिश्वर के नृत्त के अनुरूप वीणा–वादन कर रही हैं। वहीं देवता के बाएँ पार्श्व में नंदीकेश्वर को अपने सम्मुख रखे दो मृदंगों का वादन करते हुए प्रदर्शित किया गया है।

नृत्त और संगीत के समन्वयी कला रूप को प्रदर्शित करती हुई यह प्रतिमा छठीं–सातवीं शताब्दी ई. की प्रतीत होती है।

इस स्वरूप की दूसरी प्रतिमा (चित्र संख्या–2) चमोली जिले के गोपीनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है। मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपरी भित्ति पर अंकित इस प्रतिमा में देवता को एक पीठिका के ऊपर ललित मुद्रा में नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया गया है। प्रतिमा में चतुर्भुजी देवता को दो मुख्य हाथों से वीणा–वादन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। शेष दो हाथों में से दाएँ हाथ में त्रिशूल तथा बाएँ हाथ में डमरू धारण किए हुए प्रदर्शित किया गया है। देवता को जटामुकुट, दाएँ कर्ण में मकर कुंडल तथा बाएँ कर्ण में पत्रकुंडल, सर्पमाल, कंगन, सर्पकटिबंध तथा परिधान के रूप में व्याघ्रचर्म धारण किए हुए प्रदर्शित किए गए है। प्रतिमा में पीठिका के दायें पार्श्व में एक गण को मृदंग वादन करते हुए प्रदर्शन किया गया है, जबकि पीठिका के बाएँ पार्श्व में एक आसनस्थ आकृति प्रदर्शित की गई है, जो खण्डित अवस्था में है। इस प्रकार इस प्रतिमा में कलाकार ने शिव को नृत्यसम्राट के साथ–साथ संगीत के परमज्ञाता के रूप में प्रदर्शित करने का सफल प्रयास किया है। प्रतिमा में शिव के कटि भाग से ऊपर के शरीर को आगे की ओर हल्का झुका हुआ वीणा वादन की वास्तविक आंगिक अवस्था को प्रदर्शित करती है, जो कलाकार के संगति मर्मज्ञता का परिचायक है। शिव के मुखमण्डल पर ध्यानस्थ भाव का अंकन नृत्त और संगीत में तल्लीनता की अवस्था का वास्तविक चित्रण है।

इस स्वरूप की तीसरी प्रतिमा (चित्र संख्या–3) चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित मंदिर के गर्भगृह से प्राप्त हुई है। इस प्रतिमा में देवता को ललित मुद्रा में नृत्य करते हुए प्रदर्शित किया गया है। प्रतिमा में देवता का बायाँ पैर भूमि पर स्थित है जबकि दाहिना पैर कुंचित मुद्रा में प्रदर्शित है। दसभुजी देवता को अपने दो मुख्य हाथों से वीणा–वादन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। देवता के शेष दायें चार हाथों में से तीन हाथ में त्रिशूल, डमरू एवं विषभुजंग प्रदर्शित है जबकि चौथा हाथ खण्डित अवस्था में है। देवता के शेष चार बाएँ हाथों में से तीन हाथों में खटवांग, खेटक एवं कपाल प्रदर्शित है, जबकि चौथे हाथ में धार्य वस्तु अस्पष्ट है। प्रतिमा में देवता को अर्द्धचंद्र तथा पुष्प–पत्र से शोभित जटामुकुट, सर्प एवं पत्रकुंडल, हार, रूद्राक्षमाला, वक्षस्थल पर श्रीवत्स, यज्ञोपवीत, केयूर, कंगन, कटिबबंध, मेखला, वनमाला तथा पादजालक आदि अलंकरणों से अलंकृत प्रदर्शित किया गया है। प्रतिमा में नीचे पीठिका पर दाएँ पार्श्व में

एक गण को सामने रखे मृदंग का वादन करते हुए तथा बायें पार्श्व में खड़े एक गण को करतल ध्वनि उत्पन्न करते हुए प्रदर्शित किया गया है। साथ ही बाएँ पार्श्व में खड़े नंदी शिव की ओर दृष्टि करके उनके नृत्त को मंत्रमुग्ध होकर देखते हुए प्रदर्शित है। नृत्य और संगीत की सौम्य प्रस्तुति के साथ दिव्य वातावरण को प्रकट करती हुई नील–हरित पाषाण से निर्मित यह प्रतिमा दिव्य वातावरण को और भी मनमोहक छवि प्रदान कर रही है।

प्रतिमा में शिव की वीणा पर क्रीड़ारत अँगुलियों के अंकन के साथ नृत्य और संगीत में तल्लीनता को प्रदर्शित करने के लिए देवता के मुखमण्डल पर ध्यानस्थ भाव का अंकन कलाकार की संगीत और नृत्य कला की मर्मज्ञता को प्रदर्शित करता है।

अंकन शैली के आधार पर यह प्रतिमा दसवी शताब्दी ई. की प्रतीत होती है।

निष्कर्ष

इस प्रकार गढ़वाल हिमालय से प्राप्त शिव के नृत्त स्वरूप प्रतिमाओं के अध्ययनोपरांत यह विदित होता है कि इस स्वरूप के अंकन में गढ़वाल हिमालय क्षेत्र की मूर्त्तिकला का सराहनीय योगदान रहा है।

यहाँ से प्राप्त नटराज स्वरूप प्रतिमाओं के अंकन में शास्त्रीय ग्रंथों का पूर्णतः अनुपालन दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस क्षेत्र की नटराज स्वरूप प्रतिमाओं का शिल्पांकन प्रतिमाशास्त्रीय ग्रंथों, उत्तर भारतीय कला शैली की क्षेत्रीय विशिष्टताओं एवं स्थानीय प्रभावों को आधार बनाकर किया गया है। यहाँ से प्राप्त नटराज स्वरूप की प्रतिमाओं के शिल्पांकन में नटेश शिव के पैर के नीचे अपस्मार पुरुष जो कि अज्ञानता एवं अंधकार का प्रतीक है के स्थान पर पद्म पीठ का अंकन प्रदर्शित किया गया है, जिसके संबंध में यह कहना तर्कसंगत प्रतीत होता है कि ऋषि–मुनियों की प्रज्ञा–प्रदायिनी इस पवित्र भूमि में अपस्मार पुरुष का अंकन यहाँ के कलाकारों के स्वाभाविक चिंतन से परे है। इसी प्रकार शिव के हस्त में अग्निपात्र के स्थान पर उनके प्रिय आयुध के अंकन का कारण भी यहाँ के कलाकार एवं जनमानस के मानस पटल पर शिव की संरक्षक देव के रूप में कल्पित छवि है जिसमें अग्नि जैसी प्रकृति का कोई स्थान नहीं है। नटराज प्रतिमाओं के साथ शिव के वाहन नंदी का अंकन उत्तर भारतीय नटराज प्रतिमाओं की मुख्य विशिष्टता है।

गढ़वाल क्षेत्र से प्राप्त होने वाली शिव की नटराज स्वरूप की प्रतिमाओं का अंकन भूरे एवं नील हरित वर्ण के स्थानीय प्रस्तर से किया गया है। इस क्षेत्र से प्राप्त नटराज स्वरूप प्रतिमाओं में अधिकांश ललित मुद्रा में शिल्पांकित की हुई प्राप्त होती हैं। इस क्षेत्र की मूर्त्तिकला में शिव की नटराज स्वरूप प्रतिमाएँ चतुर्भुजी, अष्टभुजी एवं दसभुजी स्वरूप की प्राप्त होती है।

❒

सन्दर्भ –

1. *नाट्यशास्त्र, भाग 3, प्रथम अध्याय, पृ. 3*
2. *कुमारस्वामी, आनंद वैंकटेश, 'द डांस ऑव शिवा', पृ. 51–52*
3. *नाट्यशास्त्र, भाग 3, प्रथम खण्ड, पृ. 3*
4. *अष्टाध्यायी, माहेश्वर सूत्र, प्रथम अध्याय*

5. नाट्यशास्त्र, भाग 3, प्रथम अध्याय, पृ. 3
6. फ्रित्जॉफ, कापरा, 'द ताओ ऑफ फिजिक्स, पृ. 225
7. लिंगपुराण, 106/1/22,
'कृतमस्याः प्रसादार्थ देवदेवेन ताण्डवम्।
तृतीय शतरूद्र सन्धयायां सर्वभूतेन्द्रैः प्रेते प्रीतेन शूलिना।।'
8. शिवपुराण, तृतीय शतरूद्र संहिता, 34
9. मत्स्यपुराण, 259/11
10. शिवराममूर्ति, सी., नटराज इन आर्ट, थॉट एंड लिटरेचर, पृ. 156
11. तिवारी, मारूतीनंदन, मध्यकालीन प्रतिमालक्षण, पृ. 69–74
12. कठौच, यशवंत सिंह, 'मध्य हिमालय की कला', पृ. 128

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 48–57

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

हरियाणा में शिक्षा की स्थिति में आए परिवर्तनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन (1920–47 ई) महिला साक्षरता के विशेष संदर्भ में

निखिल कुमार
शोधार्थी, इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग,
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा)
Email : nkrc777.rs.history@mdurohtak.ac.in

सारांश

19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशक, भारत में प्राच्यवाद बनाम पाश्चात्यवाद के द्वंद्व हेतु जाने जाते हैं। परन्तु औद्योगिक पूंजीवाद से प्रेरित भारत की औपनिवेशिक सत्ता ने यह सुनिश्चित किया कि इस विवाद में पाश्चात्य पद्धतियों पर आधारित व्यवस्थाओं को ही विजयी घोषित किया जाए। यहीं से भारतीय शिक्षा के पाश्चात्यकरण की शुरूआत हुई। जैसे–जैसे कम्पनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत के क्षेत्रों पर बढ़ता रहा, वैसे–वैसे ही यह शिक्षा पद्धति भी वहाँ पहुँचने लगी। फिर अंततः हरियाणा के क्षेत्र का पंजाब में विलय हो जाने के पश्चात् यहाँ भी यह पद्धति क्रमिक तौर पर लागू कर दी गई। प्रस्तुत शोध–पत्र में हम 1920ई. तक हरियाणा के क्षेत्र में शिक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा देने के पश्चात् सर्वप्रथम यहाँ 1920–47 ई. के दौरान शैक्षणिक संस्थानों एवं शिक्षा से जुड़ी आधारभूत संरचना की स्थिति का व्यापक लेखा–जोखा प्रस्तुत करेंगे। इन संस्थानों के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा एवं लैंगिक विभेदन पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है। तत्पश्चात् इस कालखंड में शैक्षणिक सुधारों को उत्प्रेरित करने वाले तत्त्वों की पहचान कर लेने के बाद क्षेत्र में साक्षरता एवं शिक्षा की गुणवता का तुलनात्मक सामयिक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर अंततः महिला शिक्षा की तुलनात्मक स्थिति का विवरण प्रस्तुत कर क्षेत्र में सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की दशा का विस्तृत मूल्यांकन भी शोध–पत्र में दिया जाएगा। इस क्रम में उपरोक्त शैक्षणिक अवयवों के आंकड़ों का विस्तृत जिलेवार विश्लेषण प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उक्त कालखंड में हरियाणा क्षेत्र में शिक्षा की अवस्था की समग्र एवं तुलनात्मक छवि चित्रित की जा सके।

मुख्य शब्दः– साक्षरता, शिक्षण संस्थान, लैंगिक विषमता, जनगणना, अनिवार्य शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा

भूमिका

किसी भी क्षेत्र या समाज की उन्नति एवं विकास के स्तर को समझने हेतु अनेक संकेतकों का उपयोग किया जाता है। विशेषतः सामाजिक प्रगति की जांच में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं लैंगिक समानता जैसे सूचक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन सूचकों में भी साक्षरता दर, क्षेत्र में शिक्षा की आधारभूत संरचना की स्थिति एवं समाज के विभिन्न तबकों तक शिक्षा की पहुंच या उपलब्धता सर्वाधिक उपयोगिता वाले संकेतक समझे जाते हैं। वस्तुतः हरियाणा क्षेत्र के फरवरी, 1858 ई. में पंजाब में विलय से पूर्व यहाँ आधुनिक शिक्षा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी।[1] यहाँ पर अधिकतर शिक्षा जमींदारी स्कूलों द्वारा ही दी जाती थी, जहाँ मुख्य ध्यान फारसी सहित धार्मिक शिक्षा पर ही दिया जाता था। इस शिक्षा का व्यवसायिक एवं भौतिक महत्व अत्यंत न्यून था। ध्यातव्य है कि 'हरियाणा क्षेत्र' से यहाँ हमारा तात्पर्य तत्कालीन ब्रिटिश अधिपत्य वाले पंजाब राज्य के 5 जिलों यथा–अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार एवं गुड़गांव तथा इस क्षेत्र में पड़ने वाली देशी रियासतों यथा– जींद, लोहारू, पटौदी, दुजाना एवं नाभा रियासत के कुछ भाग से है।[2] विलय के लगभग 20 वर्षों के उपरांत भी स्थिति में कुछ खास सुधार दर्ज नहीं हुआ। तत्पश्चात् पंजाब के शिक्षा विभाग के निदेशक श्री हालरायड के नेतृत्व में 1879–80 ई. में बनी तीन सदस्यीय समिति ने शिक्षा के त्रिस्तरीय श्रेणीकरण का सुझाव दिया। इसके तहत किए गए प्राथमिक, सैकेण्डरी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा के वर्गीकरण के फलस्वरूप अब बहुत सारे बच्चे मकतबों, मदरसों एवं पाठशालाओं की जगह सरकारी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों में जाने लगे।[3] परन्तु फिर भी क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक ही बनी रही। यहाँ तक कि ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वयं माना कि हमारी शिक्षा पद्धति शायद इस कृषक समाज हेतु उपयुक्त नहीं है। यदि इसकी जगह के हिसाब जैसे विषय पढ़ाएं जाएं तो निश्चित ही लोग अपने बच्चों को अधिक तत्परता से स्कूलों में भेजेंगे।[4] 1908 तक आते–आते अधिकांश जमींदारी स्कूलों का स्थान देहाती स्कूलों ने ले लिया। इन स्कूलों में अब फारसी के स्थान पर हिसाब इत्यादि सम्बन्धित व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाने लगी। परन्तु फिर भी बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक से पूर्व क्षेत्र में शिक्षा विशेषतः महिला शिक्षा की दशा अत्यंत दयनीय ही बनी रही। इसी आलोक में हम हरियाणा के क्षेत्र में अगले लगभग तीन दशकों के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आए परिवर्तनों एवं सुधारों को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इन सकारात्मक परिवर्तनों के कारणों की खोज के साथ–साथ अंततः स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर क्षेत्र की शैक्षणिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हुए क्षेत्र में शिक्षा की लैंगिक पहुंच को चिन्हित करेंगे। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोध पद्धति के रूप में शोध के परिणात्मक के साथ–साथ गुणात्मक अवयवों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विषय पर मौलिक और वस्तुनिष्ठ समझ के विकास हेतु यथासंभव विभिन्न जनगणनाओं, सरकारी गजेटियरों एवं रिपोर्टों में दिए प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु मुख्य विषय पर आने से पूर्व अत्यंत आवश्यक है कि वर्णित कालखंड में आए परिवर्तनों हेतु मूलभूत कारणों एवं परिस्थितियों का उल्लेख कर दिया जाए।

शिक्षा की स्थिति में सुधार को उत्प्रेरित करने वाले कारक

बीसवीं सदी का दूसरा दशक एक विनाशकारी विश्वयुद्ध वाला समय था। इस विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की ओर से लगभग 9,43,344 भारतीय सैनिकों एवं अन्य सहायकों ने भी भाग लिया था।[5] इनमें से अधिकतर पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र के वासी ही थे। ये सैनिक जब युद्ध के विभिन्न

मोर्चों एवं खासतौर पर यूरोप पहुँचे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। सम्पर्क सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु न केवल इनमें से बहुत से सैनिकों ने पढ़ना–लिखना सीखा अपितु इन्होंने वापस आकर एवं पत्रों के माध्यम से भी अपने क्षेत्र के लोगों को इस स्थिति से अवगत एवं जागरूक कराया। उदाहरणार्थ– रोहतक के रनजीलाल ने अपने दादाजी को पत्र में बताया कि किस प्रकार यूरोप की महिलाएँ पुरूषों के पीछे से सब कुछ संभाल रही है एवं पत्राचार कर रही है तथा हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपनी लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए।[6] फिर इन सैनिकों ने वापस लौटकर भी क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति हेतु अपना आर्थिक एवं सामाजिक योगदान दिया। ध्यातव्य है कि यह समय हरियाणा–पंजाब सहित समस्त भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उभार का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय नेता इस दौरान राजनीतिक दौरों पर रहते थे। स्वयं महात्मा गांधी ने भी इस दौरान हरियाणा के प्रमुख शहरों यथा– रोहतक, भिवानी व अम्बाला आदि का दौरा किया था।[7] अपने वक्तव्यों में उन्होंने निरंतर शिक्षा में सुधार का मुद्दा भी उठाया था।[8] इसका व्यापक असर भी देखने को मिला व अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई। उदाहरणार्थ– रोहतक में 1920ई॰ में चौधरी बलदेव ने अपने जाट स्कूल का सम्बन्ध पंजाब विश्वविद्यालय से विच्छेदित कराकर उसे राष्ट्रीय स्कूल बना दिया।[9] फिर इस समय कार्यरत अनेक जातिगत एवं धार्मिक संगठनों ने भी न केवल शिक्षा सुधार हेतु सरकार पर दबाव बनाया अपितु अपने संगठनों के बैनर तले भी अनेक शिक्षण संस्थान खोलकर संचालित किये। इनमें सर्वाधिक प्रमुख जाट सभा, गौड़ सभा, वैश्य सभा, आर्य समाज व सनातन धर्म सभा आदि थे। इनमें भी रोहतक के क्षेत्र में जाट सभा व अम्बाला–करनाल के क्षेत्र में आर्य समाज सर्वाधिक सक्रिय रहे। उदाहरणार्थ– 1920ई. में अम्बाला क्षेत्र में 6 आर्यसमाजी स्कूल चल रहे थे।[10] आगे हुए संवैधानिक सुधारों एवं युनियनिस्ट पार्टी की सरकारों के कुछ कार्यों ने भी क्षेत्र में शिक्षा की दशा में सकारात्मकता लाने में योगदान दिया।

उपर्युक्त कारकों का प्रभाव हमें 1918 ई. से ही देखने को मिलने लगा जब देहाती क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष पंचवर्षीय योजना की शुरूआत की गई। इसके अंतर्गत सरकारी सहायता प्राप्त जिला बोर्ड प्रत्येक दो मील के दायरे में मात्र 50 बच्चों हेतु भी स्कूल खोल सकते थे।[11] इस योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम रोहतक में 1922ई. में 6 स्कूलों को इस बाबत चुना गया। इसी तरह 1919 ई. के भारत सरकार अधिनियम के तहत जब प्रांतों में दोहरी प्रणाली लागू हुई तो जनाकांक्षा के दबाव में सरकार को पंजाब प्राइमरी शिक्षा अधिनियम 7 पास करना पड़ा। इसके अंतर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। हालांकि शिक्षा की अनिवार्यता को स्थानीय प्रशासन की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया।[12] इसने भी क्षेत्र में खासतौर पर साक्षरता की बढ़ोतरी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम इन प्रयासों की बदौलत क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धित आधारभूत संरचना में हुए सुधार का विश्लेषण करेंगे।

हरियाणा में शिक्षा अवसंरचना की स्थिति (1920–47 ई.)

वर्ष 1922 ई. से हरियाणा में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धित योजना के लागू होने के पश्चात् क्षेत्र में नए खुले प्राथमिक स्कूलों का विवरण अग्रलिखित तालिका में दिया जा रहा है[13]–

तालिका–1

क्रं.	वर्ष	शहरी क्षेत्र में नए स्कूल	ग्रामीण क्षेत्र में नए स्कूल	कुल नए स्कूल
1.	1922–23	–	6	6
2.	1926–27	6	148	154
3.	1931–32	20	900	920
4.	1934–35	24	830	904
5.	1937–38	–	–	1975
6.	1940–41	–	–	1270
7.	1946–47	–	–	1498
8.	1947–48	–	–	1564

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से तीन बातें स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा नए स्कूल खुलना, 1930 ई. के बाद नए स्कूलों की खुलने की दर में अपेक्षाकृत कमी आना तथा 1937 ई. के बाद पुनः इस दर का तीव्र हो जाना। नए ग्रामीण स्कूलों की अधिकता का कारण शहरों में पहले से विद्यमान प्राइमरी स्कूल संरचना थी, वहीं 1930 ई. के बाद दर में कमी के दो कारण थे। पहला, इस दौर की महान् आर्थिक मंदी तथा दूसरा, 1929 ई. का हार्टोग आयोग जिसने शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु स्कूलों की संख्या में कमी लाने का सुझाव पेश किया था। इसके अनुसार प्रारम्भ में दाखिला लेने वालों में से केवल 18 प्रतिशत छात्र ही चौथी कक्षा तक पहुँच पा रहे थे। अतएव स्कूलों की संख्या के स्थान पर गुणवत्ता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी।[14] फिर 1935 ई. के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुए 1937 ई. के प्रांतीय चुनावों में पंजाब में बनी युनियनिस्ट पार्टी की अपेक्षाकृत स्वायत्त सरकार व चौधरी छोटूराम के प्रयासों के बदौलत यह संख्या फिर से बढ़नी शुरू हो गई।

यह चौधरी छोटूराम के प्रयासों का ही फल था कि इस दौरान खुलने वाले नए स्कूलों में वर्तमान पंजाब के मुकाबले हरियाणा के क्षेत्र में खुले स्कूलों की संख्या अधिक थी। इस तरह स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर 1946–47 ई. में हरियाणा में प्रत्येक 9.9 वर्गमील क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल खुल चुका था। स्वतंत्रता के पश्चात् तो इसमें और तीव्रता आई तथा यह आच्छादित क्षेत्र 1965–66 ई. तक घटकर मात्र 3.3 वर्गमील ही रह गया।[15]

वहीं उक्त कालखंड के दौरान मिडिल व हाई स्कूलों की जिलेवार संख्या को इस तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है[16]–

तालिका–2

क्रं.	जिले का नाम	स्कूल का प्रकार	1921	1931	1941	1946–47
1	अम्बाला	मिडिल	8	13	20	23
		हाई	9	12	16	18
2	करनाल	मिडिल	9	16	21	24
		हाई	7	10	15	18
3.	रोहतक	मिडिल	12	20	28	20
		हाई	7	16	20	23
4.	हिसार	मिडिल	18	21	22	25
		हाई	4	8	10	16
5.	गुड़गांव	मिडिल	10	10	20	21
		हाई	4	6	10	12

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि लगभग सभी जिलों में मिडिल स्कूलों की संख्या हाई स्कूल से अधिक थी परन्तु हाई स्कूलों के खुलने की वृद्धि दर मिडिल स्कूलों से कहीं ज्यादा थी। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि हाई स्कूलों के अंतर्गत आने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 1882 ई. से ही कलकत्ता विश्वविद्यालय की जगह पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाने लगी थीं।

उच्च शिक्षा की यदि बात करें तो हरियाणा में 1927 ई. से पहले कोई कॉलेज नहीं था। परन्तु फिर इस स्थिति में बदलाव आया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति तक क्षेत्र में 6 कॉलेज खुल चुके थे। इनमें से पांच निजी संस्थान थे जबकि एक सरकारी कॉलेज था। इनमें अधिकतर मानविकी एवं साहित्यिक विषय ही पढ़ाए जाते थे। हालांकि विश्वविद्यालय की प्राप्ति हेतु क्षेत्र को 1956 ई. तक इंतजार करना पड़ा। उन शिक्षण संस्थानों को इस विकास यात्रा को अग्रलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है–

तालिका–3

क्रं.	स्थापना वर्ष	कॉलेज का नाम	शहर का नाम
1.	1927	गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज	रोहतक
2.	1938	एस.ए. जैन कॉलेज	अम्बाला
3.	1944	ऑल इंडिया जाट हीरोज मैमोरियल कॉलेज	रोहतक
4.	1944	वैश्य कॉलेज	भिवानी
5.	1945	अहीर कॉलेज	रेवाड़ी
6.	1946	वैश्य कॉलेज	रोहतक

स्मरणीय है कि 1941 ई. में रोहतक का इंटरमीडिएट कॉलेज भी बी.ए. तक की कक्षाएँ संचालित करने लगा था। इस प्रकार यह क्षेत्र का एकमात्र सरकारी कॉलेज बना रहा।

महिला शिक्षण संस्थानों के विशेष संदर्भ में यदि बात की जाए तो इस क्षेत्र में अम्बाला व रोहतक अग्रणीय बने हुए थे। अम्बाला में इनकी अच्छी स्थिति का सर्वाधिक प्रमुख कारण वहाँ आर्य समाज की उपस्थिति थी। वहीं रोहतक में इस कार्य में युद्ध से लौटे सैनिकों एवं उनके परिवारों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। उदाहरणार्थ– रोहतक व उसके आस–पास के क्षेत्रों में विशेषतः ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु वर्ष 1939 ई. में खानपुर कलां में एक विशेष महिला गुरूकुल की स्थापना की गई थी। ऐसे ही 1940 ई. तक यहाँ लड़कियों हेतु 8 प्राथमिक, 3 मिडिल व 2 हाई स्कूल बनाए गए थे।[17] इसी तरह गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर एफ.एल. ब्रेन के प्रयासों से भी उस क्षेत्र में महिला शिक्षण संस्थानों की कुछ उन्नति अवश्य हुई थी। इस अवसंरचनात्मक विकास एवं अन्य सरकारी व गैर–सरकारी प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति में आए बदलावों का विश्लेषण शोध–पत्र के आगे के हिस्से में प्रस्तुत किया जा रहा है।

हरियाणा में साक्षरता की स्थिति (1920–47 ई.)

तत्कालीन हरियाणा क्षेत्र की कुल आबादी में से लगभग 91 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में रह रही थी, वहीं केवल 9 प्रतिशत आबादी ही देशी रियासतों के अंतर्गत आती थी।[18] ध्यातव्य है कि तत्कालीन साक्षरता स्थिति के विश्लेषण हेतु सर्वाधिक विश्वसनीय आंकड़े उस समय की जनगणनाओं में ही उपलब्ध है। अतएव 1921 ई. एवं 1941 ई.

की जनगणनाओं में प्रकाशित आंकड़ों के माध्यम से तत्कालीन साक्षरता स्थिति में आए जिलेवार परिवर्तन को अग्रलिखित तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है[19]–

तालिका–4

क्रं.	जिले कानाम	1921		1941		साक्षरता
		कुल जनसंख्या	साक्षर लोग	कुल जनसंख्या	साक्षर लोग	प्रतिशत में हुई वृद्धि
1	हिसार	816810	22204 (2.7%)	1034600	74100 (7.1%)	(4.4%)
2	रोहतक	772272	23264 (3.01%)	987000	70600 (7.15%)	(4.14%)
3	गुड़गांव	682003	20676 (3.03%)	851500	64400 (7.56%)	(4.53%)
4	करनाल	828728	20307 (2.45%)	994600	63600 (6.39%)	(3.94%)
5	अम्बाला	681477	36711 (5.38%)	847800	98500 (11.61%)	(6.23%)
	कुल	**3781290**	**123162 (3.25%)**	**4715500**	**371200 (7.87%)**	**(4.62%)**

उपर्युक्त आंकड़ों का विश्लेषण करते समय हमें 1941 ई. की जनगणना के सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ये आंकड़े हजार के गुणज में प्रकाशित किए गए हैं तथा दूसरा विश्वयुद्ध के चलते इस गणना में कुछ विलम्ब हुआ था। उदाहरणस्वरूप इस गणना के आयु सम्बन्धी आंकड़े तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् आजाद भारत की सरकार के द्वारा 1950–51 ई. में जारी किए जा सके। अतएव यह हमारे शोध–पत्र के कालखंड के संदर्भ में लगभग सही चित्र प्रस्तुत करती है। इन आंकड़ों को विश्लेषित कर तीन निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला, हमारे अध्ययन के कालखंड के प्रारम्भ में हरियाणा के लगभग सभी हिस्सों में साक्षरता की स्थिति लगभग एक समान अर्थात् 3 प्रतिशत के आस–पास थी। दूसरा, आने वाले दो दशकों से भी अधिक समय में पीछे बताए गए कारकों की बदौलत साक्षरता दर में लगभग 4 प्रतिशत की सार्वभौमिक वृद्धि दर्ज की गई। फिर अंततः यह भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है कि हरियाणा में सर्वाधिक सकारात्मक स्थिति अम्बाला की थी। इस बाबत श्रेय सरकार सहित आर्य समाज जैसी गैर–सरकारी संस्थाओं को भी दिया जा सकता है। हरियाणा में अम्बाला ही साक्षरता प्रतिशत को दहाई के अंकों में पहुँचाने वाला पहला जिला बना था।[20]

देशी रियासतों के संदर्भ में यदि बात की जाए तो इनकी स्थिति भी कमोबेश राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति ही थी। तथापि लोहारू रियासत इस मामले में सर्वाधिक पिछड़ी हुई थी। उदाहरणार्थ– 1921 ई. में यहाँ की कुल आबादी 20,621 थी जिसमें से केवल 150 लोग ही साक्षर थे। यह कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत भी नहीं था।[21] हालांकि अगली जनगणना तक

यह संख्या बढ़कर 350 हो गई परन्तु फिर भी सम्पूर्ण स्थिति को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।[22] इसी प्रकार जींद रियासत में 1921 ई. की जनगणना में कुल साक्षर लोगों की संख्या 8,377 थी जो 1931 ई. की जनगणना में घटकर 7,881 रह गई जबकि इस दौरान क्षेत्र की आबादी में लगभग 21,493 की बढ़त दर्ज की गई थी।[23] वस्तुतः इन रियासती क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर में मूलभूत सुधार स्वतंत्रता प्राप्ति एवं इनके भारत के मुख्य क्षेत्र में विलय के पश्चात् ही लाया जा सका। इन आंकड़ों के विश्लेषण से एक अन्य प्रमुख बिन्दू जो उजागर होता है, वह है– साक्षरता वृद्धि में निजी प्रयासों की भूमिका। उदाहरणस्वरूप क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में रहने वाली मुस्लिमों की मेव जनसंख्या, जिसे परम्परागत तौर पर पिछड़ा हुआ एवं शिक्षा के प्रति अरूचिकर समझा जाता था, के तहत 1921 ई. में मात्र 758 लोग ही पढ़–लिख सकते थे। परन्तु इस दशक के दौरान वहाँ के डिप्टी कमिश्नर एफ॰एल॰ ब्रेन के निजी प्रयासों एवं सफल प्रयोगों के फलस्वरूप 1931 ई॰ की जनगणना में इनकी संख्या बढ़कर 1,152 हो गई। हालांकि इस सफलता की सीमा यह रही कि इस दौरान यहाँ साक्षर महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी की बजाए मामूली कमी देखने को मिली जो पहले के 15 से घटकर अब मात्र 12 ही रह गई।[24]

हरियाणा में महिला साक्षरता की स्थिति (1920–47 ई.)

शोधपत्र के कालखंड के उक्त तीन दशकों के दौरान हरियाणा क्षेत्र के विभिन्न जिलों में महिला साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति एवं उसमें आए बदलावों को आगे दी जा रही तालिका के माध्यम से विश्लेषित किया जा सकता है[25]–

तालिका–5

क्रं.	जिले का नाम	1921		1941		साक्षरता
		महिलाओं की कुल जनसंख्या	साक्षर महिलाओं की संख्या	महिलाओं की कुल जनसंख्या	साक्षर महिलाओं की संख्या	प्रतिशत में हुई वृद्धि
1	हिसार	381248	984 (0.25%)	483200	9700 (7.1%)	1.75%
2	रोहतक	354893	1005	471700 (0.28%)	8800	1.58% (1.86%)
3	गुड़गांव	314203	964 (0.30%)	398000	8200 (2.06%)	1.76%
4	करनाल	375089	1128 (0.30%)	451700	1100 (2.43%)	2.13%
5	अम्बाला	297675	4234 (1.4%)	365300	19900 (5.47%)	2.13%
	कुल	**1723108**	**8315 (0.48%)**	**2169900**	**57600 (2.65%)**	**2.17%**

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से हमें महिला साक्षरता के संदर्भ में चार बातें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। एक, 1921 ई. में हरियाणा के अधिकतर हिस्सों में महिला साक्षरता दर

मात्र एक चौथाई से एक तिहाई प्रतिशत ही थी। 20वीं शताब्दी की आधुनिकता के संदर्भ में तो यह बात और भी अधिक अटपटी लगती है। दूसरा, अगले तीन दशकों के दौरान किए गए प्रयासों से हरियाणा का प्रत्येक भाग लाभान्वित हुआ तथा उनमें लगभग पौने दो से सवा दो प्रतिशत तक की महिला साक्षरता वृद्धि दर्ज की गई। तीसरा, महिला साक्षरता के मामले में भी अम्बाला हरियाणा के बाकी क्षेत्रों से कहीं अधिक आगे थे। इस तथ्य को इस उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि 1921 ई. में हरियाणा क्षेत्र में पड़ने वाले शेष चार जिलों में कुल साक्षर महिलाओं की संख्या संयुक्त रूप से 4081 थी जबकि अकेले अम्बाला में यह संख्या 4234 थी।[26] इसी तरह अगले तीन दशकों के दौरान सर्वाधिक वृद्धि भी अम्बाला में ही दर्ज की गई जोकि 4.04 प्रतिशत थी। चौथी और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा के समस्त जिलों में से करनाल में महिला एवं पुरूष साक्षरता के मध्य अंतर सर्वाधिक न्यून था। हालांकि लैंगिक समानता के संदर्भ में यह सकारात्मकता अत्यंत गौण ही प्रतीत होती है तथापि इसे एक सुलभ संकेतक के तौर पर अवश्य लिया जा सकता है।

यहाँ एक और तथ्य स्मरणीय है कि हालांकि इस कालखंड के दौरान साक्षर महिलाओं की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई, परन्तु यह वृद्धि उनके ज्ञान एवं शिक्षा की गुणवता का द्योतक नहीं है। दरअसल उक्त सुधारों के बावजूद भी हरियाणा के क्षेत्र में न केवल महिला शिक्षा की गुणवता ही खराब बनी रही अपितु इसमें भारी लैंगिक असमानता का पुट भी बना रहा। 1920–47 ई. के दौरान इस लैंगिक विषमता एवं अल्प गुणवता की स्थिति को आगे दी जा रही तुलनात्मक तालिका के माध्यम से समझा जा सकता है[27]–

तालिका–6

क्रं.	जिले का नाम	1921		1941	
		अंग्रेजी में साक्षर पुरूषों की संख्या	अंग्रेजी में साक्षर महिलाओं की संख्या	अंग्रेजी में साक्षर पुरूषों की संख्या	अंग्रेजी में साक्षर महिलाओं की संख्या
1	हिसार	1635	101	7900	300
2	रोहतक	1918	67	12000	200
3	गुड़गांव	1564	88	7400	400
4	करनाल	2021	70	9700	600
5	अम्बाला	7481	1385	20500	1400
	कुल	**14619**	**1711**	**57500**	**2900**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यदि अंग्रेजी साक्षरता को शिक्षा की गुणवत्ता का एक मानक मान लिया जाए तो कुल गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों में से मात्र 5 प्रतिशत ही महिलाएँ थीं। बाकी मानकों के उलट इसमें अम्बाला की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वास्तव में यह स्थिति समय के साथ और विभत्स होती चली गई। उदाहरणार्थ–1921 ई. में महिलाओं के मुकाबले पुरूषों की अंग्रेजी साक्षरता नौ गुणा थी जो 1941 ई. की जनगणना के अनुसार बढ़कर बीस गुणा हो गई।[28] यह तथ्य बढ़ती शैक्षणिक लैंगिक विषमता को ही दर्शाता है।

इस कालखंड के दौरान महिला साक्षरता की दशा के अन्य महत्वपूर्ण मानक के रूप में विभिन्न आयु वर्गों में महिला साक्षरता की स्थिति को लिया जा सकता है। इन आंकड़ों का विश्लेषण कर आसानी से नए छात्राओं के पंजीकरण एवं महिला शिक्षा की भविष्य की राह को

समझा जा सकता है। दरअसल 1920–47 ई. के दौरान दस वर्ष से कम आयु वर्ग की महिलाओं की साक्षरता व पंजीकरण में स्पष्ट सुधार हमें दिखाई पड़ता है। उदाहरणस्वरूप– 1921 ई. में रोहतक में 0–9 वर्ष आयुवर्ग की कुल 1,08,964 लड़कियों में से 61 ही साक्षर थीं जबकि इस समय अम्बाला में इसी आयुवर्ग में 83,789 लड़कियों में से मात्र 427 ही लिख–पढ़ सकती थी।[29] परन्तु स्थिति में सुधार हुआ एवं 1941 ई. तक यह आंकड़ा क्रमशः 1,39,000 में से 1100 तथा 1,07,600 में से 2100 लड़कियों की साक्षरता तक जा पहुँचा। इस नई धारा ने निश्चित तौर पर ही भविष्य हेतु हरियाणा की महिलाओं की शिक्षा की दिशा तय करने में मदद की। हरियाणा में अवस्थित देशी रियासतों में भी महिला साक्षरता की स्थिति दशक दर दशक मामूली तौर पर बेहतर होती रही। उदाहरणस्वरूप– 1921 ई. में दुजाना में केवल 7 जबकि पटौदी रियासत में केवल 28 महिलाएँ ही साक्षर थी। परन्तु 1931 ई. तक आते–आते यह संख्या बढ़कर क्रमशः 20 एवं 57 हो गई।[30] हालांकि इस अवस्था में आमूलचूल परिवर्तन स्वतंत्रता तथा फिर हरियाणा के पृथक् प्रांत बन जाने के पश्चात् ही आ सका।

1920–47 ई. के दौरान हरियाणा में शिक्षा की दशा का मूल्यांकन

1920 ई. एवं उससे पहले के कालखंड की तुलना में यदि स्वतंत्रता के समय की स्थिति को देखा जाए तो निश्चित तौर पर हरियाणा के क्षेत्र ने शिक्षा एवं उसके अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की थी। महिला शिक्षा के संदर्भ में भी यह तथ्य उतना ही ठीक जान पड़ता है। परन्तु यदि शिक्षा की दशा को समग्रता से देखा जाए तो इसमें कुछ बड़े व गहरे गड्डे भी दिखाई पड़ते हैं। विशेष तौर पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तो ये कमियाँ और प्रखरता से उजागर होती हैं। उदाहरणार्थ– तकनीकी शिक्षा के नाम पर हरियाणा में स्वतंत्रता से पहले केवल कुछ नगरों में स्थित छोटे औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र मात्र ही थे। इसी का एक उदाहरण था– श्री जी.डी. बिरला द्वारा भिवानी में स्थापित टैक्नोलॉजिक्ल इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1943 ई. में की गई थी तथा बाद में प्रौद्योगिकीविदों की पूर्ति एवं मजदूर प्रशिक्षण के उद्देश्य से इसे भिवानी कॉटन मिल्स के साथ जोड़ दिया गया।[31] कमोबेश ऐसी ही उपेक्षा की स्थिति शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों के मामले में रही। इसने भी सीधे तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया। इसी तरह उच्च शिक्षा हेतु क्षेत्र में एक भी विश्वविद्यालय न था। यहाँ पहला विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र में 1956 ई. में बन सका।[32] इसे 1961 ई. से संस्कृत के साथ–साथ बाकी विषयों हेतु भी शुरू किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण कमी के रूप में लैंगिक असमानता का समग्रता से विश्लेषण पीछे ही किया जा चुका है। परन्तु इन सब कमियों के बावजूद भी इस कालखंड के दौरान दर्ज हुई शैक्षणिक प्रगति ने आगे के समय हेतु प्रशिक्षण एवं एक सुसम्बद्ध लांचपैड के रूप में तो अवश्य ही कार्य किया।

निष्कर्ष

शोध–पत्र में दिए गए विवरण एवं तालिकाओं में प्रदर्शित आंकड़ों के विश्लेषण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि हरियाणा के क्षेत्र ने 1920–47 ई. के दौरान के लगभग तीन दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु अपने आरम्भिक दृढ़ कदम उठा दिए थे। महिलाओं की शिक्षा में सुधार हेतु भी सजगतापूर्ण प्रयास इस दौरान किया जाने लगा था। वस्तुतः इन निष्कर्षों को कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। यथा– उक्त कालखंड में प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता जिसमें महिला साक्षरता भी सम्मिलित है, के मामले में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। इसी तरह प्राथमिक शिक्षा सहित मिडिल व हाई स्कूल की शिक्षा अवसंरचना में भी अभूतपूर्व सुधार हुआ। परन्तु इस स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता कुछ खास अच्छी नहीं रही। वहीं उच्च व तकनीकी शिक्षा के मामले में भी स्थिति डावांडोल ही दिखाई पड़ती थी। ध्यातव्य है कि उच्च शिक्षा में तो सरकारी प्रयास अत्यंत गौण ही रहा था। साथ

ही क्षेत्र में शैक्षणिक लैंगिक विषमता का स्तर भी जस–का–तस बना रहा। परन्तु यदि औपनिवेशिक सरकार की उपस्थति एवं सीमित संसाधनों की उपलब्धता के आलोक में इन उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाए तो यह निश्चित ही भविष्य के समय हेतु एक मजबूत आधार सिद्ध होने जा रही थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति एवं फिर हरियाणा के पंजाब से अलग हो जाने के बाद के शैक्षणिक आंकड़ें भी इस बात की परिपुष्टि करते हैं। उदाहरणार्थ– 1966ई. में क्षेत्र की साक्षरता दर मात्र 20 प्रतिशत थी जो पंजाब से अलग होने के बाद हुई पहली जनगणना अर्थात् 1971 ई. में 26.9 प्रतिशत हो गई तथा आने वाले मात्र 20 वर्षों में यह दर 55.53 प्रतिशत तक जा पहुँची। यहाँ तक कि महिला साक्षरता भी इस समय तक 40.94 प्रतिशत हो गई।[33] इस दौरान शैक्षणिक आधारभूत अवसंरचना में भी तेजी से सुधार आया एवं जल्दी ही शिक्षा के मामले में हरियाणा की गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाने लगी।

❐

सन्दर्भ –

1. *हरियाणा स्टेट गजेटियर, वाल्यूम–1, 2001, पृ. 21*
2. *चंद्रा, जगदीश, फ्रीडम स्ट्रगल इन हरियाणा : 1919–47, विशाल पब्लिकेशन्स, कुरूक्षेत्र, 1982, पृ. 2*
3. *यादव, के.सी., हरियाणा का इतिहास (1803–1966), भाग–3, मैकमिलन पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1981, पृ. 206–07*
4. *रोहतक जिला गजेटियर, 1883–84, पृ. 55*
5. *इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वार, द गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, कलकत्ता, 1923, पृ. 96–97*
6. *कांत, वेदिका, "इफ आई डाई हियर, हू विल रिमेम्बर मी?" इंडिया एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार, लस्टर, 2014, पृ. 48*
7. *देसाई, जीवनजी, डायहाभाई, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, खण्ड–19, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1966, पृ. 373–374, 414–416*
8. *चंद्रा, जगदीश, गांधीजी एंड हरियाणा, उषा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1977, पृ. 25–26*
9. *यादव, के.सी., हरियाणा : इतिहास के झरोखे से, हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी, गुड़गांव, 2012, पृ. 228–29*
10. *अम्बाला जिला गजेटियर, 1923–84, पृ. 122*
11. *यादव, के.सी., माडर्न हरियाणा : हिन्दी एंड कल्चर, 1803–1966, मनोहर पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2002, पृ. 255*
12. *यादव, के.सी., हरियाणा : इतिहास एवं संस्कृति (1803–1966), खण्ड–2, मनोहर पब्लिशर्ज, नई दिल्ली, 1992, पृ. 294*
13. *यादव, के.सी., हरियाणा का इतिहास : आदिकाल से 1966 ई॰ तक, होप इंडिया पब्लिकेशन्स, गुड़गांव, 2012, पृ.512–13*
14. *यादव, के.सी., हरियाणा : इतिहास एवं संस्कृति, पूर्वोक्त, पृ. 294*
15. *यादव, के.सी., हरियाणा का इतिहास (1803–1966), पूर्वोक्त, पृ. 213*
16. *वही, पृ. 214–215*
17. *हरियाणा जिला गजेटियर, रोहतक, 1970, पृ. 256*
18. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1921, वॉल्यूम 15, पंजाब एवं दिल्ली, भाग–1, पृ. 98–101*
19. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1941, पेपर नं॰ 7, ऐज टेबल्स, पंजाब, पृ 12–13*
20. *वही, पृ 13*
21. *LSULL VKWQ BAFM;K, 1921, पूर्वोक्त, पृ 121–22*
22. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1931, वॉल्यूम 17, पंजाब, भाग–2, पृ 252*
23. *वही, पृ 257*
24. *वही, पृ 264*
25. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1941, पूर्वोक्त, पृ 12–14*
26. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1921, पूर्वोक्त, पृ 107–109*
27. *वही, पृ 107–108, 119*
28. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1941, पूर्वोक्त, पृ 12–13, 17*
29. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1921, पूर्वोक्त, पृ108*
30. *सेन्सस ऑफ इंडिया, 1931, पूर्वोक्त, पृ 247–48*
31. *भिवानी जिला गजेटियर, 1982, पृ 199–200*
32. *अहमद, एजाज, हरियाणा का इतिहास, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली, 2016, पृ 194–95*
33. *यादव, के.सी., हरियाणा : इतिहास एवं संस्कृति, पूर्वोक्त, पृ 303, 367–68*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 58–62

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के काव्य में प्रकृति चित्रण

सुमन सैनी
सहायक आचार्य, हिन्दी विभाग
राजकीय महाविद्यालय, गुढ़ा, झुन्झुनू (राजस्थान) 333022
E-mail – sumansainirc@gmail.com Mob – 9587123180

सारांश

प्रकृति अपने आप में सुन्दरतम् है और मनुष्य स्वभाव से ही सौन्दर्य प्रेमी होता है। मनुष्य और प्रकृति का सम्बन्ध उतना पुराना माना गया है जितना इस सृष्टि के आरम्भ का इतिहास मनुष्य और प्रकृति के इस अटूट सम्बन्ध की अभिव्यक्ति, धर्म, दर्शन, कला और साहित्य के माध्यम से चिरकाल से होती रही है। साहित्य मानव जीवन का प्रतिबिम्ब है, अतः उस प्रतिबिम्ब में उसकी सहचरी प्रकृति का प्रतिबिम्बित होना स्वाभाविक है। हिन्दी के आदि काव्य में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन व उपमान रूप में हुआ तो रीतिकाल में प्रमुख विशय श्रृंगार चित्रण होने के कारण प्रकृति चित्रण को भी अधिक प्रश्रय मिलना स्वाभाविक था। आधुनिक युग में हिन्दी काव्य में प्रकृति की छटा का चित्रण सुक्ष्मता, सरसता एवं विषदता से हुआ है। छायावादी इसी सुक्ष्मता, सरसता और विषदता का चित्रण हमें कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। इनका मन भारत माता ग्रामवासिनी में अधिक रमा है। इनके काव्य में ग्रामीण मन की निश्छलता, सौन्दर्य एवं ऋतु परिवर्तन की अनोखी छटा के साथ–साथ प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने वाले उपमानों का प्रयोग हुआ है।

मुख्य शब्द : प्रकृति, सरसता, विषदता, धर्म, ग्रामवासिनी, दर्शन

सम्पूर्ण ब्रहाण्ड में व्याप्त पंच तत्वों से निर्मित मूल भाक्ति का नाम प्रकृति है, जो देहधारियों से सम्पृक्त होते हुए भी उनकी कृति नहीं है। वह या तो किसी अदृश्य विराट सुत्रधार की निर्मिति है या स्वतः संचालित तत्व संयुक्ति है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति सृष्टि का मूल कारण है, उसी से महत्व, महत्व से अहंकार, अहंकार से ग्यारह इन्द्रिय तथा पंच सूक्ष्म तन्मात्राएँ और इन सोलह तत्वों में से पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं :

''प्रकृते र्महांस्ततोऽहड़्कार स्तस्माद् गणश्च षोडशक :।
तस्मादीप षोडशकात्पंचभ्यः पंचभूतानी।।''[1]

वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति ही जगत है और जगत ही प्रकृति है। संसार की सम्पूर्ण ख्याती प्राप्त रचनाओं में प्रकृति का सुन्दर विन्यास किसी न किसी भाँति अवश्य रहता है। मनुष्य अपने आपको प्रकृति से अलग मानता है किन्तु वास्तव में मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रकृति का अंग है। डॉ. श्यामसुन्दर दास का कहना है कि ''प्रकृति की ओर मनुष्य निसर्गतः आकृष्ट होता रहता है, क्योंकि उससे उसकी वासनाओं की तृप्ति होती है। इस नैसर्गिक आकर्षण का परिणाम यह होता है कि मनुष्य प्रकृति के उन चित्रों को अपने दुःख अथवा सुख के रस से सिक्त कर अभिव्यंजित करता है और वे भिन्न कलाओं के रूप में प्रकट हो मानव हदय को रसान्वित करते है।''[2]

प्रकृति से ही सम्पूर्ण विश्व का निर्माण होता है और प्रलयकाल में संसार की समस्त वस्तुएँ प्रकृति में ही समाहित हो जाती है। प्रकृति और मनुष्य में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। सर्वप्रथम जब मानव का जन्म हुआ तो उसने प्रकृति को पाया। प्रकृति मानव की उत्प्रेरक शक्ति है। प्रकृति माता के सदृश मनुष्य को दुलारती है, उसे संस्कारवान बनाती है और पिता के समान उसका पालन पोषण करती है। प्रकृति के सानिध्य के बिना प्रगति की परिकल्पना उसी समान होगी जैसे मरूस्थल में हरियाली की चाह रखना। प्रकृति का सामिप्य भारतीय संस्कृति की मूल परम्परा या विशेषता है। प्रकृति के वातावरण का मनुष्य पर पूरा–पूरा प्रभाव दिखाई देता है। वह कभी उसे हँसाती है तो कभी रूलाती है और कभी उसके प्रति संवेदना प्रकट करती है। सुख के समय वह मानव मन में आनन्द का संचार करती है तो दुःख के समय वही प्रकृति मानव मन को वेदना से भर देती है। प्रकृति या सुरम्य वातावरण मानव हदय को आह्लाद से भरकर स्वयं कविता की सृष्टि करती है। प्रकृति जहाँ वातावरण का चित्रण करती है वहीं मानवीय भावनाओं की संवेदनात्मक पृष्ठभूमि भी बनाती है तो साथ ही मेधदूत के रूप में सन्देश वाहिका भी बनती है। प्राकृतिक जीवन में जो प्रेम का विकास होता है वैसा विकास कृत्रिम जीवन में दुर्लभ है।

कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के गीतों में प्रकृति चित्रण

साहित्य की विभिन्न विधाओं में समान गति रखने वाले आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने 1931 से 1997 तक अपने रचनाकाल में हिन्दी साहित्य जगत् को गीतिकाव्य, खंडकाव्य, महाकाव्य नाटक, निबंध और समालोचना के कई ग्रंथों से समृद्ध किया है। कुँवर साहब का प्रकृति चित्रण स्वाभाविक एवं स्वानुभूतिपरक है। इनके गीतों में परिवेश सजगता तथा मानवीय संवेदनाओं का एक अद्भूत आलोक समाहित है। इनके प्रकृति सम्बन्धी गीतों में जो जीवन्तता है उसे हमें प्रकृति में चेतना का आरोप भी कह सकते है। इनके ये गीत ऋग्वेद के उषा वर्णन से प्रभावित प्रतीत होते है।

भारतीय महीनों पर लिखे गये इनके गीत अनुपम है। चैत्र महीने की चॉदनी का सुन्दर और सरस वर्णन कवि कितने सरल शब्दों में व्यक्त करता है :

''चाँदनी चैत की आई है।
घर, सर, सरि, उपवन,
रेत–खेत ओर छोर तक छाई है,

फूली बेला हँसता पलाश,
दृग छलते, सेमल, अमलतास,
बन बीच निवारी का विलास,
करूए ने भी छवि पाई है।
ले गन्ध अन्ध बहती बयार,
मंजरी चूमती बार–बार,
चाँदी के है खलिहान–हार,
यह परी उतर मुसकाई है।''[3]

सम्पूर्ण गीत में कवि ने मानवीकरण अलंकार का सुन्दर चित्रण किया है। इसी क्रम में कवि ने आशाढ़ महीने का वर्णन किया है किस प्रकार इस महीने में धरती की याद बादलों के उर में समाती है। पुरवाई अम्बर से उतरकर जैसे प्रियतम का सन्देश लाई है।

''आया री। आशाढ़ फिर आया।
बादल के उर में धरती सुधि का तीर समाया।
अम्बर से उतरी पुरवाई, प्रिय का सन्देशा ले धाई,
मिलन–मोद से भरी, धरा ने कंचुक हरित सजाया।''[4]

महीनों पर लिखे गए गीतों के साथ–साथ कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के ऋतु सम्बन्धी गीत अपने पूरे परिवेश की सजगता तथा जन जीवन से संयुक्त होने के कारण अपना प्रभाव छोड़ने में अधिक सफल हुए है। ग्रीष्म ऋतु का यह गीत यहां दृष्टव्य है।

''तुम्हारे प्रति अनन्त आभार।
ग्रीश्म तुम तपोमूर्ति साकार।
रसालों को रस दिया अनंत,
किया बेला को सौरभवंत
मालती मुकुलों से सज गई,
घनों की घरती रही पुकार।
तपे तुम वन वृष के मार्तंड
ज्वलिति पौरूष के रूप प्रचंड
क्रान्ति की ज्वालाओं उग्र,
लाल रसना में रहे पसार।''[5]

छायावादी काव्य में बादलों पर सर्वाधिक गीत तथा कविताओं की रचना हुई है। निराला को प्रायः बादलों का कवि कहा गया है। कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने बादलों पर बहुत से गीतों और कविताओं की रचना की है। यदि तुलनात्मक देखा जाये तो निराला के काव्य में बादल क्रांति का प्रतिमान बनकर आए है तो कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के बादल इस संसार के ताप शाप को हरने वाले तथा स्वर्ग से उतरकर वे धरती के प्रांगण पर सोम सुधा की वृष्टि करते है। कवि के बादल सत्य, वृहत् व आनन्द रूप है। वे ही ऋतु के संवाहक है।

''बादल नये–नये आयेंगे।
वे सागर से नहीं, स्वर्ग से
नवजीन प्लावन त्यायेंगे।
अति चेतन के शीर्ष शिखर पर,
इनका है अधिवास मनोहर
उर धरित्री के प्राँगण पर,
सोमसुधा ये बरसायेंगे।
सत्य, वृहत, आनंद रूप ये,
ऋतु के संवाहक अनूप ये,
चरम सत्य के परम तीर्थ में,
ये संसृति को नहलायेंगे।''[6]

गीत संग्रह के साथ साथ उनके ''जीवन आस–पास'' काव्य संग्रह की कविताएँ 'कुंआर', कातिक, अगहन आया हेमन्त, पूस का दिन, आदि उनके मधुर प्रकृति प्रेम को दर्शाने वाली रचनाएँ है। कुँआर पर लिखे गये इस गीत की छटा अनूठी है।

''ढलने लगा कुँआर शरद की शोभा दिशि–दिशि छाई,
जुते मयाये खेत पड़े हैं उतर चाँदनी आई।
पाया गया उभार सँभाले फिर जुआर क्यों यौवन,
सरल प्रेम के अभिनय होते खड़ी अखवन की वन।
बेहद फूले–फल उदर उर में किसान इतराया,
नये बीज बोने का अंतर में उल्लास समाया।''[7]

इसी प्रकार कार्तिक मास पर लिखा गया उनका यह गीत भी प्राकृतिक परिवेश का अनूठा वर्णन करता हुआ दृष्टिगत होता है।

''कातिक की भुरहरि भात शुक्रोदय का क्षण
खेतों में है मुखर गाँव वालों का जीवन।
गूँज रहा सब और भजन का विरहों का स्वर।
बैलों की घुँघरूओं घंटियों का स्वर मंथर
हार हुए तैयार बुवाई की ऋतु आई,
नवोल्लास की लहर कास–कुस तक में छाई''[8]

निष्कर्ष

आचार्य कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह ने मनुष्य के दुःख–सुख, आकर्षण–विकर्षण का सूक्ष्म एवं प्रत्यक्ष परिचय प्रकृति के माध्यम से कराया है। कुँवर जी ने अपने काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। भारतीय अध्यात्म दर्शन की आधार भूमि पर सर्वात्मवाद की अभिव्यक्ति उनके प्रकृति चित्रण को अलौकिक तथा दिव्य बनाती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते है कि कुँवर चन्द्रप्रकाश सिंह के हदय में प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम था। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति–सौन्दर्य का स्वाभाविक वर्णन किया है।

❐

सन्दर्भ –
1. सांख्य दर्शन (कारिका–22)
2. दास, डॉ. श्याम सुन्दर, साहित्यालोचन, पृ. 7
3. सिंह, कुँवर चन्द्रप्रकाश, गीत संग्रह, पृ. 29
4. वही पृ. 32
5. सिंह, कुँवर चन्द्रप्रकाश, गीत संग्रह, पृ. 13
6. सिंह, कुँवर चन्द्रप्रकाश, गीत संग्रह, पृ. 3
7. सिंह, कुँवर चन्द्रप्रकाश, जीवन आस–पास, पृ. 45
8. वही, पृ. 46

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 63–71

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

डिग्री कॉलेजों में कार्यरत महिला तथा पुरूष शिक्षक–प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द का उनके कार्य प्रेरणा के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन

श्रीकान्त सिंह
शोधार्थी (शिक्षा प्रशिक्षण) बी..एड. विभाग,
महिला महाविद्यालय, किदवई नगर, कानपुर (उ.प्र.)
E-mail: shrikantbeorank1@gmail-com Mob: 7068790605

सारांश

वर्तमान अध्ययन वर्णनात्मक है और कानपुर जिले में आयोजित किया गया है, जिसे उत्तर प्रदेश के जिलों में से एक के रूप में नामित किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य डिग्री कॉलेजों के पुरुष तथा महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच उनकी कार्य प्रेरणा के संबंध में भूमिका द्वन्द के अंतर का पता लगाना है। अन्वेषक ने सरल यादृ छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके अपने शोध जांच के लिए 20 सरकारी डिग्री कॉलेजों से शिक्षकों प्रशिक्षकों (65 पुरूष और 65 महिला) को नमूने के रूप में लिया है। डेटा के संग्रह के लिए अन्वेषक ने डॉ. प्रोमिला प्रसाद द्वारा निर्मित शिक्षक भूमिका द्वन्द सूची और के.जी. अग्रवाल द्वारा निर्मित कार्य प्रेरणा प्रश्नावली का भी उपयोग किया है। डेटा के विश्लेषण और व्याख्या के लिए अन्वेषक ने टी–टेस्ट और सहसंबंध विधि को लागू किया है। परिणाम में पाया गया कि डिग्री कॉलेजों में कार्यरत महिला तथा पुरुष शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वंद और उनके कार्य प्रेरणा स्तर में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं है ।

मुख्य बिंदु : कार्य प्रेरणा, भूमिका द्वन्द, शिक्षक प्रशिक्षक, डिग्री कॉलेज

प्रस्तावना

शिक्षक किसी भी शैक्षिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और छात्रों के शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। "शिक्षक–प्रशिक्षकों की भूमिका न केवल प्रशिक्षु शिक्षकों के व्यक्तित्व को ढालने में बल्कि समाज को आकार देने में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिक्षकों के कार्य की प्रेरणा स्वाभाविक रूप से शिक्षकों के काम करने के रवैये से जुड़ी होती है। इसका संबंध शिक्षकों की महाविद्यालयों के माहौल में शैक्षणिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की इच्छा से होता है। शिक्षकों की आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की जरूरतें होती हैं। एक शिक्षक जो

आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, उसे अपने हित के लिए, उससे मिलने वाली संतुष्टि के लिए या उपलब्धि और आत्म–साक्षात्कार की भावना के लिए कोई कार्य करते हुए देखा जा सकता है ।"[1]

इसलिए, शैक्षिक संस्थानों का उद्देश्य शिक्षकों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आंतरिक प्रेरणा का निर्माण और उसे बढ़ाना होना चाहिए और साथ ही महाविद्यालयों में सुधार के लिए कुछ बाहरी प्रेरणा प्रदान करना होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रेरणा सीधे कार्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करती है। इसके बजाय, प्रेरणा हमें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करने और उन्हें कार्यों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह बल है जो हमारे अनुभव और विशेषज्ञता के अनुप्रयोग को आरंभ करता है, सक्रिय करता है और जारी रखता है। "सफल प्रदर्शन में हमेशा सहायक कार्य वातावरण में प्रेरणा और ज्ञान का सहयोग शामिल होता है। पर्याप्त ज्ञान के बिना, अकेले प्रेरणा उपयोगी प्रदर्शन को नहीं बढ़ाती है। इसका संबंध विशेष रूप से कक्षा में छात्रों के अनुशासन और नियंत्रण में शिक्षकों की रुचि से है। कार्य को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक शिक्षक को अलग–अलग भूमिका निभानी पड़ती है, जिससे कभी–कभी तनाव जैसी अलग–अलग समस्याएँ पैदा होती हैं, जिससे भूमिका द्वन्द होता है । भूमिका द्वन्द अनिवार्य रूप से एक भूमिका की अलग–अलग अपेक्षाओं के बीच एक विसंगति है।"[2]

अगर दो शिक्षकों की एक दूसरे की भूमिका के बारे में अलग–अलग अपेक्षाएँ हैं, तो भूमिका द्वन्द होने की संभावना है। भूमिका द्वन्द इस बात से आता है कि हम एक–दूसरे को रोजाना कैसे देखते हैं और काम, पारिवारिक जीवन और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में हम एक–दूसरे को क्या भूमिका सौंपते हैं। शैक्षणिक परिसर में शिक्षक अक्सर भूमिका द्वन्द से पीड़ित होते हैं, न केवल तब जब वे ऐसी भूमिकाएँ निभाने की कोशिश करते हैं जिन्हें समाज उपयुक्त नहीं मानता, बल्कि तब भी जब वे अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और पूर्वाग्रहों को दूर करने का प्रयास करते हैं कि कुछ प्रकार के शिक्षक क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश को भारत के आर्थिक रूप से प्रमुख राज्यों में से एक माना जाता है जिसमें 75 जिले शामिल हैं। जिनमें से कानपुर जिले के शिक्षक प्रशिक्षकों का शैक्षणिक प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से उल्लेखनीय है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें समय–समय पर कई आयोगों और समितियों की नियुक्ति करती रही हैं और शिक्षक प्रशिक्षकों के शैक्षिक विकास के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती रही हैं। यह साबित हो चुका है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए शिक्षक–प्रशिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन शिक्षक प्रशिक्षकों को अलग–अलग भूमिकाएँ निभानी पड़ती हैं जो कार्य प्रेरणा के रास्ते में बाधाएँ पैदा कर सकती हैं। डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा में अंतर का पता लगाने के लिए वर्तमान अध्ययन उचित है।

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन

गिअस (2014) ने शिक्षकों की प्रेरणा पर एक सर्वेक्षण किया और पाया कि "ज्यादातर शिक्षक अपने वेतन, लाभ और अन्य सुविधाओं के बारे में अपने कार्य से कम संतुष्ट थे। एक सामाजिक व्यवस्था में, जब कई लोग इस तरह से एक साथ काम करते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लोगों के समूहों के बीच यह संबंध असंगति को जन्म दे सकता है जबकि

प्रत्येक की इच्छा समान लाभ की होती है। भूमिका द्वन्द दृष्टिकोण और विचारों, इच्छाओं और मूल्यों, कर्तव्यों और नियमों के बीच असहमति है जो प्रतिस्पर्धा, बुरे व्यवहार और कर्मचारियों की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती हैं।"[3]

संगठनों में संघर्षों का कई दृष्टिकोणों से अध्ययन किया गया है। "अन्य संगठनों की तरह संस्थानों में भी विविध श्रम विभाजन, शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के बीच संबंधों के संदर्भ में अधिकार की रेखाएँ, दिशा–निर्देश और सिद्धांत तथा खराब संचार होता है जो भूमिका द्वन्द पैदा कर सकता है। पुरस्कार और प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण और सीधा संबंध था और यह साबित हुआ कि संगठन कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए वित्तीय पुरस्कार पर आकर्षक बजट का भुगतान नहीं करते हैं।"[4]

"सहयोग का उद्देश्य प्रमुख पक्षों की सभी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली कार्य योजना बनाना है। सहानुभूति दूसरे व्यक्ति के अनुभवों और भावनाओं को समझने का कौशल है। जब आप दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझते हैं तो यह सहयोग को बढ़ाता है और संघर्षों को हल करने में मदद करता है। सबसे सराहनीय भूमिका द्वन्द समाधान तकनीक सक्रिय सुनना है। भूमिका द्वन्द समाधान को सुनने से महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, और सहानुभूति और समझ के लिए प्रवेश द्वार खुलता है।"[5]

रमानी और झिमिन (2010) के अनुसार, "द्वन्द के मुख्य कारणों में सुरक्षा, जरूरतों, पहचान, स्वीकृति, भागीदारी और स्वायत्तता की अधूरी माँगें शामिल हैं तथा किसी भी संगठन में विभिन्न स्तरों पर द्वन्द हो सकता है। निम्नलिखित कारक पारस्परिक संघर्षों के प्राथमिक कारण हैंः कार्य की स्थिति और कार्यभारय व्यक्तिगत विविधता, लक्ष्य और इच्छाएँय और पदोन्नति के लिए संसाधनों और प्रतिस्पर्धा की कमी। कर्मचारियों के सदस्यों, उद्देश्यों, कार्यों या कार्यों के बीच मतभेद या असहमति के कारण द्वन्द हो सकता है। शिक्षा स्तर में द्वन्द संस्थान, अधिकारियों, छात्रों और शिक्षकों के नियमों के बारे में अक्सर कई श्रमिकों की मौजूदगी के कारण होता है। शिक्षक, छात्र और प्रमुख अलग–अलग संदर्भों से संबंधित होते हैं और विभिन्न मुद्दों पर उनकी अलग–अलग राय और धारणाएँ होती हैं इसलिए भूमिका द्वन्द उत्पन्न होता है।"[6]

सोरेंसन (2017) ने निर्दिष्ट किया कि "अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता के साथ–साथ अन्य लोगों की भी भावनात्मकता को समझने की क्षमता होनी चाहिए। यह क्षमता भूमिका द्वन्द प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विचारधारा को दूषित होने से रोकती है। अगर आप अपने विरोधी की भावनाओं को सही ढंग से समझ सकते हैं तो उन्हें उकसाए बिना उनके साथ संवाद करना आसान होगा। जब कोई द्वन्द समाप्त हो जाता है, तो इसमें शामिल पक्षों के बीच संबंध अनिवार्य रूप से सामान्य नहीं हो जाते हैं।"[7]

त्सबालाला टी. और, मैपोलिसा, टी. (2013) ने कहा कि" द्वन्द अपर्याप्त और अनावश्यक संचार, पक्षपात और उचित नीतियों की कमी से उत्पन्न हो सकता है ।"[8]

क्रॉस रिवर स्टेट, नाइजीरिया में माध्यमिक विद्यालयों में संघर्ष प्रबंधन और संगठनात्मक प्रदर्शन पर अपने अध्ययन में, उचेंदु, अनिजाओबी–इडेम और ओडिग्वे (2013) ने निष्कर्ष निकाला

कि "प्रभावी संघर्ष प्रबंधन संगठनात्मक प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब संघर्षों को रचनात्मक रूप से प्रबंधित किया जाता है, तो इससे स्कूल का माहौल अधिक सकारात्मक होता है, शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है और छात्रों के बेहतर परिणाम सामने आते हैं। लेखकों ने संघर्ष समाधान रणनीतियों में स्कूल प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया ताकि अनुकूल शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके और शैक्षणिक संस्थानों का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।"[9]

विल्मोट और हॉकर (2011) के अनुसार "द्वन्द समाधान महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग अपनी बहुत सारी ऊर्जा संघर्षों की प्रतिक्रियाओं में लगाते हैं जब वे भूमिका द्वन्द की स्थिति में होते हैं। भूमिका द्वन्द समाधान इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कुछ व्यक्तियों में आक्रामक द्वन्द होता है और वे मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं, जिसमें समझौता प्रतिरक्षा प्रणाली, नशा और पाचन विकार शामिल हैं ।"[10]

उद्देश्य

1. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द में अंतर का अध्ययन करना।
2. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच कार्य प्रेरणा में अंतर का अध्ययन करना।
3. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच संबंध का पता लगाना।
4. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत महिला शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच संबंध का पता लगाना।
5. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच संबंध का पता लगाना।

परिकल्पनाएँ

1. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
2. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच कार्य प्रेरणा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
3. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
4. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत महिला शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।
5. डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

शोध की विधि

अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अन्वेषक द्वारा वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग किया गया है।

जनसंख्या और नमूना

वर्तमान शोध जांच के लिए उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला जनसंख्या के गठन के लिए चुना गया है। नमूनाकरण ढांचे में इस जिले में कार्यरत सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षक–प्रशिक्षक शामिल हैं। अन्वेषक ने सरल यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके 20 महाविद्यालयों से 130 शिक्षक–प्रशिक्षकों (65 पुरुष और 65 महिला) को लिया है।

प्रयुक्त उपकरण

आंकड़ों के संग्रह के लिए अन्वेषक द्वारा निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग किया गया है:

1. डॉ. प्रोमिला प्रसाद और एल. आई. भूषण द्वारा निर्मित शिक्षकों की भूमिका द्वन्द सूची।
2. के.जी. अग्रवाल द्वारा निर्मित कार्य प्रेरणा प्रश्नावली।

प्रयुक्त सांख्यिकीय तकनीकें

आंकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या के लिए अन्वेषक ने चतुर्थक विचलन और टी–परीक्षण का उपयोग किया है।

परिणाम और चर्चा

डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द में अंतर से संबंधित परिणाम :

डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों की के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द में अंतर का पता लगाने के लिए, टी–अनुपात की गणना की गई है और परिणाम तालिका संख्या 1 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक –1

लिंग	कुल	मध्यमान संख्या	मानक विचलन	स्वतंत्रता की श्रेणी	टी–अनुपात	परिणाम
पुरुष शिक्षक	65	25.13	11.39		198	0.25
महिला शिक्षक	65	26.47	14.27			

सार्थकता स्तर 0.05 = 1.97, सार्थकता स्तर 0.01 = 2.60

तालिका क्रमांक–1. दर्शाती है कि प्राप्त टी–अनुपात 0.25 है जो दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण नहीं पाया गया है। इसलिए, यह व्याख्या की जा सकती है कि डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक–प्रशिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इस प्रकार, प्रस्तावित शून्य परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच कार्य प्रेरणा में अंतर से संबंधित परिणाम :

डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच कार्य प्रेरणा के स्तरों में अंतर का पता लगाने के लिए टी–अनुपात की गणना की गई है और परिणाम तालिका क्रमांक 2 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक–2

लिंग	कुल संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता की श्रेणी	टी–अनुपात	परिणाम
पुरुष शिक्षक	65	25.97	11.54	198	0.28	सार्थक नहीं
महिला शिक्षक	65	26.13	15.48			

सार्थकता स्तर 0.05 = 1.97, सार्थकता स्तर 0.01 = 2.60

तालिका क्रमांक–2 से यह देखा गया है कि प्राप्त टी–अनुपात 0.28 जो दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण नहीं पाया गया है। इसलिए, यह व्याख्या की जा सकती है कि डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच कार्य प्रेरणा के स्तर में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इस प्रकार, प्रस्तावित शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

कार्यरत पुरुष शिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच संबंध से संबंधित परिणाम :

डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष शिक्षकों के बीच उत्पन्न भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच संबंध का पता लगाने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की गई है और परिणाम तालिका क्रमांक 3 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक–3

चर	लिंग	कुल संख्या	स्वतंत्रता की श्रेणी	सहसंबंध गुणांक	परिणाम
कार्य प्रेरणा	पुरुष शिक्षक	65	198	0.21	सार्थक नहीं
भूमिका द्वन्द	महिला शिक्षक	65			

तलिका–क्रमांक 3 दर्शाता है कि प्राप्त सहसंबंध गुणांक 0.21 है जो दोनों स्तरों पर महत्वहीन पाया जाता है। इसलिए, यह व्याख्या की जा सकती है कि डिग्री कॉलेजों में कार्यरत पुरुष शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध मौजूद नहीं है। इस प्रकार, प्रस्तावित शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

महिला शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच संबंध से संबंधित परिणाम : डिग्री कॉलेजों की महिला शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के संबंध का पता लगाने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की गई है और परिणाम तालिका क्रमांक 4 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक–4

चर	लिंग	कुल संख्या	स्वतंत्रता की श्रेणी	सहसंबंध गुणांक	परिणाम
कार्य प्रेरणा	पुरुष शिक्षक	65	198	0.13	सार्थक नहीं
भूमिका द्वन्द	महिला शिक्षक	65			

तालिका क्रमांक 4 से यह देखा गया है कि प्राप्त सहसंबंध गुणांक 0.13 है जो दोनों स्तरों पर महत्वहीन पाया गया है। इसलिए, यह व्याख्या की जा सकती है कि डिग्री कॉलेजों की महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध मौजूद नहीं है। इस प्रकार, प्रस्तावित शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच संबंध से संबंधित परिणामः

डिग्री कॉलेजों के पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के संबंध का पता लगाने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की गई है और परिणाम तालिका क्रमांक 5 में प्रस्तुत किया गया है–

तालिका क्रमांक–5

चर	लिंग	कुल	स्वतंत्रता संख्या	सहसंबंध की श्रेणी	परिणाम गुणांक
कार्य प्रेरणा	पुरुष शिक्षक	65	198	0.08	सार्थक नहीं
भूमिका द्वन्द	महिला शिक्षक	65			

तालिका क्रमांक–5 से यह देखा गया है कि प्राप्त सहसंबंध गुणांक 0.08 है, जो दोनों स्तरों पर महत्वहीन पाया जाता है। इसलिए, यह व्याख्या की जा सकती है कि डिग्री कॉलेजों के पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध मौजूद नहीं है। इस प्रकार, प्रस्तावित शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

निष्कर्ष

1. डिग्री कॉलेजों के पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसका कारण पुरुष और महिला शिक्षकों के बीच आपसी सहयोग और उचित समझ हो सकता है। इसके अलावा, हम कह सकते हैं कि उनकी सोच प्रक्रिया में थोड़ा विचलन है।

2. डिग्री कॉलेजों के पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच कार्य प्रेरणा में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। इसके कारण बेहतर संबंध, पढ़ाने का उत्साह और मौजूदा समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करना हो सकते हैं।

3. विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण डिग्री कॉलेजों के पुरुष शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

4. लिंग भेद के बावजूद विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण डिग्री कॉलेजों की महिला शिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

5. डिग्री कॉलेजों के पुरुष और महिला शिक्षक प्रशिक्षकों के बीच भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि दोनों शिक्षकों में लिंग भेद के बावजूद हर शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए उत्साही विशेषताएं होती हैं।

सुझाव

1. वर्तमान अध्ययन डिग्री कॉलेजों के शिक्षक प्रशिक्षकों पर किया गया था। शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसी तरह का शोध प्रधानाचार्यों, प्रशासकों पर किया जा सकता है।

2. इसे अधिक सत्यापन के लिए बड़ी आबादी पर दोहराया जा सकता है।

3. वर्तमान अध्ययन कानपुर जिले तक सीमित था जिसे जिलों में से एक के रूप में नामित किया गया है। अन्य जिलों की शैक्षिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन के नमूना क्षेत्र को आगे के शोध के लिए बढ़ाया या बदला जा सकता है।

सिफारिशें

1. शोधकर्ता भविष्य के शोधकर्ताओं को सलाह देता है कि उन्हें भूमिका द्वन्द पर एक शोध करना चाहिए और डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों की कम कार्य प्रेरणा के कारणों का पता लगाना चाहिए।

2. शोध भविष्य के शोधकर्ताओं को महिला शिक्षकों की तुलना में पुरुष शिक्षकों के बीच उनकी कार्यों के साथ भूमिका द्वन्द के कारणों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है।

3. शिक्षकों को संगठन में उचित मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे अपने कर्तव्यों, महाविद्यालयों में काम करने की स्थितियों से अवगत हों। यह जानकर वे महाविद्यालयों की स्थितियों के साथ प्रभावी ढंग से समायोजित हो सकते हैं।

4. भूमिका द्वन्द को कम करने के लिए, अधिकारियों को स्पष्ट दिशा–निर्देश प्रदान करने चाहिए, ताकि वे अपनी भूमिकाओं के बारे में जागरूक रहें और उन्हें क्या करना है, इसकी समझ में कोई अस्पष्टता न रहे।

5. प्रशासन एक सहायक संगठनात्मक माहौल बनाता है जो भूमिका द्वन्द को कम करने में मदद करेगा और इस तरह शिक्षकों के बीच कार्य प्रेरणा में सुधार करेगा। बेहतर कामकाजी परिस्थितियाँ प्रदान करने से, शिक्षक उस संस्थान में काम करने में अधिक संतुष्ट होंगे जहाँ वे काम कर रहे हैं।

6. वर्तमान अध्ययन भूमिका द्वन्द साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। परिणाम भूमिका संयोजनों के बारे में व्यक्तियों की धारणाओं के महत्व और इन धारणाओं का सीधे आकलन करने के मूल्य पर प्रकाश डालते हैं।

7. वर्तमान अध्ययन एक ठोस आधार प्रदान करता है जिस पर निर्माण किया जा सकता है और शिक्षकों के भूमिका द्वन्द और कार्य प्रेरणा पर भविष्य के शोध के लिए एक नई दिशा की ओर इशारा करता है।

❐

सन्दर्भ –

1. *Bua F., Terile, F., Ada, J. N., & Akinde, E. U. (2015). Conflict management and resolution for the sustainability of educational institutions in Nigeria. Journal of Literature, Languages and Linguis tics, 58-64.*
2. *Folger, J. P., Poole, M. S., & Stutman, R. K. (2021). Working through conflict: Strategies for relationships, groups, and organizations (pp. 72-106). Routledge.*
3. *Gius, M. (2014). Using fixed effects to estimate the impact of merit pay on teacher job satisfaction. Journal of Economics and Economic Education Research , 17-30.*
4. *Hafiza, N. S., Shah, S. S., Jamsheed, H., & Zaman, K. (2011). Relationship between rewards and employee's motivation in the non-profit organizations of Pakistan. Business Intelligence Journal , 327-334.*
5. *Oboegbulem, A., & Alfa, I. A. (2013). Conflict resolution strategies in non-government secondary schools in Benue State, Nigeria. US-China Education Review , 91-102.*
6. *Ramani, K., & Zhimin, L. (2010). A survey on conflict resolution mechanisms in public secondary schools: A case of Nairobi province, Kenya. Educational Research and Reviews , 242-256.*
7. *Sorensen, T. J., McKim, A. J., & Velez, J. J. (2017). A national study of work characteristics and work-family conflict among secondary agricultural educators. Journal of Agricultural Education, 214-231.*
8. *Tshabalala, T., & Mapolisa, T. (2013). An investigation into the causes of conflict in Zimbabwean schools: A case study of Nkayi South Circuit. Journal of Humanities and Social Sciences , 13-22.*
9. *Uchendu, C. C., Anijaobi-Idem, F. N., & Odigwe, F. N. (2013). Conflict management and organiza tional performance in secondary schools in Cross River State, Nigeria. Research Journal in Organi zational Psychology & Educational Studies , 67-71.*
10. *Wilmot, W., & Hocker, J. (2011). Interpersonal conflict (8th ed., pp. 16-34). McGraw-Hill.*

पूर्वदेवा– *सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका*
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 72–78

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

समावेशी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. आर. पुष्पा नामदेव
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा विभाग
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
E-mail: pushpanamdeo@yahoo.com Mob. 9425138317

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यापक परिकल्पना के साथ लागू किया गया है। जहाँ यह नीति एक ओर भारत को वैश्विक मानचित्र पर शैक्षिक दृष्टि से स्थापित करती है वहीं भारत की सांस्कृतिक, भाषीय, भौगोलिक, धार्मिक विविधताओं को संबोधित करती है। भारत, सतत विकास के एजेंडा 2030 के लक्ष्य–4 के अनुसार सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने एवं जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने के लक्ष्य के प्राप्ति हेतु अग्रसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधार, ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाना है जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी का अधिगमकर्ता के रूप में समग्र विकास किया जा सके। इस नीति में जहाँ आधुनिकता को शामिल किया गया है, वहीं इसके द्वारा इनमें भारतीय मूल्यों का समावेशन करने का भी प्रयास किया गया है। भारतीय ज्ञान एवं विचारों के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, व्यापक एवं प्रभावी बनाने के साथ ऐसे नागरिकों का विकास किया जाना है, जिनमें भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को सुनिश्चित कर 21वीं सदी के शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके साथ ही ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जाए जहां विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को समान रूप से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो। प्रस्तुत आलेख में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न नीतियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में समीक्षित करने का प्रयास किया गया है। समीक्षा द्वारा ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा हेतु पूर्व की नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना, 'जेंडर– समावेशी निधि' का गठन, प्री–स्कूल वर्ग को प्राथमिक विद्यालय से जोड़ना, गृह आधारित स्कूली शिक्षा, योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु 'सिंगल विंडो प्रणाली' लागू करना आदि मुख्य रूप से शामिल है।

शिक्षा सामाजिक गातिशीलता विशेषकर उर्ध्वाधर गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सफल एवं सुखी बना सकता है। शिक्षा जीवन कौशल के विकास में सहायक होता है एवं इन कौशलों के माध्यम से व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है एवं शिक्षा मौलिक अधिकारों में शामिल है। अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश के सभी नागरिकों का अधिकार है। शिक्षा एवं शैक्षिक प्रक्रिया में गुणवत्ता हेतु प्रयास जारी है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उपरांत एक लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है।[1]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उस परिस्थिति में लागू किया जाना जहाँ भारत ही नहीं अपितु दुनिया के सभी देश महामारी (कोविड 19) से जूझ रहे थे। वहीं यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इकनॉमिक अफ्फैर्स फॉर सस्टेनेबल डेव्लपमेंट द्वारा लक्ष्य–4 गुणात्मक शिक्षा के संदर्भ में रिपोर्ट (2021) के अनुसार कोविड19 महामारी ने शैक्षिक उपलब्धि को 20 साल पीछे कर दिया है। सस्टेनेबल डेव्लपमेंट गोल रिपोर्ट, 2021 के अनुसार अनेक देशों में विद्यालयी आधारभूत संरचना पिछड़ी हुई है। इन आकड़ों को देखते हुए यह और आवश्यक है कि भारत द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु समता एवं समावेशन को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए।[2]

एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली 2021–22 (यूडीआईएसई 2021–22) के रिपोर्ट के अनुसार "भारत में लगभग 14.89 लाख स्कूल है जिनमें 26.52 करोड़ बच्चे (प्री–प्राइमरी से हायर सेकेंडरी) और 25.57 करोड़ बच्चे (प्राथमिक से हायर सेकेंडरी) देश भर के स्कूलों में है। इस रिपोर्ट के अनुसार 22,66,794 विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12वीं तक नामांकित है।"[3]

समावेशी शिक्षा की अवधारणा

समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है ।यह इस ओर इंगित करती है कि सभी बच्चे समाज का अंग है एवं प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में विशिष्ट है। इसके अनुसार शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है साथ ही सभी बच्चे समान रूप से मूल्यवान है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को उनकी क्षमता या कमियों की परवाह किए बिना मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करना है। समावेशी शिक्षा संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने, स्वस्थ नागरिकता के विकास के साथ सामाजिक समानता हेतु आवश्यक है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं भागीदारी की कमी, अवसरों की कमी, नकारात्मक दृष्टिकोण, अति संकुल कक्षा, भौतिक संसाधनों की कमी, वित्तीय कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, सामाजिक भेदभाव, विद्यालय प्रवेश एवं मूल्यांकन में अनुपयुक्त नियम एवं विनियम, भावात्मक समस्याएँ एवं मानवता की कमी भी देखी जाती है। समावेशी शिक्षा की दिशा में ये बड़ी चुनौतियां हैं किन्तु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने न्यायसंगत एवं समावेशी शिक्षा के लिए प्रभावी सुझाव दिए है।[4]

समावेशी शिक्षा हेतु नीतिगत प्रयास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा बालिका शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विकलांग शिक्षा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व जनजाति की शिक्षा तथा दुर्गम स्थानों पर शिक्षा आदि पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया था। सुविधा युक्त नवीन विद्यालयों की स्थापना के साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों द्वारा

बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। सयमबद्ध योजनाओं द्वारा इनमें निरक्षरता उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा में पहुँच व निरन्तरता सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई साथ ही व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों, आश्रम विद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई। जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजाति बच्चों के लिए केन्द्रित एवं एकीकृत उपागमों द्वारा उनके विकास के लिए नियोजित कार्यक्रम चलाये गए, जिसमें मुख्यतः आश्रम विद्यालय, साथ ही एकलव्य आवासीय विद्यालयों की भी स्थापना की गई है। इन विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था के साथ माध्यमिक स्तर तक शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा द्वारा देश के विभिन्न भागों के प्रतिभावान ग्रामीण बच्चों को शिक्षा द्वारा प्रगति के अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि की अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को सामान्य समुदाय के साथ सहभागी बनाने पर बल दिया गया। इनके के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिला स्तर पर छात्रावास तथा स्वैच्छिक प्रयत्नों पर विशेष बल दिया गया।[5] समावेशी शिक्षा हेतु आरपीडब्लूडी अधिनियम, 2016 के अनुसार "दिव्यांग बच्चों को नियमित एवं विशेष शिक्षा का विकल्प के साथ विभिन्न प्रकार के आवश्यकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुशंसा किया गया।"[6]

एकीकृत जिला शिक्षा प्रणाली 2016–17 (यूडी.आई.एस.ई 2016–17) की रिपोर्ट द्वारा प्राप्त आकड़ों के अनुसार "इस बात की पुष्टि होती है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों में ऐसे अनेक कारक है विशेष कर सामाजिक प्रथाएँ, रीति रिवाज, आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिवेश आदि जिनके कारण नामांकन और प्रतिधारण की दरों में कमी आई।"[7] द डिसेबिलिटी डिस्क्रिमनेटरी एक्ट–2005 में विकलांग और गैर–विकलांग बच्चों के बीच भेदभाव से बचने एवं शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।[8]

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में समावेशन की नीति को हर विद्यालय एवं शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है विद्यालयों को ऐसे केंद्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चे खासकर शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ, समाज के हाशिए पर जीने वाले एवं कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का सबसे ज्यादा फायदा मिले।[9]

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा नामांकन दर बढ़ाने एवं प्रतिधारण की दर को कम करने के अनेक प्रयास किए गए है जिसमें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, एनपीईजीईएल स्कीम, बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन, मुफ्त में किताबें एवं यूनिफोर्म, छात्रवृति आदि का प्रावधान किया गया।[10] शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) के तहत ऐसे प्रावधान किए गए जैसे छह से चौदह वर्ष तक के विद्यार्थियों ले लिए अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिती एवं प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना जिससे बच्चों का नामांकन एवं प्रतिधारण दर बढ़ाया जा सके।[11] इन सभी प्रयासों के

बाद भी यह महसूस किया गया कि पूर्व में लागू विभिन्न नीति एवं नियमों के उपरांत भी नामांकन दर में गिरावट आई, विशेष कर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के विद्यार्थियों में।

समावेशी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में प्रत्येक बच्चों की विशिष्ट आवश्यकता एवं क्षमताओं की पहचान कर विकास करना, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता, सीखने के तरीकों एवं कार्यक्रमों में लचीलापन, रचनात्मकता, तार्किकता, अवधारणात्मक समझ, जीवन कौशल, नैतिकता, मानवता, बहुभाषिकता पर विशेष ध्यान के साथ एक स्थायी, सजीव, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया है। यह नीति सभी विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु प्रयासरत है। जहां सभी वर्गों के विद्यार्थियों को चाहे वे हाँसिए पर रह रहे समुदाय हो, वंचित एवं अल्पसंख्यक हो, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हो सभी को समता एवं समानता का अवसर प्रदान कर मुख्य धारा में लाना है, जिससे सभी वर्गों में सकारात्मक गतिशीलता सुनिश्चित की जा सके। इस हेतु इस नीति में अनेक आधारभूत प्रावधान किए गए है एवं इसके क्रियान्वयन हेतु समिति द्वारा सुझाव जैसे छात्रव ति, ब्रिज कोर्स, मूलभूत साक्षारता एवं संख्यात्मक ज्ञान, समतामूलक एवं परिणाम आधारित सभी के लिए शिक्षा आदि के साथ इसे लागू करने पर बल दिया गया है।[12]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात पर बल देती है कि "किसी भी बच्चे की जन्म एवं पृष्ठभूमि उसके शिक्षा में बाधक नहीं होनी चाहिए।"[13] यद्यपि समावेशन हेतु अनेक नीति एवं अनुसंशा की गई है, इस नीति में यह अवधारणा विद्यमान है कि समानता एवं सामाजिक न्याय प्राप्त करने का एक मात्र साधन शिक्षा है। इस नीति का उद्देश्य शिक्षा के समक्ष आने वाली अवरोधो को दूर करते हुए सभी को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। जिसके द्वारा समतामूलक और समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है।"[14] बच्चों के स्कूली शिक्षा तक पहुँच, समान अवसर, सहभागिता एवं अधिगम परिणामों में बच्चों के समक्ष आने वाले बाधाओं को दूर करने का प्रमुख लक्ष्य है। यह नीति नामांकन और प्रतिधारण की दरों में कमी के कारणों की पहचान कर एवं उचित समाधान द्वारा इन बच्चों तक शिक्षा की पहुँच, भागीदारी एवं अधिगम परिणामों को सामान्य स्तर तक लाने हेतु प्रयासरत है ।

शिक्षा जनजाति बच्चों के लिए उनके अधिकार को समझने एवं उनके विरासत को सहेजने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। कहीं न कहीं जनजाति समुदाय के बच्चे विद्यालय पाठ्यचर्या एवं अपनी सांस्कृतिक परिवेश में किसी प्रकार का जुड़ाव एवं प्रासंगिकता नहीं पाते, इस कारण भी उनमें प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अनुशंसित आश्रम विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालयों के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिला स्तर पर छात्रावास तथा स्वैच्छिक प्रयत्नों जैसी योजनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है।[15] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा में भी सभी वर्गों एवं समुदाय के विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने उपर्युक्त

हस्तक्षेपों के साथ विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु समान अवसर एवं सामाजिक श्रेणी के अंतराल को कम करने हेतु सक्षम प्रणाली बनाने हेतु प्रयासरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें शिक्षा के विकास हेतु हस्तक्षेप की आवश्यकता है एवं उन्हें विशेष शिक्षा क्षेत्र के रूप में अंकित कर वहाँ विशेष प्रयासों द्वारा सभी नीतिगत प्रावधानों जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षा का अधिकार आदि के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान (2021) के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बालिकाओं की शिक्षा एवं ट्रांस जेंडर विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण और न्यायपूर्ण शिक्षा हेतु 'जेंडर– समावेशी निधि' का गठन किया गया है। इस निधि द्वारा इन वर्गों तक शिक्षा नियोजित एवं सुनिश्चित रूप में पहुँचे एवं परिस्थिति जन्य समस्याओं के समाधान एवं सामुदायिक कार्य को प्रभावी बनाने हेतु इस निधि का उपयोग किया जाएगा। इस निधि का संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के सहयोग से करेगी। यह निश्चित ही इन अभ्यर्थियों हेतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समावेशन के विकास हेतु सराहनीय पहल है।[16]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा समावेशन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु "निःशुल्क छात्रावास (विद्यालय तक पहुँच बनाने हेतु) एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को सुदृढ़ किया जाएगा।"[17] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा स्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय की संख्या एवं गुणवत्ता में वृद्धि की जाएगी। प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल हेतु प्री–स्कूल वर्ग को केंद्रीय विद्यालयों एवं वंचित क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों के साथ जोड़ने एवं इस संदर्भ में वर्तमान में क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान (एनसीईआरटी) में संचालित प्री–स्कूल को प्रतिमान के रूप में लिए जाने की अनुशंसा की गई है। जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान किया जाएगा।[18]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा हेतु आरपीडब्लूडी अधिनियम 2016 को स्वीकार करते हुए इसके प्रावधानों को वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में लागू कर दिव्यांग बच्चों के विभिन्न प्रकार के आवश्यकता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ शिक्षकों की नियुक्ति, संसाधन केंद्र, उपयुक्त एवं सहायक विद्यालय परिसर, तकनीक आधारित उपकरण, उपयुक्त शिक्षण सामग्री (विशिष्ट आवश्यकता अनुरूप), शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही गृह आधारित स्कूली शिक्षा (होम स्कूलिंग) हेतु मानक एवं कौशल विकास हेतु अभिभावकों की मदद हेतु प्रावधान किया गया है। विशिष्ट बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षक प्रशिक्षण को अनिवार्य कर सभी विशिष्ट वर्गों हेतु संवेदनशीलता एवं जागरूकता विकसित किया जाएगा। विद्यालयों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप एकीकृत पाठ्यचर्या का निर्माण जिसमें परंपराओं, शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास, विषय ज्ञान एवं अवबोधन को विशेष स्थान दिया जाना सुनिश्चित है। विभिन्न वर्गों के शैक्षणिक विकास की असमानताओं को दूर करने हेतु छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम, छात्रवृति एवं फीस माफी आदि प्रावधान किए गए है, जिससे विद्यार्थी माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर उच्चतर शिक्षा की ओर अग्रसर हो सकें। साथ ही इन्हें इन योजनाओं का लाभ देने हेतु सिंगल विंडो प्रणाली लागू

करना है जिससे सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूह (एसईडीजी) वाले विद्यार्थी इन योजनाओं से वंचित न रहे। इस नीति का उद्देश्य समता एवं समावेशन हेतु विद्यालय संरचना, संस्कृति एवं वातावरण में बदलाव के साथ विद्यालय स्तर के सभी प्रतिभागियों में संवेदनशीलता विकसित करना है।[19]

समावेशन हेतु वर्तमान में किए जा रहे प्रयास

समावेशी शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की सुविधा एवं गुणवततापूर्ण शिक्षा हेतु शैक्षिक निकायों की सहायता से विशिष्ट हस्तक्षेप किए जा रहे है जैसे एनसीईटी द्वारा ई–पाठशाला पोर्टल एवं मोबाइल एप्प व ऑडियो पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, दीक्षा पोर्टल, प्रसस्त एप्प, पीएम ई–विद्या, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की सहायता से भारतीय सांकेतिक भाषा में अध्ययन सामग्री, छात्रावास, ब्रिज पाठ्यक्रम, छात्रवृति आदि। समावेशन से संबंधी अनेक दस्तावेजों जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु आधार पत्र, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023, नेशनल गईड लाइन्स एंड इंप्लीमेंटेशन फ्रमेवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एडुकेशन आदि समावेशन को प्रभावी बनाने हेतु सहायक है।

स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2023) में शैक्षिक संस्थानों में समता एवं समावेशन हेतु पाठ्यचर्या में अमूल चूल परिवर्तन के साथ उसके समावेशित अभ्यास पर बल दिया गया है जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थियों को अवसर की समानता प्राप्त हो सके।[20] इसमें समावेशन के सैद्धांतिक पहलू पर चर्चा करते हुए समावेशन के लिए अवरोध मुक्त एवं सुरक्षित वातावरण, सभी तक समान पहुँच बनाने हेतु भौतिक संसाधन, आवश्यकता अनुरूप मातृ एवं क्षेत्रीय भाषा का उपयोग, पक्षपात रहित शैक्षिक संसाधन जिसमें सभी संस्कृति एवं विविधताओं का प्रतिनिधित्व हो एवं ऐसे शिक्षणशास्त्रीय उपागमों का समावेशन जो विद्यार्थियों के विविध आवश्यकताओं को पोषित करता हो साथ ही इस पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा विशिष्ट एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु शिक्षण पद्धतियाँ एवं वातावरण निर्माण पर विशिष्ट चर्चा की गई है जिसके उपयुक्त क्रियान्वयन द्वारा समावेशन की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है।[21]

नेशनल गईड लाइन्स एंड इंप्लीमेंटेशन फ्रमेवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एडुकेशन (2023) का विकास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसंशाओं के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों की क्षमताओं को पहचानना एवं उनमें निहित विविधता को स्वीकृति प्रदान करना है साथ ही विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित कर उनके क्षमताओं को विकसित करना एवं सभी विद्यार्थियों को शिक्षा द्वारा लाभान्वित करना है।[22] यह सभी हस्तक्षेप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समावेशन की संकल्पना को आकार देने में प्रभावी भूमिका निभा रहे है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे है किन्तु इसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी है जैसे शिक्षा नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, भौतिक एवं मानव संसाधन, पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का आवंटन आदि जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समावेशी शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल अवधारणा के तहत समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा पर विशेष चिंतन किया गया है जिससे सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधारभूत संरचना को सुदृन्द बनाया जा सके एवं विद्यालय में मानवीय मूल्यों का संचरण एवं सभी को समतामूलक, समावेशी, न्याय संगत एवं संवेदनशील शिक्षा की ओर अग्रसर किया जा सके। जिसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालयी संरचना एक नई ऊर्जा के साथ सकारात्मक रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हो एवं राष्ट्र निर्माण में सभी जन सकारात्मक ऊर्जा के साथ योगदान दे सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा हेतु प्रयास किए जा रहे है, किन्तु इसकी सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है इस हेतु दृन्द इच्छा शक्ति, समर्पण, जवाबदेही एवं समन्वयन की आवश्यकता है।

❐

सन्दर्भ –

1. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 6,*
2. *पूर्वोक्त, पृ. 3.*
3. *यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एडुकेशन (2021–22). शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. पृ. 23.*
4. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 38,*
5. *नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन (1986). मानव संसाधन विकास मंत्रलाय, भारत सरकार, नई दिल्ली. पृ. 3.*
6. *आरपीडब्लूडी अधिनियम (2016). भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 8.*
7. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 38.*
8. *द डिसेबिलिटी डिस्क्रिमनेटरी एक्ट (2005). अ लॉ टू हेल्प डिसेब्लड पीपल (2009). ऑफिस ऑफ डिसेबिलिटी इसयूस, एचएम गवर्नमेंट, पृ. 6.*
9. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005). एनसीईआरटी, नई दिल्ली, पृ. 36.*
10. *सर्व शिक्षा अभियान (2000). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 5.*
11. *शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 4.*
12. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020). मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 43.*
13. *पूर्वोक्त, पृ. 38.*
14. *पूर्वोक्त, पृ. 6.*
15. *पूर्वोक्त, पृ. 41.*
16. *पूर्वोक्त, पृ. 40.*
17. *पूर्वोक्त, पृ. 41.*
18. *पूर्वोक्त, पृ. 41.*
19. *पूर्वोक्त, पृ. 42.*
20. *स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2023). एनसीईआरटी, नई दिल्ली, पृ. 180.*
21. *पूर्वोक्त, पृ. 183.*
22. *नेशनल गाईडलाइनस एंड इंप्लीमेंटेशन फ्रमेवर्क ऑन इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एडुकेशन (2023). एनसीईआरटी, नई दिल्ली. पृ. 13.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 79–84

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

आपदा से अवसर : अम्बेडकर की प्रासंगिकता

डॉ. विमल कुमार लहरी
डी. लिट.
सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग एवं पी. आई., इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उ.प्र.)
Email: vimalk-lahari1@bhu.ac.in

सारांश

प्रस्तुत शोध आलेख आपदा से अवसर के संदर्भ में अंबेडकर की प्रासंगिकता पर आधारित है, जिसमें यह दृष्टिगत करने का प्रयास किया गया है कि अंबेडकर का जीवन काल ऐसे दौर में था, जहाँ बड़े स्तर पर लोगों का जीवन मुख्यधारा से पूरी तरह अलग–थलग था। ऐसी स्थिति के बीच अंबेडकर ने स्वयं अस्पृश्यता एवं छूआछूत का दंश झेला एवं लोगों को इस स्थिति में देखा भी। अंबेडकर ने इसे नियति के रूप में नहीं माना, बल्कि एक अवसर के रूप में स्वीकार किया। अपने कठिन संघर्षों एवं सार्थक प्रयासों से हाशिये के समाज को केंद्र में लाने का आजीवन प्रयास किया। अपने प्रयासों से स्थिर समाज को गतिशील बनाया। आज अंबेडकर का भौतिक शरीर नहीं है, परंतु उनके विचार लोकजन को आपदा से अवसर की तरफ बढ़ने के लिए एक अभिकरण के रूप में उत्तरदायी हैं।

मुख्य शब्द : अस्पृश्यता, छूआछूत, नियति, अवसर, चिंता, आपदा, अभिकरण, पुरुषार्थ, समावेशन, उन्मूलन, मानवीय धर्म, अवर्णनीय, क्रांति, भिक्षुणी, प्रव्रज्या, वसुधैव कुटुम्बकम

परिचय एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

भारत ही नहीं वरन वैश्विक पटल पर हम देखें तो शोषण एवं अत्याचार के कारण जनसंख्या के एक बड़े भाग का जीवन पूरी तरह से हाशिए पर था। मानव सभ्यता की विकास यात्रा में हाशिए के लोकजन का शोषण लगभग हर कालखंडों में होता रहा है। हाशिये के समाज को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ प्रतिरोध की आवाजें जरूर उठी, लेकिन वह आवाजें इतनी कमजोर थी कि बुर्जुआ वर्ग के पैरों तले दबकर रह गयीं। व्यावहारिक धरातल पर क्रियारूप धारण नहीं कर सकीं। इन पर होने वाले शोषण एवं अत्याचार की वैचारिकी यहीं तक नहीं रूकती, बल्कि यह वैचारिकी इतनी बढ़ती गई कि मानव– मानव की परछाईयों से भी दूर भागने लगा। इस तरह एक तरफ पितृसत्ता की जडें महिलाओं को अपने पैरों तले दबाए रखी,

तो दूसरी तरफ छुआ–छूत, अस्पृश्यता एवं बेगार के नाम पर जनसंख्या के एक बड़े भाग को मुख्यधारा से पूरी तरह अलग–थलग कर दिया गया है। उनका जीवन तो था, परंतु मृत शरीर के समान, जो अपने शरीर के भार को स्वयं अपने ही कंधों पर ढो रहे थे। ऐसी स्थिति में डॉ. अंबेडकर का इस धरा पर आगमन हाशिए के लोकजन के लिए किसी ईश्वरीय सत्ता से कम नहीं था। "भीमराव अम्बेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिये एक 'महान धर्मयोद्धा' थे।"[1] इस लिए कहा जाता है कि –"अम्बेडकर ही वे महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने संवैधानिक धरातल पर विविध विकृतियों को समाप्त कर मानवीय धर्म की स्थापना के लिये सार्थक पहल की।"[2] भारत में असमानता के संदर्भ में ज्यां द्रेज एवं अमर्त्य सेन कहते हैं कि "भारत में आवश्यक सुविधाओं तथा अवसरों से जो कि हर किसी को उपलब्ध होने चाहिये, एक बड़ी आबादी को वंचित रखना सामाजिक अन्याय के सबसे खराब पहलुओं में है।"[3]

अंबेडकर ने ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अनास्था एवं अव्यवस्था के बीच हाशिये के लोकजन की स्थिति को केंद्र में लाने एवं उनके जीवन को आपदा से अवसर में बदलने के लिए सर्वप्रथम शंखनाद किया। आज अम्बेडकर जीवित नहीं हैं, परन्तु उनके विचार हाशिये के लोकजन को निरन्तर अवसर उपलब्ध कराने में एक अभिकरणके रूप में उत्तरदायी हैं। इस पक्ष को मजबूत कराते हुये प्रो. बद्रीनारायण कहते हैं कि– ''जीवित अम्बेडकर से ज्यादा मृत अम्बेडकर प्रभावी हुए।"[4] इस तरह देखा जाय तो अम्बेडकर अपने 'अवर्णनीय संघर्षों' को अवसर के रूप में स्वीकार किया। अस्तु, इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध–आलेख को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

आपदा से अवसर : अंबेडकर की प्रासंगिकता

भारतीय समाज पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा पर आधारित रहा है। वैसे इसका आधार दार्शनिक रहा, परंतु कालक्रम में कुछ स्वार्थपरक शक्तियों द्वारा इसे व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच लागू किया गया। अपवित्रता के नाम पर जनसंख्या के एक बड़े भाग को हाशिये पर ढकेल दिया गया। अंबेडकर का जीवन भी अस्पृश्यता के दंश साथ ही गतिमान रहा। इस संदर्भ में गेल ओमवेट का कहना है–"भीमा और एक अन्य अछूत विद्यार्थी को कक्षा में अलग बैठना पड़ता था। कोई भी नाई उनके बाल काटने को राजी न था। जब उन्होंने संस्कृत पढ़नी चाही तो उन्हें पता चला कि यह अछूतों के लिए प्रतिबंधित है।"[5] अंबेडकर ने इस तरह के दंश को नियति के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि अवसर के रूप में अपने जीवन का उत्सर्ग किया एवं हाशिये के लोकजन को संदेश भी दिया कि वे अपनी प्रस्थिति को, अपने पुरुषार्थ, बुद्धि एवं क्षमता से अवसर में बदल सकते हैं। अंबेडकर के इस उद्घोष से समाज में एक एक वैचारिक क्रांति का उदय हुआ। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई। इस तरह अम्बेडकर ने सिर्फ सुधार ही नहीं किया, बल्कि संघर्षों को अवसर में बदलने के लिये क्रांति का आगाज किया। कहा जाता है– ''परिवर्तन जब धीरे–धीरे आता है, तब सुधार कहलाता है किन्तु वही जब तीव्र पहुँच जाता है तब उसे क्रांति कहते हैं।"[6] वास्तव में अंबेडकर का अवदान एक 'महान क्रांति' का आगाज था।

अंबेडकर का मानना था कि अनुकूलनशीलता, दक्षता, समावेशन, अवसर, सार्वभौमिकता के माध्यम एवं कार्य संस्कृति में प्रस्तावित बदलाव से श्रमिकों एवं हाशिये के लोकजन के लिए

नए भारत का निर्माण करके और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। डॉ. अंबेडकर श्रमिकों को शोषण एवं अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी बातों को रखा और जीवन के अंतिम क्षण तक हाशिये के लोकजन को मुख्यधारा में लाने के लिए पुरुषार्थ किया। वे सदैव इस बात को लेकर क्रियाशील रहे कि किस तरह से शोषित एवं दमित मानव समाज को न्याय मिले, शोषण से मुक्ति मिले एवं एक सामाजिक मानव के रूप में जीवन व्यतीत एवं गतिमान हो। अंबेडकर ने विदेशी हुकूमतों के साथ–साथ अपने ही देशवासियों की जकड़न से जनसंख्या के एक बड़े भाग को स्वतंत्र कराने के लिए विभिन्न सत्याग्रहों, धरना, आंदोलनों, लेखन, समाचार–पत्र एवं विविध पुस्तको के माध्यम से मूर्त रूप देने का सार्थक प्रयास किया।

अंबेडकर व्यक्ति विशेष के नहीं थे, बल्कि सबके थे। समाज के हर तबके के लिए थे। यहाँ बात करे हम महिलाओं की तो महिलाएं अस्पृश्य (अछूत) समाज की बजाय अपने को सभ्य, संभ्रांत और उच्च प्रस्थिति के रूप में प्रदर्शित करने वालों के बीच कहीं अधिक शोषित और दमित रहीं। महिलाओं के शोषण और दमन की यात्रा यहीं नहीं रुकती, बल्कि पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के शव के साथ चिता में जबरन जला दिया जाता था। वास्तव में यह कृत्य मानवता पर काला धब्बा ही नहीं, बल्कि मानवता की पराकाष्ठा से ऊपर था। अंबेडकर महिलाओं की सभी स्तरों पर स्वतंत्रता एवं भागीदारी के लिए अनवरत लड़ते रहे। सदैव संबोधित भी करते रहे कि महिलाएं अपनी स्थिति को नियति या आपदा के रूप में नहीं, बल्कि अवसर के रूप में बदलें। इसी कड़ी में उन्होंने समान कार्य के लिए समान वेतन एवं कार्यक्षेत्र पर लैंगिक भेद जैसी वैचारिक को समाप्त करने के लिए भी सार्थक पहल किया। मजदूरों, हाशिए के लोगों एवं महिलाओं की प्रस्थिति तथा भूमिका को मजबूत करने के लिए स्वतंत्र श्रम पार्टी की स्थापना भी किया। महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में अजय कुमार कहते हैं कि "बुद्ध ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देखकर महिला सशक्तिकरण के आंदोलन की नींव रखी थी। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को शिक्षा पाने, भिक्षुणी बनने आदि का अधिकार दिया और उन्हें पूर्ण बौद्धिक स्वतंत्रता प्रदान की। डॉ. अंबेडकर इस बौद्धिक क्रान्ति का उल्लेख करते हुए लिखते हैं– बुद्ध ने स्त्रियों को प्रव्रज्या का अधिकार देकर एक साथ दो दोषों को दूर किया। एक तो उनको ज्ञानवान होने का अधिकार दिया, दूसरे उन्हें पुरुष के समान अपनी मानसिक संभावनाओं को अनुभव करने का हक दिया। यह एक क्रांति और भारत में नारी स्वतंत्रता दोनों थी।[7]

आज अंबेडकर का भौतिक शरीर नहीं है, लेकिन उनके विचार उत्तर–आधुनिकता के पायदान पर भी आपदा को अवसर में बदलने में सक्षम दृष्टिगोचर हैं। अंबेडकर दलितों, शोषितों एवं पिछड़ों की आवाज थे। इनके पुरुषार्थ के क्रिया स्वरूप ही हाशिए की भागीदारी सुनिश्चित हो पायी। अंबेडकर का मानना था कि हाशिये का समाज शिक्षित, संगठित एवं संघर्ष करके अपने संकट एवं 'आपदा को अवसर' में बदल सकता है। आज उसी 'आपदा से अवसर' की बात हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा की जा रही है।

अंबेडकर का मानना था कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के धार्मिक सिद्धांत एक धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना करते हैं। अंबेडकर ने अपनी इस बात को अपनी पुस्तक में गंभीरता से रखा। डॉ. अंबेडकर कहते थे कि समतामूलक समाज एवं लोकतंत्र की जड़ें भारत

में आसानी से व्यावहारिक धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो सकती। इसके लिए सभी को कड़े संघर्षों से गुजरना होगा, तभी सही मायने में असली आजादी प्राप्त होगी, और हम मूल्यों के अनुरूप जीवन जी सकेंगे एवं 'नव–समाजवाद की हवा' में 'स्वतंत्र सांस' ले सकेंगे। इसी परिप्रेक्ष में अंबेडकर ने भारत में बहुसंख्यकों के स्व–शासन का समर्थन भी किया।

अंबेडकर जीवन–पर्यंत अस्पृश्यता के दंश को झेला। 'गले में मटका' और 'कमर में बंधे झाड़ू' को बड़ी नजदीक से देखा। इन स्थितियों से मानव समाज को बाहर निकलने के लिए अंबेडकर ने 'आपदा से अवसर' का मंत्र उनके बीच रखा, और उन्हें संघर्ष करने के लिए अपनी वैचारिकी के माध्यम से उनके अंदर प्राण–वायु का का प्रवाह किया। धीरे–धीरे अस्पृश्य समाज के बीच अंबेडकर के विचारों ने चेतना का प्रवाह किया, और इस चेतना के प्रवाह ने उन्हें झाड़ू और मटके ही नहीं वरन उन्हे स्वयं की नियति से बाहर भी निकाला एवं अस्पृश्यों के प्रति अन्य तबकों के परंपरागत मान्यताओं को भी तोड़ा। इस तरह अंबेडकर ने तो स्वयं अपने जीवन को 'आपदा से अवसर' में बदलाव, तो वहीं दूसरी तरफ हाशिये के लोकजन को भी उनके जीवन के कष्टों, संघर्षों एवं आपदा को अवसर में बदलने का राष्ट्रवादी कार्य किया। इस संदर्भ में बी.के. नागला का कथन है– "उनका विश्वास था कि जब तक दलित स्वयं उठकर अपनी स्थिति पर विचार नहीं करते, तब तक दलितों को कोई सुधार नहीं सकता। हालात को उनके स्वयं के अलावा कोई जान भी नहीं सकता। अम्बेडकर ने कहा कि दलित अपनी स्थिति स्वयं पहचाने। समाज के दोषों के विरुद्ध संघर्ष के लिए उनकी अपनी आत्म चौतन्यता जाग्रत होना आवश्यक है। उनके मस्तिष्क में यह डालना जरूरी है कि वे अपना गूंगापन छोड़े और जिस अमानवीय तरीके से वे रह रहे हैं, उससे मुक्ति पाएँ। स्वतंत्रता कोई उपहार में नहीं देता। उसे संघर्ष कर पाया जाता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। आत्मा मुक्ति कोई दूसरा नहीं देता उसे स्वयं के संघर्ष से प्राप्त करना होता है।"[8] वस्तुतः यह पक्ष 'आपदा से अवसर' का एक जीवंत दृष्टांत है।

अंबेडकर जमींदारी उन्मूलन, सामूहिक खेती, औद्योगिककरण के साथ साथ बीमा के राष्ट्रीयकरण एवं उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर विशेष बल दिया। इन क्षेत्रों में हाशिये के लोकजन को अवसर तलाश करने के लिए प्रेरित भी किया। अंबेडकर धन के न्यायपूर्ण वितरण को भी आवश्यक माना। इस संदर्भ मे उन्होने ने कहा कि समाज का सुख ही राष्ट्र की सच्ची संपत्ति है, और धन का न्यायपूर्ण वितरण मानवीय जीवन को सुलभ बनाता है। जाति–धर्म से परे लोकजन के बीच सभी स्तरों पर वितरण की वैचारिकी को रखा। इस तरह देखा जाए तो अंबेडकर ने समानता आधारित मानवीय समाज की स्थापना पर विशेष बल दिया। कबीर एवं रैदास भी 15वीं शताब्दी में समानता आधारित समाज की कल्पना अपने विभिन्न पदों के आधार पर किया। यहाँ हम देखे तो डॉ. अंबेडकर कबीर एवं रैदास से विशेष प्रभावित दिखते हैं।

आज वैश्विक पटल पर मानव सभ्यता जाति–प्रजाति भेदभाव, सांप्रदायिकता एवं धार्मिक भेद के साथ–साथ अस्मिता एवं पहचान के संकट के दौर से गुजर रही है। वैश्विक सर्वोच्चता आधारित लोग इस सभ्यताओं का संघर्ष एवं विचारधारा के अंत के साथ–साथ इतिहास का अंत कहकर 'महामंडित' कर रहे हैं, जिसके कारण पूरी दुनियाँ विभिन्न खेमों में बटती नजर आ रही है, जबकि दुनियाँ को विविध खेमों में बटे विचारों की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसे विचारों की जरूरत है जो लोकजन को 'वसुधैव कुटुम्बकम' के पाठ पर ले जा सके, और यह तभी संभव

होगा जब अंबेडकर के विचार रूपी रास्ते पर चलेंगे। अर्थात 'युद्ध से बुद्ध की ओर' बढ़ना होगा। तभी इस धरा पर मानव अस्तित्व सुरक्षित होगा।

आज वैश्विक स्तर पर पूरी दुनियाँ कोरोना महामारी (कोविड–19) से जूझ रही है। जिसके कारण पूरी दुनिया का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन प्रभावित हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार छीन गए, लोग बेसहारा एवं बेघर हो गए। हाशिए के लोकजन ने हजारों किलोमीटर की यात्रा को कहीं पैदल तो कहीं नंगे पांव तय किया। एक बार फिर जनसंख्या के एक बड़े भाग के सामने इनकी अस्मिता एवं पहचान के संकट की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ऐसी स्थिती में हमें एक बार पुनः अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करना होगा। अर्थात सभी को मिलकर आपदा में अवसर की तलाश करनी होगी। इस संदर्भ में अम्बेडकर के एक लेख का कुछ अंश यहाँ उद्धत है "दर्शनशात्र का कार्य विश्व को पुनः निर्मित करना है, न कि अपना समय यह बताने में ही बर्बाद करते जाना है कि यह संसार कैसे आरम्भ हुआ।"[9]

हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अंबेडकर की वैचारिकी से प्रभावित होकर भारत के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कोरोना महामारी (कोविड–19) के संकट से उबरने के लिए अवसर की तलाश करने की बात कही जा रही है। वास्तव में यह शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिया गया 'मंत्र' अंबेडकर की प्रासंगिकता को वैश्विक पटल पर दृष्टिगत करता है। भारत के शीर्ष नेतृत्व द्वारा संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्रमिकों के जीवन की स्थिती में सुधार एवं अवसर उपलब्ध करने हेतु सारे कदम उठाए जा रहे हैं। श्रम कानून के प्रवर्तन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा रही है।

इस तरह देखा जाए तो अंबेडकर के विचार कल भी संकट एवं आपदा को अवसर में बदलने के लिए अभिकरण थे, और आज कोरोना महामारी (कोविड–19) के संकट के दौर में भी लोकजन को आपदा से अवसर की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत आत्मबल एवं अभिकरण के रूप में उत्तरदायी हैं।

समापन–अवलोकन

प्रस्तुत शोध आलेख का निष्कर्षगत मूल्यांकन किया जाय तो पाते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था विविध कालखण्डों में समान भागीदारी को लेकर बहुतायत उदासीन रही है। अस्पृश्यता एवं छूआछूत के नाम पर जनसंख्या का एक बड़ा भाग हाशिये पर रहा है। इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बड़े स्तर पर आवाजें नहीं उठीं। हाँ, धर्म की भित्ति का सहारा लेकर कबीर, रैदास, दादू, धन्ना, पीपा, सेन, त्रिलोचन, सधना आदि संतों ने कुछ सवाल जरूर किए, उन्ही सवालों को अंबेडकर व्यवहार में क्रियान्वित करने का सार्थक प्रयास किया और अस्पृश्यता एवं छूआछूत के दंश को अवसर एवं चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया। आज अंबेडकर का भौतिक शरीर नहीं है, परंतु उनके विचार हाशिये के लोकजन का आत्म संबल बने हुए हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि आज अंबेडकर अपने विचार के रूप में लाखों नहीं, बल्कि करोड़ो की संख्या में जीवित हैं। आज 'मृत अंबेडकर' कहीं अधिक प्रभावी हैं।

❐

सन्दर्भ –

1. *सिंह, जे.पी. (2005) : आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, पी.एच.आई. लर्निंग प्रा. लि., नई दिल्ली, पृ. 164*
2. *लहरी, विमल कुमार (2018) : डॉ. बी.आर. अम्बेडकर– हाशिये से मुक्ति तक, रिलायंस पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, पृ. प्राक्कथन का कुछ अंश*
3. *द्रेज, ज्यां एवं अमर्त्य सेन (अनुवादक– अशोक कुमार–2019) : भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 280*
4. *बद्रीनारायण ((2014) : लोक संस्कृति और उसका इतिहास, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. 105*
5. *ओमवेट, गेल (अनुवादक– डॉ. पूरन चंदन दास–2005) : अम्बेडकर– प्रबुद्ध भारत की ओर, पेंगुइन बुक्स इण्डिया, भारत, पृ. 05*
6. *दिनकर, रामधारी सिंह (2008) : संस्कृति के चार अध्याय, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद पृ. 475*
7. *लहरी, विमल कुमार (2019) : जनमानस के मसीहा– डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, रिलायंस पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृ. 22*
8. *नागला, बी.के. (2015) : भारतीय समाजशास्त्रीय चिन्तन, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. 281*
9. *विद्रोही, संगमजी (2011) : त्री परिवर्तनकारी– बुद्ध, अम्बेड, मार्क्स, अम्बेडकर साहित्य एवं कला केन्द्र, वाराणसी, पृ. 71*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 85–94

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

उत्तर प्रदेश की राजनीति का बदलता परिदृश्य एवं उसके निहितार्थ

कुमारी पूजा भारती
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)–226025
E-mail: Poojabharti314@gmail.com Mob.- 8840326692

प्रो. रिपु सूदन सिंह
प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, लखनऊ
E-mail: Ripusudans@gmail.com

सारांश

कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक लंबे समय तक आकर्षण का केंद्र रही है परंतु केंद्रीकरण एवं राजनीतिक अस्थिरता की वजह से एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण करने में असफल रहा है। 1950 से 1989 तक लगभग उत्तर प्रदेश में कुल 12 मुख्यमंत्री में से 10 मुख्यमंत्री उच्च जातिगत पृष्ठभूमि से थे तथा केवल दो विपक्ष दल के मुख्यमंत्री इस पृष्ठभूमि के बाहर से थे। 1991 के बाद का समय उत्तर प्रदेश के राजनीति में इस धारणा को तोड़कर अन्य पार्टियों को भी अवसर देता है। प्रदेश की राजनीति ओबीसी आरक्षण, मंडल कमीशन, राम मंदिर, पहचान की राजनीति पर मुख्य रूप से केंद्रित रही तथा मंडल कमीशन की आड़ में जाति की राजनीति को प्रदेश में और अधिक गति मिली जिसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से मुलायम सिंह को मिला। मुलायम सिंह को पिछड़ों के मसीहा के रूप में देखा गया दूसरी ओर काशीराम जो कि दलित आंदोलन को जगाने में लगे थे मंडल आयोग से उन्हे भी एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई। 1990 के दशक से मंडल की राजनीति धीरे–धीरे परिवर्तित करती हुई हिंदुत्व एवं संप्रदायवाद की राजनीति की तरफ रुख करती है। इस दशक में राम मंदिर का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में तूल पकड़ने लगा परिणामतः बीजेपी को उत्तर प्रदेश में स्थान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने पूरी लड़ाई लड़ी। 1991 के विधानसभा चुनाव का परिणाम बीजेपी के पक्ष में रहा। अतः धीरे–धीरे उत्तर प्रदेश की राजनीति वर्ग विशेष से जाति, हिंदुत्व एवं संप्रदाय के राजनीति में बदलती हुई नजर आई जिसने प्रदेश के विकास को प्रभावित किया तथा राजनीति का मुख्य मुद्दा पीछे छूटता गया। अतः इस अध्ययन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना तथा उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है।

मुख्य शब्द– अभिजात वर्गीय, आधुनिकतावादियों, मंत्रिस्तरीय समूह, असंतुष्ट समूह।

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश, लगभग 24.14 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जिसे राजनीति का निर्धारक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह प्रदेश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33 प्रतिशत क्षेत्र को समाहित करता है तथा भारत का चौथा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। भारत के इस उपखंड की तुलना विश्व के अन्य देशों से किया जाए तो उत्तर प्रदेश फ्रांस के क्षेत्रफल का आधा, स्विट्जरलैंड का सात गुना, बेल्जियम का दस गुना तथा इंग्लैंड से थोड़ा बड़ा है। यह न सिर्फ वर्तमान में बल्कि अपने ऐतिहासिक काल में भी अत्यधिक प्रभावी एवं विख्यात राज्य के रूप में जाना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से भी भारत का एक निर्णायक एवं प्रसिद्ध प्रदेश है। इस क्षेत्र ने देश को अति महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक राजनेताओं, प्रधानमंत्रियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों को जन्म दिया है।[1]

उत्तर प्रदेश विधानसभा दो सदनीय विधानमंडल का निम्न सदन है। 1967 तक एक आंग्ल भारतीय सदस्य को सम्मिलित करते हुए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 431 थी। वर्ष 1967 के पश्चात विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 426 हो गई। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन एवं उत्तराखंड के अलग किए जाने के पश्चात, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 403 तथा एक एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य को समाहित करते हुए 404 हो गई। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया परिणामतः वर्तमान में विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या 403 तथा विधानपरि ाद की कुल सदस्य संख्या 100 हो गयी है।[2] उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च, 1952 को हुआ था। तब से इसका गठन अठारह बार हो चुका है, वर्तमान में सत्तासीन अठारहवीं विधान सभा का गठन 11 मार्च, 2022 को हुआ। 1952, 1957 और 1962 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने निर्णायक बहुमत हासिल किया परन्तु राजनेताओं में मतभेद के कारण सत्ता एक पार्टी में होतें हुए भी विभिन्न नेताओं के मध्य झूलती रही तथा एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया। 1967 के बाद यह अस्थिरता और भी अधि ाक हो गई क्योंकि सत्ता कइ दलों के मध्य घूमती रही जो राज्य में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। 1990 के दशक में पिछड़ें वर्गों और दलितों के बीच राजनीतिक चेतना और मजबूत सामाजिक आंदोलन का उदय हुआ, जिससे निचली जाति के दलों–समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व स्थापित होना शुरू हुआ तथा पहचान की राजनीति ने चुनाव और जनसमूह दोनों को प्रभावित किया। कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी जैसे दल जिन्हे ऊंची जाति एवं मनुवादी पार्टीयाँ माना जाता था। अपने मतदाता आधार में गिरावट का अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप निचली जाति की पार्टियां पहली बार राज्य में सरकार बनाने में सक्षम हुई। उत्तर प्रदेश मे पार्टी की राजनीति पिछले कुछ दशकों में तेजी से उथल–पुथल भरे दौर से गुजर रही थी परन्तु 2007 के बाद से यह स्थायी हो गयी है। जाति और सांप्रदायिक संबंधी दो प्रतिस्पर्धी रणनीतियों के कारण भाजपा, सपा और बसपा मजबूत दावेदार के रूप में उभरे, वर्तमान राजनीति में भी राजनीतिक दल एवं उनके नेता अपनी रणनीतियों को दुरुस्त करने में लगे हैं।[3]

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में अब तक हुए सम्पूर्ण विधानसभा चुनावों के मुद्दों, राजनीतिक परिवर्तनों, वोट बैंक के राजनीति एवं विचारधारा, को समझने के साथ–साथ राजनीतिक दलों के कमियों एवं नेत त्व को समझने का प्रयास करेगा है। अतः सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक विचारधारा एवं प्राप्त सीटों का विश्ले ाण किया गया है।

शोध उद्देश्य

- उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण करना है।
- उत्तर प्रदेश के राजनीति में दल विशेष एवं वर्ग विशेष के प्रभुत्व का अध्ययन करना।
- उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति को समझने का अध्ययन करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन पूर्ण रूप से वर्णनात्मक एवं विश्ले ाणात्मक प्रकृति पर आधारित है, इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीय पद्धति के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई है जैसेः– पुस्तक, समाचार–पत्र, सरकारी रिपोर्ट्स एवं प्रकाशन, शोध पत्र, पत्रिकाओं, इ–रिसोर्स।

उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में कांग्रेस का दौर : 1950–1989

उत्तर प्रदेश के विधानसभा का पहला चुनाव 1937 में हुआ तथा जब इसे संयुक्त प्रांत (यूनाइटेड प्रोविसिंज) के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को तत्कालीन प्रीमियर पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थें और 1951 में पहले आम चुनाव के बाद नवगठित उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन हुआ था। जिसमें तब 430 निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे तथा आईएनसी कुल 388 सीटों के साथ सत्ता की कमान संभाली। आजादी के बाद लगभग पहले दो दशकों तक उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के संगठन में व्यक्तिगत एवं गुटबाजी की राजनीति के साथ–साथ अभिजात वर्गीय राजनीतिक व्यवस्था विकसित होती रही। यद्यपि आजादी से पहले कांग्रेस मुद्दों की राजनीति के साथ थी परंतु आजादी के बाद कांग्रेस के अंदर राजनीतिक एवं सांगठनिक परिवर्तन देखने को मिला तथा प्रदेश में कांग्रेस के आंतरिक मामलों में व्यक्तिगत, गुटबाजी एवं अभिजात वर्गीय विचारधारा हावी हो गयी। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह से कांग्रेस दल के उच्च जातियों के नेताओं के हाथों में केंद्रित थी, जो की सत्ता पाने के बाद राज्य के विकास पर ध्यान देने से जादा राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति चिंतित एवं जबाबदेह थे। कांग्रेस के मध्य गुटीय राजनीति के विकास के मुख्य कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मानसिकता एवं आंतरिक असहमति तथा केन्द्रीय नेतृत्व का अभाव आजादी के बाद उत्पन्न हुआ।[4]

आजादी से पूर्व का संघर्ष स्वतंत्रता के लिए था जो की कांग्रेस के लिए सांगठनिक प्रोत्साहन के रूप में काम किया यद्यपि आजादी के पूर्व ही उत्तर प्रदेश में कुछ गुप्त संघर्ष (अप्रत्यक्ष रूप से) व्याप्त थे जो की स्वतंत्रता के बाद प्रत्यक्ष रूप से खुल के सामने आयें जिसमें एक ओर आधुनिकतावादियों और परम्परावादियों के बीच और दूसरा संघर्ष विचारक और परिपक्व प्रखर राजनेताओं के मध्य में थी। आधुनिकतावादी और परम्परावादी विचारधारा के लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की राजनीति से अलग हो गये तथा अपनी अलग पार्टी बनाने मे लग गये अतः कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से मध्यम मार्गी राजनेताओं के हाथों में केंद्रित

हो गयी। यह वो नेतागण थें, जो दोनों समाज के विचारधारा को समझते थे। प्रथम पारंपरिक समाज की विचारधार जो की समकालीन उत्तर प्रदेश के समाज में प्रभावी था। यद्यपि उत्तर प्रदेश में आधुनिकतावादियों और परम्परावादियों के मध्य नोकझोंक चलता रहा।

इस बात पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है की पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 से 1954 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद पर भी नियुक्त रहे तथा वे हिन्दी भाषा एवं संस्कृत के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान देते हूए, हिन्दी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे यद्यपि हिन्दुत्व के प्रति टंडन जी की समर्पितता पूरा देश जानता है। वे राम मंदिर–बाबरी मस्जिद विवाद में प्रमुख रूप से सहयोग दिये तथा राम मंदिर के निर्माण को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाये। टंडन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक क्षेत्र में हिन्दी भाषा और हिन्दुत्व के प्रतिनिधि के रूप में प्रसिद्ध रहे, आधुनिकतावादियों और परम्परावादियों के मध्य संघर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में हिन्दी भाषा और हिन्दू संस्कृति का बोलबाला रहा तथा हिन्दू पुनरुथानवादी विचारधारा हावी रही। उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के दौरान हिन्दू पुनरुथानवादीयों की हार हुई हिन्दू महासभा के प्रतिनिधियों को कम सीट मिली और वे प्रशासन में भाग नहीं ले पायें अतः उत्तर प्रदेश में से राजनीतिक चरमपंथियों को हटा दिया गया तथा कांग्रेस दल में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने भाषा और संस्कृति के प्रश्नों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण और समाजवादी आदर्शों के प्रति एक क्रमिक, गैर हठधार्मिता के दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक उदारवादी आम सहमति बना पायी। तथा अब आपसी टकरार के लिए विशेष रूप से कोई मुद्दा नहीं बचा परंतु उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस प्रायः व्यक्तिवादी समूह या गुटीय राजनीति के इर्द–गिर्द घूमती रही तथा पार्टी का कमान कांग्रेस के मझे हुये राजनेताओं के हाथ में छोड़ दिया गया।

आजादी के तुरंत बाद के वर्षों में संघर्ष और संकट के इस दौर से राजनीतिक नेतृत्व में पीढ़ी गत बदलाव भी हुआ तथा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता या तो कांग्रेस से हट गए या विपक्ष में चलें गए या केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में शामिल हो गए। पण्डित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तथा उस दौर के प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। पंत उन प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रवादी आंदोलन की तरफ मोड़ा तथा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने बिना किसी चुनौती के प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। आंदोलन में पंत जी को उनकी वरिष्ठता, ईमानदारी, बलिदान एवं करिश्माई व्यक्तित्व के लिए सभी के द्वारा सम्मान दिया जाता था। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में पंत जी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कभी भी राजनीतिक विवादों में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया।[5]

1955 तक जाते–जाते कांग्रेस के सर्वमान्य नेता पंत केंद्र सरकार में प्रस्थान कर लिए यह उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक ऐतिहासिक दौर के अंत का सूचक था। नये राजनेताओं के लिए राजनीति केवल एक व्यवसाय के रूप में समझी गइ तथा समकालीन नेतागण द्वारा पद एवं प्रतिष्ठा को वरीयता देते हुए पार्टी तथा उत्तर प्रदेश के हित को गौण रखा गया। कांग्रेस पार्टी ने 1957 और 1962 में हुए विधानसभा चुनावों में निर्णायक बहुमत हासिल किया लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया गया तथा कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति, दल के सांगठनिक संरचना पर हावी होकर केवल मुख्यमंत्री का पद प्राप्त

करने वालों की रणभूमि बन गई। उतार–चढ़ाव वाले दो व्यापक समूह कांग्रेस में विकसित हो गये, प्रथम–सत्ता में आने वाले समूह को मंत्रिस्तरीय समूह और सत्ता के बाहर वाले समूह को असंतुष्ट समूह के नाम से जाना जाता है। मंत्रिस्तरीय समूह और असंतुष्ट समूह में असंतुष्ट समूह राज्य के प्रशासनिक गतिविधियों की आलोचना करता है तथा सरकार में हिस्सेदारी की माँग करता है। जबकि मंत्रिस्तरीय समूह राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से चलाने पर जोर देता है। परिणामतः एक अस्थिर एवं असंतोष का माहौल राज्य में व्याप्त था । कांग्रेस में व्याप्त मंत्रिस्तरीय समूह–असंतुष्ट समूह संघर्ष उत्तर प्रदेश में सीमित न रह कर सम्पूर्ण भारतीय राज्यों में प्रसारित होने लगा था।[6]

अतः विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, इन क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पूर्व के दलों से असंतुष्टि तथा असंतुलित क्षेत्रीय विकास, प्रतिस्पर्धा और जातीयता से लेकर धर्म की भावना इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1967 के चौथे आम चुनाव में गैर–कांग्रेसी की संकल्पना से अनेक राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चे का गठन किया गया। अनेक कांग्रेसी नेताओं ने क्षेत्रीय पार्टीयाँ बना ली जिसमें किसानों के चहेते नेता चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्गों एवं पिछड़े वर्गों के भीतर अपनी लोकप्रियता बनायी और कांग्रेस से अलग हो कर भारतीय लोक दल के नेतृत्व में थोड़े समय के लिए ही सही उत्तर प्रदेश में पहली बार गैर–कांग्रेसी सरकार बनी अथवा चौधरी चरण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे जो पिछले मुख्यमंत्रियों के अभिजात वर्गीय उच्च जाति के प्रोफाइल से बाहर थे परंतु यह बदलाव क्षणिक था।[7] जल्द ही कांग्रेस पुनः सत्ता मे लौट आयी अगले दो दशको तक उत्तर प्रदेश में सत्ता कांग्रेस तथा प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के बीच झूलती रही इस अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य के विकास में किसी भी सार्थक निवेश एवं आधारभूत संरचनात्मक विकास को असंभव बना दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऊंची जातियों का वर्चस्व 1989 तक लगभग बिना किसी चुनौती के जारी रहा। 1947 और 1989 के बीच लगभग 12 मुख्यमंत्रियों में से दस उच्च जाति के थे, ये सभी कांग्रेस से थे इस संभ्रांत समाज के प्रोफाइल के बाहर के सिर्फ दो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री थे।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त विधानसभा सीटः 1950–1989

उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 1951 के अंत से शुरू होकर 1952 में परिणाम आया जिसमें कांग्रेस का सबसे अधिक कुल 388 सीट के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वागत किया। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा 20 तथा तीसरे स्थान पर आईएनडी 15 सीटों के साथ जीत दर्ज की। इसी प्रकार आईएनसी लगातार 1974 तक 200 से अधिक सीटों पर अपना एकाधिकार कर रखी थी तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लगातार आईएनडी को देखा गया परंतु 1969, 1974 चुनाव में बीकेडी क्रमसः 98 तथा 106 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई। 1980 के चुनाव में आईएनसी के विघटन के बाद आईएनसी (आई) को उत्तर प्रदेश में 309 सीटों के साथ शानदार जीत प्राप्त हुई। 1985 के विधानसभा चुनाव में जहां आईएनसी 269 सीटे प्राप्त की वहीं दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में एलकेडी रही। 1989 का चुनाव उत्तर प्रदेश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जिसमें जेडी 208 सीटों के साथ प्रथम पार्टी के रूप में अपनी प्रभुत्व स्थापित करती है। जबकि आईएनसी 94 सीटों पर सिमट गई तथा आगामी चुनावों में

प्रदेश में लगातार अपनी लोकप्रियता खोती जाती है जैसा की ग्राफ में देखा जा सकता है। यह चरण उत्तर प्रदेश के राजनीति में कांग्रेस के अवसान के चरण के रूप में भी देखा जा सकता है।[8]

तालिका संख्या–1 स्रोत – भारत निर्वाचन आयोग,

Party	1951	1957	1962	1969	1974
INC	388	286	249	211	215
BJS	2	17		49	61
BKD				98	106
CPI		9	14	4	16
IND	15	74	31	18	5
PSP		44	38	3	
JS			49		
OTH	25		49	42	21

तालिका संख्या–2 स्रोत – भारत निर्वाचन आयोग,

Party	**1977**	**1980**	**1985**	**1989**
INC	47		269	94
BJP		11	16	57
CPI	9	7	6	6
INC(I)		309		
IND	16	17	23	40
JNP	352		20	
OTH	1	81	91	228

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अवसान तथा मण्डल–कमंडल की राजनीति 1991–2022

1979 में केंद्र की मोरारजी देसाई सरकार द्वारा जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मण्डल आयोग की स्थापना की थी। 1989 में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बदलाव हुआ। यह वह दौर था जब कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश के राजनीति से पतन हो रही थी।

उत्तर प्रदेश में मण्डल एवं कमंडल की राजनीति 1990 के दशक में शुरू हुई। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने घो ाणा की कि अन्य पिछड़ा वर्ग को केन्द्र की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों में नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपने वोट बैंक के राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा कुछ दल मण्डल आयोग के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे।[9] इस मुद्दे के कारण उत्तर प्रदेश में राजनीति एवं सामाजिक दिशा में बदलाव हुआ।

इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक वातावरण में राम जन्मभूमि–बाबरी मस्जिद विवाद का मुद्दा प्रमुख रूप से उठने लगा। आरएसएस का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश पर था परिणामतः 1992 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का मौका मिला और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश से चुन कर आये हुए, सांसदों के बल पर ही केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने में मदद मिली जैसे–जैसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर होती गयी, वह केंद्र में भी सत्ता से बाहर होती गयी। मण्डल एवं कमंडल की राजनीति का प्रभाव बिहार एवं उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव द्वारा मण्डल का झण्डा उठाया गया यद्यपि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में पूर्व भी मुख्यमंत्री रह चुकें थे परंतु मण्डल कमीशन के प्रभावी होने से मुलायम सिंह यादव ने मण्डल की आड़ में जाति की राजनीति को एक नई धार दी और उसका भरपूर लाभ उठाया।[10] जहाँ आयोध्या आंदोलन में उन्हें मौलाना मुलायम के रूप में संबोधित किया गया वही मण्डल की राजनीति में पछड़ों का मसीह कहा गया, हलाकि अंततः वह सिर्फ यादवों के नेता बन कर रह गये, यद्यपि यादव एवं मुस्लिम गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह को शक्तिशाली बनाया। काशीराम मण्डल के पहले से ही दलित आंदोलन को जगाने में लगे हुए थे। मण्डल ने उनके आंदोलन को नई ऊर्जा दी जातिवादी संवेदना दलितों में और मजबूत हुई, जिस कारण बीएसपी और मजबूत हुई। जाति एवं धर्म की राजनीति ने पूरे उत्तर प्रदेश को इस कदर प्रभावित किया कि विकास की मूल भावना पीछे रह गयी। विकास, शिक्षा, समानता, रोजगार वह पैमाना हो सकता था जिसके आधार पर ये सभी नेता अपनी संकीर्ण सीमाओं से बाहर निकल कर एक सेक्युलर पॉलिटिक्स कर सकते थे और मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। परंतु ऐसा हुआ होता तो उत्तर प्रदेश की गिनती विकास की मुख्यधारा में शामिल राज्यों में होती। बड़ा नेता वह नहीं होता जो जाति और धर्म में बंधा रहता है, बड़ा नेता वह होता है जो इन सीमाओं से स्वयं को मुक्त कर के सभी जाति व धर्म के लोगों के लिए स्वीकार्य बना लेता है।

1993 के विधानसभा चुनाओं तक समाजवादी जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी का नाम दिया जा चुका था। इस चुनाव सपा और बसपा के बीच चुनावी ताल–मेल रहा जिससे दोनों पार्टियों को काफी फायदा हुआ। पूर्व के समान कंग्रेस की स्थिति दयनीय रही यद्यपि बीजेपी को जनता का समर्थन मिला। 1996 से 2002 तक का काल उत्तर प्रदेश के संसदीय इतिहास का युद्धकाल माना जाता है। 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड के चलते मुलायम सिंह–कांशीराम की दोस्ती टूट चुकी थी। बीजेपी का समर्थन बसपा के तरफ हो गया तथा उत्तर प्रदेश में 1995 में पहली बार मायावती सत्ता की बागडोर संभाली और दलित समुदाय से उभरने वाली पहली मुख्यमंत्री बनीं परंतु यह प्रयोग क्षणिक था। छः महीने के अंदर ही बीजेपी का समर्थन हट गया तथा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। लेकिन परदे के पीछे सरकार बनाने की कवायदें जारी रहीं। सरकार बनाने के सबसे नजदीक थी बीजेपी बशर्ते उसे बसपा का समर्थन मिल जाता। दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी और कांशीराम के बीच बातचीत शुरू हुई। बीजेपी के पास भी कोई और रास्ता न होने के कारण कुछ शर्तों के साथ छः–छः महीने का मुख्यमंत्री फॉर्मूला निकाला गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2007 तक अस्थिरता से घूमती रही क्योंकि कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। 2007 से 2022 तक का दौर उत्तर प्रदेश

के राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। 1990 के दशक से ही चुनाव दर में बीएसपी मजबूत होती जा रही थी तथा 11 मई 2007 को, उत्तर प्रदेश के लोगों ने निर्णायक रूप से बीएसपी को वोट दे कर पूरे देश को आश्चर्य कर दिया। बीएसपी कुल 206 सीटों को अपने हिस्से में करते हुए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तथा अन्य सभी को पीछे छोड़ दिया जैसा की नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है। इस जीत की एक विशिष्टता यह भी थी की दलित बहुल पार्टी में ब्राह्मण वोटों का एकीकरण था, इस दृष्टिकोण को सैंडविच गठबंधन कहा गया है।[11]

2012 के विधानसभा चुनाव सपा के जीत का कारण, अखिलेश यादव को परिवर्तनशील विचारधारा के नेता के रूप में देखा गया, भ्रष्टाचार एवं अपराधिक प्रवृत्ति की राजनीति का प्रदेश के राजनीति से खत्म करना, पुरानी रूढ़िवादी एवं अराजक राजनीति से बचने के लिए शिवपाल सिंह यादव को प्रचार से बाहर रखा तथा बाहुबली प्रवृत्ति के खिलाफ अखिलेश के रवैया ने मतदाताओं को संदेश दिया कि सपा अपराध मुक्त शासन देने के प्रति गंभीर है एवं नए तजुर्बे एवं नई ऊर्जा के साथ अखिलेश यादव युवा नेता के रूप में लोगों के हृदय में, लोगों को एक नई राजनीतिक अवसर के रूप में दिखें। इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक सपा के ताकत के रूप में दिखी परिणामतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मुरादाबाद एवं रामपुर जैसे स्थान से मुस्लिम सीट पूर्णतः सपा के पक्ष में रही। जनता को भरोसा था कि वह अपने पिता के 20 साल पुरानी पार्टी को जातिवादी और मुख्यरूप से ग्रामीण इकाई के रूप में उसके रूढ़िवादी ढांचे से बाहर निकलेंगे और इसे गैर–साम्प्रदायिक और दूरदर्शी इकाई के रूप में बदल देंगे।[12]

2017 के चुनाव में जनता "मोदी लहर" से प्रभावित हो कर केंद्र के सरकार का उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव रहा परिणामतः 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी निर्णायक प्रदेश के गद्दी पर आसीन हुई यद्यपि इस शानदार जीत के पीछे विभिन्न मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएं जिसमें, सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर निर्माण तथा इसी प्रकार दूसरा सबसे पुराना मुद्दा अनुच्छेद 370 जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया, तीसरा मुद्दा तीन तलाक पर प्रतिबंध बना एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलायें गये विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रत्यक्ष लाभार्थी वोट बैंक के रूप में रहे। केंद्र सरकार की नेतृत्व एवं विचारधारा का प्रत्यक्ष प्रभाव उत्तर प्रदेश में 2017 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी पर पड़ा परिणामतः 312 सीटों के साथ बीजेपी को जनता ने अवसर दिया, तथा इसी प्रकार 2022 के चुनाव में भी योगी सरकार की 255 सीटों के साथ वापसी में केंद्र की नीतियों एवं नेतृत्व का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त विधानसभा सीट : 1991–2022

1991 का समय वैश्विक स्तर के साथ–साथ उत्तर प्रदेश के लिए भी युगांतरकारी परिवर्तन लाया जिसमें बीजेपी 221 सीटों के साथ प्रथम पार्टी के रूप में तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता दल 92 सीट तथा तीसरी पार्टी के रूप में आईएनसी जबकि जनता पार्टी चौथे स्थान पर रही। इसी प्रकार क्रमसः 1996 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी को प्रथम पार्टी के रूप में देखा गया जबकि 1993 और 1996 के चुनाव सपा क्रमशः 109, 110 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर अपनी जगह बरकरार रखी तथा तीसरे स्थान पर बसपा 67 सीट के साथ स्थिर रही। जबकि दोनों चुनाव में आईएनसी चौथे स्थान पर रही। 2002 के चुनाव में सपा को 143

सीटों के साथ प्रथम, बसपा 98 तथा भाजपा 88 सीटों पर अपनी जगह बना पाई जबकि आईएनसी फिसल कर 25 सीटों को सिर्फ अपने पक्ष में कर पाई। 2007 का चुनाव उत्तर प्रदेश राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि पहली बार प्रदेश में स्थित सरकार देखने को मिला जिसने अपना संपूर्ण कार्यकाल पूर्ण किया अथवा बसपा 206 सीटों के साथ अपना कार्यकाल पूर्ण की तथा सपा 97 सीटों के साथ दूसरी पार्टी, बीजेपी 51 सीटों के साथ तीसरी पार्टी जबकि आईएनसी अपनी लोकप्रियता 22 सीटों पर स्थापित की तथा चौथे स्थान पर रही। 2012 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता युवा नेता के रूप में अखिलेश यादव को 224 सीटों के साथ अवसर दी तथा विपक्ष पार्टी के रूप में बसपा 80 सीटों पर जबकि भाजपा 47 सीटों पर आईएनसी 6 सीटों की बढ़त दर्ज की 2017 और 2022 का चुनाव ऐतिहासिक रहा जिसमें बीजेपी क्रमशः 312, 255 सीटों के साथ जाति के राजनीति को हिंदुत्व एवं संप्रदाय के तरफ स्विच करते हुए अपनी लोकप्रियता सिद्ध की जबकि सपा क्रमशः 47, 111 सीटों पर एवं बीएसपी फिसल कर क्रमसः 19 तथा 1 सीट पर अपनी जीत दर्ज कर पाई।

तालिका संख्या–3. स्रोत – भारत निर्वाचन आयोग,

PARTY	1991	1993	1996
BJP	221	177	174
CPI	4	3	1
INC	46	28	33
JD	92	27	7
BSP	12	67	67
IND	7	8	13
SP		109	110
OTH	37	3	19

तालिका संख्या–4. स्रोत – भारत निर्वाचन आयोग,

PARTY	2002	2007	2012	2017	2022
BJP	88	51	47	312	255
INC	25	22	28	7	2
BSP	98	206	80	19	1
IND	16	9	6	3	
SP	143	97	224	47	111
RLD	14	10	9	1	8
OTH	19	8	9	14	26

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति के निर्णायक प्रदेश में एक लम्बे समय तक कांग्रेस का शासन रहा जो की अभिजनवादी उच्च जातीय प्रोफाइल के नेता एवं दल में केन्द्रीय प्रतिनिधित्व के अभाव में जूझता रहा। किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा अपना कार्यकाल पूर्ण करना असंभव रहा। प्रदेश स्थिर सरकार के अभाव में अपनी प्राथमिकतों को भूलता जा रहा था। परिणामतः एक लंबे समय तक

उत्तर प्रदेश में मूलभूत आवश्यकताओं तथा आधारभूत संरचतात्मक विकास की गतिविधि मानो थम सी गई थी। उत्तर प्रदेश की सियासी परिदृश्य में विशेष परिवर्तन लगभग 1960 के बाद से देखने को मिला जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का निर्माण हुआ एकल दलीय व्यवस्था तथा उच्च–जातिगत प्रोफाइल से सत्ता की बागडोर छूटता जाता है। द्वितीय महत्वपूर्ण परिवर्तन 80 के बाद के दशक में देखा गया जब मण्डल कमीसन का प्रभाव सम्पूर्ण देश के साथ–साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है। यही वह दौर था जब उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति को और हवा मिली तथा पहचान की राजनीति के साथ, अति पिछड़े एवं अति दलित की बात आयी, जाति के बीच जाति को महत्व दिया जाना शुरू हुआ। प्रदेश में शासनगत एक लंबी अस्थिरता के बाद 2007 से उत्तर प्रदेश को स्थिर सरकार प्राप्त हुई। इस दौर में ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति बल्कि देश के राजनीति की प्राथमिकता बदल गयी। 2012 के चुनाव में प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को युवा नेता तथा बादलाव के राजनीति को ध्यान में रख कर मौका दी, परंतु 2017 के चुनाव में जनता "मोदी लहर" से प्रभावित हो कर केंद्र के सरकार को उत्तर प्रदेश में भी स्थान दी यद्यपि डबल एन्जन की सरकार ने विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

❐

सन्दर्भ –

1. *NRI Departmenta Governmenta of Uttar Pradesh. Nri.up.gov.in*
2. *उत्तर प्रदेश का अवलोकन https://up.gov.in/hi*
3. *श्रीवास्तव, अकु (10:05:2022) "सेंसेक्स क्षेत्रीय दलों का" प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, भाग 2 (6)*
4. *मोहन, अरविन्द (2021) ''लोकतंत्र की माया'' प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, भाग 1,2 (4,6)*
5. *Datta, K Prabhas (Marcha 10 2017) "How Uttar Pradesh has voted since 1952 onlya 2 full term chief ministers" New Delhi, India Today.*
6. *Scalapino, A. Robert, Masumi Junnosuke "Parties and Politics in Contemporarya Japan" (1962) USA, Universitya of California press.*
7. *हर्षवीर, (2015) "भारत में क्षेत्रीय दलों का उद्भव और विकास" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च, अंक 13, खण्ड 2, पृ. 76*
8. *Election Commission of India-State Election to the Legislative Assemblya of Uttar Pradesh (1950-2022).*
9. *Kishor, Roshan (January,18 2022) "A Real Politic Appraisal of the 'Mandal-Kamandal' fighta in UP" Hindustan Times.*
10. *Pai, Sudha (2007) "Political Process in Uttar Pradesh: Identitya Economics Reform and Govern ance" New Delhi, Pearson Education. Pp. 1, 110, 136.*
11. *Dwinvedi, Kumar Sanjaya (2011) "Emerginga trendsa of Politics in Uttar Pradesh" The Indian Journal of Political Science, Vol.72, No.3, Indian Political Science Association, pp773-780.*
12. *Bhavdeep, Kang "Uttar Pradesh: Impact of Identitya Politics" Economic & Political Weekly, 10 Dec. 2016, Vol.50, pp 15-18.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 95–103

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

औपनिवेशिक काल में दक्षिणी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में शिक्षा का स्वरूप

मिहिर बोराना
शोधार्थी, इतिहास विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि.प्र.)–176215
E-mail- cuhp20129@hpcu.ac.in Mob.- 9462241379

प्रो. नारायण सिंह राव
इतिहास विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)–176215
E-mail- raonarayan2005@gmail.com Mob- 9462241379

सारांश

किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा एक अनिवार्य साधन है। शिक्षा के महत्व को भारतीय समाज प्राचीन काल से ही जागरूक रहा है। इसी के फलस्वरूप भारत में सुदूर अतीत से ही भारत में शिक्षा की एक समृद्ध परम्परा देखने को मिलती है। प्रागैतिहासिक काल से ही यहां के समाज ने चित्रकला, औजार बनाने की कला, खेती करने की शिक्षा के प्रमाण मिलते है। हड़प्पा सभ्यता की नगर वास्तु–शिल्प, व्यापार, मूतिकला और शिल्प कला उस काल की शिक्षा की उत्कृष्ट पद्धति के बारे बताती है। वैदिक ज्ञान जिसके भारत प्राचीन काल में विश्व गुरू रहा था। अंग्रेजी सरकार ने उस प्राचीन सिखने और सिखाने की पद्धति को उलट कर नौकर बनाने वाली शिक्षा पद्धति को लागु किया। अतः इस शोध पत्र में दक्षिणी राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में औपनिवेशिक काल की शिक्षा के स्वरूप को जानने के लिए वहां चलने वाली देशी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, इसके विकास और विकास में सहयोग देने वाली सरकारी व सरकारी संस्थाओं को प्रकाश में लाने का प्रयास किया जाएगा।

मुख्य शब्द– वागड़, सुरम्य उपत्यकाओं, औपनिवेशिक काल, हड़प्पा सभ्यता, मानव अधिवास, शिक्षा पद्धति

प्रस्तावना – भौगोलिक और ऐतिहासिक परिचय

राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित अरावली की सुरम्य उपत्यकाओं के पूर्वी भाग में पहाडियों, जल टापुओं और वनों से सुसज्जित प्रदेश 'वागड़ प्रदेश' के नाम से जाना जाता है जो सम्पूर्ण डूंगरपुर, बांसवाड़ा, धरियावद व प्रतापगढ़ के कुछ भाग को अपने भीतर समेटे हुए है। प्राचीन काल से ही इस प्रदेश के लिए वागड़ भाब्द का प्रयोग होता रहा है। विभिन्न अभिलेखों एवं प्राचीन संस्कृत व प्राकृत साहित्य में इस प्रदेश के लिए वार्गट, वग्गड़, वैयागड़,

एवं वाग्वर आदि नामों का उल्लेख हुआ है।[1] वागड़ भाब्द का अर्थ ''वीरान और उबड़ खाबड़ धरातल वाला क्षेत्र'' होता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से वागड़ क्षेत्र बहुत ही समृद्ध रहा है। वागड़ क्षेत्र में मानव अधिवास के प्रमाण आहड़ सभ्यता से ही मिलने लगते है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मौर्य, मालव, शक, गुप्त, प्रतिहार व परमार राजवंशों का भाासन रहा है। परमार वंश के शासक वाक्पतिराज के दूसरे पुत्र डबरसिंह के वंशजो ने इस क्षेत्र पर शासन किया एवं उनका राज्य वागड़ से 'छप्पन प्रदेश' तक फैला हुआ था।[2]

11वीं शताब्दी में जब गुजरात में सोलंकी वंश के प्रभाव का विस्तार हो रहा था, तब उन्होने वागड़ को भी अपने अधीन कर लिया। बडा दिवडा गाँव से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि भीमदेव द्वितीय का भी इस क्षेत्र पर शासन रहा था। मध्यकाल में यहाँ गुहिलों व सिसोदिया राजवशों का शासन रहा और तीन रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ अस्तित्व में आईं, जो प्रांरभ में मेवाड़ के अधीन थीं। मेवाड़ के शासक रावल क्षेमसिंह के पुत्र महारावल सामंतसिंह सन् 1197 ई. ने वागड़ पर अधिकार कर वहाँ नया राज्य स्थापित किया। प्रांरभ में इसकी राजधानी बडौदा या वटपद्रक को बनाया। महारावल वीरसिंह (1287ई०–1301ई.) ने भील सरदार डूंगरिया भील की हत्या कर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और डूंगरपुर नगर की स्थापना की एवं अपनी राजधानी को सन् 1358 ई. में डूंगरपुर स्थानान्तरित किया। महारावल उदयसिंह (1497ई०–1527ई.) ने वागड़ राज्य को अपने दो पुत्रों में विभाजित कर दिया, जिससे वागड़ में दो राज्य डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य अस्तित्व में आए। बांसवाड़ा राज्य की ख्यात के अनुसार रावल उदयसिंह के दूसरे पुत्र महारावल जगमाल (1515ई.–1545 ई.) ने बांसिया भील को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया और बांसवाड़ा नगर की स्थापना की एवं उसे अपने राज्य की राजधानी बनाया। मेवाड़ के शासक महाराणा कुम्भा के भाई महारावत क्षेमकर्ण (1433 ई.–1473 ई.) ने अलग राज्य स्थापित करने के प्रयास से सादड़ी पर अधिकार कर लिया। क्षेमकर्ण के पुत्र महारावत सूरजमल (1473 ई.–1530 ई.) ने कांठल पर अधिकार कर नया राज्य स्थापित किया तथा देवलिया को अपनी राजधानी बनाया। महारावत प्रतापसिंह (1673 ई.–1708 ई.) ने सन् 1699 ई. में प्रतापगढ़ शहर की स्थापना की एवं यहाँ अपनी राजधानी स्थानान्तरित की। अपने जन्म के साथ ही इन दोनों रियासतों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए मेवाड़ और मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मेवाड़ और मराठों ने इन राज्यों में लूट–मार की। अतः इस लूट–खसोट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ के शासकों ने सन् 1818 ई. में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली।

प्राचीन एवं मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति

मध्यकाल में जब डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ राज्य अस्तित्व में आए तो उन्हे अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए मेवाड़, मुगल एवं मराठों से संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के कारण राजाओं को अपने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने का उचित समय नही मिला। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नही की वागड़ क्षेत्र शिक्षा के हमेशा अछुता रहा हो। यहां निवास करने वाली भील जनजाति की अपनी शिक्षा पद्धति रही है। भील जनजाति में धार्मिक और व्यवसायिक

शिक्षा की प्रधानता थी। (व्यवसायिक शिक्षा से तात्पर्य खेती, शिकार, कला आदि से है।) जो औपनिवेशिक काल में भी सुचारू रूप से चलती रही। कालान्तर में जब वागड़ क्षेत्र में रातपूत राज्यों की स्थापना हुई तब वागड़ में पंडित या ब्राह्मण की पाठशालाएं तथा मुसलमानो के मदरसे व मकतब स्थापित हुए जिनमें वागड़वासी शिक्षा ग्रहण करते थे।[3] पाठशालाओं और मदरसों के अतिरिक्त यहां जैन उपासरे और पोसाले भी शिक्षा का प्रमुख माध्यम थे।[4] पाठशालाएं दो प्रकार की होती थीं। एक शास्त्रीय पाठशाला जिसमें संस्कृत माध्यम में शिक्षा दी जाती थी। जहां गुरू का घर ही शिक्षण का स्थान हुआ करता था। दिनभर में छात्र पहाडे और अक्षर ज्ञान सीखते थे और दोपहर तक मुहारनी बोलाई जाती थी। जिसमें एक से सौ तक गिनती, चालीस तक के पहाडे, सवाया, डेढ़ा, ढाया, घूंटा, पंचा, बडी एका पहाडे, वर्णमाला के स्वर–व्यंजन और सीधो वर्णा शामिल थे।[6]

मध्य युग में वागड़ की भील, शिल्पजीवी और कृषोपजीवी जातियां अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने बच्चों को पाठशालिय शिक्षा दिलवाने के स्थान पर उन्हे अपने–अपने व्यवसाय की शिक्षा दिलवाना ज्यादा उचित समझते थे। इसके विपरित उच्च जातिय लोग अपने वंशानुगत कार्य करने के लिए अपने बच्चों को पाठशालिय शिक्षा दिलवाते थे। जिसके कारण ग्रम, कस्बा और शहरी क्षेत्र में जो भी पाठशालाए एवं मदरसे खुलते थे। वे उच्च वर्गो के बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही खोले जाते थे और उनका पाठ्यक्रम का निर्धारण भी उसी के अनुरूप होता था।

औपनिवेशिक काल में वागड़ में शिक्षण व्यवस्था

सन् 1818 ई. में अग्रेजों से सन्धि करने के साथ ही वागड़ में औपनिवेशिक काल का आरंभ होता है। लेकिन औपनिवेशिक प्रभाव सन् 1857 की क्रान्ति के बाद ही देखने को मिलता है। राजस्थान में परम्परागत शिक्षा के स्थान पर आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ लार्ड हेस्टिंग के प्रयासों से शुरू हुआ। लार्ड हेस्टिंग ने पहली बार राजस्थान में शिक्षा का बजट बनाया और सन् 1818 ई. में अजमेर में एक शिक्षा अधीक्षक की नियुक्ति की। अजमेर चला आधुनिक शिक्षा का सिलसिला धीरे–धीरे सम्पूर्ण राजस्थान में फैल गया।[7] 19वी शताब्दि के अंत तक परम्परागत शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का प्रसार वागड़ में भी होने लगा। वागड़ में आधुनिक शिक्षा के के विकास में अग्रेज प्रशासन, स्थानीय राजाओं एवं क्रिश्चयन मिशनरी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। औपनिवेशिक काल में तीन प्रकार की शिक्षा प्रणाली देखने को मिलती है।

औपनिवेशिक काल में वागड़ में सबसे विस्तृत और सुगम शिक्षा पद्धति परम्परागत शिक्षा पद्धति थी। जहां आधुनिक शिक्षा प्रशासन के लिए नौकर उत्पन्न करने का कार्य कर रही थी तो वही परम्परागत शिक्षा लोगों के स्व को जगाने, जनता को सामाजिक और राजनैतिक रूप से जगाने और में व्याप्त कूरीतियो को दूर करने का प्रयास कर रही थी। गोविन्द गुरू, भोगीलाल पंडया, गौरीशंकर उपाध्याय, नाना भाई खांट, काली बाई, धुलजी भाई वर्मा और कालूराम डामोर आदि समाजसेवी लोगों ने वागड़ में शिक्षा की अलख जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गोविंद गुरु ने भील जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से व उनमें सामाजिक व राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए संप सभा की स्थापना की। उन्होंने गांव–गांव

जाकर अपनी धुनिया स्थापित की और लोगों को रोजाना स्नान करने, शराब न पीने, मांस न खाने, चोरी व लूटपाट ना करने, बच्चों को पढ़ाने, खेती मजदूरी से परिवार को पालने, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने, पंचायतों में फैसला करने, अदालतों के चक्कर में न पडने, बेकार न करने व स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की शिक्षाएं प्रदान की। गोविंद गुरु ने बच्चों को पढ़ाने के लिए वागड़ क्षेत्र में अनेक पाठशाला भी खोली। गोविंद गुरु के प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके एक आवाहन पर उनके हजारों शिष्य मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित हो गए और अपने गुरू की रक्षा के लिए शिष्यों ने (सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1500 और लोक मान्यता के अनुसार 20000) अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना को इतिहास में मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है।[8]

वागड़ के गांधी कहे जाने वाले भोगीलाल पंड्या ने वागड़ के लोगों में व्याप्त अशिक्षा को दूर करने के लिए अपना जीवन लोगो को शिक्षित बनाने में लगा दिया। उन्होने वागड़ में बाल शिक्षा के साथ–साथ प्रोढ़ शिक्षा का प्रारंभ किया। उनका कहना था कि जो शिक्षा मानवीय संवेदनाओं को जागृत नहीं करें, वह शिक्षा ना होकर केवल साक्षरता तक ही सीमित रह जाएगी। यदि शिक्षा को जनहित और लोक कल्याण की और प्रवत न करके यदि उसे व्यक्ति के लिए स्व केन्द्रित बना दिया गया तो शिक्षा की कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। पंड्या जी ने छात्रों को शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक छात्रावास की भी स्थापना की।[9]

भोगीलाल पंड्या से प्रेरित होकर नानालाल खाँट ने भील बालकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपने घर में ही एक पाठशाला खोली। नानालाल खाँट का मानना था कि भील शिक्षित होकर संगठन बनाएंगे और अपने अधिकारों की मांग करेंगे। लेकिन प्रशासन को नानालाल का भीलो को शिक्षित करने का प्रयास अपने लिए खतरे की घंटी लगने लगा। अतः प्रशासन ने नानालाल को मारकर स्कूल बंद कराने का आदेश दिया। पुलिस ने नानालाल खाँट पीटकर उनके शरीर को ट्रक के पीछे बांधकर सारे गांव में घसीट कर मार डालना चाहा। तभी नानालाल खाट की 12 वर्ष की छात्रा काली बाई ने अपने गुरु को छुड़वाने के लिए हाथ में हसिया लिए आगे बढ़ी और चिल्लाती रही कि मेरे गुरु जी को क्यों मार रहे हो इनको गिरा कर क्यों घसीटा जा रहा है। पुलिस ने बालिका को हटने की धमकी दी लेकिन उस वीर बालिका अपने गुरू की रस्सी काट कर ही सांस ली। तब पुलिस ने सिपाहियों ने उस बालिका को गोलियों से भून डाला। गुरू के प्रति शिष्य का इतना समर्पण केवल भारतीय संस्कृति में ही देखने को मिलता है।[10]

ईसाई मिशनरी के आधुनिक शिक्षा के विकास में प्रयास

ईसाई मिशनरी ने वागड़ में शिक्षा का प्रसार–प्रचार लोकहीत में न कर ईसाई धर्म के फैलाव के उद्देश्य से किया। शिक्षा उनके लिए अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए केवल एक साधन मात्र थी। उनका यह भी विश्वास था कि शिक्षा उस व्यक्ति के मन को प्रकाशित कर सकती है जो बदले में सुसमाचार के सत्य में विश्वास को जाग्रत कर सके। इस प्रकार यह आशा की जाती थी कि शिक्षा के माध्यम से वागड़ के लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन होने लगेगे। धर्म प्रचारकों के समक्ष धर्म परिवर्तन की पूरी प्रक्रिया में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व थी। बांसवाड़ा के धर्म प्रचारकों का ईमानदारी से विश्वास था कि जैसे ही आदिवासी बाइबल पढ़ना सीखेंगे वे ईसाई धर्म अंगीकार कर लेंगे। ईसाई धर्म प्रचारकों ने शिक्षा को स्थानीय धर्म को धीरे–धीरे नष्ट करने और उनकी जगह ईसाई धर्म स्थापित करने की अपनी सभी विधियों में सबसे अधिक शक्तिशाली समझा।

जनजातीय शिक्षा की व्यवस्थित शिक्षा योजना का उदगम कनाडा के मिशनरियों से हुआ। जिन्होंने 1918 में एक स्कूल की स्थापना की। उन्होने बांसवाड़ा शहर में मुफ्त स्कूल भी खोले थे। बांसवाड़ा में, मिशनरियों द्वारा भीलों और उनके बच्चों के बीच शिक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि वे इतने अनपढ़ रहे कि वे पढ़–लिख भी नहीं सकते थे। इसलिए यह आवश्यक हो गया कि वे, पढ़ें और लिखें और इसलिए नियमित स्कूली शिक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इस प्रकार, मिशन द्वार अपने प्रारंभिक वर्षों में लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए एक ग्रीष्मकालीन स्कूल–सह–छात्रावास खोला गया। छात्रों को किताबें, स्लेट, लेखन सामग्री, कपड़े, भोजन, आवासीय सुविधाएं आदि मुफ्त दी गईं। सोनी आंटी, गुलाबी आंटी, गेंडी आंटी और आनंदी बाई बांसवाड़ा में शिक्षक के रूप में काम करने वाली नीमच और बांसवाड़ा मिशन की पहली आदिवासी महिलाएँ थीं। मिशन ने उनका खर्च उठाने का फैसला किया और उन्होंने बांसवाड़ा में काम करना शुरू कर दिया। पढ़ाने के अलावा, ये महिलाएं, शिक्षक पवित्र संदेश का प्रचार करने के लिए गांवों का दौरा करती थीं। शिक्षा के लाभों को जानकर, कई जनजातिय लोगों ने अपने बच्चों को ग्रीष्मकालीन स्कूल में भेज दिया।[11] स्कूलों में बच्चों को स्वच्छता का प्राथमिक ज्ञान, चर्च जाना, चर्च एवं प्रार्थना से संबंधित शिष्टाचार, भक्ति गीत और हस्ताक्षर करना सिखाया गया। इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म के पवित्र संदेश के प्रसार के लिए विशेष विचार गोष्ठियों और वार्ताओं का आयोजन किया जाता था। ईसाई मिशनरी के स्कूलो में लड़कों और लड़कियों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, अंकगणित, व्याकरण, प्रार्थना, भजन और वर्तनी थे।[11]

टेबल–1. बांसवाड़ा छात्रावास में छात्र छात्राओं की संख्या

वर्ष	छात्र	छात्राएं	कुल
1924–25	10	5	15
1925–26	12	7	19
1926–27	10	5	15
1927–28	10	6	16
1928–29	12	8	20
1929–30	15	10	25
1930–31	25	15	35
1931–32	20	15	35
1932–33	25	15	40
1933–34	20	12	32
1934–35	15	10	25
1935–36	20	15	35
1936–37	25	20	45
1937–38	30	25	55
1938–39	35	25	60
1939–40	70	40	110

स्रोत–श्यामलाल, ट्राइबल्स एण्ड क्रिश्चयन मिशनरीज, मानक पब्लिकेशन, नईदिल्ली, पृष्ठ 78.

फादर चार्ल्स सबसे ऊर्जावान और साहसी फ्रांसीसी मिशनरियों में से एक थे, जो 1933 में थांदला मिशन, मध्य प्रदेश के चर्चमेन के एक बैंड के साथ बैलगाड़ी में कुशलगढ़ आए थे। फादर चार्ल्स अंबापाड़ा में बस गए, उन्होंने ईमानदारी से प्रचार कार्य शुरू किया और इसे अपना मुख्यालय बनाया, जहां वे 1941 में अपनी मृत्यु तक रहे। कुछ ही महीनों के भीतर उन्होंने नौ छात्रों के साथ अंबापाड़ा में एक लड़कों के स्कूल का आयोजन किया। वे थेः परमा रावत, जॉर्जजी रावत, दीपास रावत, हरदिया डामोर, जीता डामोर, घेबा लबाना, जीया रावत, रंगजी रावत और देवा रावत। मायकल मैदा शिक्षिका थीं। प्रारंभ में, उन्हें पर्याप्त संख्या में आदिवासी छात्रों को आकर्षित करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल आने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए हर छात्र को टॉफ बांटने लगे। तब भी आदिवासी लड़कों को अपने आप स्कूल जाना पसंद नहीं था। इसलिए फादर चार्ल्स को घर–घर जाकर लड़कों को उनके स्कूल के लिए लेने जाना पड़ा। आदिवासियों के लिए बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजना आदिवासियों के लिए नई बात थी। जॉर्ज रावत इस स्कूल में शिक्षित होने वाले मूल लड़कों में से एक थे, जो बाद में शिक्षा के उत्साही प्रचारक बन गए और उनकी वजह से ईसाई धर्म का प्रसार होने लगा।[12]

आधुनिक शिक्षा के विकास में रियासती राज्यों के प्रयास

रियासती राज्यों ने अग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी अतः अंग्रेज सरकार की नीति को अपने राज्यों में लागु करना इन राज्यों के लिए आवश्यक था। इसके अतिरिक्त रियासती राज्यों का अंग्रेज सरकार से सारा पत्राचार अंग्रेजी भाशा में होता था। जिसके लिए रियासतो में अंग्रेजी में पढ़े लिखे क्लर्क की आवश्यकता थी अतः अंग्रेजी शिक्षा को अपने राज्यों में लागु करना आवश्यक हो गया। प्रारम्भ में रियासती राज्यों द्धारा जो भी स्कूल या पाठशालाएं खोली गई उनमें केवल स्थानीय भाषाओ में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। 20वी के आंरभ में तीनों रियासतों में एग्लो वर्नाक्युलर स्कूलों की स्थापना हुई।

वागड़ क्षेत्र में पहला सरकारी स्कूल सन् 1868 ई. में बांसवाड़ा राज्य में खोला गया। यह एक छोटा हिंदी संस्थान था। जिसमें पढ़ाने के लिए गुजराती ब्राह्मणों को बुलाया गया था। जिन्हें हर महीने 9 से 10 वेतन दिया जाता था।[13] बांसवाड़ा के बाद सरकारी स्कूल प्रतापगढ़ में सन् 1875 ई.[14] और डूंगरपुर में महारावल उदय सिंह के शासनकाल में सन् 1893 ई. में खोला गया।[15] धीरे धीरे बांसवाड़ा राज्य में राजधानी के अतिरिक्त भंगुरा, घाटोल, कालिंजर एवं अन्य गांव में भी सरकारी स्कूल खुले। इसके अतिरिक्त गड़ी और कुशलगढ़ के राव ने भी अपने यहां स्कूल स्थापित किए। यदि डूंगरपुर राज्य की बात की जाए तो डूंगरपुर में डूंगरपुर शहर के अतिरिक्त सागवाड़ा, गलियाकोट और साबला एवं अन्य ग्रामीण स्थानों पर स्कूल खुले। सन् 1901 ई. तक बांसवाड़ा राज्य में दरबार स्कूल को मिलाकर 7 ग्रामीण स्कूल एवं डूंगरपुर में एक राजधानी में स्थित स्कूल के अलावा 7 ग्रामीण स्कूल संचालित थे। जबकि प्रतापगढ़ में केवल एक स्कूल के प्रमाण मिलते हैं। सन् 1903 ई. में बांसवाड़ा शहर में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना हुई।[16] सन् 1904 ई. के आसपास कैप्टन पिन्हे के प्रयासों से प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में भी पिन्हें नोबल स्कूल स्थापित हुए। यह स्कूल भी एग्लो वर्नाकुलर थे। प्रतापगढ़ में इन स्कूल में अंग्रेजी नियमित पाठ्यक्रम में शामिल थी तथा उर्दू हिंदी व संस्कृत भाषा एक भाषा थी।[17]

प्रारंभ में इन स्कूलों में मिडिल कक्षा तक ही शिक्षा देने का प्रावधान था लेकिन कालांतर में स्थानीय शासकों के प्रयासों से यह स्कूल हाई स्कूल में परिवर्तित हो गए। जहां सन् 1903–04 ई. डूंगरपुर में 8,[18] सन् 1908–09 ई. में बांसवाड़ा राज्य में 14,[19] और सन् 1908–09 ई. प्रतापगढ़ में 8 स्कूल संचालित थे। वहीं सन् 1945 ई. में डूंगरपुर में 84 प्रतापगढ़ में 54 स्कूल संचालित होने लगे। जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है।

टेबल–2. प्रतापगढ़ राज्य में स्कूलों की संख्या

क्रं.	विद्यालय का नाम	संख्या
1	पिन्हे नोबेल हाई स्कूल	1
2	राज. स्कूल प्रतापगढ़	1
3	मानसिंह कन्या पाठशाला	1
4	रघुनाथ संस्कृत पाठशाला	1
5	गांव स्कूल	23
6	जागीर स्कूल	12
7	स्थानीय निजी स्कूल	13
8	हरिजन स्कूल	1
	कुल –	53

Source : Report on the administration of the Pratapgarh State Rajputana, year 1943-44

टेबल–3. डूंगरपुर राज्य में स्कूलों की संख्या

क्रं.	विद्यालय का नाम	संख्या
1	पिन्हे नोबेल हाई स्कूल	1
2	महारावल हाई स्कूल	1
3	कन्या पाठशाला	3
4	संस्कृत पाठशाला	2
5	एंग्ला हिन्दी स्कूल	1
6	जागीर स्कूल	10
7	स्थानीय निजी स्कूल	36
8	हरिजन स्कूल	1
9	हिन्दी प्राइमरी स्कूल	25
10	नाईट स्कूल	4
	कुल –	84

Source : Report on the administration of the Dungarpur State Rajputana, year 1944-45

वागड़ में बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा देने के लिए डूंगरपुर में सन् 1907 में देवेंद्र कंवर कन्या पाठशाला खोली गई। इस पाठशाला को आदिवासी क्षेत्र में भारत का पहला या प्राचीनतम कन्या पाठशाला होने का गौरव प्राप्त है। इस पाठशाला को खुलवाने में श्रीमती नारायण पंड्या और श्रीमती बाला सुंदरी में अथक परिश्रम किया। सरकार के इन स्कूलों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य कन्याओं को गृह प्रबंधन में कुशल बनाना और उन्हें धार्मिक व सांस्कृतिक शिक्षा देकर समाज के लिए आदर्श नारी उत्पन्न करना था। प्रारंभ में इन पाठशाला में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी। स्कूलों के पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी गणित सिलाई कढ़ाई कि शिक्षा शामिल थी।[20] जुलाई 1913 में बांसवाड़ा में भी और प्रतापगढ़ में भी इस तरह की मानसिंह कन्या पाठशाला की स्थापना की थी।[21] छात्राओं में शिक्षा के प्रति रूचि उतपन्न करने के लिए महारावल रामसिंह (सन् 1929–1947 ई) ने कन्या पाठशाला के निकट 10000 रूपये की लागत से एक बोर्डिंग हाउस का निर्माण करवाया एंव छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था भी की गई।[22]

रियासती राज्यों द्वारा अपनी रियासतों में स्कूलों की स्थापना शिक्षा के अद्धोमुखी सिद्धांत के आधर पर हुई थी। अतः प्रारंभ में केवल राजपूत बालकों को ही शिक्षित करने का उद्देश्य था। गौरीशंकर ओझा बताते हैं कि राजपूत बालकों को शिक्षा में अधिक रुचि नहीं थी वह तो शिक्षा से दूर ही रहते हैं। राजाओं ने इन राजपूत बालकों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु राजधानी में राजपूत हॉस्टल स्थापित किए और उन्हें अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। प्रतापगढ़ के महाराजकुमार मानसिंह ने डूंगरपुर में महारावल विजयसिंह और बांसवाड़ा में महारावल पृथ्वीसिंह राजपूत छात्रावास की स्थापना की तथा राजपूत बालकों लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की।[23] शिक्षा के साथ–साथ छात्रों के जीवन में खेल की अस्मिता को ध्यान में रखते हुए महाराज कुमार ने छात्रों के लिए न केवल क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबाल आदि खेलों की सामग्री उपलब्ध करवाई बल्कि इन खेलों के लिए उचित एंव पर्याप्त स्थान की भी व्यवस्था की। इस प्रकार वे सदैव बच्चों को शिक्षा व खेल के लिए उत्साहित करते रहते थे। प्रतापगढ़ में ही राजपूत छात्रों के लिए दो विशेष छात्रवृतियां रखी गई थी। जिन विद्यार्थीयों को क्षत्रिय महासभा द्वारा चुना जाता था उन्हीं छात्रों को ही यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। छात्रों को इंदौर जाकर अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त 500 रूपये सालाना रघुनाथ संस्कृत पाठशाला में अध्ययन करने वाले गरीब छात्रों की सहायता हेतु दिए जाते थे।[24]

निष्कर्ष :

प्राचीन काल से आधुनिक युग के आरम्भ तक वागड़ क्षेत्र में परम्परागत शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी जो व्यक्ति का चरित्र निर्माण कर उसे समाज में रहने योग्य बनाती थी। लेकिन अंग्रेजी शासन के दौरान वागड़ प्रदेश में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का विकास हुआए जिसके कारण परम्परागत शिक्षा प्रणाली का खुबसुरत पेड़ नष्ट हो गया। जिसने वागड़ की जनता को अज्ञानता और बेरोजगारी के अंधकार में धकेल दिया। क्योकि जिस पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को वागड़ प्रदेश में लागू किया गया वह केवल भाहरों और वर्ग विशेष तक ही सीमित रही। स्थानीय समाज सूधारकों ने वागड़ की जनता के मध्य शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया लेकिन संसाधनों की कमी

के कारण उनका दायरा भी सीमित ही था। ईसाई मिशनरियों ने भी वागड़ की जनता के मध्य शिक्षा को लेकर कार्य किया लेकिन उनका मकसद वागड़ की जनता के मध्य शिक्षा का विकास करना नहीं बल्कि अपने धर्म का प्रचार–प्रसार करना था। इस तरह वागड़ प्रदेश में हर युग में शिक्षा का केन्द्र रहा लेकिन आधुनिक काल में यहां शिक्षा व्यक्ति निर्माण के स्थान पर साम्राज्य या धर्म प्रचार का साधन बनकर रह गई।

❒

सन्दर्भ –

1. *एल. डी. जोशी, बागड़ी बोली का स्वरूप और उसका तुलनात्मक अध्ययन, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, पृ. 1.*
2. *गौरीशंकर हीराचंद्र औझा, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार, जोधपुर, 1998, पृ. 32.*
3. *गौरीशंकर हीराचंद्र औझा, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर, 2000, पृ. 09.*
4. *साक्षातकार, मदन वैष्णव, 11–05–2022, प्रतापगढ़.*
5. *गिरिजाशंकर शर्मा, राजस्थान में शिक्षा का इतिहास (1818–1950ई.), कलासन प्रकाशन, बीकानेर, 2009, पृ. 20.*
6. *वही, पृ. 23.*
7. *वही, पृ. 24–25.*
8. *.बी. एल. पानगड़िया, राजस्थान में स्वतत्रंता संग्राम, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 29–30.*
9. *निमेश कुमार चौबीसा, बीसवीं शताब्दी में शिक्षा का विकास (डूंगरपुर राज्य के विशेष सुदर्भ में), हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, 2019, पृ. 117–119.*
10. *गणेशलाल निनामा, जनजातीय लोक सांस्कृतिक परम्पराओं के बदलते आयाम, एम. बी. पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2004, पृ. 34–35.*
11. *श्याम लाल, ट्राइब्लस एण्ड क्रिश्चयन मिशनरीस, मानक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,1994, पृ. 77–81.*
12. *वही, पृ. 89.*

13-Major K. D. Erskins, A Gazetteer of the Banswara State, with a chapter on The Bhils and some Statistical Tables, Scottish Mission Industries Company LTD, Ajmer,1908, p 138.

14. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास, 2019, पृ. 236. & Major K. D. Erskins, Rajputana Gazetteers, Volume 2-A, The Mewar Residency, Scottish Mission Industries Company LTD, Ajmer,1908, p 220.

15. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, 2000,पृ. 189.

16-F. L. Reid, -on the state of education in the native states of Rajputana, Appendix 5, Scottish Mission Industries Company LTD, Ajmer,1905.

17-Major K. D. Erskins, Rajputana Gazetteers, Volume 2-A, The Mewar Residency,1908, p 153.

18-Report on the administration of the Dungarpur State for the year sambat 1960, Printed at the Rajputana Mission Press, Ajmer, 1904, p 5.

19-Major K. D. Erskins, A Gazetteer of the Banswara State, with a chapter on The Bhils and some Statistical Tables, p 138.

20. निमेश कुमार चौबीसा, बीसवीं शताब्दी में शिक्षा का विकास (डूंगरपुर के विशेष सन्दर्भ में), हिमांशु पब्लिकेशन, उदयपुर, 2019, पृ.167.

21-Report on the Administration of the Banswara State, Rajputana, For the period from 1st October 1912 to 30th September 1913, 1914, p 21. & गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास, 2000, पेज न 209.एवं 2019, पृ. 256.

22-Report on the Administration of the Pratapgarh State, Rajputana, For the year ended 30th Septem ber 1940, p 29. & गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास,2019, पृ. 265.

23. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, प्रतापगढ़ राज्य का इतिहास,2019, पे 258. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, बांसवाड़ा राज्य का इतिहास, 2000, पृ. 209. गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, डूंगरपुर राज्य का इतिहास, 2000, पृ.191.

24-Report on the Administration of the Pratapgarh State, Rajputana, For year ended 30th September 1940, p 30.

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 104–111

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

राष्ट्र निर्माण और आर्थिक उन्नति के संदर्भ में दत्तोपंत ठेगड़ी के विचारों का अध्ययन

मनोज कुमार

शोधार्थी, इतिहास विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, जिला कॉगड़ा, (हि.प्र.)–176215
E-mail: thakurmanu81@gamil.com Mob- 8894828390

डॉ. राघवेन्द्र

सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश,
E-mail- 010ragvendrasingh@gamil.com Mob- 7987929120

सारांश

*दत्तोपंत ठेंगड़ी एक समग्र विचारक और दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी थे। दत्तोपंत ठेंगडी ने राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र का पुनर्निर्माण पर विशेष बल दिया और स्वदेशी, आत्मनिर्भरता एवं राष्ट्रवाद जैसे समग्र चिंतन पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक विचारों को इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। भारत में श्रम चिंतन पर विशेष पकड़ रखने वाले दत्तोपंत ठेंगडी ने भारतीय मजदूर संघ की नीतियों को परिभाषित करने की आवश्यकता से शुरुआत करते हुए उन्होंने अंततः वैश्विक आर्थिक नीतियों पर लिखा। उन्होंने भ्रमणशील प्रचारक के अपने व्यस्त कार्यक्रम में दर्शन, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, क्रांति आदि विभिन्न विषयों पर सैकड़ों भारतीय और विदेशी पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। राष्ट्रवाद के प्रखर समर्थक होने के नाते उनका दृढ़ विश्वास था कि बुनियादी हिंदू दर्शन में, दर्शन और जीवन–दृष्टि पर्याप्त एवं व्यापक है और इस बात पर बल दिया कि केवल अपने मूल सिद्धांतों को युगानुकूल को बनाए रखने से ही या अनुकूल ज्ञान के साथ मिलकर इन शाश्वत सिद्धांतों का व्यावहारिक कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। दत्तोपंत ठेंगड़ी भारतीय तत्व चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत के सनातन चिंतन में **सब एक हैं** की अनुभूति प्राप्त होती है। उन्होंने **समग्र सोच और एकात्म मानववाद** पर भी बल दिया इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं। **सब एक हैं,** के विचार को उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते है कि इन्डिव्हिजुअल, फॅमिली, नेशन, मनकाइंड, और यूनिव्हर्स यह जो सारा है, दे आर दी ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ दि डेव्हलपमेंट ऑफ कॉन्शसनेस। इंडिव्हिज्यूअल–फॅमिली–नेशन–मनकाइंड–वर्ल्ड और यूनिव्हर्स ये तो परस्पर विरोधी बातें नहीं है। तो ये मनुष्य के जागृति की कॉन्शसनेस की बढ़ती हुई अवस्था है। उनका राष्ट्रवाद सीमओं के भीतर सिमटा नही है बल्कि*

सम्पूर्ण विश्व कल्याण की बात करता है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से दत्तोपंत ठेंगडी के राष्ट्रनिर्माण एवं राष्ट्रवादी विचारों और अर्थ चिन्तन के पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

संकेत शब्द–राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता, हिंदू दर्शन, एकात्म मानववाद, राष्ट्रनिर्माण, प्रौद्योगिकीविदर्दी

प्रस्तावना

दत्तोपंत ठेंगड़ी भारतीय तत्व चिंतन का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि भारत के सनातन चिंतन में सब एक हैं इसकी अंतिम अनुभूति है। उन्होंने समग्र सोच और एकात्म मानववाद पर भी बल दिया इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आर्थिक विचार प्रस्तुत किए हैं। सब एक हैं कि विचार को उदाहरण से स्पष्ट करते हुए कहते है कि **इन्डिव्हिजुअल, फॅमिली, नेशन, मनकाइंड, और यूनिव्हर्स** यह जो सारा है, **दे आर दी ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ दि डेव्हलपमेंट ऑफ कॉन्शसनेस**। मनुष्य के जागृति की यह बढ़ती हुई सीढ़ी है एक के बाद एक आती है। छोटा–सा बच्चा रहता है। वह अपने को ही पहचानता है। मां को भी नहीं पहचानता तब उसके लिये अहंश यही केवल सत्य है बाकी सारा मिथ्या है। थोड़ा बड़ा होता है बाबा, मां, भाई, बहन का परिचय होता है वह अपनी फॅमिली के साथ एकात्म हो जाता है। उस अवस्था में फॅमिली यह ही उसके लिये हाय्येस्ट ग्रुप है। लेकिन और भी कॉन्शसनेस की प्रोग्रेस होती है वह सारा नेशन मेरा है समझने लगता है तो उसके लिए नेशन ही केवल सत्य है। नेशन सत्य है याने फॅमिली असत्य है ऐसा हमारे यहाँ नहीं माना गया। फॅमिली सत्य है याने इडिव्हुजल असत्य है यह भी नहीं माना गया। उसी तरह से उससे भी ज्यादा प्रगति हो जाती है तब मनुष्य यह सोचता है कि सारी मनुष्य जाति मेरी है और इसलिए **स्वदेशोभुवन त्रयम्**। ऐसा हमारे यहां सन्यासी कह सकता है लेकिन हर एक आदमी नहीं कह सकता। जो सन्यासी बना हुआ है वही कह सकता है लेकिन हरेक आदमी नहीं कह सकता। कि स्वदेशो भुवन त्रयं–सारा विश्व मेरा है। He is the citizen of the universe …. not only the citizen of the world but citizen of the universe सारा युनिव्हर्स इसका है। **इंडिव्हिज्यूअल फॅमिली–नेशन–मनकाइंड–वर्ल्ड और यूनिव्हर्स** ये तो परस्पर विरोधी बातें नहीं है। तो ये मनुष्य के जागृति की कॉन्शसनेस की बढ़ती हुई अवस्था है।[1] वहीं एक अन्य उदाहरण से समझाने का प्रयास करें तो दत्तोपंत ठेंगडी ने हिंदू अर्थशास्त्र पुस्तक के परिचय **को वादिस** में पश्चिमी प्रतिमान की तुलना में हिंदू प्रतिमान का सारांश प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादों की कीमत और उद्योग में निर्मित उत्पादों की लागत (व्यापार की शर्तें) के बीच संतुलन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर सगठन को एक परिवार के रूप में पूरे गांव की प्रगति के लिए काम करना चाहिए।[2] उनका मानना था कि हमारा वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं है। और सरकार सब कुछ करेगी तथा उससे देश की प्रगति होगी–यह सही धारणा नहीं है। हमें लोगों की शक्ति पर भरोसा है और वही राजनीतिक शक्ति को भी नियंत्रित करेगी।[3] एक के बाद एक संगठन निर्माण करना, राष्ट्रहित में उन संगठनों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना तथा लक्ष्य प्राप्ति पर पूर्ण विश्वास, भविष्य के बारे में भी निश्चित बताना, यह ठेंगड़ी जी ने किया है। रेनेसा (Renaissance) स्वर्णयुग, विकास के शीर्ष स्थान पर पहुँचकर विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत का सपना

ठेंगड़ी जी देख रहे थे। कर्मयोगी के रूप में निरंतर कार्यरत और मौलिक चिंतन के द्वारा भविष्य के पथ का अवलोकन करने की क्षमता उनमें थी।

दत्तोपंत ठेंगडी का आर्थिक चिंतन

दत्तोपंत ठेंगडी का मानना था कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्यत पूरी होनी चाहिए। भौतिक सम्पदा का अर्जन परमेश्वर के व्यक्त रूप समाज की सेवा के उद्देश्य से, सर्वोत्तम नैतिक पद्धति से किया जाय और उस धन या सम्पत्ति में से अपने ऊपर न्यूनतम अंश ही व्यय किया जाय। स्वयं उतना ही स्वीकार करिए, जितना आपको सेवा कर सकने योग्य बनाये रखने के लिए आवश्यक हो।[4] उससे अधिक का स्वयं व्यक्तिगत उपयोग करना अथवा उस पर अपना स्वत्व बताना (अधिकार जताना) समाज की चोरी करना है। इस प्रकार हम समाज के न्यासी (रखवाले) मात्र हैं। समाज के सच्चे न्यासी बनकर ही हम उसकी सर्वोत्तम सेवा कर सकते हैं।[5] परिणामतरू व्यक्तिगत संग्रह की कुछ सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिए। निजी लाभ के लिए किसी अन्य के श्रम का शोषण करने का अधिकार किसी को नही है। करोड़ों लोग जब भुखमरी से ग्रस्त हैं, तब अभद्र, आडम्बरयुक्त एवं दुरुपयोगपूर्ण व्यय पाप है। सभी प्रकार के उपभोग पर समुचित मर्यादाएं अवश्य होनी चाहिए।[6] उपभोक्तावाद हिन्दु संस्कृति की भावना (अन्तश्चेतना) से मेल नही खाता। इसी आर्थिक चिंतन के मध्यनजर दत्तोपंत ठेंगडी देश के औद्योगीकरण के पक्षधर थे लेकिन उनका आग्रह था कि पश्चिम का अंधानुकरण करने के बजाय देश की जरूरतों के अनुसार और अपने तरीके से औद्योगीकरण किया जाना चाहिए। इसमें कई उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ का आदर्श वाक्य है राष्ट्र का औद्योगीकरण करें, श्रम का राष्ट्रीयकरण करें, उद्योग का श्रमीकरण करें[7] (राष्ट्र का उद्योगीकरण, श्रमिकों का राष्ट्रीकरण, उद्योग का श्रमिकीकरण) यानी यह आत्मसात करना कि राष्ट्रीय हित "सर्वोच्च" है उनका कहना था कि. बीएमएस का नारा **हम देश के हित में काम करेंगे और किए गए काम का पूरा वेतन लेंगे** (देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम) कम्युनिस्टों के नारे **चाहे जो मजबूरी, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे** कितनी भी कठिनाइयां हों, हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए के लिए एक जवाब था। गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने पूंजी–उन्मुख आर्थिक संरचना के बजाय "श्रम–उन्मुख आर्थिक संरचना" की मांग की।[8]

यह अभिव्यक्ति बीएमएस लक्ष्यों के प्रमुख पहलुओं को सामने लाती है। उद्योग का स्वामित्व व्यावहारिक आधार पर तय किया जाना चाहिए। उद्योग की जरूरतों और देश के हित के अनुसार स्वामित्व सरकार, सहकारी, स्थानीय सरकार, निजी या सरकार और निजी द्वारा संयुक्त स्वामित्व हो सकता है। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) की सफलता ही दर्शाती है कि विदेशी विचारधारा के बिना भी राष्ट्रवादी श्रमिक आंदोलन भारत में फल–फूल सकता है। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने 23 जुलाई, 1955 को भारतीय मजदूर संघ की उद्घाटन बैठक में कुछ बुनियादी वैचारिक बिंदुओं की घोषणा की। ये बिंदु इस प्रकार हैं।[9]

देश के हित पहले आते हैं, उसके बाद उद्योग और श्रमिक के हित और इसी क्रम में, बीएमएस एक गैर–राजनीतिक श्रमिक संगठन होगा, जो श्रमिकों का, श्रमिकों के लिए और श्रमिकों द्वारा एक संगठन होगा जो दलगत राजनीति से दूर होगा।

यह भारतीय आर्थिक विचार और संस्कृति पर आधारित होगा समाज की संरचना जो शोषण और दुर्व्यवहार से मुक्त हो और न्याय और सद्भाव पर आधारित हो।

समाज में दलित, पीड़ित, उपेक्षित एवं पददलित व्यक्तियों के उत्थान हेतु ईमानदारी से कार्य करना ।

श्रम नीति पर बात करते हुए और श्रमिकों को सलाह देते हुए उन्होंने अपनी सोच को सीधे श्रमिकों से संबंधित मुद्दों तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे देश के आर्थिक जीवन और समग्र राष्ट्रीय जीवन पर विचार किया। श्रम को पूंजी मानकर तथा श्रमिकों के कार्य का उचित मूल्यांकन करते हुए श्रमिकों को लाभ में हिस्सा, प्रबंधन में भागीदारी तथा कुछ स्वामित्व दिया जाना चाहिए। उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न अधिशेष मूल्य पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। मालिक और श्रमिकों को इसे केवल अपने लिए नहीं हड़पना चाहिए। ऐसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उन्होंने अपने आर्थिक चिंतन में समाहित किया।

तीसरा रास्ता

दत्तोपंत ठेंगडी ने साम्यवाद के खत्म होने और पूंजीवाद के जल्द ही पतन की संभावना की पृष्ठभूमि में, तीसरे रास्ते की तलाश की बात करते थे वह कहतें हैं कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी पिछली परंपराओं, वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं के आलोक में प्रगति और विकास के अपने मॉडल की कल्पना करनी चाहिए। धर्म के अपरिवर्तनीय, शाश्वत, सार्वभौमिक नियमों के आलोक में निरंतर बदलती सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था की परंपरा, हिंदू जीवन दृष्टि द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया की नींव है। इसीलिए पारंपरिक हिंदू लोकाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अभिन्न राष्ट्रीय चेतना पैदा करने की आवश्यकता है। विकास का कोई भी विकल्प जो समाज के सांस्कृतिक मूल के अनुरूप नहीं है, समाज के लिए फायदेमंद नहीं होगा।[10] तीसरे रास्ते के लिए मानव जाति का कोलाहल–पश्चिमी विचारधाराओं की दयनीय विफलता के बाद, नियति भारत को अंधेरे में टटोलते विश्व को नया नेतृत्व प्रदान करने के लिए प्रेरित कर रही है। मानव जाति नई व्यवस्था के लिए उत्सुक है जिसे तीसरा रास्ता कहा जाता है।[11] इस तीसरे रास्ते को शुरू करने की नैतिक और ईश्वर प्रदत्त जिम्मेदारी, जो वास्तव में एकमात्र रास्ता है, भारत पर निर्भर है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लक्ष्य के प्रति समर्पित देशभक्तों का समूह ही इस कार्य के लिए पात्र है। वे एक नया व्यापक विश्व दृष्टिकोण (वेल्टान्सचाउंग) बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।[12] उन्होंने कहा कि एकात्म मानव दर्शन ही तीसरा और एकमात्र रास्ता है।

स्वदेशी

दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू स्वदेशी को देशभक्ति की व्यावहारिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया। यह स्वदेशी की एक बहुत ही आकर्षक परिभाषा है जो सभी के लिए स्वीकार्य है और राष्ट्रीय भावना और कार्रवाई के इरादे को सामने लाती है। उन्होंने समझाया कि देशभक्ति का मतलब दूसरे देशों से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि एकात्म मानव दर्शन (सभी मानवता के बीच रहने वाली केवल एक चेतना) के सिद्धांत का पालन करना है। हम समानता और पारस्परिक सम्मान के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हमेशा तैयार हैं।[13] उन्होंने लिखा, यह मानना गलत है कि "स्वदेशी" का संबंध केवल वस्तुओं या सेवाओं से है। यह

अधिक आकस्मिक पहलू है। अनिवार्य रूप से, यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वतंत्रता के संरक्षण और समान स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प की भावना से संबंधित है।[14] स्वदेशी केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित एक आर्थिक मामला नहीं था, बल्कि एक व्यापक–आधारित विचारधारा राष्ट्रीय जीवन के सभी विभागों को समाहित करती है। स्वदेशी आर्थिक नीतियों पर बोलते हुए उन्होंने कई बातों पर जोर दिया मूल्य–आधारित प्रतिस्पर्धा और सहयोग, आर्थिक समानता और अवसर, प्रकृति का शोषण नहीं बल्कि प्रकृति का दोहन, स्व–रोजगार और केवल वेतनभोगी रोजगार नहीं। इनके अलावा वह अक्सर निम्नलिखित बिंदुओं पर भी बात करते थेः हमारी प्रगति के प्रतिमान और आर्थिक नीति हमारे अनुरूप हों, संस्कृति और सामाजिक जीवन. अर्थात परिवार व्यवस्था, आचार–विचार, संयमित उपभोग, पर्यावरण मित्रता, समाज के गैर–सक्रिय सदस्यों (बच्चे, वृद्ध) की देखभाल और विकलांग), बचत पर जोर, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भरता नहीं) बुनियादी आवश्यकताओं–भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ति न केवल आर्थिक प्रोत्साहन बल्कि अन्य गैर–आर्थिक प्रोत्साहनों का महत्व, अंत्योदय (समाज के सबसे कमजोर वर्ग का उत्थान) आदि बिन्दुयों से स्वदेशी के महत्व को उजागर किया।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण

आज हम जब विश्व ग्लोबलाइजेशन की ओर अग्रसर है। दत्तोपंत ठेंगडी का ये विचार कि भारत स्वाभाविक रूप से अंतर्राष्ट्रीयवादी हैं, का स्मरण होता है। दत्तोपन्त जी का यह विश्वास कथन कि समूचा ज्ञान सार्वभौम है, यह न पाश्चात्य है न पौर्वात्य।[15] उनके व्यापक दृष्टिकोण पर चिन्तन करें, तो इसकी गहराई समझ आती है। दत्तोपन्त जी हमेशा सार्वभौम नियमों की बात करते थे। इसके तहत समय–समय पर समाज के ऊपरी ढांचे के पुनर्निर्माण की बात करते थे। हमारा राष्ट्र एक अद्‌भुत, प्राचीन एवं विशिष्ट राष्ट्र है और वह न केवल राष्ट्र बल्कि सम्पूर्ण मानवता के लिए उपयोगी है। उनका मानना था कि हम अपने अतीत की अवहेलना नहीं कर सके पर सदियों के गतिरोधकाल में जो भूल चूक हुई है, उसे सुधारे, उसे आगे ढोते ना रहे। ऐसा विवेक राष्ट्रीय चिन्तन के लिए आवश्यक है।[16] उनके विचार में मानव चेतना की प्रगति के मार्ग में राष्ट्रवाद, आदिम जातिवाद और मानववाद के बीच का सेतु हैं और स्वयं मानववाद ही न्दपअमतेंसपेंजपवद की दिशा में एक बड़ा कदम है।[17] दत्तोपंत एक कुशल संगठनकर्ता थे। उनका मानना था कि किसी भी विचार को यदि वास्तव में स्थापित करना है तो उसे अपने व्यावहारिक आचरण से प्रदर्शित करना होगा। महात्मा गांधी की भी ऐसी ही अंतर्दृष्टि थी। हमारे वैदिक दर्शन के अनुसार, संपूर्ण अस्तित्व सर्वोच्च चेतना का आविष्कार है – "सर्व खल्विदं ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम्" या "वासुदेवः सर्वम्" इन वैदिक और गीता वाक्यांशों का यही अर्थ है।[18]

दत्तोपन्त जी का अर्थ विचार बहुत गहरा एवं सर्वग्राही था। वे ऐसा चाहते थे कि भारतीय चिन्तन के अनुरूप ही अर्थव्यवस्था का निर्धारण हो। वह यह अच्छी तरह जानते थे कि पश्चिमी जगत असीम उपभोगवाद पर चलता है और भारत संयमित उपभोग पर। प्रत्येक भारतीय मन में अन्त्योदय का विचार आता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, परम्परा एवं आचरण सभी उसी रंग में रंगे हैं–Unto to Last, यहां प्राणी तथा वनस्पति तक का भी ख्याल

आत्मीयता के साथ रखा जाता है। मजदूरों और किसानों का कल्याण उनकी प्राथमिकता की सूची में था। वे देश के बहुत बड़े, शोषित–पीड़ित एवं असंगठित जन समुदाय में हमेशा आत्मविश्वास जागृत करने का कार्य करते थे। उन्होंने यह आह्वान किया था कि **हर किसान हमारा नेता** है। उन्होंने यह नारा दिया था कि **देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे।**[19] किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारतीय किसान संघ की नींव भी रखी जिनमें किसानों के हितों पर सामूहिक चर्चा करते हुए समुचित निर्णय लेकर उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जा सके। वास्तव में मजदूर और किसान ही तो हमारे समाज की रीढ़ हैं। इसी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य कम्युनिज्म पर विचार करते हुए कहते हैं कि केवल कम्युनिज्म का विरोध करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है इस राष्ट्र का निर्माण करना, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना। जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्रवाद की कसौटी में राष्ट्र के उत्कर्ष की हमारी दृष्टि यह है कि दस–पाँच पूँजीपतियों का उत्कर्ष यानी राष्ट्र का उत्कर्ष नहीं है।[20] पचास पाँच सौ मिनिस्टरों का उत्कर्ष यानी राष्ट्र का उत्कर्ष, ऐसा हम नहीं मानते। इस देश का सबसे छोटा आदमी जो सबसे गरीब, गया–बीता आदमी है (Unto the last man) उसके उत्कर्ष को हम राष्ट्र का उत्कर्ष मानते हैं। राष्ट्र के उत्कर्ष की यही कसौटी है। इस सन्दर्भ से जोड़कर सम्पूर्ण राष्ट्र को परम वैभव तक किस तरह पहुँचाया जाय, इस इच्छा से हम लोग काम कर रहे हैं और चूँकि मजदूर क्षेत्र, यह राष्ट्रीय जीवन का एक स्ट्राटिजिक (रणनैतिक महत्त्व रखने वाला) क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं ऐसा हम लोग उनको बताते थे।[21] हम नहीं जानते कि कम्युनिस्ट हमारी इस बात को समझ सके कि नहीं। क्योंकि अन्य विचार समझने की उनकी क्षमता ठीक वैसे ही बहुत सीमित रहती है जैसे घोड़ों की इधर–उधर देखने की सीमित क्षमता। घोड़ा केवल सामने देख सकता है। अतएव सम्पूर्ण राष्ट्र का विकास हो इसलिए मजदूरों का भी विकास हो, यह काम कौन करेगा? राष्ट्रहित चौखट में रह कर मजदूर हित यह हमारा ध्येय है। पहले राष्ट्रहित वाद में मजदूर हित और अंत में भारतीय मजदूर संघ का हित। इस में कोई संस्थागत अंहकार नहीं है। राष्ट्र का कल्याण हो मजदूरों का कल्याण हो यही सिद्धान्त और लक्ष्य है।[22]

सर्वसाधारण नागरिक की राष्ट्रीय चेतना का स्तर यही आधार है राष्ट्र के पुनर्निर्माण का। राष्ट्रीय चेतना का स्तर उँचा नहीं है तो पोलिटिकल पावर से कुछ नहीं हो सकता। यदि राष्ट्रीय चेतना का स्तर उँचा है तो राजनीतिक शक्ति का अच्छे रूप में उपयोग हो सकता है। जन संगठन जब खड़े रहते हैं तभी सही मायने में नैतिक नेतृत्व का उदय होता है। हमारा संगठन है धर्मदण्ड अर्थात विकृतियों पर अंकुश।[23] देश से समाज बड़ा नहीं हो सकता है। परम वैभव माने पोलिटिकल पावर नहीं है। राजनीतिक सत्ता आती है जाती है। महत्व धर्म दण्ड का है। राष्ट्रीय चेतना का स्तर यह उस को आधार है। तपश्चर्या करने वाले के हाथ में ही नियन्त्रण होना चाहिए। हमने यह कहा था The best should suffer so that rest could prosper' अर्थात दूसरों का सुखी बनाना है तो कुछ अच्छे लोगों को कष्ट सहना ही पड़ेगा– हमने नारा ही दिया था बी.एम.एस. की क्या पहचान–त्याग तपस्या और बलिदान[24] हमारे तथाकथित प्रगतिशील लोग हम पर हँसते थे कि ट्रेड युनियन में हम पैसे के लिए आते हैं और बी.एम.एस. के यह पागल लोग कह रहे हैं त्याग तपस्या और बलिदान। दूसरों को सुखी बनाना और स्वयं को सद्‌गुणी

बनाना यह प्रयास करना चाहिए। किन्तु होता उल्टा है हरेक आदमी दूसरों को सदगुणी और स्वयं को सुखी बनाने के प्रयास में लगा रहता है। हमारी राष्ट्रीय प्रगति के सम्बन्ध में, हमारी मूल समस्या यह है कि हमारी प्रगति और विकास के लिये कौन सा प्रतिमान आदर्श होना चाहिए। इन सब बातों पर विषद रूप से, निष्पक्ष रूप से, वस्तुपरक दृष्टि से विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे अपने बुद्धिजीवी मिलें, मिलकर विचार करें, अपनी विशिष्ट योग्यता का मिलकर संचयन करें, हर स्तर पर सत्य के बारे में मिलकर अन्वेषण करें और सत्य के प्रकाश में, तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्ष निकालें। ये निष्कर्ष कल्पना की उपज न हों, वरन् प्राप्त तथ्यों के आधार पर तर्क की छलनी के माध्यम से सहज रूप से निकाले जायें। इस प्रक्रिया के आधार पर हमारे बुद्धिजीवियों को संयुक्त अन्वेषण करने चाहिए।[25]

निष्कर्ष

दत्तोपंत ठेंगडी देशवासियों को अपने मूलभूत हितों की रक्षा के लिए खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। लोकतंत्र में नागरिकों को प्रदत्त विचारों की अभिव्यक्ति के अधिकार को उन्होंने सर्वोच्च स्थान दिया। स्वदेशी को अपना कर भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचा उठाने, यहां की कला–संस्कृति को संजोकर रखने के लिए उनका आह्वान किया कि स्वदेशी जागरण के अभियान में सहभागी होना, देशभक्तों का अधिकार एवं कर्तव्य है। हमारे प्रौद्योगिकीविदर्दी (Technologist) का यह दायित्व होना चाहिए कि वे शिल्पियों के हित के लिए उत्पादन की परम्परागत प्रविधियों में ऐसे ग्राह्य परिवर्तन समाविष्ट करें, जिनसे कामगारों के नियुक्ति (रोजगार) खो बैठने, उपलब्ध प्रबन्धकीय एवं प्राविधिक निपुणता के व्यर्थ हो जाने तथा उत्पादन के वर्तमान साधनों के पूर्ण विपूंजीकरण का जोखिम न होय उत्पादन–प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण पर अत्यधिक बल देते हुए वे ऐसी स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करें, जिसमें विद्युत् शक्ति का उपयोग हो, किन्तु उत्पादन का केन्द्र कारखाना नहीं वरन् घर को बनाया जाये अर्थात् उत्पादन–कार्य घर–घर में हो, केन्द्रीकृत कारखानों में नही। आज जब भारत सरकार भी स्वदेशी जैसे विचार पर बल दे रही है और उससे जुड़े कई कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे लोकल फॉर वोकल हो या एक जिला एक उत्पाद हो तो दत्तोपंत ठेंगडी के विचारों का महत्त्व स्पष्ट होता है।

❒

सन्दर्भ –

1. *दत्तोपंत ठेंगड़ी जीवन दर्शन खंड 2, संपादक अमर नाथ डोगरा, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली,2015, पृ.41*
2. *वही पृ.46*
3. *दत्तोपंत ठेंगड़ी जीवन दर्शन खंड 3, संपादक अमर नाथ डोगरा, सुरुचि प्रकाशन, नई दिल्ली,2015,पृ. 206*
4. *वही पृ.276*
5. *ठेंगड़ी, दत्तोपंत, आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ते कदम, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच, 1973 पृ. 23–24*
6. *वही पृ. 45*
7. *वही पृ.56*
8. *भारत में संसदीय प्रणाली का भविष्य, दत्तोपंत ठेंगडी द्वारा, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, 1997, पृ. 46–48*
9. *ठेंगड़ी, दत्तोपंत, औद्योगिक महासंघ, भारतीय मजदूर संघ प्रकाशन, नई दिल्ली, 1965, पृ.66*
10. *दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा थर्ड वे, साहित्य सिंधु प्रकाशन द्वारा द्वितीय संस्करण,बेंगलुरु। ई–बुक पृ. 12*

11. वही पृ.16,17
12. वही पृ. 25
13. देशप्रेम की साकार अभिव्यक्ति स्वदेशी, स्वदेशी जागरण मंच,नई दिल्ली, प्रथम संस्करण अक्टूबर 1994,पृ.3,4
14. वही पृ. 6,7
15. संघोष किसान, भारतीय किसान संघ की रजत जयंती वर्ष के उद्घाटन समारोह की स्मारिका, भारतीय किसान संघ, कोटा, 1979 पृ. 12
16. वही पृ.22
17. ठेंगड़ी, दत्तोपंत, शेषाद्री हो वे, भारतीय मजदूर संघ प्रकाशन, नई दिल्ली, 1965, पृ.34
18. वही पृ. 36–37
19. ठेंगडी दत्तोपत, पश्चिम की शोषणात्मक अर्थव्यवस्था और स्वदेशी जालघररू आकाशवाणी प्रकाशन न्यू रनवे रोड, 1992, पृ. 56–57
20. वही पृ.69–70
21. ठेंगड़ी, दत्तोपंत, ध्येय पथ पर किसान, भारतीय किसान संघ कार्यालय, लखनऊ, 2001, पृ.6–7
22. ठेंगड़ी,दत्तोपंत,कम्युनिज्म अपनी ही कसौटी पर, भारतीय संस्कृति पुनरुत्थान समिति, लखनऊ, 2004, पृ. 42 –44
23. ठेंगडी, दत्तोपंत कंप्यूटराइजेशन एक प्रकट चितन नई दिल्ली, भारतीय श्रम शोध मंडल, 1984, पृ. 64–65
24. ठेंगडी दत्तोपंत, पश्चिम देशों में श्रम संघवाद, बिहार प्रदेश प्रकाशक भारतीय मजदूर संघ, 1979, पृ. 22
25. वही पृ. 56–57

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 112–124

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Socio-Economic and Spatail Marginalization of Muslims in India

Akhilesh Maurya.
Research Scholar of Public Administration, Department of Political Science,
Banaras Hindu University,Varanasi (U.P.) - 221005
E-mail ID: 114akhil@bhu.ac.in Mob. 9198205573

Abstract

This article aims to examine the complexities of the marginalization faced by Muslims, a major minority group in India. It delves into the various aspects of their lives where marginalization is evident, including socio-economic and physical dimensions. The "othering" process, which further exacerbates their isolation, is also examined. The article investigates the direct link between the stigmatized religious identity of Muslims and their marginalization. Although India's Muslim population is diverse, they share certain similarities in their experiences of marginalization across different spheres of society. The article emphasizes how their social and secular marginalization is deeply connected to their religious identity.

Keywords -Religion, identity, marginalization, Muslims, Islamophobia

Introduction

This article is an attempt to examine the processes and consequences of the marginalization of Muslims in India. It is an exploration of how Muslims, a religious minority in India, are facing marginalization in various aspects of society, including the socio-economic and physical spheres. Moreover, it also explores the process of 'othering' which shows how this mentality contributes to their marginalization. Several studies have shown that Muslims' marginalization stems from their religious identity, lending weight to the relevance of the marginalization factor[1]. A significant aspect of their identity is their stigmatization in India[2].

In India, Muslims are stigmatized because they are perceived as the "other," cultural outsiders, invaders, the "fifth column," and "threatening others." Also, there are stereotypes of Muslim males as womanizers who use the concept of "love jihad" to woo Hindu women[3]. The Hindutva ideology and the long history of Muslim immigration to India both play a role in this. For many years, Muslims in India have

been viewed with distrust. They were seen as a disloyal fifth column that might weaken the Hindu nation as a whole. They are still suffering the effects of the division and are marginalized in all facets of society. Housing discrimination against Muslims, harassment, false encounters, the wrongful imprisonment of Muslims, acts of violence, and "programming wapsi" are all examples of the difficulties, individuals experience because of their faith.

In light of the above discussion, this article restricts its focus to one specific religious minority—Muslims, since the Indian anxieties and phobias about religious and cultural diversity are more focused on Muslims than on any other group. Muslims do not constitute a homogeneous group, but rather an imagined community of Muslims expressing the transnational aspect of Islam. The article emphasizes sociological Muslim identities, which need to be understood in the face of experiences of violence, othering, stigmatization, and marginalization. Islam is a migrant religion, arriving in the country in different waves for different reasons, and Muslims constitute the largest minority in the country. The exclusionary experience of Muslims in India has roots in anti-Muslim sentiment, which has been exaggerated only in the post-9/11 period[4].

Research Methodology

This study is based on secondary sources of information. It made use of various sources ranging from books to journals, newspapers, media reports, and working papers. It also makes use of Census data in India, various Commission and government reports such as Sachar Committee Report (SCR), Post Sachar Evaluation Committee Report, and reports by Home Office.

Defining Social marginalization

The concept of social marginalization has been defined in a variety of ways by various academicians. It is more encompassing than other terms with which it is often used synonymously, such as poverty and deprivation. Social marginalization has been used as social exclusion also. In 1974, French scholars first coined the phrase "social marginalization." It refers to groups of individuals who were stigmatized at the time because of their perceived social issues, such as the mentally and physically disabled, suicidal, and other outcasts who were not protected by social insurance. This stigmatizing and limited understanding of social marginalization were largely abandoned in the 1980s when the phrase became essential to French discussions over the nature of neo-poverty. The concept of social marginalization was expanded beyond its traditional definition of poverty to include the gradual severing of ties between individuals and society[5]. social marginalization is "the process by which individuals or groups are wholly or partially excluded from full participation in the society within which they live."

Social marginalization can indeed be seen as a problem, even if it may not always be involuntary. Brian Barry (2001) defines social marginalization as the state of individuals who are willing to participate in society, but external factors prevent them from doing so. This definition highlights the voluntary aspect of

marginalization, where some individuals may choose not to participate in societal activities. However, even in such cases, social marginalization can still be problematic for a couple of reasons. Firstly, social marginalization dilutes solidarity within society. Solidarity is the sense of unity and commonality of experience among members of a community. When certain individuals or groups are excluded, they miss out on shared experiences, opportunities for understanding one another, and collective problem-solving. This can lead to the fragmentation of society, making it difficult for people to relate to one another, empathize with each other's struggles, and work together towards common goals. Secondly, social marginalization results in an inequality of opportunity across different spheres[6]. Even if some individuals voluntarily choose not to participate in certain activities, they may still face barriers that prevent them from engaging in other aspects of society. These barriers could be related to education, employment, healthcare, access to resources, and more. As a consequence, their quality of life and chances for personal and social development may be severely hindered.

Discussions surrounding social marginalization often involve exploring the distinction between poverty and social marginalization. While some consider social marginalization as a mere synonym for poverty, others argue that it is a much broader concept that goes beyond economic factors. According to Gore and Figueiredo (1997), social marginalization can be seen as a second-tier concept that encompasses various social risk factors. These risk factors may include unemployment, lack of access to social services, and breakdown of family structures, particularly affecting certain social groups. Social marginalization is multidimensional not only because it includes diverse social risk factors but also because it emphasizes the cumulative impact of these factors, giving rise to a new phenomenon. Here, poverty is considered as a part of social marginalization, and one of the risk factors contributing to the formation of a risk regime[7]. The concept of social marginalization can be interpreted in different ways: as a descriptive concept, an analytical or normative concept, or even as an organizing framework. When used as an organizing framework, social marginalization helps us understand marginalization from various spheres and dimensions of life[8]. In this context, the work at hand draws upon the idea of using an organizing framework to examine marginalization from different angles and dimensions, offering a comprehensive understanding of social marginalization beyond just poverty and economic aspects.

In multicultural societies, there is no single dominant set of beliefs; instead, there are diverse values and beliefs held by different individuals and groups. Consequently, marginalization in such societies can be better understood by looking at individual and social participation as a crucial aspect. Social marginalization can take on various dimensions, encompassing not just material factors but also social and political aspects[9]. Multiple definitions of social marginalization emphasize that people's inability to participate is a key indicator of marginalization. To understand the concept of social marginalization, we need to consider its essential elements.

Marginalization is not an isolated phenomenon; it is relational and must be assessed within a specific context. Social marginalization is multi-faceted and can be observed in various areas such as access to goods and services, political engagement, mental and social activities, and more. It extends beyond merely income disparities. It is vital to recognize that social marginalization is not a static condition but rather a dynamic process that involves potential future outcomes. Understanding marginalization requires considering its implications for individuals and communities over time, rather than focusing solely on their current circumstances. Lastly, social marginalization should be viewed as an agentive process, meaning that certain elements within society actively contribute to perpetuating the marginalization of others.

In 1997, Bhalla and Lapeyre proposed that marginalization could be categorized into two main dimensions: (a) *distribution*, which relates to economic marginalization, poverty, and deprivation, and (b) *relations*, which pertain to its social and political aspects[10]. The interaction between these dimensions gives rise to a unique concept of marginalization that extends beyond just poverty. Social marginalization, as studied by various researchers, is found to be multidimensional, relative, and structural, distinguishing it from a simple synonym of poverty. This study adopts a notion of social marginalization that considers all these elements and emphasizes its multidimensional and structural nature. Recently, there have been calls to reconceptualize social marginalization, and Andrew Martin Fischer proposed a definition that characterizes marginalization as the result of structural, institutional, or agentive processes of repulsion or obstruction[11]. The present research aims to explore whether Muslims experience such social marginalization, analyzing how marginalization operates through both agency and structural mechanisms. By borrowing from Fischer's definition, this study investigates the multidimensional nature of marginalization and its potential impact on Muslim communities.

Marginalization can be manifest at the level of individual, community, and society. This particular study focuses on the dynamics of marginalization within communities. Community-based marginalization involves stigmatizing certain identities based on factors such as caste, ethnicity, or religion. According to Kabeer (2006), the social marginalization perspective goes beyond just considering poverty; it also takes-into-account, how specific groups in society are "locked out" or left behind due to their identities. Social identity plays a significant role in this process of marginalization, acting as a central axis that determines the disadvantages experienced by these marginalized groups. The concept of social marginalization helps us understand how these disadvantages overlap and compound, leading to complex and intersecting forms of marginalization. Cultural devaluation is a crucial aspect of this process, wherein certain groups are devalued and demeaned through societal beliefs and norms. These mechanisms are used to ridicule and justify the marginalization or denial of rights to these groups in various spheres of society[12].

Social marginalization refers to the act of exclusion of individuals or groups from participating fully in society, leading to their isolation or discrimination. It can

stem from various factors such as caste, race, gender, religion, and more. In this study, the focus is on social marginalization based specifically on religious identity. This means that individuals are being excluded or treated differently in society because of the religion they adhere to.

The Socio-economic, Spatial Status of Muslims in India

Muslims in India face discrimination and disadvantages in several aspects of their lives, which has been consistently highlighted through numerous reports and surveys. It is essential to recognize that the challenges faced by the Muslim community are diverse, encompassing issues related to security, identity, and equity. The intersection of these dimensions plays a crucial role in shaping the socioeconomic and political experiences of the community on a day-to-day basis[13]. In the subsequent sections, we will present data from various surveys, reports, and studies to delve into how Muslims in India experience marginalization.

Economic Status of Muslims

The economic challenges faced by Muslims can be traced back to various historical factors. While some attribute these problems to the decline of the Muslim Empire when they went from being rulers to subjects, it is essential to recognize that the roots of these issues date back even further. During earlier periods, many lower-caste Hindus converted to Islam in the hope of improving their socio-economic conditions. However, this transition did not always lead to the desired outcomes. In India, a significant proportion of the Muslim population comprises individuals from converted lower castes who embraced Islam in search of better opportunities. Unfortunately, their expectations for improved socio-economic status were not always fulfilled. The partition of India in 1947 further exacerbated the economic conditions of Muslims. Many middle-class and landowning Muslims chose to migrate to Pakistan[14], which led to a loss of assets and livelihoods for those who remained behind in India. Omar Khalidi, in 2006, highlighted three main reasons for the absence of Muslims in government employment. Firstly, the migration to Pakistan resulted in a significant loss of the educated and skilled workforce from the Muslim community. Secondly, discrimination against Muslims in various spheres of life, including employment opportunities, hindered their socio-economic progress. Lastly, there was an educational lag, indicating that Muslims faced challenges in accessing quality education and skill development.

The aftermath of the partition also affected the propertied classes among Muslims adversely. Their immovable assets were frozen by the Custodian of Evacuee Property until 1956[15]. This legal restriction meant that intending Muslim evacuees were not allowed to sell their properties in India, leading to financial difficulties and limitations on their economic activities. As a result of these challenges, the business classes of Muslims also faced difficulties, as they were considered less creditworthy by banks, making it hard for them to borrow money when needed.

In his work titled "The Indian Musalmans" published in 1969, W. W. Hunter shed light on the issue of marginalization faced by Indian Muslims in the employment sector. He revealed that they were systematically denied opportunities in various areas, such as the army's officer ranks, positions in the Revenue Department, and civil employment[16]. Unfortunately, even after India gained independence, this discrimination against Muslims in employment persisted. A study conducted by Thorat and Attewell in 2007 attempted to investigate job discrimination in India through a correspondence study. They devised an experiment where they responded to job advertisements in newspapers using fictitious identities with names representing upper-caste Hindus, Muslims, and Dalits. All these applicants possessed equal educational qualifications. Surprisingly, the study found evidence of discrimination based on both caste and religion. Applicants with lower-caste and Muslim names faced poorer outcomes compared to those with high-caste names, especially in the private enterprise sector[17]. This study serves as just one example of the prevailing social marginalization that Dalits and Muslims continue to experience even in modern times within the Indian economy. Despite the progress made, it highlights how deeply entrenched discriminatory practices persist and affect opportunities for certain groups based on their caste and religious identities.

To understand Muslim workforce participation, an intersectional perspective is crucial due to intergroup, regional, and gender differences. Compared to other religious communities, Muslim participation is lower, particularly in rural areas. The economic condition of the community is affected by the low economic activity rate of Muslim women (Census 2001). According to Census 2001, Muslim workforce participation was only 31.3 percent, with concerning gender disparities. Merely 14 percent of Muslim women were actively involved in economic activity compared to 47.5 percent of men. Barriers like traditional norms, childcare duties, and other responsibilities contribute to this low participation. Consequently, Muslim women often find themselves in irregular or sub-contracted work, leading to lower piece-rate wages and overall income.

A notable characteristic of employment among Muslims is the significant portion engaged in self-employment. This higher rate of self-employment raises questions about the creation of 'enclave labor markets' by minority groups[18]. Maitreyi Bordia Das examined the concept of 'minority enclaves' in her work 'Minority Status and Labor Market Outcomes: Does India Have Minority Enclaves?' This research explores whether minorities, who often face marginalization from formal employment, turn to self-employment within these 'enclaves' as an alternative**.**

The interaction between education and employment is evident among Muslims. Those with lower education levels often end up in low-paying self-employed roles. Consequently, a significant number of Muslim men are involved in various petty occupations such as tailoring, weaving, transport, carpentry, and masonry[19]**.**

The scarcity of land in rural areas and limited access to salaried jobs lead them to establish enclaves. These enclaves typically consist of small informal setups

with low productivity. Many Indian Muslim men are found working in small workshops or as mechanics in garages. A recent analysis by the Economic Times Intelligence Group reveals a striking underrepresentation of Muslims in high managerial positions. Among the BSE 500 companies, Muslims constitute only 2.67% of directors and senior executives, with a mere 62 out of 2,324 executives belonging to the Muslim community[20]. This significant disparity highlights the lack of visibility and opportunities for the Muslim minority in the Indian job market, indicating that corporate India has not yet addressed this issue. (Census 2001).

When analyzing the distribution of workers by occupational category, it becomes apparent that only a small proportion of Muslims are engaged in specific sectors: around 8 percent in industry and approximately 21 percent in agriculture, while the majority falls under the category of 'other workers[21].' The Social Consumption on Education Report (SCR) published in 2006 indicates that about 61 percent of Muslims are self-employed, slightly higher than 55 percent of Hindu workers. Muslim workers are predominantly casual laborers, with only 27 percent holding regular jobs in urban areas.

Surprisingly, their involvement in street-vending activities is 12 percent higher than other groups, surpassing the national average of less than 8 percent. Despite efforts like the Kundu Committee Report to address the conditions of Muslims since the SCR, the situation has not significantly improved. The Kundu Report's findings during 2011-2012 indicate that in urban areas, 50% of Muslim households were self-employed compared to 33% among Hindus. Moreover, only about 28% of Muslim households earned regular wages, while the figure was 43% among Hindu households.

The Post Sachar Evaluation Report (2014) indicates that the employment situation and poverty among Muslims in India have not significantly improved since the adoption of the Sachar Committee Report. Muslims face discrimination not only in regular employment but also in government jobs, which reveals concerning statistics. Religious identity plays a crucial role in the deprivation of Muslims in India[22].

The representation of Muslims in government employment has decreased over time compared to the post-partition era. Similarly, the percentage of Muslims in defense has declined significantly, with their representation dropping from 32 percent at the time of partition to a mere 2 percent currently[23]. These figures underscore the ongoing challenges and disparities faced by the Muslim community in the country's workforce.

The Gopal Singh Committee Report (Gopal Singh Committee Report on Minorities, 1983, cited in Najiullah, 2006, p. 688) highlights the concerning underrepresentation of Indian Muslims in the Indian Administrative Services. The statistics reveal that only 2.86 percent of Indian Administrative Services comprised Muslims, while Sikhs and Christians constituted higher percentages at 4.71 and 5.64 percent, respectively. This disparity underscores the significant gap in representation between Muslims and other religious communities in this prestigious govern-

ment service.The disturbingly low percentage of Muslims in government employment is often attributed to their religious identity. In some cases, lower-caste Muslims are more likely to be identified as Muslims rather than being recognized as Dalits by both the majority community and the state administration[24]. This religious identification becomes a significant barrier to their inclusion in government jobs.

In states with a high Muslim population, such as Uttar Pradesh, West Bengal, and Bihar, the representation of Muslims in government employment is significantly lower than their share in the total population. For example, in West Bengal, where Muslims make up 25.2 percent of the population, only 4.2 percent of government employees are Muslims[25]. Similarly, in Assam, with a 30.9 percent Muslim population, the percentage of Muslim employees in key judicial positions is just 9.4 percent. This underrepresentation of Muslims in government positions reflects the prevailing religious prejudice and highlights the need for more inclusive policies and measures to address this disparity.

Table 1 from the Sachar Committee presents primary data collected from various departments and institutions, encompassing 8.8 million employees. The data reveals a strikingly low representation of Muslims, accounting for only 5 percent of the total workforce. Within this, Muslims constituted 3.3 percent of central Public Sector Undertakings (PSUs) and 10.8 percent of state-level PSUs[26]. In national-level civil services, the employment of Muslims is even lower, with only 3 percent in the Indian Administrative Service (IAS) and 1.8 percent in the Indian Foreign Service (IFS). A notable trend among Muslims recruited for high-ranking positions is that a majority of them are 'promoted candidates' rather than those recruited through direct competitive examinations. Overall, Muslims face significant under-representation in government jobs across all departments, and a majority of them are confined to lower positions. These findings highlight the need for targeted efforts to address this imbalance and create more inclusive opportunities for the Muslim community in the workforce.

India experienced its first Muslim Intelligence Bureau Chief in 2012, 125 years after its establishment[27]. This highlights the persistence of stereotypes and prejudices, suggesting that notions of unpatriotic and anti-national Muslims persist in society. Looking at statistics of Muslims in jails and on trial, it becomes evident that Muslims are often subjected to higher suspicion.

Although Islamophobia may not be deeply entrenched in India, it is gradually gaining ground. The earlier discussion also revealed that Muslims face significant challenges across all employment sectors, be it government or private.

With lower educational levels and limited social and cultural capital, they have limited options, often resulting in irregular contract-based work or self-employment. These factors collectively contribute to the difficulties faced by the Muslim community in accessing better economic opportunities and social mobility.

Table 1. Muslim Employees in Government Sector Employment

Departments/ Institutions Reporting	Reported Number of Employees	Reported Number of Muslim Employees	Muslims as Percentage of Reported
State-level departments	4,452,851	278,385	6.3
Railways	1,418,747	64,066	4.5.
Banks and RBI	680,833	15,030	2.2
Security agencies*	1,879,134	60,517	3.2
Postal services	275,841	13,759	5.0
Universities**	137,263	6,416	4.7
All reported government employment (excludes PSUs)	8,844,669	438,173	4.9
Central PSUs***	687,512	22,387	3.3
States PSUs	745,271	80,661	10.8
All PSUs	1,432,783	103,048	7.2

Source: *Sachar Committee Report (2006, p. 165).*

Notes: *CRPF, CISF, BSF, SSB, and other agencies; **129 universities (central and state) and 84 colleges; *** data from 154 PSUs.

Spatial Marginalization

The geography of Indian cities has contributed to the marginalization of Muslims, leading to their marginalization in areas where they were once rulers. The historical background of Hindu-Muslim cohabitation has not always been harmonious, with the majority community often holding inhibitions about Muslims living in the same neighborhoods due to notions of purity and pollution. Additionally, Hindu-Muslim antagonism stemming from historical events, such as Muslim invasions and the memory of partition, further reinforces the segregation of Muslims from majority areas. Communal riots have also played a significant role in the spatial segregation of Muslims. These violent events have instilled fear among Muslims, leading them to seek safety and security by residing in ethnically segregated enclaves. Paradoxically, while these enclaves provide a sense of security, they are also stigmatized as dangerous and seen as breeding grounds for crime, creating a serious concern for the Muslim community. As a result, Indian Muslims find themselves facing various challenges due to the historical, geographical, and communal factors that contribute to their seclusion and marginalization in their cities.

Due to the factors mentioned earlier, Muslims in India are often unevenly distributed in residential areas, forming ghettos and ethnic enclaves. Unfortunately,

these Muslim-concentrated areas frequently lack proper physical and social infrastructure. This includes inadequate access to sanitation, health, and transportation facilities. The educational and medical facilities in such areas are also limited. Villages with a significant Muslim population tend to have fewer primary and elementary schools, as well as a lack of proper medical facilities, particularly in larger villages. Data from the 55th and 61st NSSO revealed that areas with a large number of Muslims and SCs/STs (Scheduled Castes/Scheduled Tribes) were categorized as the least electrified areas at the household level[28]. Additionally, the 60th round of NSSO data on household use of tap water showed that while urban areas were better served with tap water, rural areas, especially those with a Muslim population, had limited access to this essential resource. Overall, these findings highlight the disparities and challenges faced by Muslims in India, particularly in terms of living conditions and access to basic amenities[29].

In various Indian cities, there are numerous ghettos and segregated localities where Muslims predominantly reside. Nida Kirmani's research (2008) on Zakir Nagar, a segregated migrant locality in Delhi that began developing in the 1970s and is now part of the wider Okhla area, sheds light on the spatial segregation of Muslims. Kirmani's work in this Muslim neighborhood in Delhi demonstrates how memories of historical events influence the formation of contemporary urban localities. The research highlights that during periods of conflict and communal violence, there is a heightened awareness of religious boundaries. Through discussions with the residents of Zakir Nagar, it was evident that their preference for living in a 'Muslim area' is strongly influenced by memories of violent events, ranging from the Partition riots to the Gujarat pogrom. For the residents, living in Zakir Nagar provides a sense of protection against religion-based violence and discrimination that has become part of their collective memory. Essentially, this locality serves as a way for them to shield themselves from the historical traumas and communal tensions they have experienced in the past.

The Babri Masjid demolition and the Gujarat riots have heightened religious identity as a significant marker of identity in India. In the aftermath of communal violence and riots, people tend to seek safety and security, leading to a desire to stay in neighborhoods where they feel protected[30]. This feeling of insecurity among Muslims has resulted in the "ghettoization" or self-segregation of the community. Laurent Gayer's study of the Abul Fazal Enclave in Delhi, a Muslim-dominated neighborhood, further supports this phenomenon. In addition to the middle-class and migrant population from other areas, the rise of Hindu-Muslim violence across North India and the destruction of the Babri Masjid prompted wealthy Muslim industrialists to relocate to this enclave as a way to find security in numbers and feel safer amid communal tensions[31].

Abdul Shaban's study in Mumbai reveals a compelling case of spatial segregation. Muslim ghettos like Nagpada, Byculla, and Dongri are characterized by poor planning, congestion, and a lack of essential urban amenities such as schools, colleges, banks, and hospitals[32]. Shaban points out that the politics of ethnicity and

violence in Mumbai has alienated Muslims from public spaces, leaving them confined to their own ghettoes. Public spaces are now dominated by regional and right-wing groups, who control parks, streets, and roads. The boundaries between Muslim and Hindu neighborhoods are demarcated through the use of symbols, flags, graffiti, and banners. Saffron flags often symbolize areas dominated by Hindus, while green flags with crescents and stars indicate Muslim neighborhoods[33]**.** This visual divide highlights the extent of spatial segregation and the lack of integration between different communities in the city.

The contested spaces for Muslims in India are not limited to just residential areas but also extend to their places of worship, which have frequently been at the center of controversy. One such case is presented by Williams (2012) in Madanpura, a traditional weaving neighborhood in the heart of Varanasi, where the majority of the population is Muslim. Williams' work highlights the issue of Muslim rights in the city, particularly the closing down of a mosque in Madanpura. The shutting down of the mosque in this neighborhood raises important questions about Muslim citizenship and their right to representation in the urban landscape[34]. Refusing to recognize the legitimacy of a mosque in an area predominantly inhabited by Muslims indicates a broader debate on the rights and status of Muslims in India, especially in urban spaces. This act of denying their religious spaces further contributes to the challenges faced by the Muslim community in the country.

The shutting down of the mosque in Madanpura is not an isolated incident but reflects a broader issue of questioning Muslim rights in Indian cities. Muslims have faced threats to their religious minority status, and this has led to self-segregation and the formation of ghettos. The insecurities arising from communal violence have prompted Muslims to create ethnic enclaves, seeking a sense of security and protection in these areas. These enclaves serve as a response to the challenges and uncertainties faced by the Muslim community in their quest for safety and religious freedom.

In contrast to the marginalized and excluded status of Muslims in some parts of India, Radhi Kakanchana's (2012) study in Kuttichira, Calicut, reveals a different scenario for Muslims in South India. In Kuttichira, Muslims are not considered urban outcasts or severely deprived groups. The presence of oceanic trade and gulf migration has contributed to the improvement of their economic conditions. The positive exclusivity of the locality's Muslim inhabitants in Kuttichira is defined by their origins, economic activities, and cultural practices[35]. Unlike regions in the Hindi belt, the area has been spared from the violence of partition and other communal conflicts. This relative lack of communal violence has likely played a significant role in enabling Muslims in Kuttichira to thrive and avoid the same level of marginalization seen in other parts of the country.

The marginalization of Muslims in India may vary across different regions, with some areas experiencing more pronounced disparities than others. However, it is essential to acknowledge that the marginalization of Muslims exists in various

spheres in complex ways throughout the country. The experiences and challenges faced by Muslims are multifaceted and can be influenced by historical, social, economic, and political factors, making the issue of Muslim marginalization a complex and nuanced one.

Conclusion

Muslim communities in various geographical regions exhibit differences in their structure, practices, and culture. Despite these variations, the concept of transnationalism and shared belongingness to a global religious community has recently gained prominence. This pan-religious identity growth is seen as a response to anti-Muslim sentiments and a means of asserting recognition. The previous discussion highlights that Indian Muslims are not a homogeneous community. They face marginalization in different aspects of society, experiencing marginalization and being relegated to the periphery in social and secular spheres. Muslims encounter a "religious penalty" in the labor market, suffer from spatial segregation, and are sometimes unfairly incarcerated.

The marginalization faced by Muslims is closely tied to their religious identity and is a distinctive feature of Indian society. However, the extent of marginalization varies across different spheres and is not uniform for all Muslims. There are signs of selective marginalization and inclusion, and the complexity of marginalization differs in each sphere. It is essential to recognize that not all Muslims experience marginalization in the same way, with factors like class, caste, and ethnicity playing a role in how they are affected. Nevertheless, the common thread that unites them is the experience of marginalization based on their religious identity.

❐

References :

1. *Robinson, R. (2008). Religion, socio-economic backwardness, and discrimination: The case of Indian Muslims. Indian Journal of Industrial Relations, 44(2), 194–200.*
2. *Shaban, A. (2016). Identity, citizenship, and Hindu–Muslim conflict in India. In H. Gorringe, R. Jeffery, & S. Waghmore (Eds.), From the margins to the mainstream: institutionalizing minorities in South Asia (pp. 1–30). Sage Publications.*
3. *ibid*
4. *Rabasa, Angel M., et al. (2004). The Muslim World after 9/11. Santa Monica, CA: RAND.*
5. *Rao, Y. C., & Karakoti, S. (2010). Exclusion and discrimination: Concepts, perspectives, and challenges. Kanishka Publishers.*
6. *Le Grand, J. (2003). Individual choice and social exclusion. CASE Paper 75.*
7. *ibid., pp. 40-41*
8. *ibid., p. 44*
9. *Millar, J. (2007). Social exclusion and social policy research: Defining exclusion. In D. Abrams, D.*
10. *ibid. cited in Bhalla & Luo, 2013, p. 21*

11. *Fischer, A. M. (2011). Reconceiving social exclusion. BWPI Working Paper 146. The University of Manchester, Brooks World Poverty Institute. http://papers.ssrn.com/sol3/ papers. cfm?abstract_id=1805685*
12. *ibid., p. 2*
13. *Basant, R. & Shariff, A. (2009). Handbook of Muslims in India. Oxford: Oxford University Press.*
14. *Hasan, M. (2007). Living with secularism. Manohar Publishers.*
15. *ibid., p. 224*
16. *Khalidi, O. (2006). Muslims in the Indian economy. Three Essays Collective.*
17. *ibid.*
18. *Das, M. (2008). Minority status and labor market outcomes: Does India have minority enclaves? Policy Research Working Paper 4653. The World Bank. http://documents. worldbank.org/curated/ en/2008/06/9592751/minority-status-labor-market-outcomes-india-minority-enclaves*
19. *ibid., p. 14*
20. *ibid., p. 16*
21. *Karunakaran, N. (2015). Muslims constitute 14% of India, but just 3% of India Inc. Economic Times, 7 September. http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-09- 07/news/ 66297409_1_private-sector-muslims-india-inc#*
22. *Sachar Committee Report. (2006). Sachar Committee Report: Social, economic and educational status of the Muslim Community of India; A report, Prime Minister's High-Level Committee. Cabinet Secretariat, Government of India.*
23. *Shaban, A. (2016). Identity, citizenship, and Hindu–Muslim conflict in India. In H. Gorringe, R. Jeffery, & S. Waghmore (Eds.), From the margins to the mainstream: institutionalizing minorities in South Asia (pp. 1–30). Sage Publications*
24. *Sonalkar, S. (1993). The Muslim problem: A perspective. Economic and Political Weekly, 28(26), 1345–1349.*
25. *Shaban, A. (2016). Identity, citizenship, and Hindu–Muslim conflict in India. In H. Gorringe, R. Jeffery, & S. Waghmore (Eds.), From the margins to the mainstream: institutionalizing minorities in South Asia (pp. 1–30). Sage Publications.*
26. *Bidwai, P. (2016). Muslims, the new underclass. The Transnational Institute, 15 November. https:/ /www.tni.org/en/archives/act/15988 Cesari, J. (2010). Muslims in the West after 9/11. Routledge.*
27. *Sachar Committee Report. (2006). Sachar Committee Report: Social, economic and educational status of the Muslim Community of India; A report, Prime Minister's High-Level Committee. Cabinet Secretariat, Government of India.*
28. *Hebbar, N. (2012). Appointment of India's first Muslim IB chief Syed Asif Ibrahim a potentially transformational symbol? The Economic Times, 23 December. http:// articles. economictimes.indiatimes.com/2012-12-23/news/35969754_1_ib-officer intelligence-bureau-Mus lim-officer*
29. *Sachar Committee Report. (2006). Sachar Committee Report: Social, economic and educational status of the Muslim Community of India; A report, Prime Minister's High-Level Committee. Cabinet Secretariat, Government of India.*
30. *ibid.*
31. *Kirmani, N. (2008). Constructing 'the other': Narrating religious boundaries in Zakir Nagar. Contemporary South Asia, 16(4), 397–412.*
32. *Gayer, L. & Jaffrelot, C. (2012). Muslims in Indian cities. Uttar Pradesh: Harper Collins Publish ers.*
33. *Shaban, A. (2012). Lives of Muslims in India. Routledge.*
34. *ibid.*
35. *Williams, P. (2012). India's Muslims lived secularism and realized citizenship. Citizenship Stud ies, 16(8), 979–995*
36. *Gayer, L. & Jaffrelot, C. (2012). Muslims in Indian cities. Uttar Pradesh: Harper Collins Publishers.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 125–141

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Resurgence of Adivasi Identity: Pathalgadi Movement and Politics of Indigeneity in Jharkhand

Alok Mishra
Research Scholar, Department of Humanistic Studies,
Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi, (U.P.) 221005
E-mail ID: alokmishrax210@gmail.com Mob.8009590603

Abstract

Traditionally, 'Pathalgadi' signifies 'placing a stone' and holds symbolic significance in transmitting governance and genealogy-related knowledge to generations, primarily practised by the Austro-Asiatic language families such as Mundari. This practice is revived in the current socio-political circumstances through the traditional Gram Sabhas, predominantly led by the Adivasi villages in the Khunti district of Jharkhand. This resurgence of the Pathalgadi movement has transformed material culture into not only a site of resistance to political recognition but also a marker of distinct cultural history. The study attempts to revisit the challenges it raises vis-a-vis the political institutions. Further, it seeks to elucidate the underlying concerns driving the movement, which extend beyond its immediate causes and encompass deeper, more systemic issues. Specifically, this study will investigate the Pathalgadi movement by tracing its historical context and analysing the narratives presented by its protagonists. By considering the historical events, newspaper reports, and the voices of its protagonists, this paper focuses on the politics of indigeneity and cultural impulse within the socio-political milieu. It attempts to delineate the dynamic of political revivalism in the form of Abua dishum, abua raj. Furthermore, it highlights how this form of mobilisation epistemically challenges existing power structures and articulates demands for recognising Adivasi rights and autonomy.

Keywords: Pathalgadi Movement, Indigeneity Politics, Adivasi, Identity, Jharkhand

Introduction

There are multiple sets of governance models. Nevertheless, today's world preferably endorses liberal democracy, which acknowledges the individual as a self-

sufficient entity capable of participating in the political realm. Liberal democracy is characterised by a specific set of institutions such as legislative assemblies, parliament, and impartial courts. These institutions enable competing interests and discursive practices to function, providing an outlet to transform 'enemies' into 'adversaries.'

Although liberal democracy often portrays itself as a universal form of governance, but its values and institutions have been repeatedly challenged by various racial, ethnic, and religious groups. The forces of liberalisation and globalisation have facilitated the expansion of liberal principles. However, in practice, these principles and institutions are not sacrosanct and face numerous challenges. For instance, in India, liberal institutions and principles are continually tested on multiple fronts. These institutions must navigate identity assertions that are sometimes accommodative and, at other times, challenging to integrate. This dynamic underscores the ongoing tension between the ideals of liberal democracy and the complex realities of diverse societies.

The eruption of the Pathalgadi Movement in Jharkhand, particularly in the district of Khunti and its neighbouring areas, holds significant implications and prompts re-evaluation of the questions it raises in relation to the state. Despite the numerous movements by Adivasi groups in post-colonial India, the Pathalgadi Movement stands out, especially as it emerged after the formation of Jharkhand from the state of Bihar and secondly for its method of assertion.

The study attempts to revisit the challenges it raises vis-a-vis the political institutions. It seeks to elucidate the underlying concerns driving the movement, which extend beyond its immediate causes and encompass deeper, more systemic issues. Specifically, this study will investigate the Pathalgadi movement by tracing its historical context and analysing the narratives presented by its protagonists.

It is observed that the emergence of the Pathalgadi movement cannot be viewed as an isolated event devoid of historical context. On the contrary, this particular case encapsulates both immediate and deeper causes. The study suggests that immediate causes, such as the failure of state delivery mechanisms and proposed changes to protectionary laws, play a significant role in the Pathalgadi movement. However, the distinctiveness of the Pathalgadi movement extends beyond these immediate causes or material concerns. Adivasi movements in India are often translated as mere claims over resources, which tends to generalise and reduce Adivasi movements to the material domain alone. It contends that such a reductionist view fails to capture the broader socio-political and cultural dimensions of the Pathalgadi movement.

This work, therefore, examines the specific case of the Pathalgadi movement to demonstrate a broader trend within the Adivasi movements in Jharkhand. While these movements may strategically negotiate within a limited domain, they are inherently part of a 'tradition of protest' that subtly challenges the dominant discourse and proposes an alternative worldview.

The Practice of Pathalgadi

I begin with the expansion of the term 'Pathalgadi' and the way it gathers a symbolic significance in the present context. Literally, 'Pathalgadi' means placing a stone. Traditionally, this practice has served as a means of transmitting knowledge about governance and genealogy to future generations within the community. The tradition of 'Pathalgadi' is predominantly observed among Adivasi communities, particularly those belonging to the Austro-Asiatic language families, such as the Mundas and Khasis. It is known as *Sasandiri* (burial site) or *hargarhi* among Mundas, this practice involves cremating bones under stone slabs. This ritual holds significant spiritual and socio-political importance. Also, it demarcates village boundaries and integrates aspects of community governance and ancestral reverence[1].

However, the Pathalgadi practice has been modified to adapt to changing circumstances. The incorporation of remnants of the past has remained a unique strategy of resistance for relatively weaker and culturally distinct groups. Alfredo Gonzalez-Ruibal addresses a similar question: what structural factors enable certain societies to survive in some of the earliest areas of state formation in Africa? He emphasises the importance of examining contemporary material culture to understand the resistance involved in their survival[2].

This perspective is equally applicable to the Pathalgadi movement, demonstrating how material culture serves as a powerful tool of resistance.

The traditional Gram Sabhas (village councils) had revitalised this practice as a form of resistance by placing the stones outside the Gram Sabhas, claiming their control over the villages vis-a-vis the state and the outsiders, inscribing the constitutional provisions and invoking the claims based on their supposed indigeneity. In this context, villagers have further restricted the entry of outsiders, invoking constitutional protections to justify their actions. Additionally, they have proposed the establishment of their own schools and banking systems designed to align with and promote the Adivasi knowledge system. The resurgence of 'Pathalgadi' has thus transformed material culture into a symbol of both a distinct cultural history and an active site of resistance. The revival of Pathalgadi among the Adivasis in the region reflects not only their demands vis-à-vis the state but also symbolically represents a unique strategy of resistance that bridges the past and the present.

As Devalle argues,

Among subordinate ethnic groups, it is the cultural domain that provides the elements for a strategy of survival, for social reproduction and for strengthen to check and question the advance of an attempted hegemonic order[3].

Further, she adds

The cultural language in which a particular ethnic identity is lived and expressed has codes and meanings that are significant only to those who create and share them. There lies the force of culture in situations of dominance-subordination: the

preservation of coded spaces that can become zones of resistance[4].

Precisely, the customisation of the practice of the Pathalgadi in the recent context revives in the '90s after the enactment of the PESA act, former IAS officer BD Sharma and former IPS officer Bandi Oraon restarted using the traditional practice of pathalgadi to spread awareness about the provisions of the enacted Panchayat (Extension to Scheduled Areas) Act that extended the provisions of panchayat act to the scheduled areas for ensuring self-governance through Gram Sabhas. However, in the recent context, the practice of pathalgadi outbursts in the form of resistance to revive the traditional Gram Sabhas in real terms, which includes Munda-Manki, Majhi-Parganait systems, etc., for the governance of the Scheduled areas under the fifth schedule of the constitution of India.

Immediate Trigger of the Movement

There are 24 districts in Jharkhand, which are further grouped into five divisions for administrative purposes, namely the Palamau Division, North Chotanagpur Division, South Chotanagpur Division, Kolhan Division and Santhal Pargana Division. The Pathalgadi movement was most active in the South Chotanagpur division. Multiple reasons eventually provoked such a huge mobilisation of Adivasi villagers. After initial mobilisation, the movement spread to approximately 70 villages in the Khunti district and other neighbouring areas[5].

The motivations behind the Pathalgadi movement can be delineated into two categories: immediate causes and underlying causes. The deliberate use of the term 'underlying cause' for the second category underscores that the issue extends beyond the material domain and encompasses ideological dimensions and discourse generation. This categorisation is employed for operational purposes, acknowledging that the two categories are not mutually exclusive but are directly interrelated.

One of the main reasons which have been widely discussed and considered as the triggering moment for the eruption of the Pathalgadi moment was the amendment bill passed by the legislative assembly of Jharkhand, which was returned to the assembly for reconsideration by the Governor of the state Draupadi Murmu[6]. The proposed bills were related to the amendment in the Chotanagpur Tenancy Act (1909) and the Santhal Pargana Tenancy Act (1949). Originally, these acts were introduced to protect Adivasis' interests. It protects the land of Adivasis communities from the unjust land alienation in the hands of non-adivasis. Regarding the amendment of these protective measures, sections 21, 49, and 71A of the CNT Act and section 13 of the SPT Act were proposed for amendment[7]. Particularly, section 71A [Power to restore possession to a member of the Scheduled Tribes over land] explicitly deals with unlawful transfer of Adivasi lands and emphatically directs the concerned authority to restore such transfer to the original transferor.

Quoting the excerpt from the act itself related to section 71A of the CNT Act

If at any time, it comes to the notice of the Deputy Commissioner that transfer of land belonging to a Raiyat [or a Mundari Khunt-Kattidaror a

Bhuinhari] who is a member of the Scheduled Tribes has taken place in contravention of Section 46 [or Section 48 or Section 240] or any other provisions of this Act or by any fraudulent method, [including decrees obtained in suit by fraud and collusion] he may, after giving reasonable opportunity to the transferee, who is proposed to be evicted, to show cause and after making necessary inquiry in the matter, evict the transferee from such land without payment of compensation and restore it to the transferor or his heir, or, in case the transferor or his heir is not available or is not willing to agree to such restoration, re-settle it with another Raiyat belonging to Scheduled Tribes according to the village custom for the disposal of an abandoned holding[8].

This protects Adivasis from unlawful and fraudulent methods of grabbing their lands. This was further reiterated in the case of Jitu Oraon v. Commissioner, South Chotanagpur Division[9], where the judgement lays down the intention of the CNT Act. One thing related to this act should be taken into cognisance that the said act already allows the government to acquire the land of Adivasis in the name of *'mining'* and *'industrial activities'* but the two new proposed ordinances attempt to enlarge the content of acquisition to acquire the land for other purposes and seeks to transfer the land for other activities such as Road, Canal, Railway, Cable, transmission, water pipes, and other service utility as pipelines, schools, colleges, University, Panchayat building, Hospital, Aganwadi or any public purposes and projects or activity which the State Government may add[10]. The proposed ordinances precipitated extensive demonstrations and protests, fueled by fears of land alienation and the denial of rights protected under the Chotanagpur Tenancy (CNT) Act and the Santhal Parganas Tenancy (SPT) Act. Many Adivasi activists apprehended that these proposed acts were designed to facilitate the transfer of Adivasi lands into the hands of powerful entities.

Additionally, several policies of the then Raghubar Das government faced significant criticism, particularly the Land Bank Policy, in which the Jharkhand government began compiling a Land Bank record. The stated purpose of maintaining this record was to attract investments to Jharkhand. The 'Momentum Jharkhand' initiative was launched to increase the presence of global investors in the state. This initiative and the associated policies were perceived as further threats to Adivasi land rights and autonomy, exacerbating the unrest and resistance epitomised by the Pathalgadi movement.

In Bengaluru July 2016, Das says

Land acquisition has never been a challenge for us because we have a Landbank of 1,75,000 acres readily available for different industries to set up their businesses. Farmers are ready to give us land as we are paying a handsome price. We currently hold 40% of India's natural mineral wealth, and we are on the way to becoming the power hub of the country by 2019[11].

Conversely, allegations surfaced that lands were being acquired unlawfully, as supported by various reports. For instance, a report based on Perka village in the

Murhu development block of Khunti district revealed that many villagers were unaware that the state government had already registered three plots of their village forest, covering approximately 1,214 acres, with the Land Bank. One of the respondents says,

I have land record papers of 1932, where we have been given the right to use the forest land. How can the government take away our forest land and enlist it in the Land Bank without the consent of our Gram Sabha[12].

Another respondent says,

It has been 20 years since we have been protecting our forests. We keep a watch round the clock to ensure that no one cuts trees. We also discuss how to protect and minimise the use of forests in our weekly Gram Sabha meetings[13].

The report of Tarique Anwar also cites the allegation of Gladson Dungdung, who is an Adivasi rights activist based in Ranchi;

The state government acquired 42 acres of uncultivated land at Dambuli village in West Singbhum district's Manoharpur block and gave it to Vedanta. Now, the company is attempting to acquire the private land of Adivasis against their consent. They don't have a way to reach the land they cultivate on[14]

Though the government deemed it necessary to develop the Scheduled areas of Jharkhand, the Land Bank policy was not welcomed and faced heavy criticism from Adivasi rights activists. This policy exacerbated fears and apprehensions of losing land rights, ultimately becoming a triggering moment for the movement. Nevertheless, interpreting the immediate cause might suggest that the movement is merely about land rights or material interests that the Adivasi communities are keen to secure.

However, a closer examination of the movement, particularly the claims made by the Pathalgadi movement, reveals a deeper dimension that I refer to as the underlying cause. This deeper cause extends beyond material concerns and encompasses broader ideological and discursive elements.

Situating the Underlying Concerns

Locating the Pathalgadi movement merely as a demand against the state or an assertion that emerged out of immediate concerns would not be sufficient to locate the genesis of the problem. Confining the movement merely as a reaction to the proposed changes in the CNT and SPT act or the dissatisfaction with the policies of the then government of Jharkhand such as the Land Bank policy[15] may not be able to answer the underlying concerns of the movement or the genesis by which the movement derives its vigour.

Referring to an underlying cause, the study aims to highlight the intermittent struggle waged by Adivasi communities in the region against external dominant powers. To study the Pathalgadi Movement without considering the history of struggles in those areas would result in a limited analysis of the event. Viewing the movement not as an isolated occurrence in the socio-political sphere but as part of a continuum that reflects a profound connection with a series of events. This

approach aids in comprehending a deeper cause that transcends mere concerns for land rights and access to resources, extending to broader ideological dimensions.

Beyond immediate concerns, the Pathalgadi movement can be comprehended at three additional levels. Firstly, Jharkhand has been a locus of Adivasi assertions, particularly in South Chotanagpur and the Kolhan division. Therefore, it is pertinent to examine the ideological continuity of these assertions within the context of the movement. Secondly, it is crucial to analyse the effectiveness of existing policies and safeguard mechanisms in meeting the aspirations of the Adivasi communities. Lastly, focusing on the narratives emerging from the movement is imperative to grasp the underlying cause driving the movement forward.

Adivasi Resistance in Jharkhand

The Adivasi assertions have been a major concern from the administrative perspective, be it in the colonial or postcolonial history of India. The history of Adivasi resistance to the outside powers is not a new phenomenon. The colonial and post-colonial history of India has witnessed the ebb and flow into the socio-political space of India as a series of resistance by the Adivasi communities.

In present-day Jharkhand, Adivasis constitute around 26 per cent of the total population, and the region's history is not solely one of dominance but also of resistance. Historically, Adivasi groups have consistently challenged encroachments into their polity and way of life. The land has borne witness to numerous Adivasi struggles against interventions into their community-based existence and polity, including events such as the Tamar rebellion (1780-1820), Kol insurrection (1831-32), Hul Rebellion (1855), and Birsa Rebellion (1890s). These rebellions have demonstrated ideological continuities, often envisioned under Santhal Raj, Munda Raj, or Oraon Raj. Over the course of the 20th century, particularly in South Bihar (present-day Jharkhand), unified struggles have been successfully developed among Adivasi communities. Organisations such as the Chotanagpur Unnati Samaj, which later transformed into the Adivasi Mahasabha, have advocated for the cause of Adivasis.

Jaipal Singh Munda emerged as one of the prominent leaders who utilised legal and constitutional means to assert Adivasi rights. Unlike the assertions of the nineteenth century, the twentieth century witnessed non-violent movements such as the Tana Bhagat movement, which later aligned with the Gandhian movement. However, it is noteworthy that while the nature of assertions shifted, they did not lose their ideological continuity. They retained their ideological foundations, grounded in a shared consciousness of distinct history and polity, and invoked claims of indigeneity. Adivasis have continuously engaged in negotiations with the state, invoking claims of indigeneity. Postcolonial India has also witnessed numerous Adivasi assertions. These assertions have taken various forms, some of which have been severely violent and posed challenges to the modern state, such as the Naxalite movements in tribal areas. However, there are many examples demonstrating tribal assertions within the confines of constitutional limits, such as the Niyamgiri movement, Plachimada struggle, Narmada Bachao Andolan, and even the campaign to save

the Hasdeo forest, which are integral parts of nonviolent resistance movements. Therefore, Adivasis have interacted with the state in various ways in postcolonial times to assert their demands.

Postcolonial India and the Fifth Scheduled Areas

The Fifth Schedule of the Constitution is equipped with provisions that deal with the administration of Scheduled areas as well as Scheduled Tribes residing in any state other than the states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram. The differential form of administration in these areas aspired to develop the concerned areas on the lines of their own genius and to avoid the imposition of alien values abruptly on the tribal communities, a principle laid down as the Panchsheel doctrine[16]also known as the NEFA philosophy.

The areas are notified by the President of India, who is responsible for peace and good governance. A tribal advisory council is made to enhance the scope of participation in the decision-making body.

Despite these arrangements, multiple reports, such as the Bhuria Commission (2004) and the Xaxa Committee report (2014), suggest the dismal situation of Adivasis in India.

The Bhuria Commission or 'The Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission' 2002-2004 was set up by the government of India with a view to evaluate, scrutinise and review the administration of the fifth scheduled areas and the sixth scheduled areas, particularly with reference to the PESA and the tribal sub-plan.

The Commission acknowledged some serious loopholes in administrative functioning under the Fifth Schedule. Commenting on the Governor's report, the committee recommends that some states do not submit the report in a timely manner and that reports have been pending for years. In addition, the committee invoked various questions concerning the no-fixed format of drafting of the reports.

The Commission further suggests,

We believe unless there is correct reporting done about the sensitivity that is emerging in certain tribal habitats on account of lurking fear the tribals have about the cultural invasion from outside and the exploitative control over the tribal economy and the land resources from outside, nothing tangible can be done for the peace and good governance of the Scheduled Areas[17]

Here, the report also brings in the fear of the Adivasi communities about the cultural invasion. The committee report, in this way, commented on various aspects of the issues and recommended that,

The Governor's Reports offer quantitative rather than qualitative or analytical data about the status of tribal administration in the concerned States...The reports do not offer an independent assessment of the policies of the State Governments vis à-vis Scheduled Areas and instead seem to uncritically accept government claims of tremendous achievements with regard to tribal development[18].

The committee questions the process of report-making. Additionally, the committee focussed on issues such as the role of the TAC and the tribal sub-plan. It explicitly mentions that 'The tribals' life-support systems are based mainly on two resources: land and forest. We found that in respect of both these resources, the tribals were losers[19].

While commenting on the plight of the Adivasis in Jharkhand, the committee observes and writes in its report,

Loss of tribal land is a burning problem. Alienation of tribal lands takes place in Jharkhand in many ways, like forcible occupation by non-tribals, transfer through fraud, manipulation of land records, denial of possession of land decreed in tribal favour, and the marriage of a non-tribal with a tribal spouse. Some of these hurdles in law, while some others may be due to negligent or motivated implementation. All these need to be looked into by the State Administration[20].

Summingly, the committee report finds multiple loopholes in the implementation of policies and laws. The report shows that the promises of the constitution of India are not adequately catered to on the ground, the development of these communities is half-baked, and large-scale land alienation, migration, loss of forest resources, and exploitation are common phenomena.

Virginius Xaxa has observed questions about livelihood and employment, education, health, involuntary displacement and migration, and legal and constitutional matters. The committee observes the Fifth Schedule Area. It mentions that the role of TAC is limited as an advisory body but has no stake in implementation or decision-making processes.

In addition, the committee pointed out that, unlike the Sixth Schedule, wherein the Autonomous District Council have been given significant legislative, executive and judicial powers, the administration of the Fifth Schedule Areas is mainly concentrated in the hands of the Governor[21]. Besides that, the committee observed that the Governor's report does not incorporate several issues such as displacement and rehabilitation, law and order problems, tribal protests and atrocities against tribes.

Commenting on education, it is mentioned that there is no effort in developing curricula and creating instructional materials by considering the socio-cultural understanding of the tribal children, the tribal knowledge and their understandings are not provided with enough space in the school curriculum, there is high drop rates and lack of 'Quality' teachers.

Also, research shows the importance of early education in the mother tongue, but the committee observes 'language barriers' for tribal children who are getting early education. The committee recommends that the state adopt a policy of multilingual education that can help early education in the local language.

The committee further suggests an urgent need to extend the pattern of the sixth schedule in the form of autonomous councils in the Fifth Schedule Areas, as provided in the provisions of Panchayat (Extension to Scheduled Areas) 1996.

The report acknowledges that after the liberalisation and privatisation, drastic changes have occurred to tribal life. Government acts such as the PESA and FRA recognise the autonomy and rights of tribal communities, but the implementation of these laws are reluctant, so the Gram Sabhas and the institutional system should be strengthened. The committee recognises that the consent of Gram Sabhas has been fraudulently obtained, and the proper implementation of the laws has not been implemented. As a result, the committee recommended that the state be vigilant about the fair consent procedure.

If we evaluate both these committees, we observe several facets of the administration in the scheduled areas of the Fifth Schedule, but a closer look at both reports shows the poor implementation mechanism of the state in terms of meeting the aspirations of the communities.

Furthermore, land alienation is one of the major problems for the tribal communities in Jharkhand. According to the Ministry of Rural Development's annual report 2004-2005, Jharkhand topped the list of land alienation in the country with 86,291 cases involving 10,48,93 cases of land. The Santhal Pargana and the Chotanagpur regions are covered under the tenancy acts to protect the lands and resources of the Adivasi communities, but still, cunning practices lead to the loss of land and resources in the hands of the powerful. The PESA has given extensive rights to the tribal communities regarding decision-making at the local level. The PESA defines 'The gram Sabha as an organic self-governing community rather than just a basic administrative unit of self-governance[23].' It provides a framework for autonomous and empowered Gram Sabhas in the Fifth Scheduled Areas. However, poor implementation of the PESA Act has been a serious issue.

Chaubey argues that the PESA 'has not been implemented in its true spirit, and it has been violated at many levels.[24]' In addition, he mentions several reports like 'Report of Expert Group of the Planning Committee on Development Challenges in Extremist Affected Areas'' 2008, 2nd ARC or Bhalchandra Mungekar Committee Report (2009) have clearly mentioned the bleak condition of the implementation of PESA[25].

These reports illustrate a dismal situation in implementing the policies and providing an inadequate response to the grievances. Even a state like Jharkhand, where the tribal population consists of approximately 26%, does not have state-specific rules for PESA[26]. Ananth and Kalaivanan write that PESA has not been effective in terms of delivering what it was supposed to be due to multiple factors such as lack of clarity, bureaucratic pathy, dearth of political will, etc[27]. Similarly, Bara argues that PESA has not implemented in its true spirit due to political apathy, the internal conflict of Maoism and unawareness among the Adivasis[28]. Kindo and Bhowmick contend that calling PESA 'an unmatched weapon' is an illusion as much has not been changed even after the implementation of the PESA and FRA in Jharkhand, and to achieve the desired goals, the main tool is to ensure the effective structures and space for participation of the tribal population in the matters of decision making. According to them, the creation of Jharkhand has made participation in

decision-making a bit closer to the scheduled areas, but effective functioning requires due space to traditional social structures to ensure their rights are enshrined in the Constitution[29].

Guha argues that the introduction of forest policy, management, and legislation in colonial times and its continuation in the post-independence period have curtailed the customary rights of forest communities. The forest policy in the colonial period was guided by the need for raw materials, whereas, in the latter phase, it was guided by 'commercial and industrial interests.[30']

Rao argues that the introduction of the Santhal Pargana Tenancy Act 1949 in Santhal Pargana was sought to protect Adivasi rights to land and resources but also contends that there has been a significant transfer of land through privately negotiated, temporary lease arrangements for stone quarrying and crushing from Adivasis to outside contractors[31]. The process has seriously impacted the lives of Adivasis as land alienation has become a common phenomenon.

Firdos[32] takes the case of the Birhor tribe of Jharkhand and evaluates the trajectory of change in the livelihood patterns of the community. He shows how the loss of forests and resources and the restrictions to the traditional sources of livelihood such as hunting, gathering, and rope-making have led to the dispersion of their population.

Mathew Areeparmpil argues displacement due to Mining in Jharkhand and discusses the impact of mining on the rights of Adivasis and the phenomena of 'Enslavement of Indigenous people.' He argues, *In the name of 'development' for national interest', the Jharkhand area is witnessing not development but the rape of the people and its natural wealth through a process of colonialist and capitalist exploitation...The large-scale capitalist exploitation of the wealth of Jharkhand requires a vast army of cheap casual labour. The Indigenous people who are reduced to destitution are forced to accept this role[33].*

Areeparmpil questions the development narrative and argues that unilateral developmental notions have only disregarded the Adivasi interests.

The section is developed to represent the present mode of being of Adivasis in the postcolonial set-up. It hints that the Adivasi mode of being is hanging between what is aspired for and what it is, particularly in the Fifth Scheduled Areas.

Narratives and the Pathalgadi Movement

During the peak of the movement, the Pathalgadi movement brings multiple narratives to the scene. These narratives can be broadly discussed in three categories: the anti-movement narrative, the pro-movement narrative, and the protagonists' voices. Though the section briefly discusses the narratives emerging from the movement, the study primarily locates the voice of the protagonist of the movement as well as incorporates the fact-finding reports in the process to analyse the underlying concerns of the movement.

The anti-movement narratives attempted to shake the very base of the movement by delegitimising the moral grounds of the movement itself. These attempts were made by government officials and some politicians. The anti-movement narrative resorted to the strategy of connecting the thread of the movement to the aspects commonly unacceptable to the larger society. This process of delegitimation not only limits the authority of the actors to stand for the cause but simultaneously distorts or completely falsifies the underlying discourse of the act. The anti-movement narrative in the course of delegitimisation put forward at least three allegations. The first attack was on the ground that the movement had strong links with the radical left. It was alleged that the entire movement was all about Naxalism and having a close connection with their ideology; even the then Union Minister of Tribal Affairs has called it a 'new strategy of Naxals.' It was alleged that the act was 'anti-national' and 'anti-constitutional' in its content and suggested that it was forged to destabilise the region[34].

Second, there were allegations about the cultivation of opium in large amounts in the villages. Several leaders and even the administrative officers alleged that the movement was nothing but an act to veil the illegal activities such as the production of opium in those areas.

Third, some politicians alleged that the Pathalgadi movement was fuelled by Christian missionaries. This argument presupposes that the movement was motivated by evil concerns and has no real cause. The anti-movement narrative also led to arrests and sedition acts against the leaders and unnamed supporters of the movement.

On the other hand, the pro-movement narrative managed to support the movement and accepted that the movement's claims had been, to some extent, particularly that the constitutional interpretations were exaggerated and oversimplified but treated as rightful assertions. The narrative focuses on the intermittent deprivation of Adivasi communities and their marginalisation in the socio-political space. Social activists Dayamani Barla share the view and criticises the Government for repression of Adivasis in the name of sedition charges. In an interview, she argues, 'How can writing a part of the constitution on stone be an unconstitutional and seditious act?[35]' She was concerned about the state's harsh action on the pathalgadi activists and the supporters, as approximately 10000 unnamed people were booked under the sedition act. Even the former Minister of State for Tribal Affairs and the chairperson of the National Commission for Scheduled Tribes, Dr Rameshwar Oraon, wrote a letter to the President regarding the repercussions of not following proper procedures while promulgating an ordinance by the State Government of Jharkhand[36].

Xaxa suggested that it has more to do with the continuous marginalisation of Adivasis and, more precisely, the case of land alienation, which has a colonial legacy as the process was institutionalised during the colonial rule in which the introduction of new land and revenue settlements infused the idea of private property was one instance that created trouble in tribal areas[37]. Some scholars view it as an identity assertion that emphasises an alternative agency of village governance for the devel-

opment and governance process[38], and few interpret it as a 'constitutional messianism[39].' There are variations in interpreting the Pathalgadi Movement among the scholars and activists, but more or less, there is general agreement among them that the movement has a deep relation with the continuous marginalisation of Adivasis, and the movement has larger implications in the socio-political space.

The third narrative primarily comes from the protagonists themselves, the leaders and the activists of the movement. This narrative is a claim the Pathalgadi movement put forward vis-a-vis the state, which refers to the rights of the community based on the idea of 'original inhabitants.' The activists of the movement articulated that their assertions were very much in consonance with the promises that the constitution had made to the community.

One of the prominent leaders of the Pathalgadi Movement, Joseph Purty. in an interview with News code executive Rakesh Kumar, explains how the pathalgadi movement is a legitimate assertion and very much in consonance with the constitutional aspirations and in no way violates the soul and spirit of the constitution[40]. However, interestingly, he not only refers to the rights and constitutional safeguards conferred to the community by the constitution of India but also simultaneously invokes the rights derived from Queen Victoria of England during colonial times.

Additionally, he mentions the colonial legacy of their rights in the form of provisions related to 'excluded' and 'partially excluded areas,' Wilkinson's rule (1837) for the Kolhan estate that legitimised the customary rights of Adivasis even in the criminal issues in Kolhan region after the Ho revolt in Kolhan region, The Chotanagpur Tenancy Act (1908), The Santhal Pargana Tenancy Act (1957) etc. Pointing out the negligence of central and state governments while dealing with the Adivasi issues and suggesting the control of Gram Sabhas over all the matters related to the Adivasis in their areas.

He further questions the intention of the then Government of Jharkhand and their policies regarding the Adivasi communities. He makes the point that the state is only interested in the resources of the Adivasi villages and does not heed their custom, language, tradition and way of being[41].

Following the customary practice of pathalgadi, Adivasis of different Gram Sabha started placing stone slabs painted green with the constitutional provisions and the PESA Act inscribed on them. Additionally, there are greenstone slabs inscribed 'India Non-Judicial.' However, there are contestations about the interpretation of the constitutional provisions and the provisions mentioned in the PESA. The Pathalgadi movement invokes multiple references to assert their claims, and sometimes the points of reference are contested.

Calling Adivasis the 'real owner of India, Purty makes one important distinction that he made in the process of assertion, which was a difference between the 'Judicial' and the 'Non-Judicial.' The categorisation, he maintains, is different from the normal use of these categories in a legal space. In common parlance, these

categories are used to define activities directly related to the court work or indirectly related to documentation purposes such as the power of attorney, rent agreement, affidavits, etc. Joseph Purty refers to this distinction in a quite vague manner. He makes the distinction to refer to all the systems of a modern state and its operation on the ground as 'judicial' and the practices, symbols, languages, customs and knowledge of Adivasi life as 'non-judicial.' In other words, all the systems that evolved naturally and are in harmony with the natural world are non-judicial, and the rest of the systems are merely imposed on him. His point was to show the discrimination against the Adivasi knowledge, customs, tradition and *Adivasiyat.*

In the process of making this assertion, he emphasised their connection with the 'Sati Pati Cult' of Gujrat led by AC Dada Kunwar Keshari Singh, 'AC' before the name signifies here Ante-Christ. This cult primarily prefers to remain aloof from the present system of governance. The cult believes that they possess some documents, such as the announcement of Queen Victoria, the Land Revenue Act, the Gandhi-Irwin Pact, etc., which not only acknowledge them as Indigenous people but also as real owners of Bharat. The idea of distinguishing between India Judicial and India Non-Judicial was influenced by this cult only, which was explained by Joseph Purty in his interviews.

Furthermore, in an interview, when an interviewer asked why the Gram Sabhas had decided to close the schools? He shows disappointment with the state and the then Chief Minister of Jharkhand, Raghubar Das, and argues, '*Under the Judicial system, our non-judicial system is not taught, Civics is being taught in colleges that is a study of democracy, nowhere our system is being taught.*[42]'

He further adds, '*because of this, be it children or old are mentally, intellectually and physically the slaves of the Judicial system. We need to come out from the chain of slavery. Therefore, why do not we impart our children the education of our traditional system*[43].'

The statement asserts the epistemic differences between the Adivasi and non-Adivasi social formations. it further asserts the process through which the Adivasi knowledge is systematically disregarded by the mainstream knowledge system. In this manner, Purty not only invokes indigeneity claims but also asserts fundamental problems with the mainstream society in conceptualising the Adivasis.

A fact-finding report in Pathalgadi villages found similar expressions by the end of villagers. The committee report mentions a villager in Birbanki says,

Adivasiyon ke dharam mein prakriti hai aur shasan vyvastha mein bhi prakriti hai. Hum Adivasi hain, humko Adivasi ke tarah hi manana chahiye (Nature is an integral part of *the Adivasi religion and governance system. We are Adivasis and we should be recognised as Adivasis*)[44]

Like Purty's argument, this villager also demarcates a separate boundary between the other administrative model and the model of administration from the viewpoint of Adivasis. whereas another person in the village, Bhandra contends,

Bhasha, sanskriti, jal, zameen ki loot ho rahi hai. Isliye apni

paramparaon ko bachane, fir shanti bahal karne ke liye gram sabha ki shakti ko jagane ki zarurat hai. Isi soch ke sath pathalgadi shuru ki gayi (Language, culture and natural resources are being looted. In the coming days, our generations will have to face more problems. So to save our traditions and to establish peace, it is important to strengthen the Gram Sabha. Pathalgadi was started with this thought)[45]

Similar to the statement made by Purty. First it remarks on the potential threats to Adivasi language, culture and customs, then it claims that the system of Adivasis exhibits different understanding.

There are multiple versions that a movement captures, and the actors have different interests. However, reading the voices of the protagonists makes it clear that the movement was not limited to the immediate cause; rather, it exhibits a problem at another level, which we may call the underlying cause. It not only questions the relative marginalisation of Adivasis but also emphasises epistemological differences. It further calls for an Adivasi knowledge system and alternative Adivasi polity such as Munda-Manki, Majhi-Parganait or Doklo-Sohor.

Conclusion

The movement surfaced as a challenge in front of the political institutions. Even after seventy years of independence in India, the Adivasis feel alienated from the institutions. Shah demonstrated in her ethnographic work how the Munda Adivasis were interested in 'keeping themselves away from the state.' Her work points out where the Munda Adivasis participated in the elections just to avoid state interference[46]. Further development of the paper analysed the movement at three levels: the ideological assertion of Adivasis in the region, the postcolonial interactions of the Adivasis with the state and the narratives articulated by the Adivasis.

Firstly, the region has historically shown ideological continuity in terms of the assertion of Adivasi identity. Though the language of assertion shifted over time, it still did not lose its ideological moorings. Secondly, at the level of postcolonial administration, the reports and the studies suggest that the aspirations of the Adivasis of the region are not met. Their mode of being is hanging between what is aspired and what it is.

Furthermore, the narratives emerging from the Pathalgadi movement itself have shown that along with the immediate concerns, the movement also carries underlying reasons that go beyond. It not only seeks to bring in the indigeneity discourse to lay claim on *Jal, Jungle aur Jameen* but also laid ideological contestations envisioned in the discourse of what Adivasi activists prefer to call *Adivasiyat*. It challenges epistemological superiority claims of non-Adivasis. Furthermore, it claims to revive Adivasi polity in the form of Munda-Manki, Doklo-Sohor or Majhi-Pargainait, taking the calls for slogans like *Abua Disum, Abua Raj* (our land, our governance). In this manner, the Pathalgadi movement needs to be looked beyond immediate concerns, having deep underlying concerns that it shares with the liberal model of governance. At one level, it seeks to assert and negotiate the Adivasi identity, and on the other level, it illustrates the limitation of the liberal framework in dealing with collective identities.

❐

References :

1. Das, Subhasis (2015).The Hagarhis of Jharkhand: A Brief Study of the Megaliths of Jharkhand.
2. RUIBAL, A.G (2014). *An Archaeology of Resistance: Materiality and Time in an African Border land*, Rowman & Littlefield, UK
3. Devalle, S.C (1989). *Discourses of Ethnicity:The Adivasis of Jharkhand*, PhD Thesis submitted to School of Oriental and African Studies University of London, p-294.
4. ibid.
5. "Brutal State Repression Against the Non-violent Pathalgadi movement." A fact finding report in Pathalgadi villages of Jharkhand by *Jharkhand Janadhikar Mahasabha* (JJM). *p*-1
6. Pandey P. (2017, 27 May). Tenancy Laws: Jharkhand Governor returns Bill, BJP leaders call for fresh strategy. The Indian Express. https://indianexpress.com/article/india/tenancy-laws-jharkhand-governor-returns-bill-bjp-leaders-call-for-fresh-strategy-4723622/lite/
7. Kiro, S.K.(2017, Aug 24). In Jharkhand, BJP Makes Thinly-Veiled Attempts to Shift Spotlight From Changes in Land Laws.The Wire. https://thewire.in/politics/jharkhand-religious-freedom-bill-tribes-cnt-spt
8. The Chotanagpur Tenancy Act, 1908 (provision 71-A)
9. Jitu Oraon v Commissioner, South Chotanagpur [1987]
10. Singh, Jeet. (2016 24 November). Tribal Protest and Government's Oppression over Proposed Amendment to Tenancy Laws. *RGICS Brief*.
11. Anwar, T. (2019 June 18). Jharkhand's Land Bank: Injustice to Adivasis Continues. NewsClick.https://www.newsclick.in/Jharkhand-Land-Bank-Adivasis-Tribes-Revenue-Land-Re forms
12. ibid.
13. ibid.
14. ibid.
15. R Krishna Das (2016, July 1). 'Jharkhand building land bank to woo industry,' Business Standard. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/jharkhand-building-land-bank-to-woo-industry-116070100023_1.html
16. Elwin, V. (2009). *A philosophy for NEFA*. Gyan Publishing House.
17. Dileep Singh Bhuria Commisson Report 2004, p. 42.
18. ibid. p-72
19. ibid. p-374
20. ibid. p-388
21. Xaxa Committee Report (2014). Ministry of Tribal Affairs GOI. pp.71-72
22. Chotanagpur Tenancy Act (2015). A Handbook on Tenancy Law in Jharkhand. *Human Rights Law Network*.
23. Choubey, K.N (2015, Feb 21). Enhancing PESA: The Unfinished Agenda. *Economic and Political Weekly*. VOL L NO 8 p-21
24. ibid. p-21
25. ibid. p-22
26. D.P Kindo and P.K Bhowmick (2019, June). Panchayati Raj in Scheduled Areas of Jharkhand and Natural Resource Management. *Jharkhand Journal of Development and Management Studies*. Ranchi. Vol. 17. No.2 p-8071
27. Ananth P & Kalaivanan,S. (2017). Grassroots governance in scheduled areas in India: The way forward of the PESA act. *International Journal of Innovative Research and Advanced Studies*. 4(1). 18-21
28. Bara. A.H. (2017). A critical inquiry of the rule of PESA in Jharkhand. SRSC Seminar Proceedings. Governance, Resources and Livelihoods of Adivasis in India: Implementation of PESA and FRA. *National Institute of Rural Development and Panchayati Raj*.

29. D.P Kindo and P.K Bhowmick (2019). Panchayati Raj in Scheduled Areas of Jharkhand and Natural Resource Management. *Jharkhand Journal of Development and Management Studies*. Ranchi. Vol. 17. No.2 p-8083
30. Guha,R. (2012). Forestry in British and Post-British India: A Historical Analysis. In Indra Munshi (ed.) *The Adivasi Question:Issues of Land, Forest and Livelihood* (pp.25-58) Hyderabad: Orient Blackswan Private Limited.
31. Rao, N. (2012). Displacement from Land: Case for Santhal Parganas. In Indra Munshi(ed.) *The Adivasi Question: Issues of Land, Forest and Livelihood* (pp.117-124) Hyderabad: Orient Blackswan Private Limited.
32. Sohel Firdos (2012). Forest Degradation, Changing Workforce Structure and Population Redistri bution: The Case of Birhors in Jharkhand. In Indra Munshi(ed.) *The Adivasi Question: Issues of Land, Forest and Livelihood* (pp.117-124), Hyderabad: Orient Blackswan Private Limited
33. A. Mathew. Displacement due to Mining in Jharkhand. In Indra Munshi(ed.) The Adivasi Ques tion: Issues of Land, Forest and Livelihood, Hyderabad: Orient Blackswan Private Limited.
34. Dutta, P.K(2018, Jun 27).” Pathalgadi Movement, a rebellion against government with opium taint”. India Today https://www.indiatoday.in/india/story/pathalgadi-movement-kjharkhand-kunti-1270963-2018-06-27
35. Sharma, Supriya(2019, Nov 2019). ‘’What sedition cases against 10,000 Adivasis in Jharkhand reveals about Indian democracy” Scroll.in https://scroll.in/article/944240/what-sedition-cases-aggainst-10000-adivasis-in jharkhand-reveals-about-indian-democracy
36. Dr. Rameshwar Oraon, wrote a letter to the President of India. Dated 01/08/2016
37. Xaxa, Virginius (2019). Is the Pathalgadi Movement in Tribal Areas Anti-constitutional. *Eco nomic and Political Weekly* Vol LIV No 1.
38. Singh, Anjana (2019). Many Faces of the Pathalgadi Movement in Jharkhand. *Economic and Political Weekly* Vol LIV No 11.
39. Sundar, Nandini (2018, May 16). Pathalgadi is nothing But Constitutional Messianism, So Why is the BJP Afraid of it?, The Wire. https://thewire.in/rights/pathalgadi-is-nothing-but-constitutional-messianism-so-why-is-the-bjp-afraid-of-it
40. Joseph Purty’s interview by Rakesh Kumar on the *News Code* channel, accessed in December 2020. https://youtu.be/oFov2RsLzLE
41. Ibid.
42. Joseph Purty’s interview on YouTube on *News Wing* was published on 3 Jul 2018 and accessed in December 2020. https://youtu.be/RLwrV4187ks.
43. Joseph Purty’s interview on YouTube on *News Wing* was published on 3 Jul 2018 and accessed in December 2020. https://youtu.be/RLwrV4187ks.
44. Jharkhand Janadhikar Mahasabha (2019). Brutal State Repression Against the Non-violent Pathalgadi Movement: Report of fact-finding inquiry in Pathalgadi villages of Jharkhand. *Jharkhand Janadhikar Mahasabha* (JJM). p-3. https://counterviewfiles.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/11/report-of-pathalgadi-factfinding-inquiry-english.pdf
45. Ibid. p-3
46. Shah, A. (2007). ‘Keeping the state away’: democracy, politics, and the state in India’s Jharkhand. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, *13*(1), 129-145.

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 142–154

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Emergence of Kanshiram and the Organisational Development in Dalit Politics

Babli
Ph.D. Scholar, Central University of Punjab, Bathinda (Punjab)-151401
Email ID- bgbabli1.bg@gmail.com

Abstract

Every newspaper, local to national, was filled with the news of new Dalit political wave some calling it Nili Andhi[1], some new era, or what exaggerative metaphor not. However, the aggressive and offensive slogans of the Bahujan Samaj Party (BSP) and its workers had already won political and academic criticism. But what compelled its founder, Kanshiram, to form a non-political organisation as an employees' federation and evolve his Bahujan movement from non-political to quasi-political to a political party? What was in the womb of two decades of journey of Kanshiram until the BSP was not formed ? Are the questions to answer in the making of Bahujan ideology, its movement and a political party. This paper will discuss comprehensively socio-political organisations of his time and his emergence as a craftsman of Bahujan organisations. This paper has been categorised into two sections where section one would discuss Ambedkar and his legacy in the form of organisations formed by him and his successors; organisations of Dalit and section two would talk about emergence of Kanshiram with instances which pushed him to introduce a 'cadre bas-mass base-broad base' organisation[2], Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti (DS-4) and the BSP a long with different phases of his life.

Keyword: Bahujan Politics, BAMCEF, Bahujan Movement, Mobilisation

Introduction

Bengal is noted as land of 'Indian Renaissance' but Maharashtra is a land of Dalit Renaissance. This place has given India its prominent Dalit leaders from Mahatma Phule to Babasaheb Ambedkar and has played crucial role in making Kanshiram a fierce Bahujan political leader whose ideas and strategies have shaped contemporary Dalit politics. Although 'Bahujan-Samaj' term was coined by Ma-

hatma Phule and frequently used by Dr. Ambedkar also, has become a decisive factor of today's Indian politics due to Kanshiram. Kanshiram's introduction to Dalit politics was a turning point in Indian politics, especially to Dalit politics of North India.

Discontented by contemporary social movements and the politics of Dalits, Kanshiram emerged as an unforgettable political leader of the late 20th Century. Although he never enjoyed any ministership during the three short-lived tenures of his party's government, he is valued more than any leader of his party due to his craftsmanship of the Bahujan movement. His life's journey can be divided into four phases; personal life until he resigned his job; life as a maker of social force until he launched DS-4; life as a political craftsman; and later days of dependence and helplessness. But this paper only discusses the major reasons which compelled Kanshiram to establish another socio-political organisation where many prominent Dalit organisations were already working for their people and gradual development of his socio-political organisations parallel to other Dalit organisations.

Some studies have already discussed briefly about Kanshiram's political journey that Dinabhana's case at Explosive Research and Development Laboratory (ERDL), Pune, introduced him to caste discrimination and its reality; his introduction to Ambedkar's writings and Dalit literature; his discontentment from Dalit leaders and the Republican Party of India (RPI); his alienation from his family and relatives; and so on (Singh, 1994; Pai, 2001; Dubey, 2001; Narayan, 2014; Teltumbde, 2019 and Sarkar, 2021).

His followers use to address him fondly as Saheb or Manyawar, and he was also generally considered to be 'the messiah of the oppressed'[3]. He was born on 15th March, 1934 in a Ramdasia Sikh (converted from scheduled caste) family in Khawaspur village of Ropar district in Punjab[4]. He was fortunate enough to get an education and, later, employment in the government sector. In 1958, after his degree, Kanshiram took up a job as researcher in the Explosive Research and Development Laboratory (ERDL), an ammunitions factory in Pune. Kanshiram, who grew up in a protected military environment and as a follower of Sikhism, a religion that preaches egalitarianism, had little experience of the oppressive nature of the caste system and the suffering of Dalits as untouchables. It was in Pune that he was exposed for the first time to the stark realities of caste, which shocked him and then there was no comeback. He himself admitted it and also that only there he came across with the books and ideas of Dr B R Ambedkar (Singh, 1994, P. 8-9; Pai, 2002, P. 87; Teltumbde, 2006, P. 4531; Narayan, 2014 and Jaffrelot, 2003, p. 35).

Kanshiram, a worker in the ERDL, encountered an instance of cultural hegemony in 1965, which changed his life and the course of the Dalit movement and politics in contemporary India. The ERDL cancelled two holidays to celebrate Baba Saheb Ambedkar and Gautama Buddha, instead sanctioning a holiday on Tilak's birthday and adding one more day to Diwali holidays. A class forth worker named Dinabhana lost his job due his disagreement with the cancellation of these holidays.

Despite Ambedkarite organizations in Maharashtra, no Dalit organization addressed this issue. However, Kanshiram, fueled by his outrage, supported Dinabhana and filed a case against his suspension. The court ruling revoked Dinabhana's suspension and reinstated holidays, affecting Kanshiram and other Dalit employees. This incident prompted the need for a robust Dalit organization to challenge upper-caste authorities in the ERDL. Kanshiram and his colleagues joined various Dalit organizations in Maharashtra, such as the People's Education Society and Buddha Club even the RPI (Singh, 1994, p. 8; Pai, 2002, 87 and Gundimeda, 2015, p. 85). However, he did not find them eligible to transform Indian politics.

Dr. Ambedkar and his socio-political organisations

Kanshiram, several times, claimed that his views about Dalit and Bahujan Samaj evolved due to Dr. Ambedkar's writings. He had always asked his supporters to follow Ambedkar's ideas and pay back to the society which they have got due to Dr. Ambedkar's efforts. To teach about Ambedkar's ideas and his mission, 'Ambedkar Mela on Wheels' were organised in nine states surrounding Delhi/NCR from 14th April to 14th June 1980 (The Oppressed Indian, May, June and July, 1980). Therefore, Dr. Ambedkar and his ideology was centre of Kanshiram's movement.

The Dalit movements of the early 20th century formed in different locations with the objective of increasing knowledge about human rights and advocating for government concessions to ameliorate socio-economic conditions. Dr. B.R. Ambedkar, himself from a military Mahar nobility, played a crucial role in consolidating these regional movements into a nationwide Dalit movement. His personal experiences of caste prejudice, such as being humiliated as a scholar and professor, motivated him to engage in rational analysis and ultimately led to the Dalit movement becoming a powerful political force (Teltumbde, 2019, p. 68-70).

Ambedkar, as a prominent Dalit leader, gained recognition for his advocacy for Dalit rights through his involvement in franchise reforms. He founded the Bahishkrut Hitkarini Sabha in 1924, leading to his first mass struggle in Mahad. Ambedkar's principles of non-violence and socio-cultural struggles emerged during this period. He was dissatisfied with Mahad and focused on political solutions, participating in the Simon Commission and Round Table Conferences. This led to the Communal Award in 1932, granting reserved seats and separate Dalit electorates (Ibid, p. 70-73). Unfortunately, due to Poona Pact, signed by M. K. Gandhi and Dr. Ambedkar, it could not become a reality for his Dalit brethren. Later, Ambedkar's early struggles laid the groundwork for his later role in shaping Dalit political consciousness.

Sarkar (2020) emphasises the Poona Pact as a pivotal moment in Ambedkar's political trajectory, as it prompted him to redirect his attention toward the organisation of political activities and electoral strategies. His objective was to empower the marginalised social groups by ensuring their access to government positions and lobbying for symbolic representation in political matters. Ambedkar believed that

governmental authority is crucial for societal acknowledgment and placed great emphasis on the significance of education, mobilisation, and consciousness-raising among marginalised communities (Sarkar, 2021, p. 21).

Consequently, Ambedkar founded the Independent Labour Party (ILP) in 1936 as a response to his disappointment with the Poona Pact. The ILP gained popularity among not just the Mahars but also other groups, and it successfully won 14 seats in the Bombay Legislative Council. The ILP prioritised class-based changes, organising large-scale protests against Khoti landlordism and pushing for the rights of workers. Ambedkar's attempts to create a coalition against Congress that opposed feudalism and the caste system were mostly symbolic and focused mostly on Dalits, namely the Mahars (Omvedt, 1994, p. 190 and Teltumbde, 2019, p. 74-76).

Although the ILP managed to get Scheduled Caste seats in the Bombay Presidency, its election result highlighted the lack of power and influence of the minority group. Ambedkar conceived the ILP as a political forum to establish a central support base for Dalits and to create a coalition with other economically disadvantaged groups in society. Nevertheless, its influence underscored the difficulties of minority representation and the intricacy of tackling socio-economic disparities through electoral politics (Sarkar, 2021, p. 22).

The outbreak of World War II brought strategic shifts, leading Ambedkar to extract concessions for Dalits from the British. However, the Cripps Mission's failure to address Dalit demands prompted Ambedkar to return to caste politics. Dissolving the ILP, he formed the Scheduled Castes Federation (SCF) and demanded separate identity, reservations, and safeguards for Dalits during the Nagpur Conference in 1942. Ambedkar's subsequent role in the viceroy's executive council marked both progressive legislations and listless performance by the SCF. As Britain decided to withdraw from India, Ambedkar's protests against the Cabinet Mission Plan in 1946 highlighted his relentless pursuit of Dalit rights, demanding inclusion as a minority (Teltumbde, 2019, p. 77-78).

These developments in Ambedkar's movements led the foundation for present day Dalit politics and identity formation. After Ambedkar, many Dalit organisations emerged based on his ideology but few of them remained popular from Maharashtra such as RPI and Dalit Panthers. Later on, in 1970s, Kanshiram's the All India Backward (S. C. S. T., OBC) and Minority Communities Employees Federation (BAMCEF) which was also originated in Maharashtra, became popular across the country.

Post-Ambedkar Dalit organisations and Kanshiram's Resentment

Republican Party of India

The Republican Party of India (RPI) was established by the post-Ambedkar leadership in independent India on October 3, 1957, succeeding the All India Scheduled Castes Federation (AISCF). After Ambedkar's death, the group's members were mostly restricted to Bombay and transitioned towards establishing a diverse

political party that could collaborate with other political parties. However, they knew that other groups were not attempting to rally the Dalits and get their backing. The Congress rejected the AISCF's communitarian policy, which mobilized Dalits by co-opting local notables in each district instead of rallying them as a community (Duncan, 1979, p. 229).

Due to reserved seats granted in the Poona Pact, Ambedkar knew that Dalit candidates could not win solely without depending on other caste voters. He saw clear defeat in the 1951-52 general elections and concluded that it was essential to establish coalitions with other political parties and social groupings. To achieve this goal, it was necessary to discontinue the current SCF and establish a new political party with a wider scope than that of the SCF (Gundimeda, 2015, p. 60 and Teltumbde, 2019, p. 88).

In October 1956, Ambedkar contemplated forming a non-communist opposition party, consulting leaders like Lohia and Joshi. In a September 30, 1956 SCF committee meeting chaired by Ambedkar, they decided to dissolve the SCF and establish the Republican Party of India (RPI) (Teltumbde, 2021, p. 89). Ambedkar focused on empowering Dalits independently and forming strong connections with non-Brahmans, Shudras, laborers, and peasants during his political career (Omvedt, 2000, p. 113-40). The primary goal of the new party was to unite lower-caste communities as a 'federation of oppressed populations' who faced discrimination due to their inherited social position (Jaffrelot, 2005, p. 87).

Unfortunately, Ambedkar's death and impending elections hindered its implementation. The 1957 elections were fought under the SCF banner, winning eight Lok Sabha seats, with significant contributions from Bombay. The SCF's alliance with the Samyukta Maharashtra Samiti (SMS) in Bombay yielded electoral success with five seats in Lok Sabha, 15 seats in the Legislative Assembly, and notable victories in municipal corporation elections (Teltumbde, 2019, p. 89).

In April 1957, the SCF working committee decided to convene a general meeting to establish a new party as per Ambedkar's wishes. At the All India Bouddha Mahasabha conference on October 3, 1957, a committee was elected to frame the RPI's constitution. Reflecting Ambedkar's vision, the RPI's constitution was adopted in March 1959, emphasizing the emancipation of the oppressed. The party aimed to form a broad alliance, focusing on socio-economic issues (Ibid, p. 89-90).

Despite its promising start, internal conflicts among ambitious and egotistical leaders led to the fragmentation of the RPI. The power struggle began immediately after Dr. Ambedkar's cremation and culminated in separate conferences in Nagpur and Aurangabad in 1959. The formal split occurred on May 14, 1959, between groups led by B. C. Kamble and B. D. Gaikwad (Teltumbde, 2019, p. 90-91).

Moreover, in Uttar Pradesh for a short time, the RPI was a minor political party, facing challenges related to organization and finances. In the 1962 and 1967 elections, the Party won 10 seats and around 4% of the votes. However, its success declined to only two seats in 1969, with 3.5% of the votes. The RPI established an

electoral alliance with Muslim groups in four districts of western UP, but struggled in Maharashtra but gained traction in Uttar Pradesh, Punjab, Andhra Pradesh, and Karnataka (Brass, 1983, P. 239, 263-66 and 288).

However, in the 1962 elections, the RPI struggled in Maharashtra but gained traction in Uttar Pradesh, Punjab, Andhra Pradesh, and Karnataka. Its Uttar Pradesh success, attributed to B. P. Maurya's leadership, waned post the 1969 Congress split. By 1971, Maurya joined Congress, marking the RPI's decline in Uttar Pradesh (Yadav, 2011, 1370).

Thus, these splits and mergers of the RPI restricted it to a Dalit party, dominated by Mahars in Maharashtra and Jatavs in Uttar Pradesh, which could not fulfil Dr. Ambedkar's mission to unite all the exploited and oppressed communities of the country. Kanshiram had already understood that this party could not go long way. Hence, he did not invest much time in the party, although in the programmes of BAMCEF and DS-4 he used to invite members of the RPI.

Dalit Panthers

Dalit literature in India embodies a call for revolt against oppression, advocating for a dignified life. The movement's ideological diversity, including Marxism and internationalist perspectives, led to a split within the Panther organization (Gokhale-Turner, 1979, P. 84 and Murugkar, 1991, p. 73-96). The Panther organization emerged in the early 1970s, drawing inspiration from the American Black Panthers and mobilizing the Mahar community. They pursued an independent, mass-based political movement, employing confrontational tactics like demonstrations and strikes (Gokhale-Turner, 1979; Murugkar, 1991; Pai, 2002; Teltumbde, 2019, P. 96-99; Kumar, 2006, P. 37-38; Sarkar, 2021). P. 32-33.

The Dalit Panthers made a significant literary and cultural impact, pioneering a protest literature that transcended caste boundaries. Their works expressed the struggles and aspirations of India's exploited classes, diverging from bourgeois Marathi literature to amplify the voices of the marginalized through street vernacular (Murugkar, 1991, p. 77).

The Dalit Panther organization operated with a flexible and ad-hoc management style, characterized by decentralized chhavanies operating somewhat autonomously under the Panther name. Communication relied on informal channels, and membership estimates fluctuated, leading to ideological inconsistency and susceptibility to external influences. Financial irregularities further undermined organizational stability (Murugkar, 1991, p. 65-72).

Thence, the Dalit Panther movement's early collapse can be attributed to several factors. Leadership, characterized by youthfulness and lack of political experience, faced challenges in understanding the complexities of the social context and defining clear revolutionary goals. Personal interests often took precedence over the broader goals of the movement, resulting in factionalism and a deterioration of leadership quality. Additionally, the leaders' literary backgrounds clashed with

the movement's objectives, and their lack of pragmatism hindered effective engagement with progressive elements.

Externally, perceptions of the Panthers varied, with some viewing them as symbols of hope for the oppressed while others dismissed them as extremists or criminals. Despite initial enthusiasm, the movement struggled to sustain its momentum due to internal divisions, ideological confusion, and a failure to effectively mobilize rural Dalits. Hence, the Dalit Panther movement's collapse underscores the challenges of sustaining grassroots movements amidst societal complexities and political dynamics.

Kanshiram discusses the emergence and subsequent fragmentation of Dalit Panthers, attributing its decline to divisions into six groups, lack of focused leadership, and an ineffective organizational structure. He argues that an inept Dalit political leadership, lacking a credible organization, cannot challenge the pervasive influence of the upper caste ruling Brahminic ideology.

Moreover, Kanshiram also never associated himself with the communist movement and always criticised their actions as follows;

"They keep talking about change but work for status quo. The BJP is better, they never talk about change. So people never feel duped." *Illustrated Weekly, March 8, 1987.*

"The communists have been saying all along that they are for revolution, but when will they bring it about? Seventy years are not sufficient for them. We will do it in seven months. Actually, they are blocking the path of revolution." *The Telegraph, 3.12.1989*

"No party except the BSP want to change the political status quo. The "left' is also no exception and has even stopped reciting their old slogan "Dharti bant ke rahegi" (Land will definitely be divided amongst all people)." *The Telegraph 16.3.1991*

"We think the communists are snakes in the grass." *Current, 19.1.1991*

"They are also a Brahminical force. They are perhaps worse than the others because they (Communists) profess to work for change and yet work only for the status quo. All communist parties are dominated by Brahmins and Thakurs. When I decide to got to West Bengal, they will be in the Bay of Bengal." *The Telegraph, 28.4.1987*

"Our party has nothing in common with the Leftist who cheated the people. Their true colour came out in the open when they declared the 'Raja' and other feudal elements as the real proletariat of India and gave him their full-blooded support. They declared that they were in favour of dictatorship of such a proletariat. Our proletariat comprise the have-nots." *Sunday Mail, 26.8.1990*

"What relevance do they (Communist Party) have when they ignore the biggest reality in Indian Society, Caste?" (Rajan, 1994, p. 41-42.)]

In contrast to all the organisations of his time, he was not in the favour of a "reactive" organisation because his major focus was to develop a kind of organisation which could provide organisational support for a later political thrust. Although there was a strong Dalit base of his organisations yet he was always in favour of including backward classes and minority communities which is also reflected in the name of his first such organisation-BAMCEF. DS-4 was a denunciation of Poona pact which marked 50 years of discrimination and misleading of Dalits by the Congress. It is called "limited political action" due to its trial of electoral participation in few parts of north Indian states such as they put up forty-six candidates in Haryana assembly elections in 1982. (The Oppressed Indian, June 1982).

Birth of BAMCEF

Disillusioned with existing Dalit political parties, Kanshiram and associates founded BAMCEF in 1973 to promote Ambedkar and Phule's ideals. It aimed to combat caste discrimination in civil services and was officially inaugurated in 1978. Establishing a base in Delhi in 1976 facilitated expansion across Punjab, Haryana, UP, and MP. Despite efforts, OBC representation remained limited. BAMCEF primarily served marginalized and oppressed sections, predominantly comprising Dalits, with attempts to include OBC members, albeit with limited success.

Although today BAMCEF has its many splinters, especially working in Maharashtra yet, only Waman Meshram's BAMCEF actively works at the pan India level, but it is also limited to a small chunk of supporters and its website. He has also formed a political party named 'Bahujan Mukti Party' to combat Brahminical ideology and establish Bahujan Samaj. Today, as they claim, they have formed around a hundred offshoot organisations for different groups of Bahujan communities across the country to overcome their issues. However, his movement and political party did not get any mass recognition so far. Although he tries working on the same ideology that Kanshiram worked on, he is unable to mobilise the masses. But Kanshiram's BAMCEF was meant to be the entire base or backbone of his Bahujan movement.

BAMCEF was an acronym used for 'The All India Backward (S. C. S. T., OBC) and Minority Communities Employees Federation, Delhi' (BAMCEF). It limits minorities to Muslims, Christians, Sikhs, Budhists and Parses only. Its basic objective was to organise educated employees of backward and minority communities for 'pay back to the oppressed and exploited society' to which they belong .(Ram, 1981, p. 4)

BAMCEF is a non-governmental organization founded in 1978 to empower oppressed communities, including SC, ST, OBC, and minorities, through educated employees. The organization aims to combat societal indifference and promote collective action to safeguard rights and interests among marginalized groups. BAMCEF was born out of disillusionment with the failure of elite leaders and educated employees to uplift the oppressed and exploited, reflecting Dr. B.R. Ambedkar's social responsibility. (Ibid, p. 4-10).

BAMCEF's structure is tailored to serve the oppressed and exploited society

and achieve its objectives. It comprises ten major organs, including a mass-based framework, secretariat, organizational setup, network of offices, BAMCEF Brotherhood, BAMCEF Adoption, Medical Aid and Advice, Literary Wing, Probing Wing, and BAMCEF Volunteer Force (BVF). Each organ serves a specific purpose within BAMCEF's mission of empowering the oppressed and exploited sections of society. (Ibid, p. 11-12).

Operating the complex structure of BAMCEF requires a deep understanding of its various organs and their interrelationships. Cadre Camps are designed to provide this understanding, ensuring lower-level functionaries grasp the organizational framework while higher-level functionaries gain comprehensive knowledge. Knowledge of relevant rules, regulations, and budgets is crucial for navigating the structure and engaging relevant authorities through BAMCEF's organs. (Ibid, p. 22-24).

BAMCEF must maintain a non-agitational and non-political stance due to legal restrictions, drawing inspiration from Babasaheb Dr. B. R. Ambedkar who emphasized the importance of political power for social progress. With only 1.5% of the marginalized communities being educated employees, BAMCEF's role is crucial in strengthening these roots, leading to eventual political and agitational success. (Ibid, p. 25-31).

Kanshi Ram's shift to electoral politics was an unexpected development for many associates, who initially perceived BAMCEF as a mere strategic move. After learning from the downfall of the RPI, he recognized the importance of mobilizing resources and instilling confidence within the Dalit community. BAMCEF initially served the purpose of tapping into the untapped potential of Dalit employees in government and public sector undertakings. With a robust organization and accumulated resources, Kanshiram ventured into active politics through DS4 as an interim step before launching the Bahujan Samaj Party (BSP), showcasing adept electoral strategies (Teltumbde, 2019, 154). Since BAMCEF was an employees' federation, its members could not actively participate in political activities. Hence, DS-4 was launched to test the political grounds.

Dalit Shoshit Samaj Sangharsh Samiti (DS-4)

"I started with the idea of social transformation and economic emancipation. I still want my people (Dalits) to advance socially and economically. But I have realized that unless we have political clout, we cannot advance much on those sides." (Kanshiram cited in Jaffrelot, 2003)

BAMCEF, led by Kanshiram, has long advocated for political empowerment of oppressed Indians. However, the organization's focus on educated Dalits is insufficient. To address broader engagement, particularly in rural areas where caste-based oppression persists, BAMCEF established the Dalit Shoshit Samaj Sangharsha Samiti (DS-4) in 1981. DS4 excluded government employees from its membership, targeting ordinary Dalits with an annual membership fee of Rs 3. DS-4 activists highlighted societal caste divisions and the need for equitable political power distri-

bution, resonated with lower caste individuals, and facilitated unity (Narayan, 2014, P. 53 and Singh, 1994, P.91).

The DS-4 comprised ten wings, including Jagriti (Awareness), Mahila (Women's), and Chhatra (Students'), which organized cycle rallies in 1983–84 to mobilize people in the countryside. These rallies attracted nearly three lakh DS4 activists, who chanted slogans, sang songs, and electrified Dalit communities, especially in states like UP, Bihar, and Haryana. DS-4 rejected official terms like 'backward class' and embraced politicized labels like 'Dalit' and 'shoshit', aiming to mobilize a broad spectrum of Dalits towards a socially secure Bahujan Samaj (Narayan, 2014, p. 53-54).

Kanshiram felt the need for a more politically oriented body and established DS4 on December 6, 1981, with a focus on political activities surpassing those of BAMCEF. The rallies received extensive media coverage, enhancing Kanshiram's popularity. He leveraged his newfound hero status to address numerous gatherings, setting conditions like no four-wheelers within a five-kilometer radius and demanding Rs 12,000 and 12,000 people to present at the rally. Before formally launching the Bahujan Samaj Party (BSP) in 1984, Kanshiram tested the political waters by contesting the Haryana assembly elections through DS4 in 1982. Although DS4 secured 1.11% of the total votes (47,499 votes), Kanshiram considered it a success and declared DS-4's readiness to form a national party for Dalits by June 30, 1983.

DS4 also focused on social initiatives, such as curbing alcohol consumption in Dalit hamlets, which paved the way for the eventual establishment of the BSP in 1984. The legacy of DS4 persists as the Dalits in Uttar Pradesh owe their self-awareness to the organization, fuelling their political rebellion against upper-caste oppression after the emergence of the BSP (Narayan, 2014 and Kumar, 2006, p 121-23). DS-4 ran various programmes for the cultural and political mobilisation of the Bahujan. However, DS-4 was launched for two purposes, first to mobilise Bahujan community to form a political force against the Congress and second was to test the political grounds through filling candidature on limited constituencies of Delhi and its surrounding states to know whether conditions are in favour of lunching a political party or not.

The Bahujan Samaj Party

'Bahujan Samaj Party of Kanshiram is an absolute example of Dalit political assertion' (Omvedt, 1994, p. 152). The Bahujan Samaj Party (BSP) is an anti-party that represents Dalit and low-caste communities in India. Described as an "anti-party," it rejects traditional affiliations, ideological frameworks, and political positioning. The BSP evaluates other parties solely based on their commitment to dismantling the caste system, embodying characteristics of a "new social movement" with a modern outlook. Despite its vague rhetoric and absence of a clear ideology, the BSP exhibits an anti-systemic, left-leaning orientation. The BSP's emphasis on uniting the marginalized majority opens avenues for dialogue (Omvedt, 1994, P. 167-168).

By establishing the Bahujan Samaj Party, Kanshiram provided a common nomenclature for Dalit (SCs and STs), OBCs, and Minorities termed as "Bahujan." He accepts the 'Aryan' theory of Jyotiba Phule to mobilize 'Adi-Hindus' or non-upper castes (Kumar, 2006, 129).

The BAMCEF was a non-political organization that raised money to run the BSP after its inception in 1984, covering monthly expenditures that ran up to nearly one crore rupees. Many of the BSP members were also BAMCEF members, and several political leaders of the BSP, including Mayawati, were initially members of BAMCEF and fulfilled their political aspirations through the party. BAMCEF was also involved in the functioning of the BSP in its early and formative years, helping to maintain its accounts and decide the political strategy of the party at the local level.

Differences came up between the BSP and BAMCEF, especially over the role of Kanshiram who remained president of the latter. Eventually, in the 1990s, there was a split in the organization.

Thousands of people, including Mayawati, joined the movement, putting their youth at stake and joining BAMCEF, DS4, and eventually the BSP. Kanshiram was looking for a Dalit with local credentials, preferably from the Chamar sub-caste, who could carry forward his movement in UP. Mayawati was deeply involved in radical Dalit politics since her early youth and was impressed by her feistiness and excellent oratorical skills (Narayan, 2014, p. 58-59).

Formation of the BSP was a new phase in Dalit politics which shaped contemporary Indian politics. Before the unfortunate demise of Kanshiram, party had become decisive force in Uttar Pradesh and formed its government thrice through the post-election coalitions. Moreover, it gained absolute majority in Uttar Pradesh assembly elections of 2007. Although, it gained tremendous support in north Indian states such as Madhya Pradesh, Haryana, Punjab and exclusively in Uttar Pradesh yet it could not become a national force which could form government at central level.

Conclusion

In this paper, the organisational development of Dalit-Bahujan organizations, including of organisations formed by Dr. Ambedkar and his successors after him have been discussed. A review of this development is important for evaluating the reasons for the emergence of Kanshiram and his Bahujan movement and politics. Case of Dinabhana at ERDL and influence of Dr. Ambedkar's work and writings and Ambedkarite movement of Maharashtra which helped Kanshiram to understand social, political and economic conditions of Dalits and Bahujan influenced Kanshiram to work for these communities. However, his urge to form an employees' federation and eventually a political party was influenced by several reasons as discussed below.

If start with Dr. Ambedkar and his successors, there can be find a contrast. On the one hand, Dr. Ambedkar was liberal and progressive socio-political thinker

which can be traced by transformation in his ideology and development of his socio-political organisations. His ideological affiliation grew from 'Marxism' to 'Budhism' and his socio-political organisations evolved from 'Bahishkrit Hitkarini Sabha' to 'Republican Party of India' through 'Independent Labour Party' and 'Scheduled Caste Federation'. His literary work also resembles this evolution. Moreover, his publication ideas from 'Mooknayak' to 'Prabudh Bharat' magazine also shows his transformational journey. However, post-Ambedkar Dalit organisations could only split into several factions instead of their evolution, the RPI and the Dalit Panthers are such examples. As a result, this phenomenon weakened the Dalit movement and helped in falling prey of capable Dalit leaders in the hands of the Congress which ultimately led to emergence of the *Chamcha* age. On the other hand, Dalit and backward movements and riots kept sprouting for small period of time at different places but they were limited to particular caste and region only.

Moreover, the communist and Maoist movement also remained stick to the conventional "Class struggle" theory and could not transform themselves to the reality of caste in Indian society. In addition to it, the Adivasi movement of Jharkhand remained limited to the Jharkhand movement only instead of spreading itself to Adivasi movement in other regions too.

Additionally, instead of having sizable population of Bahujan in North Indian states, it did not have a reliable socio-political organisation which could address their issues.

Hence, all these factors contributed in emergence of Kanshiram and evolution of Bahujan movement and politics in the form of all political and non-political organisations founded by him. Kanshiram's ideology grew from working for Dalits to Bahujan. His idea of Bahujan Samaj had a capacity to change Indian politics upside down but making of Bahujan Samaj needed a cultural revolution along with socio-political developments to unite the entire Bahujan community.

❐

Notes:

1. *Deshbandhu, Rewa, 2nd December 1993 "Matpetiyon se Nikli 'Nili Andhi'" on unexpected win ning of two seats by the BSP which was equal to the Congress and BJP, compelled its author to term it as 'Nili Andhi.'*
2. *Omvedt, 1994, in K L Sharma and M. T. Borkar, a senior ex cadre of BAMCEF, worker of DS-4 & BSP, retired RMS officer. Interviewed at his resident in Nagpur in October, 2023.*
3. *Ambeth Rajan (Former Rajya Sabha MP of the BSP), told that his people considered him their Messiah and Mr. Rajan himself wrote a biographical booklet about Kanshiram named as "New Messiah" which he presented to Kanshiram after seeing that, Kanshiram laughed and then said on serious note that 'I am not a Messiah, I can not take that title because I only want to work for my people' hence, he suggested 'New Hope' as a title of that booklet. In a conversation with Ambeth Rajan at Teen Murti, Delhi.*
4. *'I am a Ramdasi-a scheduled caste group which is largest in Punjab; we have been contributing the maximum number of soldiers to the Indian Army. (Blitz, 18th Jun, 1988) cited in Omvedt (1994); Pai (2002). P. 86; Dubey, 2001, p. 291.; Rajan (1994). p. 55; Singh, R. K. (1994). P. 8; Pai, Sudha*

(2002). P. 86; Teltumbde, Anand (2006). P. 4531; Narayan, Badri (2014). P.; Gundimeda, Sambaiah (2015). P. 84; Jodhka, S. S. (2021). Kanshi Ram and the Making of Dalit Political Agency Leader ship Legacies and the Politics of Hissedari. Economic and Political Weekly, 56, 35–41.

References :

Brass, P. R. (1983). Caste, Faction, and Party in Indian Politics: Faction and Party. Vol. 1. New Delhi: Chanakya Publications.

Dubey, A. K. (2001). 'Anatomy of a Dalit Power Player: A Study of Kanshiram', in Ghanshyam Shah (ed.). Dalit Identity and Politics, Sage Publication, New Delhi, p. 288-310.

Duncan, R. I. (1979). Levels, the communication of programmes, and sectional strategies in Indian politics, with reference to the Bharatiya Kranti Dal and the republican party of India in Uttar Pradesh State and Aligarh district (UP). Ph.D. Thesis submitted to University of Sussex.

Gokhale?Turner, J. B. (1979). The Dalit panthers and the radicalisation of the untouchables. Journal of Commonwealth & Comparative Politics, 17(1), 77-93.

Gundimeda, Sambaiah (2015). Dalit politics in contemporary India. Routledge India.

Jaffrelot, Christophe (2003). India's silent revolution: the rise of the lower castes in North India. Orient Blackswan.

Jodhka, S. S. (2021). Kanshi Ram and the Making of Dalit Political Agency Leadership Legacies and the Politics of Hissedari. Economic and Political Weekly, 56, 35–41.

Kumar, Vivek (2006). India's Roaring Revolution: Dalit Assertion and New Horizons, Gagandeep Publication.

Murugkar, Lata (1991). Dalit Panther movement in Maharashtra: A sociological appraisal. Sangam Books.

Narayan, Badri (2014). Kanshiram: leader of the Dalits. Penguin UK.

Omvedt, Gail (1994). Kanshi Ram and the Bahujan Samaj Party, in Sharma, K. L. (ed.). Caste and Class in India, Jaipur: Rawat Publications. p.152-69.

Omvedt, Gail. (1994). Dalits and the democratic revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit move ment in colonial India. Sage Publication.

Pai, Sudha (2002). Dalit assertion and the unfinished democratic revolution: The Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh. Sage Publications.

Yadav, Pradeep Kumar (2011, January). Dalit movement and Republican Party of India: A case study of political emancipation of dalits in Uttar Pradesh. In Proceedings of the Indian History Congress (Vol. 72, pp. 1368-1376). Indian History Congress.

Ram, Kanshi (1981). An Introduction to BAMCEF, Third National Convention, Chandigarh, 14th October, 1981.

Ram, Kanshi (1982). The Chamcha Age: An Era of the Stooges. New Delhi.

Rajan, Ambeth (1994). My Bahujan Samaj Party. ABCDE Publications.

Sarkar, Jayabrata (2021). Politics as Social Text in India: The Bahujan Samaj Party in Uttar Pradesh. Routledge India.

Singh, R. K. (1994). Kanshiram aur BSP: Dalit Aandolan ka Vaicharik Aadhar Brahminvaad Virodh. Allahabad: Kushwaha Book Distributors.

Teltumbde, Anand (2006). An Enigma Called Kanshi Ram. Economic and Political Weekly, 4531-4532.

Teltumbde, Anand (2020). Dalits: Past, present and future. Routledge India.

The Oppressed Indian (1979-1983), Several Editions.

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 155–168

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Social and Economical Impact of Post Liberalization Reforms of the Civil Aviation Sector of India

Dr. Lalee Sharma
Assistant Professor, Department of Commerce,
Govt V.Y.T. PG. Autonomus College, Durg, (C.G.).
E-mail: sharmalalee@gmail.com Mob. 9425564230

Dr. Smita Barge
Assistant Professor, Department of Commerce, Govt. Naveen College,
Gudhiyari, Raipur, (C.G.).

Abstract:

The Indian government has taken major steps towards privatization and liberalization of the Civil Aviation sector since 1991. As a result, this sector has made tremendous progress by adopting advanced technology and allowing the participation of private Civil Aviation operators. The present study highlights the current scenario of Indian Civil Aviation sector and examines its growth in the last two decades from 2010-11 to 2021-22. For the study, secondary data is used from various sources and descriptive statistical tools are used for the analysis- annual growth rates, compound annual growth rates and percentage shares. The civil aviation sector makes so many positive effects of the society by creating jobs, simulating trades, improving connectivity, promoting tourism, supporting international trade and so on. So this study this study not only included the growth of the civil aviation but also includes the social effect of the industry. The study concludes that the growth and structure of Civil Aviation in India on various aspects such as Scheduled , public & private service providers in both domestic and International areas, number of passenger , cargo. The share of the public sector has come down, while the share of the private sector has increased remarkably. It is recommended that the Indian government should make the regulatory and policy framework more adaptable to the fast-changing needs of the Civil Aviation sector where as post liberalization effect of the industry indicates low fare, increased routes, job creation, attracting investment, controlling regional imbalance, improving infrastructure facility, enhancing cultural awareness etc.

Key Words- Civil Aviation Sector, Privatization, Scheduled Aviation, Social Effect.

1. Introduction of Civil aviation sector

1.1 Civil Aviation : Aviation Industry Includes toe major categories Called Military and non military or civil aviation. According to Cambridge Dictionary the definition of civil aviation is "Flight and aircraft used for personal and business purpose , such as transporting goods or passengers, rather then for military purpose. "

Civil aviation sector is essential for the progress of local as well as global aviation facilities. The important factors are as follows:

1. It provides high speed network for global business.
2. It creates jobs for the unemployed enthusiastic youth.
3. It supports international trade and tourism.
4. It provides medical and foods services in emergency time.
5. It provides air services in critically geographical areas where other means of transports cant approach the destination.
6. It has three main categories scheduled air transport services, Non scheduled air transport services and Air cargo services.

   In this paper our main focus is on scheduled air transport services .

Scheduled Air Transport Services: According to the ministry of civil aviation's policy " Scheduled Air Transport service means an Air transport service between the two or more places and operated according to a published time table or with flights so regular or frequent that they constitute a recognizably systematic series each flight being open to use by members of public."

1.2 Civil aviation sector and Liberalization Period:

LPG reforms of 1991 is a strategic shift in Indian economy which changed the very Nature of Indian reality today. The policy of liberalization, privatization and globalization of the Government has made a significant impact on the working of enterprises in business and industry. As a result of changes in the rules of industrial licensing and entry of foreign firms, competition for Indian firms has increased especially in service industries like telecommunications, airlines, banking, insurance, etc. which were earlier in the public sector. The Indian Civil Aviation industry is called as "sunrise industry". India has become the third-largest domestic aviation market in the world and is expected to overtake the UK to become the third-largest air passenger market by 2024. It has contributed 5% of India's GDP and creating a total of 4 million jobs. In addition to it, there is a US$ 72 billion gross value-added contribution to GDP by this industry. The aviation industry not only transports passengers from place to place but also greatly contributes to the transportation of all types of cargo around the world. The aviation sector offers global connection, which is crucial for advancing international trade and business. Further, it greatly influences how a nation's economy is shaped by linking it to other nations and continents. In today's global economy, connectivity is essential since it delivers people to work, visitors to locations, and products to markets. All of these are crucial to the progress of India. India's aviation sector is failing, and recovery is hampered by high taxes, inadequate infrastructure, escalating expenses, and restrictive investment laws that make it difficult for the business to thrive.

India has a vast history in the field of aviation. During the initial years of the Indian aviation industry, the operations of air transport were entrusted to three public undertakings, namely: Air India for international services, Indian Airlines for domestic services, service to neighboring countries Vayudoot. Since independence, the Indian Civil Aviation sector was a regulated sector and until 2000, the government first permitted foreign direct investment up to 40% in the domestic airline sector. However, no foreign airline was allowed to invest either directly or indirectly in the domestic airlines industry. Non Resident Indians were permitted to invest up to 100%. Furthermore, the foreign investor was required to take prior approval of the government before making the investment. Subsequently, the central government eased the foreign investment norms in this sector. On September 14, 2012, the central government announced that foreign airlines would now be allowed to invest up to 49% in domestic airlines. Under the policy announced by the government, the ceiling of 49% foreign investment includes foreign direct investment and foreign institutional investment .Up to 100% FDI in civil aviation in India is permitted in Non-scheduled air transport services under the automatic route, helicopter services and seaplanes under the automatic route ,MRO for maintenance and repair organizations; flying training institutes; and technical training institutes under the automatic route ,permitted in Ground Handling Services subject to sectoral regulations & security clearance under the automatic route. Thus, liberalization and privatization of the Indian Civil Aviation market have resulted in huge inflows of FDI and increased competition with the participation of international Civil Aviation operators. The present study investigates the impact of liberalization and privatization on the growth and structure of the Indian Civil Aviation sector.

2. Review of Literature

Vedant Singh, et al (2014)[1] ,Evolving base for the fuel consumption optimization in Indian air transport: application of structural equation model objective of this paper is to design the methodology and to develop five facet model of fuel consumption optimization (FCO). Limited researches have been conducted to explore influencing factors for FCO in air transport industry. Madhavan Meena, et al (2020)[2] - Short-term forecasting for airline industry: the case of Indian air passenger and air cargo. This study aims to forecast air passenger and cargo demand of the Indian aviation industry using the autoregressive integrated moving average (ARIMA) and Bayesian structural time series (BSTS) models. This study utilized 10 years' (2009-2018) air passenger and cargo data obtained from the Directorate General of Civil Aviation (DGCA-India) website. The study assessed both ARIMA and BSTS models' ability to incorporate uncertainty under dynamic settings. Findings inferred that, along with ARIMA, BSTS is also suitable for short-term forecasting of all four (international passenger, domestic passenger, international air cargo, and domestic air cargo) commercial aviation sectors. Sujan K Saraswati (2001)[3], Operating environment for a civil aviation industry in India this paper gives a brief history of civil aviation in India and analyses the operating environment in which civil aviation industry in the country is operating. Civil Aviation has slowly transformed itself from

a mode of transportation for the elite to an essential infrastructure necessity for the society. How this important infrastructure develops and prospers in a country, depends totally on the kind of support it gets from the operating environment. Majra hurfrish, et al (2016)[4] -Structuring technology applications for enhanced customer experience: Evidence from Indian air travelers the objective of the study influence of self-service technology on customer experience and the attributes that constitute customer experience. The results of the study show that there is a significant positive relationship between self- service technology and customer experience. Devi Prasad Dash, et al (2021)[5] - The main objectives of this study are threefold: First, to measure the impact of hotel sector upon the aviation market outcome of India post 2005: Second, to measure the impact of human fatality from the communicable diseases upon the Indian aviation market: Third, is to test the impact of economic uncertainty and pandemic uncertainty upon the Indian aviation market. Xiaowen Fu, et al (2015)[6] , this study investigates the links between domestic market regulation, dominant airline performance, and international market liberalization in Northeast Asia (NEA). The study focuses on China, where substantial regulations are still present in the aviation market, particularly in areas such as route entry, airport slot allocation, input supply, and aviation support services. Rico Merkert, et al (2011)[7] The impact of strategic management and fleet planning on airline efficiency-A random effects Tobit model based on DEA efficiency scores As a result of the liberalization of airline markets; the strong growth of low cost carriers; the high volatility in fuel prices; and the recent global financial crisis, the cost pressure that airlines face is very substantial. Eunice A Dobby(2021)[8] - the study sought to determine the underlying factors influencing implementation of the Yamoussoukro Decision. It establishes policy challenges confronting Kenya's civil aviation in the realization of the Yamoussoukro Decision. It also determines factors influencing full implementation of the safer skies policy in Kenya given benefits of air transport to the economy and international trade. The study utilized international trade and liberalization theory to assess the levels of perceived impact of liberalization of air transport services on international trade. Brajesh Mishra, et al (2021)[9] -Impact of Regional Air connectivity on Regional Economic Growth in India In this study used the panel data of 15 federal states to evaluate the empirical linkages between regional economic growth, air transport traffic, and surface transport indicators. There is a dearth of academic articles focusing on inter-dependence between these factors in the context of India. Pedroni panel cointegration, FMOLS, panel VECM causality techniques, and variance decomposition analysis have been used to evaluate dynamics between the three variables. Pukar KC(2012)[10] - The models make use of Nash non cooperative, Stackelberg and Cournot game models to illustrate how the airline industry is impacted when liberalization in the form of granting air traffic rights and antitrust immunity to airlines is implemented. Beginning with the discussion of regulation in the airline industry, the thesis goes on to study the spread of air transport liberalization in several parts of the world.

3. Objectives of the Study

This study has the following objectives:

- To study the current status of Indian Civil Aviation sector .
- To examine the growth and structure of Scheduled Civil Aviation in India .
- To examine the growth of Public & Private service providers in India on various aspects domestic and international service .
- To study the effect of civil aviation facilities on Indian society.

4. Research Methodology

Data Source For the study, secondary data is collected from the annual reports of Directorate General of Civil Aviation (DGCA-India), Ministry of Civil Aviation India (DGCA-India) website

Methodology

To study the specified objectives, tabular analysis is done and descriptive statistical tools have been used such as year-wise Annual Growth Rates (AGR),Compound Annual Growth Rates(CAGR) and percentage shares. The Annual Growth Rate is computed by using the following formula:

$$AGR = [(X2- X1)/ X 1] *100$$

X1 = first value of variable X and X 2 = second value of variable X

Compound Annual Growth Rate is computed by using the following formula:

$$CAGR = [\{(Vn/V0)1/n\}-1] *100$$

V0: start value;Vn: end value; n: number of years.

5. Limitation of study

1. In study only Scheduled Civil Aviation in India has been taken .
2. In study Civil aviation includes Commercial air transport,(including scheduled passenger and cargo flights),Aerial work,General aviation (GA).
3. In study both Domestic and International service of all Scheduled Public & Private service providers has been taken.
4. The Period of study was from 2010-11 to 2021-22.

6. Data Analysis and Interpretation

This research study gives an insight into the present status of the Civil Aviation industry and examines its growth in the last 12 years on following aspects-

Table 1: Year- on- year Growth and CAGR in Aircraft Flown and Passengers Nos.by All Scheduled Indian Airlines (Domestic and International Services) over the Last 12 years

YEAR	AIRCRAFT FLOWN		PASSENGERS	
	Departure (Nos.)	**Hours** (Nos.)	**Carrie** (Nos.)	**MS. Performed** (Million)
2010-11	6,32,758	1374,728	6,70,00,819	1,03,171
Growth	-	-	-	-
CAGR	-	-	-	-
2011-12	7,04,554	14,60,502	7,52,16,631	1,12,794
Growth	11.3%	7.8%	12.3%	9.3%
CAGR	11.3%	7.8%	12.3%	9.3%
2012-13	6,53,181	13,12,388	7,15,94,505	1,05,208
Growth	-7.3%	-10.1%	-4.8%	-6.7%
CAGR	1.6%	-1.6%	3.4%	1.0%
2013-14	7,00,076	14,33,016	7,64,33,474	1,14,036
Growth	7.2%	9.2%	6.8%	8.4%
CAGR	3.4%	1.9%	4.5%	3.4%
2014-15	7,34,736	15,00,005	8,74,12,197	1,26,903
Growth	5.0%	4.7%	14.4%	11.3%
CAGR	3.8%	2.6%	6.9%	5.3%
2015-16	8,23,732	16,85,787	10,38,22,908	1,45,787
Growth	12.1%	12.4%	18.8%	14.9%
CAGR	5.4%	4.5%	9.2%	7.2%
2016-17	9,46,379	19,46,015	12,45,62,836	1,70,085
Growth	14.9%	15.4%	20.0%	16.7%
CAGR	6.9%	6.2%	10.9%	8.7%
2017-18	10,73,127	22,15,496	14,71,20,152	1,99,409
Growth	13.4%	13.8%	18.1%	17.2%
CAGR	7.8%	7.3%	11.9%	9.9%
2018-19	12,18,108	25,65,278	16,62,33,287	2,25,341
Growth	13.5%	15.8%	13.0%	13.0%
CAGR	8.5%	8.3%	12.0%	10.3%
2019-20	12,02,222	24,26,254	16,39,25,024	2,11,485
Growth	-1.3%	-5.4%	-1.4%	-6.1%
CAGR	7.4%	6.7%	10.5%	8.3%
2020-21*	5,37,753	10,67,111	5,87,57,505	74,190
Growth	-55.3%	-56.0%	-64.2%	-64.9%
CAGR	-1.6%	-2.4%	-1.3%	-3.2%
2021-22	7,30,526	12,38,804	8,42,98,830	82,065
Growth	35.8%	16.1%	43.5%	10.6%
CAGR	1.31%	-0.81%	2.11%	-2.1%

Source : Authors' Own Compilation. from various IRDA Annual Reports. [11]

The all scheduled Indian Airlines total aircraft flown departures (nos.) in domestic and international services in India grew from 6,32,758 in 2010-11 to 12,18,108 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 730526 in 2021-22, registering a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 1.31% . The annual growth rate of total aircraft flown departures (nos.) over previous years is always positive, except for the year 2019-20 and 2020-21, when the growth rate was -1.3% and -55.3% due to the covid pendamic . The highest growth rate has been observed as 35.8% in 2021-22 and the lowest growth rate as -55.3% in 2020-21 due to the reasons already cited earlier .

The all scheduled Indian Airlines total aircraft flown hours (nos.) in domestic and international services in India grew from 13,54,728 in 2010-11 to 25,65,278 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 12,38,804 in 2021-22., registering a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of -0.81%. The annual growth rate of total aircraft flown hours (nos.) over previous years is always positive, except for the year 2012-13, 2019-20 and 2020-21, when the growth rate was -10.1% ,-5.4% and -56.0%. 2019-20 and 2020-21 growth rate negative due to the covid pendamic . The highest growth rate has been observed as 16.1% in 2021-22 and the lowest growth rate as -56.0% in 2020-21 due to the reasons already cited earlier.

Passengers Carried segment has been the key contributor to spectacular growth in the aviation network in India. The total passengers carried (nos.) in India grew from 6,70,00,819 in 2010-11 to 16,62,33,287 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 8,42,98,830 in 2021-22 thereby making India the Third -largest civil aviation market in the entire world. The annual growth rate of total passengers carried (nos.) over previous years is always positive, except for the year 2019-20 and 2020-21, when the growth rate was -1.4 % and -64.% due to the covid pandemic. The highest growth rate has been observed as 43.5% in 2021-22 and the lowest growth rate as -64.2% in 2020-21 due to the reasons already cited earlier.The Compound Annual Growth Rate (CAGR) of total passengers carried for the period 2010-11 - 2021-22 of 2.11% .In the present era, air transport are preferred by passangers due to the time saving and convenience.

Table 2: Year- on- year Growth and CAGR in Aircraft Flown And Passengers Nos. by All Scheduled Private Airlines (Domestic and International Services) over the Last 12 years

YEAR	AIR CRAFT FLOWN		PASSENGERS	
	Departure (Nos.)	Hours (Nos.)	Carried (Nos.)	MS. Performed (Million)
2010-11	4,63,191	9,16,549	5,12,87,756	66,940
Growth	-	-	-	-
CAGR	-	-	-	-
2011-12	5,37,553	10,34,777	5,88,33,819	75,650
Growth	16.1%	12.9%	14.7%	13.0%
CAGR	16.1%	12.9%	14.7%	13.0%

2012-13	4,98,793	9,37,620	5,48,54,167	70,492
Growth	-7.2%	-9.4%	-6.8%	-6.8%
CAGR	3.8%	1.1%	3.4%	2.6%
2013-14	5,33,456	10,08,612	5,79,95,684	74,147
Growth	6.9%	7.6%	5.7%	5.2%
CAGR	4.8%	3.2%	4.2%	3.5%
2014-15	5,67,350	10,61,294	6,72,54,851	84,149
Growth	6.4%	5.2%	16.0%	13.5%
CAGR	5.2%	3.7%	7.0%	5.9%
2015-16	6,52,819	12,21,124	8,21,62,730	99,821
Growth	15.1%	15.1%	22.2%	18.6%
CAGR	7.1%	5.9%	9.9%	8.3%
2016-17	7,62,543	14,28,072	10,09,17,507	1,19,612
Growth	16.8%	16.9%	22.8%	19.8%
CAGR	8.7%	7.7%	11.9%	10.2%
2017-18	8,69,950	16,39,384	12,07,76,795	1,42,757
Growth	14.1%	14.8%	19.7%	19.3%
CAGR	9.4%	8.7%	13.0%	11.4%
2018-19	9,98,688	19,34,433	13,80,10,499	1,64,254
Growth	14.8%	18.0%	14.3%	15.1%
CAGR	10.1%	9.8%	13.2%	11.9%
2019-20	9,74,634	17,74,232	13,49,78,636	1,47,862
Growth	-2.4%	-8.3%	-2.2%	-10.0%
CAGR	8.6%	7.6%	11.4%	9.2%
2020-21	4,52,420	8,17,867	5,02,84,476	53,779
Growth	-53.6%	-53.9%	-62.7%	-63.6%
CAGR	-0.24%	-1.13%	-0.2%	-2.2%
2021-22	6,39,243	10,80,380	7,68,28,203	74,921
Growth	41.3%	32.1%	52.8%	39.3%
CAGR	3%	1.51%	3.74%	1.03%

Source : Authors' Own Compilation. from various IRDA Annual Reports. [11]

The all scheduled Private Airlines total Aircraft Flown departures (nos.) in domestic and international services in India grew from 4,63,191 in 2010-11 to 9,98,688 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 6,39,243 in 2021-22., registering a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 3%. The annual growth rate of total aircraft flown departures (nos.) over previous years is always positive, except for the year 2012-13,2019-20 and 2020-21, when the growth rate was -7.2% ,-2.4% and -53.6%. 2019-20 and 2020-21 growth rate negative due to the covid pendamic.

The highest growth rate has been observed as 41.3% in 2021-22 and the lowest growth rate as -53.6% in 2020-21 due to the reasons already cited earlier The all scheduled private airlines total Passengers Carried (nos.) in India grew from 5,12,87,756 in 2010-11 to 13,80,10,499 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 7,68,28,203 in 2021-22, registering a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 3.74%. The annual growth rate of total Passengers Carried (nos.) over previous years is always positive, except for the year 2012-13, 2019-20 and 2020-21, when the growth rate was -6.8% , -2.2% and -62.7%.

Table 3: Year- on- year Growth and CAGR in Cargo Carried by All Scheduled Indian Airlines (Domestic and International Services) over the Last 12 years

YEAR	**CARGO CARRIED** (TON)			**TON KMS. PERFORMED** (MILLION)		
	FREIGHT	MAIL	PAK	FREIGHT	MAIL	TOTAL
2010-11	6,19,784.8	24,845.5	9,068.7	1,647.1	48.4	10,764.3
Growth	-	-	-	-	-	-
CAGR	-	-	-	-	-	-
2011-12	6,02,252.2	18,591.8	10,151.1	1,749.9	44.9	11,945.9
Growth	-2.8%	-25.2%	11.9%	6.2%	-7.3%	11.0%
CAGR	-2.8%	-25.2%	11.9%	6.2%	-7.3%	11.0%
2012-13	5,93,329.4	6,987.6	9,323.8	1,558.7	48.5	10,931.0
Growth	-1.5%	-62.4%	-8.1%	-10.9%	8.0%	-8.5%
CAGR	-2.2%	-47.0%	1.4%	-2.7%	0.0%	0.8%
2013-14	7,47,925.5	7,193.4	10,156.4	1,749.0	42.8	11,948.2
Growth	26.1%	2.9%	8.9%	12.2%	-11.7%	9.3%
CAGR	6.5%	-33.8%	3.8%	2.0%	-4.0%	3.5%
2014-15	8,15,210.6	31,816.0	11,205.6	1,874.2	57.1	13,136.9
Growth	9.0%	342.3%	10.3%	7.2%	33.5%	9.9%
CAGR	7.1%	6.4%	5.4%	3.3%	4.2%	5.1%
2015-16	8,39,234.7	36,399.6	12,930.7	1,797.5	59.0	14,787.2
Growth	2.9%	14.4%	15.4%	-4.1%	3.2%	12.6%
CAGR	6.2%	7.9%	7.4%	1.8%	4.0%	6.6%
2016-17	8,91,126.8	39,954.8	15,080.5	1,999.6	61.3	17,141.4
Growth	6.2%	9.8%	16.6%	11.2%	4.0%	15.9%
CAGR	6.2%	8.2%	8.8%	3.3%	4.0%	8.1%
2017-18	10,24,286.0	42,863.4	17,690.9	2,490.6	77.3	20,258.8
Growth	14.9%	7.3%	17.3%	24.6%	26.0%	18.2%
CAGR	7.4%	8.1%	10.0%	6.1%	6.9%	9.5%
2018-19	10,99,186.4	45,933.6	20,024.8	2,677.7	77.8	22,780.3
Growth	7.3%	7.2%	13.2%	7.5%	0.6%	12.4%
CAGR	7.3%	7.2%	13.2%	7.5%	0.6%	12.4%
2019-20	9,19,417.6	32,136.3	19,163.2	1,722.8	59.6	20,945.6
Growth	-16.4%	-30.0%	-4.3%	-35.7%	-23.3%	-8.1%

CAGR	4.5%	2.9%	8.7%	0.5%	2.3%	7.7%
2020-21	5,64,415.3	24,566.0	6,457.5	949.7	23.6	7,430.8
Growth	-38.6%	-23.6%	-66.3%	-44.9%	-60.3%	-64.5%
CAGR	-0.9%	-0.11%	-3.3%	-5.4%	-6.9%	-3.6%
2021-22	5,81,619	24,550	7,162	695	26	7,883
Growth	3.05%	-2.7%	10.91%	26.82%	10.13%	6.1%
CAGR	-0.58%	-0.11%	-2.12%	-7.54%	-5.5%	-2.8%

Source : Authors' Own Compilation. from various IRDA Annual Reports. [11]

The all scheduled Indian Airlines freight ton has increased from 6,19,784.8 in 2010-11 to 10,99,186.4 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 581619 in 2021-22. the annual growth rate of freight ton was negative in 2011-12, 2012-13 , it also became negative in 2019-20 to 2020-21 the growth rate was -16.4% and -38.6% due to the covid pendamic . The CAGR of the freight for the period 2010-11 - 2021-22 is -0.58%. the all scheduled Indian Airlines mail has increased from 24,845.5 in 2010-11 to 45,933.60 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 24550 in 2021-22. the annual growth rate of mail was negative in 2011-12, 2012-13 , it also became negative in 2019-20 to 2021-22 the growth rate was -30.0% , -23.6% and -2.7% due to the covid pendamic . The CAGR of the mail for the 2021-22 is -0.11%. India's domestic and international air cargo handling grew by 7.5% compounded annual growth rate (CAGR) between FY 2010-11 and FY 2017-18 . Air cargo tonnage in 2021-22 surpassed pre- Covid averages.

The all scheduled Indian Airlines ton kms. performed (million) has increased from 10,764.3 in 2010-11 to 22,780.3 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 7883 in 2021-22. the annual growth rate of ton kms. performed was positive from 2010-11 - 2021-22 , but 2012-13 , 2019-20 and 2020-21 it became negative showing. The CAGR of the ton kms. performed for the period 2010-11 - 2021-22 is -2.8% .

Table 4: Year- on- year Growth and CAGR in Cargo Carried by All Scheduled Private Airlines (Domestic and International Services) over the Last 12 years

YEAR	CARGO CARRIED (TON)		TON KMS. PERFORMED (MILLION)			
	FREIGHT	MAIL	PAK	FREIGHT	MAIL	TOTAL
2010-11	4,43,941.8	3,359.7	5,482.7	1,009.8	6.7	6,499.1
Growth	-	-	-	-	-	-
CAGR	-	-	-	-	-	-
2011-12	4,49,096.9	4,790.8	6,484.8	1,178.3	9.9	7,673.0
Growth	1.2%	42.6%	18.3%	16.7%	46.6	18.1%
CAGR	1.2%	42.6%	18.3%	16.7%	46.6%	18.1%
2012-13	4,57,878.4	5,215.6	5,918.6	1,121.4	10.2	7,050.1

Growth	2.0%	8.9%	-8.7%	-4.8%	2.8%	-8.1%
CAGR	1.6%	24.6%	3.9%	5.4%	22.8%	4.2%
2013-14	5,69,570.5	4,763.6	6,248.8	1,136.7	9.6	7,395.1
Growth	24.4%	-8.7%	5.6%	1.4%	-5.8%	4.9%
CAGR	8.7%	12.3%	4.5%	4.0%	12.4%	4.4%
2014-15	6,09,079.6	12,352.0	7,157.2	1,204.9	19.0	8,381.1
Growth	6.9%	159.3%	14.5%	6.0%	98.5%	13.3%
CAGR	8.2%	38.5%	6.9%	4.5%	29.6%	6.6%
2015-16	6,47,461.0	17,308.1	8,490.6	1,218.0	22.5	9,731.1
Growth	6.3%	40.1%	18.6%	1.1%	18.7%	16.1%
CAGR	7.8%	38.8%	9.1%	3.8%	27.3%	8.4%
2016-17	7,02,963.2	26,749.0	10,176.2	1,329.7	31.0	11,536.9
Growth	8.6%	54.5%	19.9%	9.2%	37.5%	18.6%
CAGR	8.0%	41.3%	10.9%	4.7%	29.0%	10.0%
2017-18	8,04,724.1	28,103.4	12,123.8	1,651.0	37.7	13,812.6
Growth	14.5%	5.1%	19.1%	24.2%	21.6%	19.7%
CAGR	8.9%	35.5%	12.0%	7.3%	28%	11.4%
2018-19	8,67,139.2	32,227.0	14,108.8	1,756.3	39.8	15,904.8
Growth	7.76%	14.67%	16.4%	6.4%	5.4%	15.1%
CAGR	8.7%	32.7%	12.54%	7.2%	24.9%	11.8%
2019-20	6,91,032.9	17,531.7	12,988.6	837.0	17.8	13,843.5
Growth	-20.3%	-45.6%	-7.9%	-52.3%	-55.1%	-13.0%
CAGR	5.0%	20.2%	10.1%	-2.1%	11.5%	8.8%
2020-21	4,76,743.2	24,466.2	4,661.7	603.4	23.2	5,288.3
Growth	-31.0%	39.6%	-64.1%	-27.9%	29.9%	-61.8%
CAGR	0.7%	22%	-1.6%	-5%	13.2%	-2.04%
2021-22	5,24,681.7	24,534.8	6,505.2	624.4	25.9	7,155.6
Growth	10.1%	0.3%	39.5%	3.5%	11.9%	35.3%
CAGR	1.53%	19.8%	1.57%	-4.3%	13.1%	-0.87%

Source : Authors Own Compilation. from various IRDA Annual Reports. [11]

The All Scheduled Private Airlines Freight Ton has increased from 4,43,941.8 in 2010-11 to 8,67,139.2 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 524681.7 in 2021-22. the annual growth rate of freight ton was positive from 2010-11 to 2018-19, but year 2019-20 and 2020-21 it became negative, when the growth rate was -20.3% and -31.0% due to the covid pandemic . The CAGR of the freight for the period 2010-11 to 2021-22 is 1.53**%.** the all scheduled private airlines mail has increased from 3,359.7 in 2010-11 to 32,227.0 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 24534.8 in 2021-22. The annual growth rate of mail was positive from 2010-11to 2018-19, but 2013-14, 2019-20 it became negative , 2019-20

it became -45.6% showing declining due to covid . The CAGR of the mail for the period 2010-11 - 2021-22 is 19.8%. The all scheduled private airlines ton km. Performed (million) has increased from 6,499.1 in 2010-11 to 15,904.8 in 2018-19 but thereafter started declining and reached 7155.6 in 2021-22. The annual growth rate of ton km. Performed was positive from 2010-11 - 2021-22 , but 2012-13 , 2019-20 and 2020-21 it became negative showing. The CAGR of the ton kms. performed for the period 2010-11 - 2021-22 is -0.87%.

7. Conclusion

Impact occurred in Civil Aviation sector after liberalization :

The Indian Civil Aviation sector has experienced substantial growth in terms of technology, penetration, as well as policy and has emerged as one of the two large growing Civil Aviation markets of Asia, next to China. This Civil Aviation revolution has led to an increase in the demand for basic and value-added services, an increase in domestic and international air service , an increase in air passenger traffic, an increase in the number of airports , an increase in the number of aircraft and higher participation of the private sector in the industry. Still, there are wide disparities in the distribution of aviation access among different states of the country Moreover, the Indian Civil Aviation market is getting stronger due to the fierce competition among the operators company.

Air passenger traffic in India is increasing on a tremendous pace. There has been a growth of over 47% in the number of passengers carried by Indian domestic and international carriers in 2021 as compared to 2020. (1605.27 lakh passengers in 2021-22 while 1090.42 lakh passengers in 2020-21). It also plays a crucial role in promoting tourism by offering a robust transportation network. The promotion of the tourism industry also helps the economy and employment sector both domestically and globally. For Foreign Tourist Arrivals (FTA), air travel is the most chosen mode of transportation. Given that Civil Aviation services generate many externalities in the economy, the government should take initiatives to promote sector development and increased penetration. It should put in place investor-friendly business policies and make the regulatory framework more responsive to the rapidly changing needs of the Civil Aviation sector. There is a need to create an ecosystem that encourages foreign investors to view the markets as an opportunity for future expansion with immense potential for sustainable revenues. foreign investors may be given tax holidays for establishing aviation infrastructure and providing Civil Aviation services in remote areas. Special efforts are needed through customized value addition, innovative marketing and pricing in the country . All the stakeholders, viz. the government, Civil Aviation operators, equipment vendors and various local bodies will need to collaborate and work together to continue to make the Indian Civil Aviation sector attractive to foreign companies and allow the country to benefit from the latest technological advances and to attract necessary finance for the development of the Civil Aviation industry.

Impact on the society after the changes occurred in Civil Aviation sector :

Civil aviation is a mile stone for any modern society. Its contribution to the development of the society is enormous. In India this sector effects both positively and negatively after its post liberalization reforms. It leads to a massive change in reshaping the economic pattern and life style choices of Indian citizen. Some important changes are as follows :

1. It creates job opportunities for the youth of the country by expanding new airports and airlines and helps to reduce unemployment problem of the country.
2. It attracts Investment from domestic and foreign countries for Aviation infra structure and Aviation related industry so that society can enjoy more facilities in low cost.
3. It enhances connectivity between other countries with urban cities which pro vides easy and quick transportation services to the people of India.
4. This easy connectivity provides access to rural and remote areas of India as the number of Airports and Airline facilities increased after liberalization.
5. Effective and reliable Aviation is continuously attracting domestic as well as international tourism in various beautiful destinations of India. It is also provid ing better facilities for business tours in various business centers of India.
6. As the competition increases after privatization of Aviation sector, it results in lower fares for the consumers. This lower fares made air travel affordable for upper middle class and middle class population of India.
7. So many new routes and destinations are included by the government to make the air travel convenient.
8. New increased air facilities are always helping in promoting medical facilities and critical response during the time of natural disaster and pandemic like COVID 19 .
9. By enhancing social mobility it increases the quality of life and upgrade the standard of living of the people living in the society.
10. As the number of International flights are increased It creates bridge for cul tural and educational exchange among people not only within India but also in whole world .

❐

References :

1. *Vedant Singh, Somesh K Sharma Evolving base for the fuel consumption optimization in Indian air transport: application of structural equation model .European Transport Research Review 6 (3), 315-332, 2014*
2. *Meena Madhavan, Mohammed Ali Sharafuddin, Pairach Piboonrungroj, Ching-Chiao Yang Short-term forecasting for airline industry: the case of indian air passenger and air cargo,Global Busi ness Review,0972150920923316, 2020*
3. *Sujan K Saraswati Operating environment for a civil aviation industry in India .Journal of Air Transport Management 7 (2), 127-135, 2001*
4. *Hufrish Majra, Rajan Saxena, Sumi Jha, Srinath Jagannathan Structuring technology applications for enhanced customer experience: Evidence from Indian air travelers Global business review 17 (2), 351-374, 2016*

5. *Devi Prasad Dash, Aruna Kumar Dash, Narayan Sethi Understanding the pandenomics: Indian aviation industry and its uncertainty absorption*
6. *Xiaowen Fu, Tae Hoon Oum, Ruowei Chen, Zheng Lei Dominant carrier performance and interna tional liberalization- The case of Northeast Asia. Transport Policy 43, 61-75, 2015*
7. *Rico Merkert, David A Hensher The impact of strategic management and fleet planning on airline efficiency-A random effects Tobit model based on DEA efficiency scores .Transportation Research Part A: Policy and Practice 45 (7), 686-695, 2011*
8. *Eunice A Dobby The Role of Civil Aviation in Promoting International Trade in Africa: a Case Study of Kenya Aviation Industry.University of Nairobi, 2021*
9. *Brajesh Mishra, Fateh Bahadur Singh, Ronak Batra Impact of Regional Air connectivity on Regional Economic Growth in India.2021 .European Transport\ Transporti Europei (2021) Issue 83, Paper no4 ISSN1825-3997*
10. *Pukar KC Modeling the Effects of Air Transport Liberalization on the Airline Industry.2012.Economics Honors Papers.7.*
11. *Annual Report (2010-2011 to 2021-22), Directorate General of Civil Aviation, website. www.dgca.gov.in*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 169–180

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

A Study on Crimes against Scheduled Castes in Southern States of India

Dr. Sukanta Sarkar

Associate Professor, Department of Economics,
College of Business and Economics, Gambella University, Ethiopia,
Email: sukantaeco@gmail.com, ORCID ID- 0000-0003-3041-061X

Abstract

The paper discussed crimes against Scheduled Castes in Southern States of India. It has found that they are classified as "depressed" castes or classes in Government of India Act 1935 and later in the constitution of free India in 1950. Dr. B.R Amedkar, the founder of our Constitution played vital role for dignity and rights for such classes people. They are generally economically and socially backward and Constitution of India given various rights and protection for such classes people for their empowerment. Tamil Nadu has the highest number of Scheduled Castes population followed by Andhra Pradesh and Karnataka. Highest number of crimes against scheduled castes has been registered Andhra Pradesh followed by Karnataka and Telangana. Highest incidences of murder, attempt to commit murder, assault or use of criminal force on women with intent to disrobe, rape of children, rioting, robbery, dacoity voyeurism and assault on women are reported in Karnataka. Incidences of sexual harassment, grievous hurt, and assault of children are highest in Kerala. Highest incidences of simple hurt have been found in Tamil Nadu. Incidences of stalking crime, kidnapping, abduction, missing children deemed as kidnapped, and procuration of minor girls are highest in Andhra Pradesh. The overall incidences of rape are highest in Telangana followed by Karnataka and Kerala. Therefore, governments of the concern states should implement proper policies and regulations for minimizing such crimes against people of scheduled castes.

Keywords: Acts, Empowerment, Untouchability, Scheduled Castes, and Welfare.

Introduction

Scheduled caste are often called as 'Dalit' or 'Harijans' and Discriminates by the

other people. Historically they are known as 'Untouchables.' Birth became a decisive criterion for caste of any person in India. They are also sub-divided in various groups. They are considering as lower class people in Hindu social hierarchy. They are discriminated by the upper caste people from the ancient times and not accepted by such superior classes. There are differences between Scheduled Tribes and Scheduled Castes. Scheduled Tribes are the community of people who lives in hilly or forest, on the other hand, Scheduled Caste are the people who were previously untouchables. According census report 2011, Scheduled Tribes and Scheduled Castes comprise about 8.6 percent and 16.6 percent population of India. As per Article 366 (24) of Constitution of India the Scheduled Castes is defined as "Such castes, races or tribes or part of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under Article 341 to be Scheduled Castes for the purpose of this [Indian] constitution." National Commission for Scheduled Castes was constructed under Articles 338 and 338A for safeguard of people belongs of Scheduled Caste.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes are socially and economically most deprived class people and officially defined in the Constitution of India. The term "Scheduled Castes" was first used by British Government for identifying the lower raking Hindu castes for statutory safeguards and other benefits. Scheduled Castes are generally lives in the rural areas and involves in particular occupations. According census 2011, among the all states, Punjab have the highest percentage (35%) population as scheduled castes. Literacy rate of the Scheduled Castes is highest in Mizoram (92.43%) followed by Tripura (89.45 %) and Goa (83.73 %). On the other hand, literacy rate is lowest in Bihar (48.65 %) preceded by Jharkhand (55.89%) and Rajasthan (59.75 %). The sex ratio among the Scheduled Castes are highest in Kerala (1057) followed by Goa (1015) and Andhra Pradesh (1008). On the other hand, sex ratio is lowest in Mizoram (509) preceded by Haryana (887) and Delhi (889). There are no Scheduled Castes population in Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Arunachal Pradesh and Nagaland.

Objectives

The main objectives of this paper are: (a) to study the trends and patterns of crimes against Scheduled Castes in Southern states of India, and (b) to identify various initiatives of government for mitigating such crimes.

Methods and Materials

· **Design and Approach:** This study is descriptive in design and has utilized qualitative approach. Secondary data for the study has been collected from various govt. reports, National Crime Record Bureau website, report of international agencies, research papers, published or unpublished thesis's, articles, etc.

· **Method of Analysis:** To reveal the crimes against scheduled castes in general and the women in particular, method of qualitative analysis comprising of descriptive analysis, content and text analysis have been performed.

The Study Area

South India is the southern part of peninsular Deccan Plateau in India. It constituted by five states (Andhra Pradesh, Karnataka, Telangana, Tamil Nadu and Kerala) and two union territories (Puducherry and Lakshadweep). Total area and population of the region are respectively 635,780 km2 and 25.30 crores (accordingly census 2011). Density of population is 400/km2. Literacy rate and sex ration in the region are 76.43 percent and 986. Malayalam, Kannada, Tamil, and Telugu are the main languages of the region.

Results and Discussion

According census 2011, percentage of scheduled castes in total population in Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu are respectively 16.41, 17.51, 9.10, and 20.01. Nellore, Prakasam and Chittoor districts of Andhra Pradesh has the higher percentage of Scheduled Castes population. Majority of Scheduled Castes population in Karnataka are concentrated in Bangalore Urban, Gulbarga, Kolar, Mysore, Bijapur and Chitradurga districts. According Census 2011, Palakkad district has the highest number of Scheduled Castes population followed by

Thiruvananthapuram and Kollam. On the other hand, number of scheduled castes population is lowest in Wayanad preceded by Kasaragod. Palakkad, Idukki, Pathanamthitta and Kollam districts are dominated by such castes population. Viluppuram, Kancheepuram, Vellore, Thiruvallur and Chennai districts of Tamil Nadu are well-known for number of scheduled castes population. Major scheduled castes of Tamil Nadu are Chakkiliyar, Paraiyan and Pallan, belonging to the Dravidian linguistic group.

Table 1: Scheduled Castes Population in Southern States of India

State	Population	Males	Female	Child (0-6)	Literacy	Sex Ratio
Andhra*	13,878,078	6,913,047	6,965,031	11.17%	62.28%	1008
Karnataka	10,474,992	5,264,545	5,210,447	12.97%	65.33%	990
Kerala	3,039,573	1,477,808	1,561,765	9.43%	88.73%	1057
Tamil Nadu	14,438,445	7,204,687	7,233,758	11.02%	73.26%	1004

https://www.census2011.co.in/scheduled-castes.php),
Note: * shows data of the undivided Andhra Pradesh.

Table 1 discussed the Scheduled Castes population in Southern States of India. It has found that Tamil Nadu has the highest number of Scheduled Castes population followed by Andhra Pradesh and Karnataka. Kerala has the least number of Scheduled Castes population in the region. Except Kerala, male population is higher than the female population in four states. Literacy rate of Scheduled Casts is highest in Kerala followed by Tamil Nadu and Karnataka. On the other hand, it is lowest in Andhra Pradesh. Except Karnataka, other states have higher sex ratio, i.e. number of female is more than male.

Table 2: Crime against Scheduled Castes in South Indian States

State	2020	2021	2022	Actual Population of STs (in Lakhs)	Rate of Total Crime against SCs (2022)	Charge sheeting Rate (2022)
Andhra	1950	2014	2315	84.5	27.4	73.4
Karnataka	1398	1673	1977	104.7	18.9	83.6
Kerala	846	948	1050	30.4	34.5	78.5
Tamil Nadu	1274	1377	1761	144.4	12.2	84.1
Telangana	1959	1772	1787	54.3	32.9	81.6

Source: Crime in India 2022 report, p.537, National Crime Record Bureau, Govt.of India.

Table 2 discussed the crime against scheduled castes in south Indian states. It has found that highest number of crimes against scheduled castes occurred in Andhra Pradesh followed by Karnataka and Telangana. On the other hand, least number of incidences occurred in Kerala preceded by Tamil Nadu. The rate of total crime against SCs are highest in Kerala followed by Telangana and Andhra Pradesh. On the other hand, least rate of total crime against SCs occurred in Tamil Nadu preceded by Karnataka. It has also found that charge sheeting rate is highest in Tamil

Nadu followed by Karnataka and Telangana. On the other hand, the least percentage of charge sheeting rate has been found in Andhra Pradesh preceded by Kerala.

Table 3: Murder and Attempt to Commit Murder Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC (Total)			SC/ST (Prevention of Atrocities) Act					
				Murder (Sec. 302 IPC) Murder			Attempt to Commit (Sec. 307 IPC)		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	2190	2296	25.9	49	50	0.6	77	79	0.9
Karnataka	1930	2418	18.4	72	73	0.7	140	183	1.3
Kerala	1021	1047	33.6	11	11	0.4	24	25	0.8
Tamil Nadu	1684	1830	11.7	55	56	0.4	56	61	0.4
Telangana	1725	1820	31.8	31	31	0.6	25	25	0.5

Source: Crime in India 2022 report, p-538, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 3 showed the murder and attempt to commit murder crimes against Scheduled Castes in South Indian States. It has found that highest number of incidences of murder reported in Karnataka followed by Tamil Nadu and Andhra Pradesh. On the other hand, least number of such crime has been recorded in Kerala preceded by Telangana. The incidence of attempt to commit murder is highest in Karnataka followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The least number of such crimes is recorded in Kerala preceded by Telangana.

Table 4: Simple Hurt and Grievous Hurt Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Simple Hurt (Secs. 323 r/w 324, 327, 328, 330, 332 353 IPC)			Grievous Hurt					
				Grievous Hurt (Sec. 325 & 326 IPC) (Total)			Grievous Hurt		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	601	657	7.1	5	5	0.1	5	5	0.1
Karnataka	374	520	3.6	37	55	0.4	36	52	0.3
Kerala	231	249	7.6	61	64	2.0	61	64	2.0
Tamil Nadu	736	783	5.1	5	7	0.0	5	7	0.0
Telangana	266	302	4.9	9	9	0.2	9	9	0.2

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 4 discussed the simple hurt and grievous hurt crimes against scheduled castes in South Indian States. It has found that highest incidences of simple hurt have been found in Tamil Nadu followed by Andhra Pradesh and Karnataka. The least number of incidences of such crime has been found in Kerala preceded by Telangana. The highest incidences of grievous hurt have been recorded in Kerala followed by Karnataka. The least number of such crime has been registered in Andhra Pradesh preceded by Tamil Nadu and Telangana.

Table 5: Assault on Women Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty								
	Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty(Adults+ Children)			Assault on Women (Above 18 years)			Assault on Adult Women with Intent to Outrage her Modesty (Sec.354 IPC)		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	245	248	2.9	232	235	2.7	165	167	2.0
Karnataka	283	324	2.7	264	296	2.5	210	235	2.0
Kerala	252	253	8.3	169	170	5.6	97	97	3.2
Tamil Nadu	92	109	0.6	42	42	0.3	26	26	0.2
Telangana	112	115	2.1	104	107	1.9	66	68	1.2

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India.

Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 5 discussed the assault on women crimes against scheduled castes in South Indian States. It has found that the highest incidences of assault on women with intent to outrage her modesty (adults+ children) has been recorded in Karnataka followed by Kerala and Andhra Pradesh. The least number of incidences of such crime has been recorded in Tamil Nadu preceded by Telangana. The incidences of assault on women (above 18 years) is highest in Karnataka followed by Andhra Pradesh and Kerala. The least incidences of such crime occurred in Tamil Nadu preceded by Tamil Nadu preceded by Telangana. The incidences of assault on adult women with intent to outrage her modesty is highest in Karnataka followed by Andhra Pradesh. The least incidences of such crime has been found in Tamil Nadu preceded by Telangana and Kerala.

Table 6: Sexual Harassment and Voyeurism Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty								
	Sexual Harassment (Sec. 354A IPC)			Assault or use of Criminal Force on women with intent to Disrobe (Sec.354B IPC)			Voyeurism (Sec. 354C IPC)		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	35	35	0.4	14	14	0.2	2	2	0.0
Karnataka	17	23	0.2	35	36	0.3	0	0	0.0
Kerala	59	60	1.9	8	8	0.3	1	1	0.0
Tamil Nadu	12	12	0.1	2	2	0.0	0	0	0.0
Telangana	22	22	0.4	4	5	0.1	1	1	0.0

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 6 discussed the sexual harassment and voyeurism crimes against scheduled castes in South Indian States. It has found that incidences of sexual harassment are highest in Kerala followed by Andhra Pradesh and Telangana. The least number of such incidence of such crime has been recorded in Tamil Nadu preceded by Karnataka. The highest incidences of assault or use of criminal force on women with intent to disrobe has been found in Karnataka followed by Andhra Pradesh and Kerala. The least number of such crime is recorded in Tamil Nadu preceded by Telangana. Highest incidences of voyeurism crime are registered in Karnataka followed by Telangana and Kerala. There are no incidences of such crime in Tamil Nadu and Karnataka.

Table 7: Stalking, Assault of Children, and Insult to the Modesty of Women Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Assault on Women with Intent to Outrage her Modesty						Insult to the Modesty of Women (Sec. 509 IPC)		
	Stalking (Sec. 354D IPC)			Assault of Children POCSO Act 8&10 or POCSO Act (Sec. 8&10 r/w 354 IPC)					
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	16	17	0.2	13	13	0.2	113	113	1.3
Karnataka	2	2	0.0	19	28	0.2	3	3	0.0
Kerala	4	4	0.1	83	83	2.7	8	8	0.3
Tamil Nadu	2	2	0.0	50	67	0.3	0	0	0.0
Telangana	11	11	0.2	8	8	0.1	41	41	0.8

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 7 discussed the stalking, assault of children, and insult to the modesty of women crimes against scheduled castes in South Indian States. It has found that the incidences of stalking crime are highest in Andhra Pradesh followed by Telangana. On the other hand, incidences of such crime is least in Tamil Nadu and Karnataka preceded by Kerala. The incidences of assault of children is highest in Kerala followed by Tamil Nadu and Karnataka. On the other hand, least number of incidences of such crime is registered in Telangana preceded by Andhra Pradesh. The incidences of Insult to the modesty of women crime is highest in Karnataka followed by Telangana. On the other hand, least number of incidences of such crime is registered in Andhra Pradesh preceded by Karnataka and Kerala. There is no incidence of such crime in Tamil Nadu.

Table 8: Kidnapping, Abduction, and Missing Children Deemed as Kidnapped Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Kidnapping and Abduction Other Kidnapping & Abduction (Sec.365,366B, 367,368,369 IPC)			Kidnapping and Abduction (Sec. 363 IPC)			Missing Children Deemed as Kidnapped		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	25	25	0.3	13	13	0.2	2	2	0.0
Karnataka	11	11	0.1	7	7	0.1	1	1	0.0
Kerala	7	7	0.2	5	5	0.2	0	0	0.0
Tamil Nadu	10	10	0.1	2	2	0.0	0	0	0.0
Telangana	13	13	0.2	6	6	0.1	2	2	0.0

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 8 discussed the kidnapping, abduction, and missing children deemed as kidnapped crimes against Scheduled Castes in South Indian States. It has found that the incidences of kidnapping and abduction incidences are highest in Andhra Pradesh followed by Karnataka and Telangana. Highest incidences of missing children deemed as kidnapped is registered in Telangana and Andhra Pradesh. Least number of such crime is recorded in Karnataka. There is no incidence of such crime in Kerala and Tamil Nadu.

Table 9: Kidnapping on Ransom and Procuration of Minor Girls Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC Kidnapping and Abduction								
	Kidnapping for Ransom (Sec. 364A IPC)			Kidnapping and Abduction of Women to compel her for marriage (Sec.366 IPC)			Procuration of Minor Girls (Sec. 366A IPC)		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	0	0	0.0	6	6	0.1	2	2	0.0
Karnataka	0	0	0.0	1	1	0.0	0	0	0.0
Kerala	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1	0.0
Tamil Nadu	0	0	0.0	6	6	0.0	1	1	0.0
Telangana	0	0	0.0	6	6	0.1	0	0	0.0

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 9 discussed the kidnapping on ransom and procuration of minor Girls crimes against Scheduled Castes in South Indian States. It has found that there are no incidences of kidnapping for ransom in the region. The incidences of kidnapping and abduction of women to compel her for marriage is higher in Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Telangana. There is no incidence of such crime in Kerala. The incidences of procuration of minor girls is highest in Andhra Pradesh followed by Kerala and Tamil Nadu. There are no incidences of such crime in Karnataka and Telangana.

Table 10: Kidnapping, Abduction, Rape and Rape of women Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Kidnapping and Abduction Other Kidnapping &Abduction (Sec.365,366B, 367 ,369 IPC)			Rape (Sec. 376 IPC) (Total)			Rape of Women (Sec. 376 IPC) (Above 18 yrs.)		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	4	4	0.0	144	145	1.7	86	87	1.0
Karnataka	3	3	0.0	204	207	1.9	67	69	0.6
Kerala	1	1	0.0	192	192	6.3	82	82	2.7
Tamil Nadu	1	1	0.0	166	168	1.1	50	50	0.3
Telangana	1	1	0.0	277	280	5.1	151	151	2.8

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 10 discussed the kidnapping, abduction, rape and rape of women crimes against scheduled castes in South Indian States. It has found that incidences of kidnapping and abduction is highest in Andhra Pradesh followed by Karnataka. The least incidences of such crime is found in Kerala, Tamil Nadu and Telangana. The incidences of rape of women (above 18 years) is highest in Telangana followed by Andhra Pradesh and Kerala. On the other hand, the least incidences of such crime has been found in Tamil Nadu preceded by Karnataka. The overall incidences of rape are highest in Telangana followed by Karnataka and Kerala.

Table 11: Rape of Children, Attempt to Commit Rape, and Rioting Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Rape of Children (Below 18 yrs.)			Attempt to Commit Rape			Rioting		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	58	58	0.7	6	6	0.1	13	39	0.2
Karnataka	137	138	1.3	0	0	0.0	166	342	1.6
Kerala	110	110	3.6	3	3	0.1	12	12	0.4
Tamil Nadu	116	118	0.8	0	0	0.0	65	98	0.5
Telangana	126	129	2.3	0	0	0.0	2	2	-

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 11 discussed the rape of children, attempt to commit rape, and rioting crimes against Scheduled Castes in South Indian States. It has found that the incidences of rape of children is highest in Karnataka followed by Telangana and Tamil Nadu. On the other hand, the least incidences of such crime has been found in Andhra Pradesh preceded by Kerala. The incidences of attempt to commit rape is highest in Andhra Pradesh followed by Kerala. There are no incidences of such crime in Karnataka, Tamil Nadu and Telangana. The incidences of rioting are highest in Karnataka followed by Tamil Nadu and Andhra Pradesh. The least incidences of such crime has been occurred in Telangana preceded by Kerala.

Table 12: Robbery and Dacoity Crimes against Scheduled Castes in South Indian States

State	SC/ST (Prevention of Atrocities) Act r/w IPC								
	Robbery			Dacoity					
				Dacoity			Dacoity with Murder		
	I	V	R	I	V	R	I	V	R
Andhra	2	2	0.0	1	1	0.0	0	0	0.0
Karnataka	9	9	0.1	2	5	0.0	0	0	0.0
Kerala	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
Tamil Nadu	1	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
Telangana	1	1	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 12 discussed the robbery and dacoity crimes against Scheduled Castes in South Indian States. It has found that highest incidences of robbery have been registered in Karnataka followed by Andhra Pradesh. Kerala has no incidence of such crime. The highest incidences of Dacoity are registered in Karnataka followed by Andhra Pradesh. There is no incidence of such crime in Kerala, Tamil Nadu and Telangana. There are no incidences of Dacoity with murder in the region.

Table 13: Total Crime/Atrocities against Scheduled Castes in South Indian States

State	Protection of Civil Rights Act, 1955			Total Crime/Atrocities against Scheduled Tribes		
	I	V	R	I	V	R
Andhra	0	0	0.0	2315	2431	27.4
Karnataka	5	5	0.0	1977	2488	18.9
Kerala	0	0	0.0	1050	1079	34.5
Tamil Nadu	0	0	0.0	1761	1908	12.2
Telangana	0	0	0.0	1787	1882	32.9

Source: Crime in India 2022 report, National Crime Record Bureau, Govt.of India. Note: I= No. of Incidences/Cases, V= No. of Victims & R=Crime Rate per lakh population.

Table 13 described the total crime/atrocities against scheduled castes in South Indian States. It has found that the highest incidences of crimes are recorded in Andhra Pradesh followed by Karnataka. The least incidences of crimes are registered in Kerala preceded by Telangana and Tamil Nadu. The crime rate per lakh population is highest in Kerala followed by Telangana and Andhra Pradesh.

Government of India has assumed a wide range of responsibilities for welfare of such deprived class people. Government has introduced Special Coaching Scheme and Computer Training schemes for Scheduled Castes and Scheduled through Coaching-cum-Guidance Centres. The main objective of such scheme is to reduce drop-out rates among such categories students. Schemes for family welfare, water supply, recreational, educational, housing, and medical benefits are implemented for workers of scheduled castes. Development Commssioner (Handlooms) has introduced various handloom schemes, such as (a) Integrated Handloom Development Scheme; (b) Marketing & Export Promotion Scheme; (c) Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme; (d) Mill Gate Price Scheme; and (e) Diversified Handloom Development Scheme, for welfare of SC/ST workers. National Commission for Scheduled Castes was formed in 19th February 2004 to provide safeguards against the exploitation of Scheduled Castes. It is a constitutional body that work under the jurisdiction of Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Central government has already reserved 15 percent vacancies in educational institutions for study and jobs for the scheduled castes candidates.

Constitution of India has granted some rights and benefits for empowerment of such deprived classes. Under Article 341(l), the Constitution after consultation with the governor of a State may specify, "The castes, races, tribes or, parts of groups within castes or races, tribes which shall be deemed to be scheduled castes for the purpose of the constitution." According to the Article 341 (2) the Parliament of India, can include or exclude any group from the list of Scheduled Castes through an enactment of law. Under Article 46 of the constitution, it is the responsibility of the State to promote with special care the educational and -economic interests of the weaker sections of people and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in particular, and to protect them from social injustices and all forms of exploitation. There are a number of articles included in Part-III of the constitution which provides fundamental rights to the citizens, Article 14, 15, 16 and 17 provide rights to equality. Article 14 of the constitution provides right to equality before law that means, every citizen in the country is equal before law. Article 15 prohibits social and educational discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.

Article 16 prescribes the equality of opportunity in matters of public appointment. Article 17 of this part of Constitution legally abolishes the practice of untouchability in any form against the Scheduled Castes. Article 46 mentions specifically that the State must endeavour to promote the educational and economic interests of the Schedule Castes and Scheduled Tribes among the weaker sections of the society. Articles 330 and 332, lay down that there shall be reservation of seats in the Lok Sabha (Article 330) and State Legislative Assembly (Article 332) in proportion to the number of the Scheduled Castes in various states. according to Article 340, the President can appoint a commission to investigate the difficulties of

the socially and educationally backward classes of citizens and to make recommendations to remove such difficulties.

Conclusion

Scheduled Caste term was first coined by the Simon Commission and then Government of India, Act, 1935. Scheduled Castes are also known as "Harijans." They are most socially and economically deprived class people in the society. Majority of such people lives in rural areas and are working as marginal farmers, tenants, share-croppers, and agricultural workers. Large number of scheduled castes are engaged in jobs like tanning, scavenging and sweeping. They have very low literacy and most of them live below poverty line. They live in exploitative situation and this exploitation has gone on for centuries. Constitution of India guaranteed certain essential rights and benefits of such deprived classes people.

Tamil Nadu has the highest number of Scheduled Castes population followed by Andhra Pradesh and Karnataka. Highest number of crimes against scheduled castes has been registered Andhra Pradesh followed by Karnataka and Telangana. Highest incidences of murder, attempt to commit murder, assault or use of criminal force on women with intent to disrobe, rape of children, rioting, robbery, dacoity voyeurism and assault on women crimes reported in Karnataka. Incidences of sexual harassment, grievous hurt, and assault of children are highest in Kerala. Highest incidences of simple hurt have been found in Tamil Nadu. Incidences of stalking crime, kidnapping, abduction, missing children deemed as kidnapped, and procuration of minor girl's crimes are highest in Andhra Pradesh. The overall incidences of rape are highest in Telangana followed by Karnataka and Kerala.

Central government already given 15 percent reservation of Scheduled Castes in government jobs and education. State government also implemented reservation for scheduled castes as per their population in the concern state. State Governments have also adopted benefits for school children of the Scheduled Castes, like as provision of stipends, school uniform, books, educational equipment's, mid-day meals etc. Many developmental schemes have been adopted Scheduled Castes in particular in the rural areas. Government implemented various plans for social equality, social justice and social progress for such classes people.

❐

References :

1. *Dushkin, L. (1967). Scheduled Caste Policy in India: History, Problems, Prospects. 7 (9): p.626–636.*
2. *Parvathamma, C. (1981). The Weaker Sections of Society-the Scheduled Castes in India, Sociological Bulletin. 30 (1). p.12-13.*
3. *Patra, P. (2021). Present Status of Scheduled Castes in India. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research. 8 (9). P.157-168.*
4. *Prabhakar, K (2017). Problems and Prospects of Schedule Caste and Schedule Tribes at present political Situations in India. International Journal of Creative Research Thoughts. 5 (2). P.362-364.*
5. *Raghavendra, H. (2020). Literacy and Health Status of Scheduled Castes in India. Contemporary Voice of Dalit. 12(1) p.97–110,*
6. *Sushma, N. (2016). Empowerment of Schedule Caste women in India: An Overview. 3. 4 (2). P.65-66.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 181–191

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Electoral Candidate Selection in India and the USA Party Nominations Versus Primaries

Dr. Sunil Devi Kharb

Assistant Professor, Political Science. MDU-CPAS, Gurugram -122001
E-mail: sunildevi.cpas@mdurohtak.ac.in Mob. 8178632752

Shivani Deshwal

Research Schollar,Dept. Political Science. MDU, Rohtak

Abstract

Candidate selection is one of the defining functions of political parties in a representative democracy. Political parties nominate and select candidates who would participate in electoral contests and be chosen as their representatives by the electorate. Selection of candidates is generally regarded as the internal function of political parties and, as such, out of the realm of formal electoral procedures. However, it is indeed a crucial aspect of the democratization of politics. Selective bias and highly centralized party structures limit the opportunities for political participation and thereby affect representational outcomes. In this context, many democracies chose to democratize candidate selection by adopting more inclusive and decentralized practices. USA, in the early twentieth century, introduced the mechanism of conducting primaries for the selection of party candidates and sought to regulate the internal functioning of political parties legally.

The adoption of American primaries has been seen as a significant step toward enhancing the democratic structure within party nominations, expanding the decision-making process to a broader base of participants. This approach emphasizes a high level of inclusivity in the selection of party candidates, contrasting sharply with the more exclusive, often centralized candidate selection methods observed in countries like India.The paper delves into the comparative analysis of these differing approaches, assessing the potential of the American primary system to act as a catalyst for reforming intra-party democracy. Additionally, it explores the complexities and challenges associated with regulating party activities within the framework of liberal democracies, mainly focusing on the Indian context.

Key words: Primaries, Winnability, Nomination, Candidate selection

Introduction

Selecting candidates for elections is a fundamental part of democratic process for various reasons such as representation of diverse interests, values and views of the electorates, to provide choice to voters. On the other hand, selection of winnable candidates with ideological alignment is important for political parties as it directly impacts their chances of electoral success, ability to advance their political agenda and their overall image in the mind of voters. The choice of candidates can significantly impact the future of political parties in democratic process.

It is one of the first things that political parties do prior to elections. It is generally regarded as an internal affair of political parties to determine the selection of candidates for taking part in electoral contests specifically in democratic countries like India. Leon Epstein (1967, 201) asserted that the selection of political candidates is, in essence, a private matter, regardless of any legal requirements. Austin Ranney (1981, 75) defined candidate selection as 'the predominantly extra-legal process by which a political party decides which of the persons legally eligible to hold an elective public office will be designated on the ballot and in election communications as its recommended and supported candidate or list of candidates.' However, it is crucial to understand the dynamics of different candidate selection methods on the intra-party effects of the electoral systems (Colomer, 2004; Shugart, 2005). The study of the distinctions between electoral systems that allow voters to elect parties and those that allow them to elect candidates is as important as the contestation of proportional representation versus majoritarianism (Grofman 2002, 37). It is also an important aspect strongly connected to the representation and policy outcomes. The selection of candidates and the opportunity structures within the parties have a significant effect on the composition of the legislature. In nations with single-member districts, the selection process of candidates becomes even more important when the proportion of safe seats becomes large. It means that the effective choice of who will become a legislator is made not by the voters in the general election but by the party's selection process (Hazan & Rahat 2010, 11).

Candidate selection and 'intra-party' conflict

Candidate selection within parties is often viewed as 'battle before the ballot' or what political scientists have described as 'gatekeeping' by political elites to narrow down the gates for political selection. As Pesonen points out, 'the nomination stage eliminates 99.96 percent of all eligible people. The voters choose from only 0.04 percent.' It provides the opportunity for political parties to provide selective incentives to its members and reward loyal and active members by allowing them to have influence on the selection of candidates and even the chance of getting themselves elected as party representatives (Gallagher & Marsh 1988, 2). Moreover, the choice of candidates can have a significant impact on the party's capacity to remain unified in the legislature. In cases where nominations are managed centrally, it is likely that representatives will adhere to the party's policy in the parliament as any deviation from the party's line will result in their deselection

(Gallagher,1988). Parties ought to reduce intra-party competition by limiting and structuring selection as the fair game on the basis of party internal regulations. Vote-seeking might get negatively affected by overt intra-party competition (Reiser, 2023, 87).

Method of Candidate Selection in USA: Conducting Primaries

The United States has the peculiar feature of conducting primaries for the nomination of party candidates for the elections. Since the beginning of the twentieth century, primaries have emerged as the main instrument for electing party candidates. Earlier candidates were nominated at the party conventions by the selected delegates. While delegates were sent from their states to attend these conventions, they were often hand-picked by state and local party bosses who held sway over delegates' allegiances. They were often accused of buying convention floor votes with power, patronage or even money. At the time American law considered political parties as private associations free from any legal interference and party leaders/members could not recourse to legal mandates for party issues. This called for a series of reforms to mitigate the corrupt control of party leaders and provide the people with a say in the candidate selection process. The McGovern- Fraser Commission set up in 1968 for reforming the party structures recommended a more transparent nominating process with more representation of rank-and-file citizens at nominating conventions, significantly lowering delegates selected by State Party committees. It also called for an increased diversity of representation (especially of gender and race) in the nomination process (Jenkinson, 2022).

Still in some states, party candidates are selected through national or local appointment agreements instead of at the primary level, by tradition or at the discretion of political parties, but most of the states have passed laws to regulate the parties' functioning. Once the primary elections have taken place, general elections are held to elect members to the legislature. Voters make the final decision among the candidates on the ballot in general elections. Independent candidates can also stand up in the general elections by sending a certain number of petition signatures. These candidates can be qualified as 'self-appointed' and occasionally win the election for public office (Ranga 2019, 198). Where parties nominate by means other than the primary elections, they have to properly give the names and other documents of the candidates to election officials on time (Hale et al. 2015, 44).

The topmost positions of the federal structure vis-a-vis the President and State governors are filled through the primaries but with a differentiation that State governors are chosen in direct primaries – unlike the indirect primaries used for the presidency. The precinct committee members which are at the bottom of the party structures are also chosen through primaries. But between these levels' primaries are absent. Party leaders in Congress, state legislatures, and city councils aren't elected through primaries, and neither are the leaders of state, county, or national committees (Sandri et al. 2016, 42). Broadly, three types of primaries are conducted in the USA of which the direct party primary is particularly relevant for the candi-

date selection.

Non-partisan primaries - These are usually conducted for the elections of local governments, in which party labels are not allowed on the ballot and parties are prohibited from officially endorsing any candidate. A variant of a non-party primary is the non-party blanket primary, in which all candidates, regardless of their party identification, are included on the ballot. If a candidate receives 50 per cent plus 1 of the votes cast, the election is considered a general election and the candidate is deemed to be elected to office. A runoff election will be held if no candidate achieves this share of the vote. The nonpartisan blanket primary was first used in Louisiana in 1978, and a few other states have tried to adopt it since then.

Cross-filing primary- Used in California from 1915 to 1959, this method allowed candidates to stand in more than one party primary. So, a popular Republican could run in both their party's primary and the Democrats' primary, and if they won both, they wouldn't have to worry about facing major party opposition in the general election.

Direct Primary-It is a method in which the primary election results in the nomination of the party's candidate for office and there are no subsequent procedures involved. It was adopted for the majority of public offices between the late nineteenth century and the early twentieth century, although it was used in some places earlier. The consequence of conducting all these primaries resulted in taking the decision over candidate selection away from party-committee rooms and intra-elite negotiations.

There are two sets of rules that influence primaries. Firstly, there are rules governing the involvement of parties in the primary process. Secondly, there are variations within the state laws with regard to who can vote in primary elections. Some states allow anyone to vote in any primary, only with the regulation that they have not voted in the primary more than once while others allow parties to restrict voting to only those members of the party who have registered themselves well in advance of the election day. These are commonly known as open and closed primaries. There are even some states who do not hold separate Democratic and Republican primaries and place all candidates on the same ballot to get the top two candidates who will be placed in the general election (Boatright 2014, 132). Political parties and primaries laws also determine the extent of competition among candidates. There is the absence of formal party membership in the United States and there is no necessity that a candidate who stands for the election in a primary is formally enrolled as a member of the political party. But there have been variations in some American states that have created a greater role for a party in choosing candidates. Some states like Colorado called for the pre-primary endorsing convention in which a certain threshold was maintained for the seeking candidates to be eligible to be placed on the primary ballot. The candidate who received the majority of votes would be placed at the head of the ballot and other candidates were placed in rank order according to their vote share. The consequence of it was that most primary contests were won by those placed first on the ballot (Sandri et al. 2016, 49).

Challenges in conducting Primaries:

The Primaries in the USA were introduced in order to give voters a choice over the selection of candidates and to avoid the manipulation of rules by the party elites. But primaries have come to be characterized by a number of issues including a low level of turnout, insufficient information on choices and a weakening of political parties (Epstein, 1967; Ranney, 1975). Opening up the selectorate for wider and inclusive participation has resulted in low-quality participation and dismissal turnout. The majority of members are 'instant members' who joined the party for the purpose of the primaries, but are likely to abandon the party once the primaries are concluded, many are not even supporters of the party they joined but rather did so to select a specific candidate (Rahat 2008, 76). Primary elections provide parties with the opportunity to attract and mobilize a large number of new members, however this mobilization is short lived, those who lose in the primary may disengage from party activity. Parties conducting primaries would benefit greatly from developing strategies to include those who have lost in the primary into the party and form a more lasting and meaningful relationship with the party rather than their preferred candidate (Bucur & Field, 2018, 52-56). It has also demonstrated the patterns of incumbency advantage in the electoral competition. Incumbents tend to be more likely to be re-elected than non-incumbents in similar presidential electoral districts. Empirical surveys have shown that voters are more inclined to support a congressional candidate whose name they recognize and that incumbents are more often recognized by their constituents than new and outside members (Erikson 1971, 2).

Dynamics of Candidate Selection in USA

There is an interplay of various political and sociological factors which play a critical role in the selection of candidates at the primaries.

Ideology- Candidates who have extreme ideological preferences have more chances of winnability. Compared to ideological candidates (liberal for Democrats and conservative for Republicans), moderate candidates were assessed as 3% less likely to be deemed electable. More ideologically radical candidates also don't seem to suffer among the electorate. This particular trait is considered more viable among Republicans. For Republicans, candidates with moderate views are seen as less electable. On the other hand, there's no similar disadvantage for moderate candidates compared to those with more extreme views among Democrats (Hassell & Visalvanich, 2024, 13).

Race and Ethnicity- The racial and ethnic composition of electorates within a specific state have influenced the political inclinations of the state's voter base. A survey conducted by Pew Research Centre has shown that the Democratic Party maintains a wide support base among Black, Hispanic and Asian American voters whereas the Republican Party has a high support base among White voters. However, this does not show linear and rigid preferences. The changes in demographics and the relative share of ethnic groups impact the partisan alignment of that state over time. For instance, in Florida, historically, Republicans were more inclined to be

Cuban-Americans, making them the largest Hispanic-American ethnic group. Yet, in the last ten years, Puerto Rican-Americans, who lean towards the Democratic Party, have become the state's most rapidly increasing Hispanic-American group, even surpassing Cubans in population. Concurrently, in states such as California and Nevada, Mexican Americans, who generally favor the Democratic Party, are the most prevalent Hispanic-American ethnic group (Igielnik & Budiman, 2020).

Gender- There is a clear positive impact of candidate gender on voting preferences. The overall direct and indirect connections between candidate gender and voting preferences via electability differ based on political party affiliation. Female Democrats exhibit a stronger preference for female candidates compared to female Republicans. The variations in supporting female candidates despite concerns about their electability are influenced by both the demographics of the parties and varying preferences across party lines (Hassell & Visalvanich, 2024, 17).

Religion- The correlation between political affiliation and the religious beliefs of voters remains robust, particularly about their membership in organized religious groups. The Republican Party is mostly supported by Christians that too with a Protestant majority. Around 81% of Christians lean towards Republican candidates. Whereas Democrats maintain a wide diversity along the religion. Democratic coalition. Approximately 54% of the Democratic coalition consists of Christians, with 38% being religiously unaffiliated, and 8% following non-Christian faiths (Pew Research Centre Report, 2024, 33).

Economic factor- Fundraising and Campaigning is another determining factor for candidates' selection as the financial viability for successful fundraising and campaigning is also important. Financial support is a critical factor in gaining party endorsement and voter support (Verdinez & Tierney, n.d).

Method of Candidate Selection in India: Party nomination

Candidate selection in India is primarily done through party nominations. It is inherently limited to political parties and is outside the preview of formal electoral procedures. Parties have their own rules and structures to nominate candidates for party ballots. There are established internal selection procedures in which the proposed nominations begin at the lowest level and progresses to the highest level. This element of decentralization is important in making the candidate selection more inclusive and participatory. The decentralized system improves the level of participation by bringing the selection process closer to the appropriate selectorate. Decentralization of the selection method can be either territorial or functional. It can involve the appointment or selection of party candidates by local party leaders, party agencies, all party members, or voters in a given electoral district. Decentralization can also be functional, including the representation of delegates from trade unions, women's groups, minorities, etc (Rahat 2008, 297-322). But the studies on the process of candidate selection in Indian parties has revealed that despite having decentralized structures for the selection of candidates, the decision-making process is largely centralized in the hands of the political leadership. Palmer (1967, 285) noted

that the selection process for the Congress and the majority of other parties involved the involvement of mandal committees, district committees, state committees and national committees. There was a general acceptance of the recommendations made by the subordinate committees at the state level, though not uniformly. In many instances (they) were unable to reach an agreement and referred the selection of candidates to national committees. There is also unpredictability in the selection of candidates as candidate lists are frequently changed by the parties. Parties often contend to show up the fairness in candidate selection by making it open to all, but in practice winnow out a large number of candidates from the selection process. Support for candidates also comes from long-standing relationships between members and party leaders. These affective connections are used to win favors, share power, and accumulate momentum over time until they reach the point where they are actively lobbying for party nomination. (Singh 2023, 93).

Dynamics of Candidate selection in India:

In the Indian context, there are considerable informal influences and rules that shape candidate selection. The strong influence of background lobbying and the considerable influence of party leaders over nomination choices creates a high degree of unpredictability in the candidate selection process. Apart from these various political and sociological factors shape the nomination process of Indian parties such as :

Party Organization- In the majority of the Indian political parties, the central leadership or the "high command" plays a crucial role in selecting candidates based on surveys and feedback. Candidate's loyalty to the party leadership and performance as a party worker is very much taken into consideration while fielding candidates (Magesan, et al. 2024, 8)

Economic Consideration- Parties are increasingly involved in nominating wealthy candidates who may be advantageous on the part of self-financing by running expensive local campaigns and can mobilise resources to run their own campaigns. Competitive parties (those that finished in the top two in a constituency) selected candidates who were about 20 times wealthier than candidates from non-competitive or minority parties (Sircar, 2018).

Social and Regional Dynamics- Due to the increased federalization of political parties and the rise of coalitions, states have assumed special importance in the Indian political landscape. Big states like UP, MP, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal and Maharashtra hold substantial say in deciding the political fate of parties. Parties typically nominate candidates who are local or have strong ties to the region to ensure better representation and connect with regional sentiments and concerns (Jacob, 2024).

Caste- Political parties aim to create a balanced ticket distribution that appeals to the caste composition of each state (Verniers, 2015). For instance, no political parties can ignore certain castes such as Jats in Punjab, Haryana and Western UP, upper castes, Backward Castes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Yadavs in

Bihar, and UP, Patel and Patidars in Gujarat, Vokkaligas and Lingayats in Karnataka, Kammas and Reddys in Andhra Pradesh (Kumar A. 2022) .

Religion- In India religion as a factor is identified in terms of Hindu and Muslims voters. Religion has assumed special importance the post-Babri mosque incident and the rise of BJP with its agenda of Hindutva. Religion has an impact in the local community and influences the choice of candidates particularly in the states like UP, West Bengal and Bihar where there is a sizable population of Muslims (Jain, K. 2014).

Gender - The realm of Indian politics is certainly dominated by men and political parties at times oppose the nomination of female candidates. This is particularly evident from the nomination patterns of Indian parties where they field women candidates from the least significant areas or where male politicians are least powerful. The existing quota system appears to have interacted with these efforts in a way that benefited minority-group women. There has been a substantial increase in the nomination of minority-group women compared to other women in recent years (Jensenius, 2016, 459).

Comparative Analysis:

If we compare both the electoral systems Indian political parties have a more centralized candidate selection process compared to the USA, where the primary and caucus system decentralizes the selection. Besides, in the USA, the general public specifically registered party members have a more direct role in candidate selection through primaries and caucuses, while in India, party members and leaders have a more significant influence. Further, the legal and electoral frameworks guiding the selection process differ, with India's Election Commission having a substantial regulatory role and the USA has state-specific rules for primaries and caucuses. These dynamics reflect broader cultural, historical, and institutional differences between the two countries' political systems.

Discussion on optimal Balance:

Regulating Political Parties: Public-Private dichotomy

The fundamental precept that political parties emerged as civic organizations for the interest aggregation and articulation of the masses has raised important concerns about their functioning as the public or private institution of society. The public–private dichotomy is particularly important in the context of state regulation which necessitates the fundamental inquiry of whether political parties form the part of the state apparatus and whether the state has the power to regulate the functioning of political parties and to what extent. If political parties are classified as public organizations, the regulation of political parties, their internal activities, and the manner in which political parties compete for power may be morally acceptable, for example, to promote specific democratic principles (e.g., intra-party democracy), or to achieve desired outcomes (e.g. quotas for gender or minority groups in candidate selection contests).

On the other hand, if they are considered as private entities, then the state regulation (especially with regard to candidate selection and other anti-discriminatory provisions) may be viewed as forced intrusion in the autonomy of these independent political entities and an unnecessary interference with citizens' freedom of political expression (Gauja 2010, 12). The public-private distinction does not advance the argument that political parties are, or are becoming, agents of the state as it is commonly seen that sometimes parties may register and compete in elections and become public entities, but they may never reach public office or receive state funding. Alternatively, some political parties may be able to achieve political representation and state support, but remain private organizations internally, without demanding external scrutiny. It is also difficult to categorize political parties as either public or private entities on the part of unitary factors as and when the members of the party act as individual or organizational members. People voluntarily join these organizations to promote their political interests, which highlights the role of political parties as private vehicles for political expression in civil society. The interpretation of parties as public or private entities will evolve depending on functional priorities – between people and over time (ibid).

Conclusion:

The article has analyzed candidate selection as a key means of electoral participation in the context of candidates who stand up as electoral contestants and the selectorates who take part in the selection of these candidates. It is inherently the function of political parties to choose and nominate candidates for elections. There are various candidate selection methods adopted by the parties worldwide. The model of American and Indian candidate selection as presented here stand on the extreme sides of inclusivity vs exclusivity which have their own consequences.

The discussion here reveals that opening up the space of candidate selection for common voters has resulted in the selection of candidates with no political experience and allegiance to the party objectives. It has weakened party cohesion which is much needed in parliamentary democracies like India. On the other hand, the exclusive and unregulated selection of candidates by political parties in India has made the selection process highly limited and opaque in nature. Candidate selection is also pivotal for intra-party democracy, as it plays a critical role in ensuring that representatives remain responsive and accountable within the political system. Hence, there is the need to place in statutory regulations on the internal functioning of political parties keeping in mind their importance as vehicles of political expression and participation.

❐

References :

1. *Boatright, R. G. (2014). Congressional Primary Elections. Routledge.*
2. *Bucur, C., & Field, B. (2018). Selecting presidential candidates in European semi-presidential democracies. In Democratizing candidate selection: New methods, old receipts? Springer.*
3. *Colomer, J. (2004). The handbook of electoral system choice. Palgrave.*

4. *Epstein, L. D. (1967). Political parties in western democracies. Praeger.*
5. *Erikson, R. S. (1971). The advantage of incumbency in congressional elections. Polity, 3(3), 395–405. https://doi.org/10.2307/3234117*
6. *Gallagher, M. (1988). Introduction. In Candidate selection in comparative perspective. Sage.*
7. *Gauja, A. (2010). Political parties and elections: Legislating for representative democracy. Ashgate Publication Company.*
8. *Grofman, B. (2002). Introduction. In The evolution of electoral and party systems in the Nordic countries. Agathon Press.*
9. *Hale, K., Montjoy, R., & Brown, M. (2015). Administering elections: How American elections work. Springer.*
10. *Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). Democracy within parties: Candidate selection methods and their political consequences. OUP Oxford.*
11. *Hassell, H. J. G., & Visalvanich, N. (2024). Perceptions of electability: Candidate (and voter) ideology, race, and gender. Political Behavior. https://doi.org/10.1007/s11109-023-09909-3*
12. *Igielnik, R., & Budiman, A. (2020, September 23). The changing racial and ethnic composition of the U.S. electorate. Pew Research Center. Retrieved July 7, 2024 from https://www.pewresearch.org/social-trends/2020/09/23/the-changing-racial-and-ethnic-composition-of-the-u-s-electorate/*
13. *Jacob, S. (2024, March 31). Regional dynamics of Congress and BJP support: What do past elections tell us? Ala / ??. Retrieved July 8, 2024 from https://alablog.in/issues/66/bjp-congress-elections-translation/*
14. *Jain, K. (2014, May 8). Religion and the Indian election. Harvard Gazette. Retrieved July 7, 2024 from https://news.harvard.edu/gazette/story/2014/05/religion-and-the-indian-election/*
15. *Jenkinson, C. S. (2022, May 29). Why does America have primaries? Governing. Retrieved June 2, 2024 from https://www.governing.com/context/why-does-america-have-primaries*
16. *Jensenius, F. R. (2016). Competing inequalities? On the intersection of gender and ethnicity in candidate nominations in Indian elections. Government and Opposition, 51(3), 440–463.*
17. *Kumar, A. (2022, February 23). BSP's going solo in UP, but ticket distribution tells a different story. Theprint. Retrieved July 8, 2024 from https://theprint.in/opinion/bsp-going-solo-in-up-but-ticket-distribution-suggests-its-attempting-coalition-of-extremes/843141/*
18. *Magesan, A., Szabo, A., & Ujhelyi, G. (2024). Candidate selection by parties: Crime and politics in India. Canadian Public Economics Group Meetings. Retrieved June 28, 2024 from https://uh.edu/~gujhelyi/AAGS.pdf*
19. *Ostrogorski, M. (1964). Democracy and the organization of political parties, Volume 1. Anchor Books.*
20. *Palmer, N. D. (1967). India's fourth general election. Asian Survey, 7(5), 275–291. https://doi.org/10.2307/2642657*
21. *Personen, P. (1968). An election in Finland: Party activities and voter reactions. Yale University Press.*
22. *Pew Research Center. (2024, April). Changing partisan coalitions in a politically divided nation. Retrieved July 8, 2024 from https://www.pewresearch.org/politics/2024/04/09/changing-partisan-coalitions-in-a-politically-divided-nation/*
23. *Rahat, G. (2008). Which candidate selection is more democratic. In CSD Working Papers. Univer sity of California, Irvine.*
24. *Ranga, A. (2019). Role of Election Commission in India: Issues and challenges, PhD Thesis. Shodhganga. http://hdl.handle.net/10603/305617*
25. *Ranney, A. (1975). Curing the mischiefs of faction: Party reform in America. Univ of California Press.*
26. *Reiser, M. (2023). The informal rules of candidate selection and their impact on intra-party compe tition. Party Politics, 30(1), 85–95. https://doi.org/10.1177/13540688231172336*
27. *Roy, R. (1966). Selection of Congress candidates. Economic and Political Weekly, 1(20), 833–840.*
28. *Sandri, G., & Seddone, A. (2016). Party primaries in comparative perspective. Routledge.*
29. *Shugart, M. (2005). Comparative electoral systems research: The maturation of a field and new*

challenges ahead. In The politics of electoral systems. Oxford University Press.
30. *Singh, R. (2023). Candidate selection in India: Municipal elections and the Bharatiya Janata Party (BJP). Commonwealth & Comparative Politics, 61(1), 90–114. https://doi.org/10.1080/14662043.2023.2172792*
31. *Sircar, N. (2018). Money matters in Indian elections: Why parties depend on wealthy candidates. Carnegie Endowment for International Peace. Retrieved July 7, 2024 from https://carnegieendowment.org/posts/2018/07/money-matters-in-indian-elections-why-parties-depend-on-wealthy-candidates?lang=en*
32. *Verdinez, D., & Tierney, K. (n.d.). Why money is so important in US elections. Portland Communi cations. Retrieved June 30, 2024 from https://portland-communications.com/us-presidential-election/why-money-is-so-important-in-us-elections/*
33. *Verniers, G. (2015, November 5). Role of caste in elections. Outlook India. Retrieved July 8, 2024 from https://www.outlookindia.com/national/role-of-caste-in-elections-news-295807*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 192–201

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Understanding the Role of Information, Education and Communication Activities in Swachh Bharat Mission

Neelesh Vigyanvratam
Doctoral Fellow, Department of Political Science,
Banaras Hindu University, Varanasi-221005
E-mail: neeleshvigyanvratam@bhu.ac.in

Abstract

The Swachh Bharat Mission (SBM), launched in 2014 by the Government of India, aims to achieve universal sanitation coverage and eliminate open defecation. Central to its success are Information, Education, and Communication (IEC) activities this research paper investigates the role of (IEC) activities in bridging the gap between policy formulation and implementation within the context of the SBM. Through a comprehensive literature review and empirical analysis, this study examines the design, implementation, and impact of IEC interventions within the SBM framework. It explores the effectiveness of various communication strategies, channels, and tools utilized to raise awareness, change behaviour, and promote sustainable sanitation practices at the grassroots level. Moreover, this paper evaluates the IEC activities and identifies key lessons learned for improving the integration of communication strategies into sanitation policies and programs. By elucidating the nexus between policy formulation and practice through the lens of IEC, this research contributes valuable insights to the discourse on sanitation governance and underscores the importance of strategic communication in driving behaviour change and achieving sustainable development goals.

Keywords: Swachh Bharat Mission; Information, Education and Communication; Sanitation; Governance; Behavioural Change;

Introduction

The Swachh Bharat Mission (SBM), initiated by the Government of India in 2014, represents one of the most ambitious cleanliness and sanitation campaigns in the world, aiming to achieve universal sanitation coverage and eliminate open defecation by 2nd October 2019, the 150th birth anniversary of Mahatma

Gandhi. Rooted in the principles of public health, environmental sustainability, and social equity, the SBM encompasses a comprehensive set of policies, programs, and interventions to address the multifaceted challenges of poor sanitation and hygiene practices prevalent across the country. While significant progress has been made towards sanitation infrastructure development and toilet construction, the translation of SBM policies into tangible improvements in sanitation behaviour and practices at the grassroots level remains a formidable task.

The effectiveness of sanitation policies and programs hinges not only on the adequacy of infrastructure provision but also on the ability to induce behavioural change and sustain sanitation practices over time (Gaurav, 2018)[1]. As highlighted by Datar, Mahajan, & Das (2019)[2], the success of the SBM depends crucially on its capacity to engage communities, raise awareness, and foster behavioural change towards hygienic practices and toilet usage. Information, Education, and Communication (IEC) activities play a pivotal role in this regard, serving as key mechanisms for disseminating information, influencing attitudes, and catalyzing behaviour change (Matsubayashi, 2020)[3].

However, despite the recognition of IEC as an integral component of sanitation programming, there exists a gap in understanding the dynamics of communication strategies and their impact on sanitation behaviour within the context of the SBM. While several studies have examined the policy dimensions and infrastructure investments of the SBM, there is limited empirical research that systematically evaluates the design, implementation, and effectiveness of IEC interventions in driving behavioural change and sustaining sanitation outcomes (Pandey & Pal, 2019)[4]. Thus, there is a pressing need to bridge this knowledge gap and comprehensively assess the role of IEC activities in translating SBM policies into practice.

Review of Literature

Varun Gauri, Tasmia Rahman, and Iman K Sen (2020): The research paper focuses on addressing the challenge of reducing open defecation in rural India by understanding and influencing social norms related to latrine use. The study measures social norms through beliefs about what others do (social empirical expectations) and beliefs about what others believe to be normatively appropriate (social normative expectations). By disaggregating social norms into these components, the research aims to develop interventions that can effectively change behaviour. The research also highlighted the importance of understanding and addressing social norms to promote positive behaviours like latrine use. Overall, the research emphasizes the significance of social norms in shaping behaviours and the effectiveness of targeted interventions in promoting positive changes in sanitation practices in rural India[5].

Gadadhara Mohapatra (2019): The paper discusses the Swachh Bharat Mission (SBM) in India from a public policy perspective, focusing on the shift from toilet construction to achieving behavioural outcomes like an open-defecation-free India by 2019. It emphasizes the importance of grassroots-level-trained motivators for

generating demand for toilets and cleanliness. The paper also highlights the need to accelerate behavioural change and Information, Education, and Communication (IEC) activities at a wider scale to meet the mission's goals. The SBM's approach is inspired by participatory rural appraisal and emphasizes triggering behavioural change through shame and disgust to promote hygiene and sanitation. The paper also discusses the challenges in integrating systematic IEC and Interpersonal Communication (IPC) elements into the SBM and the importance of community-level information about sanitation[6].

Rachel Sigler, Lyana Mahmoudi and Jay Paul Graham (2014): This research paper discusses the analysis of behavioural change techniques in community-led total sanitation (CLTS) programs. It explores the common behaviour change frameworks and techniques used in CLTS interventions, how these activities are implemented in various regions, and which activities are most effective in promoting sanitation behaviours. The study utilized a taxonomy of behaviour change techniques to create a questionnaire for program managers, gathering data on the activities conducted in CLTS interventions. The survey was administered online to project directors, and the results were analyzed to identify trends in behaviour change models and regional demographics. The study highlights the importance of understanding and applying effective behaviour change techniques to promote community sanitation practices[7].

Samuel Ginja, Stephen Gallagher & Mickey Keenan (2021): This research paper emphasizes the critical need to analyze contingencies of reinforcement in WASH behaviour change research. It highlights that despite the potential of safe WASH practices to reduce diarrheal diseases, current behaviour change interventions have had limited success. The paper argues for a shift towards a contingency-based perspective, focusing on the antecedents and consequences of behaviour, particularly the role of reinforcement in shaping behaviour. The authors suggest that understanding and manipulating contingencies of reinforcement, including contrived reinforcers to counterbalance natural reinforcers of convenience associated with risky practices, can be instrumental in designing effective behaviour change strategies. They stress the importance of considering both antecedents and consequences of behaviour, as well as the selection of appropriate reinforcers to sustain desired behaviours over time. Furthermore, the paper discusses the significance of social reinforcement, such as community support and recognition, in promoting long-term behaviour change. By gradually withdrawing contrived reinforcers, researchers can assess the maintenance of behaviour change and the presence of naturally occurring reinforcers that support sustained practice[8].

Christoph Lüthi, Jennifer McConville and Elisabeth Kvarnström (2009): This research paper discusses the importance of community involvement in addressing urban sanitation challenges. It highlights the effectiveness of Community-Led Total Sanitation (CLTS) in rural and peri-urban settings, emphasizing the need for collective action and involvement of the entire community in achieving Open

Defecation Free (ODF) status. The paper also introduces the Household-Centered Environmental Sanitation (HCES) approach, which focuses on developing people's capacity, skills, and local knowledge in urban contexts. It stresses the significance of participatory planning principles, relevant participation, and flexible planning frameworks to promote community-based action. The paper underscores the role of natural leaders, and local politicians, and the importance of sensitizing all stakeholders in driving successful sanitation initiatives. Additionally, it discusses the challenges faced by CLTS in urban settings related to local politics and technology subsidies, emphasizing the need for institutional support and knowledge for developing appropriate sanitation systems[9].

Objective and Methodology

The objective of this research paper is to comprehensively explore and analyze the effectiveness of Information, Education, and Communication (IEC) activities within the Swachh Bharat Mission (SBM) in India. This study aims to understand how these activities influence the adoption of sanitation practices and the overall success of the SBM. By investigating the implementation of IEC strategies at various levels, including national, state, and local, the research intends to identify key factors that contribute to the translation of policy objectives into practical outcomes on the ground.

The present study is based mainly on secondary sources of data, collected from books, research articles, and government reports from various ministries.

Need for Behaviour Change Communication (BCC)

According to the World Bank, there was an increase in rural sanitation coverage in rural India from 1% in 1981 to 24.7% in 2012. However, the construction of latrines and access to sanitation have not led to regular usage by all family members. As a result, open defecation continues as a widely accepted practice with a detrimental impact on health, livelihoods and the economy. People in rural India despite having toilets are reluctant to use them and practice open defecation.

Even though it is commonly acknowledged that personal hygiene and sanitation are extremely important, as few as 39% of Indians have access to proper sanitation up to 2014. Before 2014, almost 55 crore people lived in rural areas without access to toilet facilities. The health and dignity of rural people especially women and children were seriously impacted by the lack of toilets.

It was not that sanitation initiatives were not attempted before. India has made efforts over the past few decades to provide clean and safe sanitation access. But even after 32 years of independence, the sanitation coverage was only 2% in 1982. To provide rural sanitation, the Central Rural Sanitation Program (CRSP) was launched in 1986. However, the primary focus of CRSP was on building toilets and allocating funding for them; behaviour modification was not given much attention. Consequently, the supply-based strategy failed to produce the desired outcomes. Due to the limitations of this programme, The Total Sanitation Campaign (TSC) in

1999 and The Nirmal Bharat Abhiyan were introduced in 2012. However, these programs also failed to have an impact because they lacked strong political will, leadership, and a behaviour change approach. These programmes rely on the supply-driven approach of toilet construction rather than the demand-driven approach. Previous sanitation programmes fail to generate awareness level among people. They were unable to generate demand for toilet construction and their sustainable usage. This was mainly because of the lack of planned BCC techniques and poor implementation of IEC activities.

Due to this the rural sanitation coverage in 2011 was 29.70 per cent (Census, 2011)[10]. In 2014, before the launch of SBM, the rural sanitation coverage was close to 38.70 per cent which represents the poor condition of health and sanitation facilities in rural areas. The poor performance of previous sanitation programmes in rural India and the lack of demand for toilets construction further deteriorated the conditions. The lack of demand for toilets and centuries-old traditions and habits of people need to be changed to achieve sanitation goals. **Behaviour Change Communication (BCC)** techniques incorporated in SBM to change the habits of people by modifying people's behaviour and creating toilet infrastructure demand in rural and urban areas. BCC techniques such as IEC, CLTS, and Community Approaches to Sanitation (CAS) are used in SBM to modify the behaviour of people.

SBM was launched in 2014 as a people's movement to end open defecation. In earlier sanitation programmes people were not aware of the harmful impact of open defecation on health and well-being. In the previous sanitation programme, the participation of citizens was negligible. This was the main reason for the dismal performance of the programmes. At the same time, lack of political will and strong leadership was also responsible for the practice of open defecation. SBM not only relies on BCC techniques but also incorporates the creation of toilet demand from the citizens. BCC helps in raising the people's awareness level regarding the harmful consequences of open defecation. It also gives a new dimension of thought to women and adolescent girls. BCC helps protect women's dignity by creating demand for toilets among rural women.

The Swachh Bharat Mission recognises that improving sanitation and promoting cleanliness requires not only the implementation of policies and interventions but also effective information, education and communication activities (Bala, 2022)[11]. Information, education, and communication activities play a crucial role in the success of the Swachh Bharat Mission by raising awareness about the importance of cleanliness and sanitation, promoting behaviour change, and engaging communities in the process (Khare and Suresh, 2023)[12]. These activities help bridge the gap between policy and practice, by translating the goals and objectives of the Swachh Bharat Mission into tangible actions at the grassroots level. One source highlighting the importance of information, education, and communication activities in the Swachh Bharat Mission is a statement by Coates, who emphasizes the complexity of tackling development scenarios related to cleanliness and sanitation. Another important

aspect of information, education, and communication activities in the Swachh Bharat Mission is creating awareness about the impact of environmental problems caused by poor sanitation practices. One study highlights the need for environmental discourse to show community members the disastrous consequences of environmental problems caused by poor sanitation practices. These activities not only address the health impacts of inadequate sanitation but also highlight the economic and environmental benefits of improved sanitation practices. Improving sanitation and promoting cleanliness through the Swachh Bharat Mission not only has direct health benefits but also contributes to achieving other global health and non-health objectives.

Role of Information, Education, and Communication in SBM

- **Information Dissemination**- IEC activities under SBM focus on disseminating crucial information regarding the importance of sanitation, health hazards associated with open defecation, and the benefits of adopting proper sanitation practices. This is achieved through various channels such as mass media campaigns, community meetings, and educational materials distributed at the grassroots level (Ministry of Drinking Water and Sanitation, 2018)[13].

- **Education and Awareness -** Education forms the cornerstone of behaviour change initiatives within SBM. Educational campaigns targeting different demographics, including children, women, and community leaders, aim to raise awareness about sanitation and hygiene practices. These campaigns often utilize innovative approaches such as street plays, interactive workshops, and school curriculum integration to impart knowledge and instill behavioural change (WaterAid India, 2019)[14].

- **Behaviour Change -** SBM employs various communication channels, including interpersonal communication through trained volunteers, social media campaigns, and community-led initiatives, to engage stakeholders at the grassroots level. By empowering communities to take ownership of sanitation initiatives, SBM promotes sustainable behaviour change among people (Bhatnagar & Jain, 2017)[15].

- **Community Mobilization** - Effective communication strategies are deployed to mobilize communities and foster collective action towards sanitation goals. This involves engaging stakeholders through interpersonal communication, social media campaigns, and community-led initiatives (Patel et al., 2020)[16].

- **Empowerment and Ownership** - IEC activities empower communities to take ownership of sanitation initiatives by fostering a sense of collective responsibility. By encouraging community participation and leadership, these activities contribute to sustainable behaviour change and the maintenance of sanitation infrastructure (Garg & Nagpal, 2018)[17].

- **Targeted Messaging** - IEC interventions employ targeted messaging to reach diverse populations across urban and rural landscapes. By tailoring communication strategies to specific demographics and cultural contexts, these initiatives

ensure the effective dissemination of sanitation-related information (WaterAid India, 2019)[18].

- **Monitoring and Evaluation** - IEC activities are continuously monitored and evaluated to assess their effectiveness in achieving behaviour change and sanitation objectives. This involves collecting feedback from communities, measuring the uptake of sanitation practices, and identifying areas for improvement to optimize the impact of communication interventions (Ministry of Drinking Water and Sanitation, 2018)[19].

IEC Activities Under SBM

- **Inter-Personal Communication (IPC)–** This strategy's key approach is to raise awareness about the importance of sanitation among the rural community and support the increased interest and willingness to uptake sanitation and hygiene practices, it helps in providing detailed information to the audience. It also allows for immediate feedback on ideas, messages and practices. Interpersonal communication will effectively use existing social networks or interpersonal relationships (family, friends, acquaintances, neighbours and colleagues) that bind people together to enhance the communication process. IPC is a key tool in the drive for increasing awareness and actual toilet construction and usage. It will be used extensively for follow-up, especially after households realize the benefits of toilets to ensure toilet construction and use. Frontline workers, community leaders, volunteers and multiple social networks, including religious groups, clubs and community gatherings will promote sanitation and hygiene using interpersonal communication.

- **CAS Training of Swachhagrahis –**Swachhagrahis or Ambassadors of Cleanliness are volunteers who promote the construction and use of toilets using a popular method called Community Led Total Sanitation at the village level. The most important IEC activity is the training of grassroots motivators in Community Approaches to Sanitation (CAS). The Ministry of Drinking Water and Sanitation has empanelled many Key Resource Centres (KRCs) for sanitation. These KRCs conducted many CAS training to raise awareness regarding sanitation. Swachhagrahis conducted 'Nigrani' activities which include early morning visits to common open defecation spots in the village.

- **Mass Media –** Mass media can be used to communicate effectively with a large number of people with impact. It overcomes barriers of literacy, gender, geography or language. It is ideal for delivering a simple, clear and focused message. Although there are several media-dark areas in the country, there has been rapid progress towards increased TV and radio coverage and penetration. Release of the film 'Toilet Ek Prem Katha' and other documentaries are part of a mass media campaign and used to raise awareness level among citizens.

- **Digital Media –** Due to its interactive mode of communication, digital media plays a critical role in raising awareness and promoting social interactions. Digital media can include podcasts, audiobooks, articles, ads, music, films, digital art, and

Over-the-Top (OTT) content. It can be used to spread awareness related to sanitation-related content among its citizens. It can be used for the dissemination of key messages to promote critical behaviours and mission information through social media channels like Twitter, Facebook, YouTube, and Instagram and to facilitate the exchange of thoughts and ideas.

Major SBM Campaign and IEC Activities

The following are the major IEC activities under the SBM campaigns:

Darwaza Bandh Media Campaigns – To change the sanitation behaviour of people, an aggressive mass media campaign 'Darwaza Band' was launched featuring Amitabh Bachchan to promote the continued use of toilets especially among men.

Shaucha Singh Radio Campaigns – To change the old practice of open defecation, a special radio campaign aimed at behaviour change has been created and launched around a central character, salesman 'Shaucha Singh' who educates, informs and creates mass awareness on the importance of Safe Sanitation & ODF.

Swachh Shakti – Swachh Shakti was organised on March 8, 2017, on the occasion of the International Women's Day. Around 6000 selected women sarpanches and grassroots workers from across the country attended the event.

Freedom from Open Defecation (FOD) week – One week from Aug 9 to Aug 15 dedicated to IEC activities like door-to-door IPC, Swachhata Raths, Rallies, Marathons, Felicitation of Champions, Quiz/painting competitions for Awareness generation and mass mobilization of communities across the rural hinterland was carried out for triggering Behaviour Change.

Swachh Sankalp se Swachh Siddhi Competition – In the pursuit of the vision of Prime Minister 'Sankalp se Siddhi', the then Ministry of Drinking Water and Sanitation organised a Film, Essay and Painting Competition between 17 August and 8 September 2017 all across the country. This helped SBM in making the People's Movement.

Swachhata Hi Seva – In his 'Man ki Baat' address Prime Minister, called the nation to invoke a spirit of cleanliness and perform activities or SHRAMDAN and urged all schools, colleges, social and cultural leaders, political leaders, NGOs, government officials and sarpanches to accelerate cleanliness related activities.

Swachhata Rath - Roll out of 'Swachhata Rath' across the villages proved to be a very effective IEC strategy for engaging community members using IPC and IEC materials primarily Audio-Visual (AVs) and printed panels with key messages on various themes. More than 1200 Swachhata Raths ran across the country as part of various SBM-G campaigns.

Conclusion

IEC activities have been instrumental in disseminating crucial information, raising awareness, and fostering behavioural change regarding sanitation and hygiene practices among diverse demographic groups. Mass media campaigns, community

outreach programs, educational workshops, and interpersonal communication have collectively contributed to increasing knowledge and promoting the adoption of safe sanitation behaviours. The success of SBM's IEC initiatives lies in their ability to engage communities, empower individuals, and mobilize collective action towards sanitation goals. By fostering community ownership and participation, these activities have not only facilitated behaviour change but also promoted the sustainability of sanitation interventions at the grassroots level (Bhatnagar & Jain, 2017)[20]. While significant progress has been made, challenges remain in ensuring the effectiveness and scalability of IEC activities within SBM. Limited access to information in remote areas, cultural barriers, and the need for continuous monitoring and evaluation poses ongoing challenges that require innovative solutions and sustained efforts. Moving forward, it is essential to build upon the successes of SBM's IEC interventions while addressing existing challenges. This entails leveraging technology, enhancing community participation, and tailoring communication strategies to diverse contexts to maximize impact and achieve sustained sanitation outcomes nationwide.

❐

References :

1. *Gaurav, A. (2018). Making Swachh Bharat Mission a Success. Yojana, 62(11), 15-18.*
2. *Datar, S., Mahajan, P., & Das, R. (2019). Swachh Bharat Mission: Sanitation in India. Economic and Political Weekly, 54(25), 19-22.*
3. *Matsubayashi, T. (2020). Improving Community Health Through Sanitation in Rural India: Evi dence from the Swachh Bharat Mission. World Development, 136, 105117.*
4. *Pandey, A., & Pal, R. (2019). Swachh Bharat Mission and Sanitation in India: A Review. Interna tional Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), 4(2), 1-6.*
5. *Gauri, V., Rahman, T., & Sen, I. (2020b). Shifting social norms to reduce open defecation in rural India. Behavioural Public Policy, 7(2), 266–290. https://doi.org/10.1017/bpp.2020.46*
6. *Mohapatra, G. (2019). Projected Behavioural Change in Swachh Bharat Mission: A Public Policy Perspective. Indian Journal of Public Administration, 65(2), 451-474.*
7. *Sigler, R., Mahmoudi, L., & Graham, J. P. (2015). Analysis of behavioral change techniques in community-led total sanitation programs. Health promotion international, 30(1), 16-28.*
8. *Ginja, S., Gallagher, S., & Keenan, M. (2019). Water, sanitation and hygiene (WASH) behaviour change research: why an analysis of contingencies of reinforcement is needed. International Jour nal of Environmental Health Research, 31(6), 715–728. https://doi.org/10.1080/ 09603123.2019.1682127*
9. *Lüthi, C., McConville, J., & Kvarnström, E. (2009). Community-based approaches for addressing the urban sanitation challenges. International Journal of Urban Sustainable Development, 1(1–2), 49–63. https://doi.org/10.1080/19463131003654764*
10. *https://censusindia.gov.in/census.website/data/data-visualizations/Sanitation_Gauge-Chart*
11. *Bala, A. (2022). Societal awareness towards activities related to swachh bharat abhiyaan: a cross sectional study. International Journal for Multidisciplinary Research, 04(04), 540-552. https:// doi.org/10.36948/ijfmr.2022.v04i04.061*
12. *Khare, K. and Suresh, L. (2023). Justice and sanitation governance: an enquiry into the implemen tation of the swachh bharat mission-rural programme in up, india. Water Policy, 25(4), 379-398. https://doi.org/10.2166/wp.2023.187*
13. *Ministry of Drinking Water and Sanitation. (2018). Swachh Bharat Mission (Gramin) - IEC Guidelines.*
14. *WaterAid India. (2019). Sanitation Behaviour Change Communication (BCC) Strategy 2019-2022.*

15. *Bhatnagar, T., & Jain, N. (2017). Community-Led Total Sanitation and Information, Education, and Communication: A Review of Evidence.*
16. *Patel, R. B., et al. (2020). Impact of Swachh Bharat Mission on Knowledge, Practice, and Coverage of Handwashing with Soap and Sanitation: A Systematic Review.*
17. *Garg, S., & Nagpal, J. (2018). Behaviour Change Communication in Swachh Bharat Mission (Grameen): An Evidence-based Study.*
18. *Ibid*
19. *Ibid*
20. *Bhatnagar, T., & Jain, N. (2017). Community-Led Total Sanitation and Information, Education, and Communication: A Review of Evidence.*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 202–217

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Assessment ot Healthcare Expenditure and Accessibility A Case Study on Kannur District of Kerala

Dr. Manohar V. Serrao
Associate Professor, Department of Economics,
St. Aloysius (Deemed to be University), Mangaluru, Karnataka -575003

Dr. Alwyn Stephen Misquith
Assistant Professor, Department of Economics,
St. Aloysius (Deemed to be University), Mangaluru, Karnataka, India -575003
E-mail: alwyn_misquith@staloysius.edu.in Mob: 9538189529

Janvi P. V.
St. Aloysius College (Autonomous), Mangaluru-575003
E-mail: janviprabhakaran95@gmail.com

ABSTRACT

Health is the most integral part of human life. Enjoying good health is rightly related to leading a fruitful lifestyle. In India healthcare is provided by both public and private sectors. During 2023 around 2% of central Governments expenditure was spent on the department of health and family welfare (PRS India 2023-24).[1] With a population of over 2.4 million and a literacy rate of 95.10%, Kannur is a vibrant district in Kerala, India, that is dedicated to improving its healthcare standards. In an effort to improve Kannur's healthcare system and identify areas for improvement, this study looks at healthcare spending and the perceptions of the services. The study aims to analyse the socioeconomic situation of the participants, evaluate the quality, accessibility, and efficiency of healthcare services, and propose methods to improve healthcare availability, affordability, and access, with a particular focus on the "Aardram" program. The study is based on primary data which is collected from 100 Kannur locals through direct interview method with the help of a structed questionnaire the respondents were selected randomly. The study is based on the objectives such as to study the socio-economic conditions of respondents of Kannur District, to examine the quality, accessibility, and effectiveness of healthcare services, in meeting the healthcare needs of the population in Kannur district, to make suggestions for increasing healthcare availability, affordability and accessibility in Kannur District with special reference to "Aardram" initiative.

Keywords: Healthcare Accessibility, Healthcare expenditure, Healthcare system, Primary healthcare.

INTRODUCTION:

Kannur, known as "The Theyyam Land" or "The Land of Looms and Lores," is a district in Kerala renowned for its trade, commerce, and nautical history. The serene Payyambalam Beach offers a peaceful retreat. With a metro population of over 2.4 million and a literacy rate of 95.10%, Kannur is committed to enhancing healthcare access and quality. The district's inclusive development vision prioritizes health as a fundamental right, investing in improved basic care facilities and innovative health programs tailored to its diverse community (Kerala Tourism Guide 2024).[2]

The wisdom of implementing comprehensive or selective primary health care (PHC) has been up for debate ever since the World Health Organization's Alma Ata Declaration on PHC. The latter's proponents contend that a more focused strategy will yield short-term benefits, while supporters of a comprehensive strategy contend that it is necessary to address the root causes of illness and enhance health outcomes in a long-term manner. The private sector is the predominant source of inpatient care in urban Kerala. The public sector has an important role in providing access to care for the poor. Investing in the quality of public services is essential to ensure equity in access (Levesque J. F. et al 2007)[3]. Records indicate that because of the decentralization and healthcare being a state's responsibility, a considerable disparity can be observed in the health-care delivery standards among different states; some states are still struggling, whereas others display enormous improvements. Kerala is well known for maintaining one of the best healthcare system in the country for decades. According to experts, irrespective of its low per capita income, Kerala's health system has excelled and continuously garnered national and international attention. (Muraleedharan M. & Chandak A.O. 2021)[4].

Kerala is one of the most decentralised states in India, with improved access to healthcare services and better outreach activities based on 'wellness', attributable to contributions from local governments (LG). However, Kerala had lately been experiencing a relative failure to cater to changing health needs of the population, along with increasing privatisation and high out-of-pocket (OOP) expenditure. In the backdrop of the Sustainable Development Goals (SDGs), the state of Kerala, India, revamped its existing primary health centres (PHCs) into people-friendly family health centres (FHCs) to provide comprehensive primary care as part of a mission-based (Aardram) initiative (Krishnan, R. P. et al March 2023)[5].

Despite significant efforts, challenges persist in Kannur's healthcare system. This study evaluates healthcare expenditure patterns and perceptions in Kannur, Kerala, through a detailed questionnaire survey. It covers demographic information, healthcare costs, financial challenges, accessibility, affordability, and satisfaction with healthcare services. Findings reveal diverse expenditure patterns, financial difficulties, and funding sources. The study examines perceptions of affordability, accessibility, and satisfaction, providing insights into residents' experiences and preferences. This research advocates for equitable healthcare access and quality for all, aiming to empower the community through detailed analysis and engagement.

REVIEW OF LITERATURE:

The "Kerala model of development" became a widely used term after the survey conducted by the Centre for Developmental Studies on poverty and unemployment in 1975. According to experts, irrespective of its low per capita income, Kerala's health system has excelled and continuously garnered national and international attention (Sara John 2018).[6] The state of Kerala in the country of India has been getting on the wrong side of nature over the past few years. From raging floods to massive outbreaks of viral diseases, the state of Kerala has been in turmoil over the past few years (S. Datta 2019).[7] Kerala's health gains are uneven in a closer analysis between districts, population groups, and age groups. The apparent impressive gains of overall averages hide that many are being left behind (Joe Thomas 2021).[8] The 'Ardram' Mission under the 'Nava Kerala' initiative has transformed the Primary Health Centres (PHC) into Family Health Centres (FHC), capable of meeting the healthcare needs of all members of the family extending preventive, promotive and rehabilitative healthcare interventions of local community (PRC Report Series 2020).[9] It has been pointed out that the private provision of health care services will be discriminatory against the rural population. the poor and the chronically sick (Sadanandan. R. 2001).[10] Kerala state is known for its highly literate and female literate, and poor income population, but it's well-advanced state of demographic transition. There is a declining population growth rate, a high average marriage age, a low fertility rate, and a high degree of population mobility. One of the unique features of Kerala is the high female literacy, and the favourable position of women in decision making and a matrilineal inheritance mode. The rights of the poor and underprivileged have been upheld. (Anumol. P.S 2018).[11] Kerala is one of the most decentralised states in India, with improved access to healthcare services and better outreach activities based on 'wellness', attributable to contributions from local governments (LG). However, Kerala had lately been experiencing a relative failure to cater to changing health needs of the population, along with increasing privatisation and high out-of-pocket (OOP) expenditure. In the backdrop of the Sustainable Development Goals (SDGs), the state of Kerala, India, revamped its existing primary health centres (PHCs) into people-friendly family health centres (FHCs) to provide comprehensive primary care as part of a mission-based ('Aardram') initiative (Krishnan, R. P. Varma, et al 2023).[5] The fiscal crisis of the state has affected the quality of care provided in the public sector. A number of people the author interviewed mentioned that they preferred to utilize the private sector because the care provided at the public sector did not satisfy them (Koji Nabae 2003).[12]

STATEMENT OF THE RESEARCH PROBLEM:

Despite significant progress in public health, Kannur, Kerala, still faces major healthcare challenges. With a population exceeding 2.4 million, disparities in healthcare quality, cost, and availability persist. This study analyzes healthcare spending trends and public opinions to understand the impact of socioeconomic factors on

healthcare access and assess system effectiveness. It evaluates the effectiveness, availability, and quality of healthcare services alongside the socioeconomic status of Kannur residents. The method involves a comprehensive analysis using academic articles, official reports, and a survey of 100 randomly selected residents. By combining secondary and primary data, the study aims to provide insights into healthcare expenditures and access in Kannur. The findings will guide policy decisions and healthcare initiatives to establish a more equitable and improved healthcare system, ensuring essential care for all residents, regardless of socioeconomic status or location.

OBJECTIVES:

· To study the socio-economic conditions of respondents in Kannur District.

· To examine the quality, accessibility, and effectiveness of healthcare services, in meeting the healthcare needs of the population in Kannur district.

· To make suggestions for increasing healthcare availability, affordability and accessibility in Kannur District with special reference to "Aardram" initiative.

METHODOLOGY:

The present study is based on both primary and secondary data, The primary data has been collected from 100 residents of Kannur district through direct personal interview method using pre designed and tested questionnaire. The respondents were selected using random sampling method. The questionnaire was carefully prepared with the goal of gathering in-depth information on healthcare spending trends, socioeconomic factors impacting the behaviour of those seeking healthcare, and opinions about the calibre of healthcare services. Furthermore, secondary data has been acquired from a variety of sources, such as government reports, thesis, articles, journals, magazines, websites, and library materials. This secondary data includes a broad range of variables relevant to the research, including socio-economic factors, healthcare service availability in the Kannur area, and trends in healthcare spending. The results of the study had been presented through simple percentage method.

DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION:

***Table 1. Age Group of the Respondents**

No	Age Group of Respondents	Frequency	Percentage
1	18-25	31	31%
2	26-35	15	15%
3	36-45	26	26%
4	46-55	13	13%
5	Above 55	15	15%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The age group of the respondents is a prime indicator of the socio-demographic profile of the respondents. It reveals a varied age distribution among the respondents. The largest proportion, 31%, fell within the 18-25 age group, indicating a significant representation of young adults. Additionally, 15% were aged 26-35, 26% were aged 36-45, 13% were aged 46-55, and 15% were 55 years and older. This distribution suggests a fairly balanced representation across different age groups, with a notable presence of younger adults.

*** Table 2. Gender Composition of The Respondents:**

No	Gender	Frequency	Percentage
1	Male	35	35%
2	Female	65	65%
3	Other	0	0%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The gender composition data indicates that the respondents were predominantly female, comprising 65% of the sample, while males accounted for 35%. The absence of respondents identifying as "others" suggests a binary gender representation in the survey. This gender distribution may imply a higher participation of females in the study or potentially reflect the demographic composition of the target population.

***Table 3. Educational Qualification of The Respondents:**

No	Educational Qualification	Frequency	Percentage
1	SSLC & below	11	11%
2	11th – 12th or equivalent	22	22%
3	Graduate	31	31%
4	Postgraduate & above	36	36%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data indicates a diverse educational background among the respondents. Notably, no respondents reported being illiterate. Instead, educational attainment was distributed as follows: 11% had completed SSLC or below, 22% had completed 11th, 12th, or equivalent, 31% were graduates, and the highest proportion, 36%, were postgraduates or held higher degrees. This distribution suggests a relatively high level of educational attainment among the surveyed population, with a significant portion having completed postgraduate or higher education.

***Table 4. Occupation of the Respondents:**

No	Occupation	Frequency	Percentage
1	Student	28	28%
2	Private Sector	22	22%
3	Public Sector	21	21%
4	Self-employed	4	4%
5	Retired	8	8%
6	Unemployed	15	15%
7	Business	2	2%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data from Table No. 4 reveals a diverse range of occupations among the respondents. A notable proportion, 28%, were students, while 22% were employed in the private sector and 21% in the public sector. Self-employed individuals accounted for 4% of the respondents, while 8% were retired. Moreover, 15% reported being unemployed, and 2% were involved in business. This distribution highlights a mix of students, employed individuals across various sectors, retirees, and a smaller representation of self-employed and business owners among the surveyed population.

***Table 5. Number of Dependants**

No	Number of Dependants	Frequency	Percentage
1	1-2	5	5%
2	3-4	67	67%
3	5-6	24	24%
4	7+	4	4%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data regarding the number of members in households suggests that the majority of respondents, accounting for 67%, reside in households with 3-4 members. Additionally, 24% of respondents reported living in households with 5-6 members, while a smaller proportion, 5%, indicated having 1-2 members. Only 4% of respondents reported having 7 or more members in their households. This distribution reflects a prevalence of mid-sized households among the surveyed population, with fewer respondents living in smaller or larger household configurations.

***Table 6. Annual Household Income:**

No	Annual Household Income	Frequency	Percentage
1	Below 5 lakhs	49	49%
2	5-15 lakhs	42	42%
3	15-25 lakhs	8	8%
4	Above 25 lakhs	1	1%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data indicates that a significant portion of households surveyed, 49%, reported an annual income below 5 lakhs, while 42% fell within the 5 to 15 lakhs income bracket. Additionally, 8% of households reported an income ranging from 15 to 25 lakhs, and only 1% reported an income exceeding 25 lakhs annually. This distribution suggests that a majority of households surveyed have relatively modest incomes, with fewer households reporting higher income levels.

***Table 7. Permanent Health Status of Respondents:**

No	Chronic health condition status	Frequency	Percentage
1	Yes	8	8%
2	No	92	92%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data from Table No. 7 reveals that only 8% of respondents reported having a chronic illness, while the vast majority, 92%, did not. This suggests that chronic illnesses are relatively uncommon among the surveyed population. However, it's essential to consider that self-reported data on chronic illnesses may be subject to underreporting or misclassification biases, so the actual prevalence of chronic illnesses within the population may vary.

***Table 8. Frequency of Healthcare Service Utilisation:**

No	Frequency of Healthcare Service Utilisation	Frequency	Percentage
1	Monthly	10	10%
2	Quarterly	11	11%
3	Bi-annually	9	9%
4	Annually	6	6%
5	Only when necessary	64	64%
	Total	100	100%

Interpretation:

The table indicates that most respondents, 64%, utilize healthcare services only when necessary. Additionally, 10% utilize healthcare services monthly, 11% quarterly, 9% biannually, and 6% annually. This pattern suggests that a significant

proportion of respondents may prioritize seeking healthcare only when they perceive it as essential, possibly due to various factors such as perceived health status, accessibility of healthcare services, or financial considerations.

***Table 9. Beneficiaries Health Insurance Scheme**

No	Health Insurance Scheme Coverage	Frequency	Percentage
1	Yes, government scheme	33	33%
2	Yes, private scheme	22	22%
3	No	45	45%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

33% of respondents were covered under a government health insurance scheme, 22% were covered under a private health insurance scheme, and 45% were not covered under any health insurance scheme. This suggests that a significant portion of respondents, nearly half, lacked coverage under any health insurance scheme, potentially indicating gaps in access to healthcare financing and services.

***Table 10. Satisfaction with Current Healthcare Facilities:**

No	Level of Satisfaction	Frequency	Percentage
1	Highly satisfied	4	4%
2	Satisfied	73	73%
3	Less satisfied	19	19%
4	Least satisfied	4	4%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The majority of respondents, 73%, expressed satisfaction with current healthcare facilities, while 20% indicated being less satisfied. Additionally, 4% reported being highly satisfied, and 4% indicated being least satisfied. This suggests that overall satisfaction with healthcare facilities is relatively high, with a notable portion expressing high satisfaction.

***Table 11. Percentage of Annual Income Spent on Healthcare:**

No	Percentage of Annual Income Spent on Healthcare	Frequency	Percentage
1	Below 10000	67	67%
2	10000-25000	22	22%
3	25000-50000	10	10%
4	Above 50000	1	1%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data reveals that a significant portion of respondents (67%) spend below 10,000 annually on healthcare expenses, indicating that a majority of individuals allocate a relatively small portion of their income to healthcare. However, it's notable that 22% spend between 10,000 to 25,000 annually, suggesting a considerable proportion of the population faces moderate healthcare expenses. Additionally, 10% spend between 25,000 to 50,000 annually, and only 1% spend above 50,000 annually, indicating that a smaller percentage incurs higher healthcare costs.

***Table 12. Type of Healthcare Service Utilised:**

No	Type of Healthcare Service Utilised	Frequency	Percentage
1	Hospitalisation	12	12%
2	Medication	31	31%
3	Consultations	43	43%
4	Diagnostic tests	14	14%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data indicates that the most commonly utilized healthcare services among respondents are consultations (43%) and medication (31%), followed by diagnostic tests (14%) and hospitalization (12%). This distribution suggests that preventive and primary care services such as consultations and medication are more frequently sought after than specialized services like hospitalization and diagnostic tests.

***Table 13. Financial Impact on Healthcare Expenses:**

No	Frequency of Difficulties Encountered	Frequency	Percentage
1	Rarely	70	70%
2	Occasionally	27	27%
3	Frequently	3	3%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data suggests that a majority (70%) of respondents rarely face financial difficulties due to healthcare expenses, indicating that healthcare costs are generally manageable for most. However, a significant minority (27%) occasionally encounter financial challenges, while a small portion (3%) face them frequently. This highlights the need for measures to alleviate financial burdens on those who struggle with healthcare expenses, ensuring equitable access to affordable healthcare for all.

***Table 14. Healthcare Access and Financial Constraints:**

No	Delay or Avoidance Due to Costs	Frequency	Percentage
1	Yes	18	18%
2	No	82	82%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

This suggests that a significant portion, 18%, of respondents have experienced delays or avoidance in seeking healthcare due to financial constraints. This indicates a potential barrier to accessing timely healthcare services, which could impact health outcomes. However, the majority, 82%, reported no such delays, indicating relatively better financial access to healthcare among the majority of respondents.

***Table 15. Trends in Healthcare Expenditure:**

No	Changes in Healthcare Expenditure Over Time	Frequency	Percentage
1	Increased	68	68%
2	Decreased	9	9%
3	Remained stable	23	23%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The substantial majority, 68%, reporting an increase in healthcare expenditure indicates a potential challenge in managing healthcare costs for most respondents. This could imply either rising healthcare costs, increased utilization of healthcare services, or both. The smaller proportions reporting a decrease (9%) or stable expenditure (23%) suggest variations in how different households are affected financially by healthcare expenses. Further investigation might reveal factors contributing to these trends, such as income levels, insurance coverage, or healthcare needs.

***Table 16. Sources of Healthcare Financing:**

No	Funding Methods Utilised by Respondents	Frequency	Percentage
1	Private insurance	3	3%
2	Savings	34	34%
3	Loans	2	2%
4	Family support	44	44%
5	Government schemes	17	17%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data indicates that a significant portion of respondents rely on personal savings (34%) and family support (44%) to fund healthcare expenses, highlighting the importance of financial preparedness and social networks in managing healthcare costs. Only a small percentage resort to private insurance (3%) or loans (2%),

suggesting potential gaps in coverage or access to credit. The reliance on government schemes (17%) underscores the role of public healthcare initiatives in supporting healthcare affordability for some individual.

***Table 17. Priority of Healthcare Expenses Over Household Expenses:**

No	Priority of Healthcare Expenses Over Household Expenses	Frequency	Percentage
1	High priority	41	41%
2	Medium priority	49	49%
3	Low priority	10	10%
	Total	100	100%

Interpretation:

The data suggests that a majority of respondents (90%) prioritize healthcare expenses either with medium (49%) or high (41%) priority over household expenses. This indicates a significant recognition of the importance of healthcare within household budgets. However, the 10% who assign low priority to healthcare expenses might face challenges in accessing necessary medical care or could be more financially strained, highlighting a potential area for adsxintervention or support. Overall, the findings emphasize the major role of healthcare within household financial planning and decision-making.

***Table 18. Perception on Healthcare Accessibility:**

No	Are Healthcare Services in Kannur Easily Accessible	Frequency	Percentage
1	Yes	77	77%
2	No	23	23%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The majority of respondents, 77%, perceive healthcare services as easily accessible, while 23% indicated otherwise. This suggests that there is generally a positive perception of healthcare accessibility among the surveyed population. However, it's important find the reasons behind the minority who find healthcare inaccessible to address any underlying issues and ensure equitable access to healthcare services for all.

***Table 19. Perception on Healthcare Affordability:**

No	Affordability of Healthcare Services in Kannur	Frequency	Percentage
1	Affordable	35	35%
2	Somewhat affordable	56	56%
3	Not affordable	9	9%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data indicates that a significant portion of respondents, 56%, perceive healthcare as somewhat affordable, while 35% consider it affordable. However, 9% of respondents view healthcare as not affordable. This suggests that while a majority find healthcare costs manageable to some extent, there is still a notable proportion who perceive it as unaffordable.

***Table 20. Perception on Reasonability of Health-Care Services:**

No	Are The Healthcare Services Reasonable	Frequency	Percentage
1	Yes	40	40%
2	No	19	19%
3	To some extent	41	41%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data indicates that 40% of respondents find the costs of healthcare services in Karno district reasonable, while 41% believe it is to some extent reasonable. However, 19% of respondents disagree and consider the costs unreasonable. This suggests that there is a mixed perception regarding the affordability of healthcare services in Kannur district, with a significant portion feeling that the costs are not entirely reasonable.

***Table 21. Perception on Awareness of Health-Care Services:**

No	Awareness about Healthcare Services in Kannur	Frequency	Percentage
1	Yes	50	50%
2	No	50	50%
	Total	**100**	**100%**

Source: Field survey.

Interpretation:

The responses indicate a split perception regarding the adequacy of awareness about healthcare services in Kannur, with 50% of respondents affirming adequate awareness and the other 50% indicating a lack thereof. This suggests a need for improving awareness initiatives to ensure comprehensive understanding and access to healthcare services in the region.

***Table 22. Satisfaction with Healthcare Pricing Transparency and Billing Clarity:**

No	Satisfaction with the Transparency in Pricing and Billing	Frequency	Percentage
1	Very satisfied	3	3%
2	Satisfied	62	62%
3	Dissatisfied	32	32%
4	Very dissatisfied	3	3%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The data indicates a mixed sentiment regarding satisfaction with transparency in pricing and billing. While 65% of respondents expressed satisfaction to some degree, with 3% being very satisfied and 62% satisfied, a notable portion, comprising 35%, expressed dissatisfaction, with 32% being dissatisfied and 3% very dissatisfied. This suggests a need for greater transparency and clarity in healthcare pricing and billing practices to enhance overall satisfaction levels among the respondents.

***Table 23. Perception of Government Support for Healthcare Affordability:**

No	Do You Feel That Government is Doing Enough to Support Healthcare Availability ?	Frequency	Percentage
1	Yes	25	25%
2	Somewhat	56	56%
3	No	19	19%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The analysis indicates that there is a significant portion of the population (56%) expressing some level of satisfaction with the government's efforts towards healthcare affordability. However, the fact that nearly one-fifth (19%) feel that these efforts are inadequate highlights potential areas for improvement in government policies and initiatives aimed at enhancing healthcare availability. This underscores the importance of ongoing efforts to address healthcare accessibility and affordability concerns to ensure the well-being of all citizens.

***Table 24. Recommendation of Health-Care Services in Kannur District:**

No	"I Recommend Healthcare Services in Kannur District"	Frequency	Percentage
1	Strongly agree	9	9%
2	Agree	83	83%
3	Disagree	7	7%
4	Strongly disagree	1	1%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

The majority, 83%, agreed to recommend healthcare services in Karno district, with 9% strongly agreeing. However, 7% disagreed, and only 1% strongly disagreed, suggesting overall positive sentiment but room for addressing concerns among a minority.

***Table 25. Suggestions for Healthcare System Improvements:**

No	Improvements to be Made in Healthcare System	Frequency	Percentage
1	Lower healthcare costs	31	31%
2	More government support	34	34%
3	More specialised healthcare services	24	24%
4	Improved cleanliness & sanitation	10	10%
5	Improved accessibility for differently abled people	1	1%
	Total	**100**	**100%**

Interpretation:

Responses indicate various areas for improvement in the healthcare system. The most prominent concerns include lowering healthcare costs (31%), followed closely by the need for more government support (34%). Additionally, 24% emphasize the importance of enhancing specialized healthcare services, while 10% prioritize improved cleanliness and sanitation. Only a small percentage, 1%, highlights the need for better accessibility for differently abled individuals.

SUGGESTIONS:

1. The study reveals that there is a lack of access for specialised treatment in primary health care centres, therefore it is suggested to provide specialised treatment in public healthcare which immensely brings down the private healthcare expenditure of the people. This can be achieved through the establishment of additional specialty clinics, mobile medical units, and telemedicine facilities.

2. The study also explores about the limited coverage of public healthcare. By implementing measures to reduce expenses for healthcare services, such as expanding the coverage of government healthcare schemes, providing subsidies for medical treatments, and promoting the use of health insurance among the population will increase the accessibility to healthcare for all people.

3. The study came across the fact that the respondents are not informative about various government health schemes, therefore it is suggested to create awareness about health schemes through community outreach programs, media campaigns, and collaboration with local community leaders and organizations to educate the community about government healthcare schemes, insurance options, and financial assistance programs available to them.

4. It is suggested to establish, invest and promote in various mechanisms for continuous quality improvement in healthcare delivery, such as conducting regular audits, soliciting feedback from patients, and implementing evidence-based practices which can improve the overall quality of care.

5. It is suggested to embrace the Aardram initiative's model clinics concept, which aims to transform primary healthcare facilities into patient-friendly, efficient, and technology-driven centres. By upgrading primary health centres (PHCs) in Kannur

district to Aardram model clinics, the government can improve the quality of care at the grassroots level, enhance patient satisfaction, and reduce the burden on tertiary care hospitals.

6. It is suggested to encourage community engagement and participation in healthcare decision-making and service delivery processes. Through initiatives such as health committees, community health volunteers and participatory planning forums, the Aardram initiative promotes active involvement of local communities in identifying health priorities, mobilizing resources, and monitoring the implementation of healthcare programs.

CONCLUSION:

This study has revealed key insights about the current state of healthcare delivery and local expectations in Kannur district. The opinion of the respondents reveals that while the healthcare system has positive aspects, significant improvements are necessary. The study emphasizes the urgent need for better specialized healthcare services, increased government support, lower healthcare costs, improved accessibility for those with disabilities, and higher hygiene and sanitation standards in healthcare facilities. The study also highlights the need for raising awareness about healthcare programs, maintaining pricing and billing transparency, investing in preventive healthcare, improving rural accessibility, and promoting community involvement. Stakeholders need to work together to create a more inclusive, affordable, and accessible healthcare system in Kannur. Cooperation among legislators, medical professionals, and community leaders is crucial to address these issues and ensure the health and well-being of every citizen. Additionally, incorporating ideas from the Kerala governments Aardram project offers an opportunity to enhance medical facilities and services in Kannur. By adopting Aardram strategies, such as improving primary care, optimizing resource use, and fostering community engagement, Kannur can make significant strides toward a better healthcare system that serves all residents effectively.

❐

References :

*Source of Table - 1 to 25 : *Based on Field Survey*.

1. PRS India (2023-24). Demand for grants 2023-24 analysis: Health and Family Welfare. Retrieved from PRS legislative research, www.prsindia.org.
2. Kerala Tourism Guide (2024). Retrieved from www.keralatourism.guide.
3. Levesque J F, Haddad S, Narayana D, Fournier P. (2007). Insular pathways to health care in the city: a multilevel analysis of access to hospital care in urban Kerala, India. Trop Medical Institution of Health. July:12(7):802-14. Retrieved from www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.
4. Muraleedharan M. and Chandak A.O. (2022). Emerging challenges in the health systems of Kerala, India: qualitative analysis of literature reviews. Journal of Health Research, Vol. 36 No. 2, pp. 242-254. Retrieved from www.doi.org.

5. Krishnan, R. P. Varma, R. Kamala, R. Anju, K. Vijayakumar, R. Sadanandan, P. K. Jameela, K. S. Shinu, B. Soman, R. M. Ravindran (March 2023). Re-engineering primary healthcare in Kerala. Retrieved from www.shsrc.kerala.gov.in.
6. Sara John (2018). Kerala's Healthcare System Is Cracking; It Needs to Reach Out to Private Sector. Retrieved from www.cppr.in.
7. Sara Datta (2019). A systematic study on the recent crisis in public health in Kerala. Asian Journal of Health Sciences. Retrieved from www.doi.org.
8. Joe Thomas (2021). Reimagining health: A people's manifesto for Kerala. Retrieved from www.policycircle.org.
9. PRC Report Series (2020). Aardram National Health Mission. Retrieved from www.arogyakeralam.gov.in.
10. Sadanandan R. (2001). Government Health Services in Kerala: Who Benefits? Economic and Political Weekly, 36(32), 3071-3077. Retrieved from www.jstor.org.
11. Anumol P. S. (2018). Health Care Challenges in Kerala. Shanlax International Journal of Economics, vol. 6, no. S1, 2018, pp. 89–92. Retrieved from www.doi.org.
12. Koje Nabae (2003). The Health Care System in Kerala- Its Past Accomplish ments and New Challenges. J. Natl. Inst. Public Health, 52 (2): 2003.

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 218–224

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

Political Violence and Targeted Killings: A Study of Jmmu & Kashmir

Sunil Kumar
Research scholar, Department of History, Central University of Himachal Pradesh, District Kangra (H.P.)- 176215
Email: Sunilhstry@gmail.com

Dr. Pravat Ranjan Sethi
Asstt. Professor, Department of History, Central University of Himachal Pradesh,
Email. pravatjnu@gmail.com

Abstract

Political violence, particularly targeted killings, has long plagued the state of Jammu and Kashmir. This study examines the complex dynamics of targeted killings in light of the region's larger political unrest and conflict. The research looks at the patterns, reasons behind these killings, and outcomes to identify the underlying socio-political and religious factors that fuel this kind of violence. We consider the roles that state and non-state actors, such as security forces and militant organisations, play in enabling or lessening these acts. The research employs qualitative techniques, such as case studies, to conduct a thorough analysis. It also looks into how targeted killings affect human rights abuses, community solidity, and Jammu and Kashmir's general security situation. Additionally, the study critically assesses how well counterterrorism policies work to stop this kind of violence.

Keywords: Political Violence, Targeted Killings, unrest, Conflict, Militant.

Historical context of political violence in Jammu and Kashmir

The Kashmir dispute stems from India and Pakistan's divergent assessments of historical events during the partition. The partition was primarily based on the state's demographic distribution of Hindus and Muslims. However, the state's rulers had the authority to decide which dominion to join. According to the 1941 census, the Muslim population of Jammu and Kashmir was 93.45% in the Kashmir Valley, 61.35% in the Jammu area, and 86.7% in the frontier territories of Gilgit and Ladakh. (Balraj,1993)

Following the formal integration of Jammu and Kashmir into India, despite ongoing counterclaims by Pakistan, the Kashmiri leadership was motivated to preserve their special status to enhance their negotiating power with both nations. In May 1953, Sheikh Abdullah established a commission to investigate the possibility of

achieving independence and the practicality of conducting a referendum. (Habibullah, 2008) As a result of these actions, Kashmir unintentionally became a long-term battlefield. In 1953, Jammu and Kashmir relieved Sheikh Abdullah of his Prime Minister duties and apprehended him. He spent 11 years in detention. Bakshi Ghulam Mohammad, the successor, lacked the same level of political legitimacy among the general population. He dedicated most of his time to bolstering his political standing. Meanwhile, Mirza Afzal Beg, a trusted associate of Sheikh Abdullah, formed a political movement called the '*Plebiscite Front'*. The Plebiscite Front emerged as the first influential political faction that actively fostered and preserved the plebiscite matter in J&K, thereby preventing the state from fully integrating into India's national identity. Pakistan viewed the challenges arising from J&K's political dynamics as an opportunity to seize control of the region from India. The organization began providing complete assistance to Kashmiri separatists.

The Pakistani claim to Kashmir is solely based on religious reasons, resulting in a detachment from the actual situation on the ground. Other than the long-abandoned two-nation notion, it lacks any cultural or ethnic connections with the state. Although Kashmir has a Muslim majority, the main obstacles to Pakistan's attempts to control Kashmir are the differences in Kashmiri Islam's religious practices compared to Islam in Pakistan, as well as Kashmir's distinct cultural identity. Kashmir has consistently adhered to a syncretic form of Islam, greatly influenced by Sufism. Kashmiriyat, the amalgamation of cultures, embraced and honoured all religious beliefs and rituals. Recognizing these obstacles, Pakistan tried to undermine the essence of Kashmiri culture by endorsing the Saudi-influenced, extremist Salafi-Wahhabi interpretation of Islam. It has endeavoured to accomplish the exclusion of other religions, divide Kashmiri society, and ultimately cause its fragmentation. (Wirsing, 2003) In the latter case, Pakistan was moderately effective in orchestrating the forced departure of Kashmiri Hindus from the valley. The endeavour to establish a distinct Muslim constituency was based on the desire to gain demographic advantages.

Following the widely believed manipulation of the 1987 state elections, Pakistan recognised a favourable situation and seized the opportunity. (Snedden, 2013 p.208) Even though Pakistan's goal of incorporating Kashmir into its territory did not align with the JKLF's goal of achieving independence, Pakistan took advantage of the circumstances and assisted the militant movement. JKLF acknowledged and endured it for around four years (1989–92) before recognizing its error. Twenty The internal and exterior components of the J&K crisis have become so intertwined that they appear to be indistinguishable. The winter of 1989–90 witnessed the beginning of the Kashmiri insurgency, while the Ladakhi Buddhists started their violent protest for recognition as a union territory in August 1989. In subsequent years, various political movements in the state showed a growing inclination towards the collective adoption of political vocabulary, practices, and goals. The Kashmiris articulated their aspiration for independence by highlighting a religious divide between Hindus and Muslims, notably following the forced departure of the Pandits in 1990. As a result, the Buddhists countered the Kashmiris by emphasizing a schism be-

tween Buddhists and Muslims, which they also applied to the Shias of Leh. Notably, the Shias of Leh, predominantly of Balti descent, exhibit ethnic affinities with Ladakhi Buddhists. Authorities in the Valley attempted to weaken the political support of parties advocating for regional autonomy in the late 1960s by forming new political alliances based on religious or communal lines, which sowed the seeds of communalization. (Behera,2006) One of Pakistan's goals, starting in the late 1970s and continuing after that, was to retaliate for the perceived humiliations it experienced, particularly about Bangladesh. Inspired by the Iranian Islamic Revolution of 1979 and the Afghan mujahedeen's triumph over the Soviets in the late 1980s, Pakistan embarked on a path of Islamic Jihad to seize control of Kashmir from India.

Political violence and targeted killings in Jammu and Kashmir

The political developments before 1989 were profoundly unsettling for the Kashmiri populace. These modifications led to a consistent buildup of grievances from the populace against the central authority, which continued to amass in large quantities. A series of events began in 1984 when Farooq Abdullah lost his position as Chief Minister despite his considerable electoral victory. The Congress party subsequently appointed Ghulam Mohammad Shah as his successor. Over time, Farooq Abdullah acknowledged the importance of the federal government's aid in facilitating political matters in Jammu and Kashmir. Consequently, he became a party to the Farooq-Rajeev alliance in 1987. However, the general public interpreted this conduct as a betrayal by Farooq, and resistance in the state continued to escalate. As a result, the inhabitants of Kashmir experienced both animosity towards the central government due to its deceptive activities and a sense of betrayal from their mainstream leadership. This sudden change moved the responsibility of opposing something from major political figures to religious and other groups that wanted to separate from the larger group. The widely acknowledged rigged elections of 1987 dealt the last blow to the legitimacy of democratic and federal politics. (Choudhary Rekha, 2015)

On March 31, 1988, an explosion occurred within the Telegraph Office located in central Srinagar by the Jammu and Kashmir Liberation Front, who claimed that the incident marked the start of a belligerent conflict. In 1966, authorities apprehended Mohammad Maqbool Butt, a prominent figure in the JKLF's formation, on charges of killing an intelligence officer. Butt's operation sparked a multitude of like-minded ventures. As early as 1967, there were significant arrests connected to terrorism in Jammu and Kashmir. During this time, a gang of young persons attempted to murder a policeman from the Central Reserve Police Force. A year later, they launched an attempt to steal firearms from the National Cadet Corps chambers at Islamia College. The terrorist organisation al-Fateh apprehended several individuals in 1971 for plotting a bank robbery to finance their liberation movement. Additionally, Hashim Qureshi, an operator of the JKLF, successfully hijacked an Indian Airlines plane and diverted it to Lahore. Ten years later, the JKLF organisation faced accusations of involvement in the murder of Ravindra Mhatre, an In-

dian ambassador residing in London. The same group considered carrying out a second hijacking to secure Maqbool Bhatt's release. (Qureshi, 1999, pp.44-47)

The militants also made a deliberate effort to gain exclusive control over the means of violence by launching attacks on police stations in Srinagar without facing any consequences and brutally murdering police officials in an exceptionally savage way. (Marwah Ved, 1995) These murders severely disrupted the morale of the police force. By 1989, many prominent militant organizations had emerged in the valley, primarily based in the cities of Srinagar, Anantnag, Baramulla, and Sopore. (Malhotra Jagmohan, 2019) Their goal was to achieve either full autonomy or integration with Pakistan. Jagmohan stepped down from his role as governor on July 2, 1989, after serving for five years. In his autobiography, he recounts how he has been issuing 'warning signs' to New Delhi about the building storm since 1988. Unfortunately, New Delhi disregarded all of these explicit and direct warnings. (Malhotra Jagmohan, 2019) On August 21, 1989, Mohammed Yusuf Halwai, a prominent member of the National Conference, was assassinated near his residence in downtown Srinagar. In response to this tragic event, merchants closed their businesses due to a combination of fear, perplexity, and little dissatisfaction. (Balraj,1994) Jammu and Kashmir Liberation Front takes responsibility for his death. A week later, the BJP leader and High Court counsel, Tikka La1 Taploo, the first Kashmiri Pandit, fell victim to assassination. On November 4, 1989, they fatally shot Neel Kanth Ganju, who had managed to evade the previous assault, during daylight hours. The Hindus, who had coexisted peacefully with the Muslims for many years, started to experience a sense of apprehension for their safety.

At the start of March 1990, some 140,000 Hindus departed from the valley and sought safety in camps located outside Jammu. Wealthier individuals chose to live in their secondary residences in Delhi, while the majority of people found shelter in unsanitary tents located in over fifty camps on the outskirts of both Jammu and Delhi. The table below shows the trends in terrorist violence in J&K over the past five years.

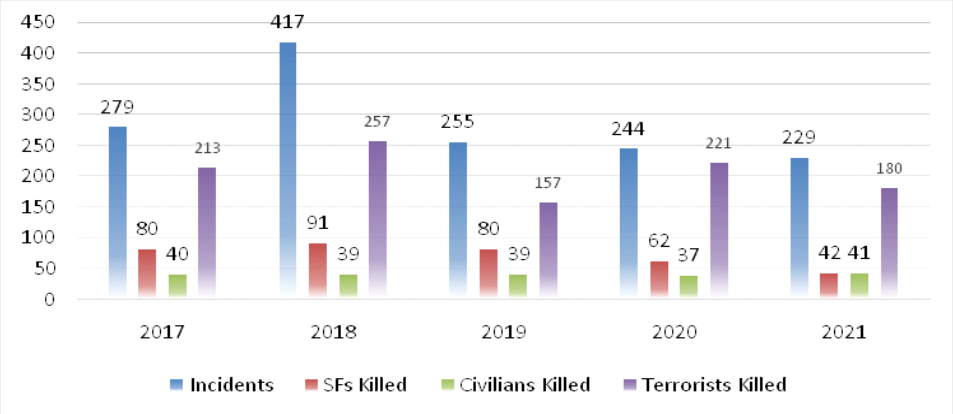

Terrorists Infiltrate Jammu & Kashmir Through The "Line of Control" and the "International Border," contributing to the ongoing insurgency. The reported infiltration attempts and Net infiltration in J&K since 2017 are indicated in the table below:

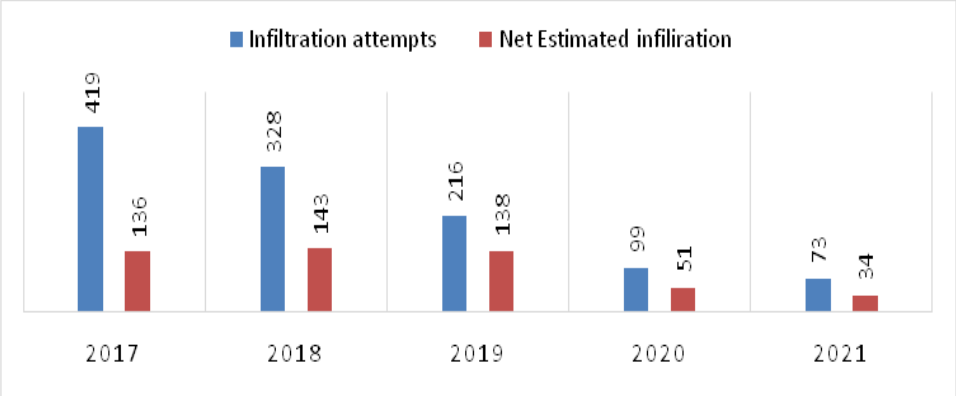

Source: Ministry of Home Affairs, Government of India

The Army and various security agencies, including the Central Armed Police Forces (CAPFs), monitor and assess the security situation in J&K. The Ministry of Home Affairs, in collaboration with the UT of J&K and the Ministry of Defence, closely monitors the security situation.

As of August 2022, there have been 21 fatalities resulting from deliberate and focused attacks. People with a clear association with the state, whether direct or indirect, are the primary target of these attacks. In recent years, there has been a significant increase in the number of attacks against local law enforcement officers, resulting in a higher proportion of casualties among the security forces. According to the data presented by the Ministry of Home Affairs in Parliament on July 20, 2022, the Union Territory (UT) has suffered an average of 3.26 casualties from terror attacks every month since August 5, 2019. This is in contrast to an average of 2.8 deaths per month in the almost five years preceding that period. Between August 2019 and July 9, 2022, there were 118 civilian fatalities in the UT, including 5 Kashmiri Pandits and 16 individuals from other Hindu and Sikh sects. (Unstated question, MHA) Moreover, data acquired through a Right to Information (RTI) request in 2022 revealed that over the past thirty years, militants have been responsible for the deaths of 1,724 individuals in Jammu and Kashmir, with 89 of them being Kashmiri Pandits. The RTI claims that during the same time, 1,635 people of various religions also perished in addition to the 89 Kashmiri Pandits. (Indian Express, 17 Dec, 2022) The facts indicate that both Muslims and Hindus have been victims of extremists.

Following the government's decision to suspend Jammu and Kashmir's constitutional autonomy and divide it into two federally administered areas, violence has persisted. As of October 2022, there have been 229 recorded killings, including 28 civilians, 29 security force members, and 172 suspected terrorists. Despite local Kashmiris' complaints about the alleged misidentification of terrorists as civilians in gunfights, no publicly disclosed impartial inquiry took place. Attacks targeted the minority Hindu and Sikh populations in the mostly Muslim Kashmir Valley. In May

2022, there were a total of seven deliberate homicides, with four of the victims being Kashmiri Hindus, specifically referred to as Pandits. The remaining three individuals were police personnel who practiced the Islamic faith. After armed individuals shot Rahul Bhat, a government employee from the Kashmiri Pandit community, on May 12, Kashmiri Pandits in government positions in the Kashmir Valley initiated an indefinite strike, demanding relocation. (Human Rights Watch Reports, 2023)

Human Rights Concerns and Indian Response

Since 1989, the sporadic violations of human rights committed by terrorists in Kashmir have grown to be a serious issue. Meanwhile, in January 1990, Lakhs of Hindi Sikhs and Muslims were forced to flee the valley. Numerous individuals in Kashmir have experienced abduction, murder, and theft of property valued at millions of rupees. Pro-Pakistani Kashmiri militants have occupied more than 25,000 houses in their community and set over 4,000 burnings, according to Kashmiri Pandits. Not even Muslims were exempt. Forced reforms carried out in the name of religion severely restricted the freedom of the valley's inhabitants, "*Jehad,"* for a theocratic state, severed the long-standing bonds of fraternity and amity among the community. In Srinagar and other towns, attacks on security personnel have occurred frequently, especially in congested areas, resulting in property devastation and the loss of valuable lives in the crossfire. The security forces have occasionally been ferociously involved in the harassment, death, and devastation of innocent people. For some reason, human rights groups have focused primarily on the security forces violations of human rights, inadvertently aiding the cause of militants. Pakistani officials also used these biased reports to promote their negative image of India. (Verma P.S,1994, p,.246)

Counter-terrorism strategy

To counteract Pakistan's persistent efforts to incite unrest in the Kashmir Valley, India will need to develop a novel counter-terrorism policy that efficiently harnesses technology. Four individuals, including three high-ranking security services officers, tragically lost their lives during the recent week-long counterterrorism (CT) operation in the Anantnag area of Kashmir from September 13–19, 2023. Furthermore, the operation eliminated two terrorists, including Uzair Khan, the commander of *Lashkar-e-Taiba* (LeT). The terrorists deliberately selected a location in a rugged and heavily wooded area to prolong the conflict, but security forces employed state-of-the-art surveillance equipment and advanced methods of delivering firepower. Additionally, they utilized highly accurate drones equipped with powerful weaponry to eliminate the terrorists. The Anantnag encounter highlights the shift in strategy by terrorists in the Kashmir Valley, who are opting to confront security personnel in dense forests instead of urban areas, where they are at a disadvantage. This tendency became more apparent after 2020 when terrorist organizations moved their activities from the valley to the wooded regions of Poonch and Rajouri in the Pir Panjal hills. During the past three years, a total of 26 troops, including five paratroopers, have lost their lives in counterterrorism operations in this region.

Conclusion

The examination of political violence and deliberate assassinations in Jammu and Kashmir exposes a multifaceted and deeply rooted conflict that has significant consequences for both the area and beyond. In this research paper, we have thoroughly analysed the historical context, factors that led to the issue, individuals or groups involved, various forms of violence, and global viewpoints on the matter.

The historical backdrop of Jammu and Kashmir, which involved its formal joining with India in 1947 and following political events, established the foundation for a prolonged struggle defined by conflicting assertions of authority, ethnic and religious conflicts, and geographical rivalry. The interplay of these variables has led to a recurring pattern of aggression involving government entities, factions advocating for separatism, and external forces, leading to substantial harm and forced migration of individuals. Targeted assassinations have had severe consequences for the functioning of government institutions, society's unity, and civilian communitie's well-being. Political leaders, activists, security officials, and innocent people have all fallen prey to these deliberate acts, intensifying fear and suspicion throughout communities and impeding attempts towards peace and healing. Ultimately, comprehending the historical development and complex aspects of political violence and targeted killings is crucial to formulating effective policies and initiatives that promote reconciliation and guarantee a peaceful future for all residents of Jammu and Kashmir, despite the challenging path ahead.

❒

References :

1. *Behera, N. C. (2006). Demystifying Kashmir. United States: Brookings Institution Press, p.148*
2. *Chowdhary, R. (2015). Jammu and Kashmir: Politics of Identity and Separatism. India: Taylor & Francis, p.13*
3. *Habibullah, W. (2008). My Kashmir: conflict and the prospects for enduring peace. Washington: United States Institute of Peace Press.p,158*
4. *Human Rights Watch, World Report 2023, https://www.hrw.org/world-report/2023/country-chapters/india#0b5853*
5. *Indian Express 17, Dec 2022,https://indianexpress.com/article/cities/srinagar/jammu-and-kashmir-shopian-militant-attack-kashmiri-pandit-killed-8093034/*
6. *J. (2017). My Frozen Turbulence in Kashmir. India: Allied Publishers Private Limited, p.751*
7. *Ibid, p.58*
8. *Marwah Ved, Uncivil Wars: Pathology of Terrorism in India, Harper Collins, New Delhi, p61*
9. *Ministry of Home Affairs, Government of India Annual reports, https://www.mha.gov.in/en/documents/annual-reports*
10. *Puri Balraj,(1993), Kashmir Towards Insurgency, Orient Longman, New Delhi, p.13*
11. *Qureshi Hashim,(1999) Kashmir: Unveiling the truth, Juddojudh publisher Lahore,p.44-47*
12. *Unstarred Question No. 386, Rajya Sabha, Ministry of Home Affairs, Govt. of India. https://www.mha.gov.in/MHA1/Par2017/pdfs/par2022-pdfs/RS20072022/386.pdf*
13. *Verma. P.S., Verma, P. S. (1994). Jammu and Kashmir at the Political Crossroads. India: Vikas Publishing House, p.246.*
14. *Wani Ajaz, (2023), Changing dynamics of counterterrorism in Kashmir, ORF,*
15. *Wirsing. G. Robert, (2016), Kashmir in the Shadow of War: Regional Rivalry in a Nuclear Age, Routledge, p.158*

पूर्वदेवा– सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
वर्ष 30, अंक, 119, अक्टूबर–दिसम्बर, 2024 पृ. 225–232

UGC Care Listed Journal
ISSN 0974 -1100

An Analysis of China's Cultural Incursion in Nepal and Its Implications for India

Krishn Kumar
Research Scholar, University of Lucknow, Lucknow (U.P.)-226007
E-mail: krishnphd@gmail.com

Abstract:

This research paper examines China's increasing cultural presence in Nepal and its implications for India's traditional influence in the country. The study analyzes the various means through which China has been promoting its culture and language in Nepal, including language training programs, educational exchanges, and cultural events. The paper argues that China's cultural incursion in Nepal is part of its broader "soft power" strategy to increase its influence in the region and to counterbalance India's traditional dominance in Nepal.

The study also explores the geostrategic context of China's cultural incursion in Nepal, including China's desire to maintain stability and security in Nepal, to promote its Belt and Road Initiative (BRI), and to gain a greater foothold in the country. The paper argues that China's growing cultural presence in Nepal has significant implications for India's strategic interests in the region, including the potential erosion of India's influence in Nepal, the risk of increased competition and tension between India and China, and the possibility of Nepal becoming a battleground for Sino-Indian rivalry.

The research is based on a comprehensive review of existing literature, as well as primary data collected through ministry of foreign affairs of Nepal and India. The study finds that while China's cultural incursion in Nepal is likely to continue to grow, India still maintains significant cultural, economic, and political ties with Nepal. The paper concludes that India needs to engage more actively with Nepal to maintain its influence in the country and to counterbalance China's growing presence. The study also suggests

that Nepal should seek to balance its relationships with both China and India to avoid becoming a pawn in their strategic rivalry.

Keywords: Cultural incursion, soft power, Belt and Road Initiative,Geostrategic, Sino-Indian rivalry.

Introduction

China-Nepal relations have a long history dating back to the 7th century when cultural and trade exchanges began along the Silk Road. The formal establishment of diplomatic relations between the two countries took place in 1955. Since then, the relationship has been characterized by mutual respect for each other's sovereignty and territorial integrity, as well as non-interference in each other's internal affairs. Scholars argued that the historical ties between Nepal and China have strengthened over time. These ties can be traced back to the 5th century when various saints and sages, including Nepali scholar Budhabhadra, visited with the aim of seeking knowledge and promoting peace. The relations between China and Nepal are deeply rooted and age-old, having consistently remained friendly and cordial (Panda 2019, Gokhale 2021, Chakrabarty 2019, Khan 2019).

In recent years, Chinese cultural influence in Nepal has significantly increased as part of China's broader soft power strategy. This rise in cultural influence can be attributed to various factors, including increased people-to-people exchanges, educational initiatives, media presence, and tourism. One of the primary channels for the spread of Chinese culture in Nepal is the Confucius Institute, a non-profit organization aimed at promoting Chinese language and culture worldwide. In June 2007, Hebei University of Economics and Business and Kathmandu University jointly established the first Confucius Institute in Nepal[1]. Confucius Institute has played a crucial role in popularizing Mandarin language learning among Nepalese students. Additionally, China has been offering scholarships to Nepalese students to pursue higher education in Chinese universities, further fostering cultural exchange. Chinese media presence in Nepal has also grown, with Chinese state-owned media outlets such as Xinhua News Agency and China Central Television (CCTV) expanding their operations in the country. This increased media presence has contributed to the dissemination of Chinese perspectives on regional and global issues, as well as the promotion of Chinese culture and values.

Tourism has been another significant factor in the rise of Chinese cultural influence in Nepal. The number of Chinese tourists visiting Nepal has surged in recent years, with China becoming the third-largest source of tourists for Nepal in 2023[2]. This influx of Chinese visitors has not only boosted Nepal's tourism industry but has also led to increased cultural interactions between the two nations.

China has been investing in the restoration and preservation of cultural heritage sites in Nepal, such as the Lumbini Development Project, aimed at enhancing the birthplace of Buddha. These initiatives have further strengthened China's cul-

tural presence in Nepal and showcased its commitment to preserving shared cultural heritage. The combined effect of these factors has led to a noticeable rise in Chinese cultural influence in Nepal, which has geopolitical implications for the region, particularly for India.

Understanding cultural dynamics in geopolitical contexts is vital for assessing the implications of China's cultural incursion in Nepal and its impact on India. It provides insights into the power dynamics, local perceptions, and potential strategic responses, which are essential for formulating effective policies and maintaining regional balance.

China's Cultural Incursion in Nepal: Methods and Manifestations

China's cultural incursion in Nepal has been a subject of interest and concern for many observers of international relations. This phenomenon refers to the various ways in which China seeks to expand its influence in Nepal through cultural means, including language promotion, educational exchanges, media outreach, and tourism. Here are some of the methods and manifestations of China's cultural incursion in Nepal:

China has been promoting the Mandarin language in Nepal through Confucius Institutes, which are Chinese government-funded cultural centers that offer language classes and cultural programs. China has strategically utilized cultural and language initiatives to strengthen its influence in Nepal. By establishing Confucius Institutes in major cities and towns, China promotes its language and culture through these non-profit public bodies. The Confucius Institutes in Nepal offer Chinese language courses, cultural exchange programs, and other activities aimed at promoting Chinese culture and language. They also provide scholarships for Nepalese students to study in China and organize events to celebrate Chinese festivals and cultural traditions. Additionally, China has built Chinese schools and study centers in politically sensitive areas along the Indo-Nepal border. The China Study Centers (CSCs), which began in 2000 as informal civil society groups to foster cultural interactions, have expanded significantly. These centers now play a pivotal role in promoting Chinese perspectives on key issues concerning Nepal. The proliferation of CSCs, particularly near the Indo-Nepal border, has raised concerns in India about China's growing influence in the region[3].

China has been offering scholarships and other incentives to Nepalese students to study in Chinese universities. This has resulted in an increase in the number of Nepalese students studying in China, which some see as a way for China to cultivate a pro-China constituency in Nepal. According to Ministry of Foreign Affairs of Nepal, China provides scholarships every year not exceeding a total of 100 Nepalese students studying in China. Besides, the Chinese side has been providing Chinese language training for 200 tourism entrepreneurs (40 per year) of Nepal for five years as per the understanding reached between two sides in March 2016. So

far, 120 Nepali tourism professionals have graduated 6-month long Chinese language training, each 40 professionals in 2016, 2017 and 2018. Both sides have been carrying out activities in culture and youth sectors as per the provisions of the MoU on Cultural Cooperation-1999 and MoU on Youth Exchange-2009. Both sides have been promoting people-to-people relations through regular hosting of cultural festival, friendly visits of the peoples of different walks of public life, exhibition, cultural and film show, food festivals etc. Sister city relations between the cities of two countries are growing. These relations are basically meant for carrying out exchanges and cooperation in the fields of economy, trade, transportation, science and technology, culture, tourism, education, sports and health, personnel, etc[4]. Critics argue that the Confucius Institutes are part of China's broader strategy to expand its cultural influence and promote its political agenda in Nepal. They point out that the institutes are funded and managed by the Chinese government and are therefore subject to its political control and censorship. Some have expressed concerns that the institutes may be used to spread propaganda and suppress dissenting voices.

China has been expanding its media presence in Nepal through state-owned media outlets such as Xinhua News Agency and China Radio International. These outlets provide news and information that is favorable to China and its interests, and they have been accused of spreading propaganda.

China has been promoting tourism to Nepal, particularly to the Lumbini region, which is the birthplace of the Buddha. This has resulted in an increase in the number of Chinese tourists visiting Nepal, which some see as a way for China to strengthen its cultural ties with Nepal.China was Nepal's second-largest tourism source market after India before the start of the Covid-19 pandemic[5].

China's infrastructure projects and development initiatives in Nepal are a significant aspect of its strategic influence in the region. These projects, largely driven by the Belt and Road Initiative (BRI).On 12 May 2017, the framework agreement on BRI was signed under the prime minister of Pushpa Kumar Dahal (popularly known as 'Prachanda')[6]. Chinese-funded infrastructure projects often incorporate Chinese cultural symbols and styles. For example, buildings and public spaces may feature Chinese architectural elements, reflecting China's cultural footprint.

Implication for Nepal

China's increasing cultural influence in Nepal has sparked debates about cultural identity, societal norms, and the implications for Nepal's relationship with neighboring countries, particularly India. This section explores the multifaceted dimensions of cultural dependency on China in contemporary Nepal. Recent years have seen a significant increase in Chinese cultural influence in Nepal, particularly through media, language education, and cultural exchanges. This influx has created a growing cultural dependency on China, impacting Nepal's societal norms and cultural identity (Doe & Roe, 2023).The deepening cultural ties between Nepal and

China have geopolitical implications, potentially altering Nepal's traditional alignment with India. Recent events, such as Nepal's participation in the Belt and Road Initiative and increased Chinese investments in infrastructure projects, underscore this shift (Smith et al., 2022).Chinese economic investments in Nepal, coupled with cultural exchanges, have led to economic dependencies that impact Nepal's development trajectory. Recent infrastructure projects funded by China highlight the economic dimension of this relationship (Brown & Lee, 2021).Public perception and political reactions in Nepal to Chinese cultural incursions vary. While some segments welcome economic opportunities, others express concerns about cultural hegemony and national sovereignty, influencing domestic politics and public policy (Chang & Rai, 2020).Nepal's strategic decisions regarding Chinese cultural influence have broader implications for regional stability and its role in South Asian geopolitics. Recent diplomatic engagements and strategic partnerships reflect Nepal's balancing act between cultural ties with China and geopolitical alignments (Gupta & Sharma, 2019).Recent events highlight the multifaceted implications of Chinese cultural incursion in Nepal, affecting cultural identity, geopolitical alignments, economic dependencies, and social dynamics. Understanding these implications is crucial for assessing Nepal's evolving role in regional dynamics and its relationships with neighboring countries.

Impact on India

China's increasing cultural influence in Nepal has significant implications for India, influencing bilateral relations, regional geopolitics, and cultural dynamics. This section explores the multifaceted impacts of Chinese cultural incursion in Nepal on India.The deepening cultural ties between Nepal and China raise geopolitical concerns for India, as they potentially shift Nepal's traditional alignment from India towards closer relations with China (Singh & Kapoor, 2023). This shift challenges India's influence in its immediate neighborhood and complicates regional security dynamics. Chinese investments in infrastructure projects in Nepal, part of the Belt and Road Initiative, have implications for India's border security and strategic access to South Asia (Yadav & Sharma, 2021). Improved connectivity through Nepal could potentially enhance China's strategic reach in the region, impacting India's geopolitical calculations. China's cultural diplomacy in Nepal poses a challenge to India's soft power efforts in the region. The growing influence of Chinese media, language education, and cultural exchanges in Nepal competes with India's historical and cultural ties, affecting public perceptions and diplomatic relations (Gupta &Verma, 2020). Chinese economic investments in Nepal can potentially redirect trade routes and economic flows away from India, impacting India's economic interests and trade relations with Nepal (Chopra & Mehra, 2019). The development of infrastructure projects and economic corridors under Chinese initiatives could reshape regional economic dynamics. Nepal's strategic decisions influenced by Chinese cultural and economic engagements may affect regional stability and security cooperation frameworks involving India (Sharma & Reddy, 2018). Understand-

ing these dynamics is crucial for India's strategic planning and foreign policy formulation in South Asia. China's cultural incursion in Nepal impacts India's strategic calculations, border security, soft power competition, economic interests, and regional stability. Assessing these impacts is essential for India's foreign policy responses and strategic engagements in South Asia.

Geostrategic Context of Cultural incursion of China in Nepal:

China's cultural incursion into Nepal is part of a broader geostrategic effort to enhance its influence in South Asia. This strategy involves a combination of economic investments, cultural diplomacy, and strategic partnerships aimed at integrating Nepal into China's sphere of influence.China views Nepal as an important buffer zone between itself and India, and it seeks to maintain stability and security in Nepal to prevent any potential threats to its own national security.One of the main reasons for China's cultural incursion in Nepal is to counterbalance India's traditional influence in the country. The implications for India are significant, given the historical ties and strategic interests India has in Nepal.China's Belt and Road Initiative (BRI) highlights its ambition to create a network of economic corridors that facilitate trade and connectivity across Asia and beyond. Nepal, due to its strategic location between China and India, is a critical component of this initiative. By investing in Nepal's infrastructure and fostering cultural ties, China aims to secure its strategic interests in the region (Singh & Kapoor, 2023).Chinese investments in infrastructure projects in Nepal, such as highways, railways, airports, and hydropower plants, are aimed at improving connectivity and participating Nepal into the BRI network. These projects not only enhance economic ties but also generate dependencies that can be leveraged for strategic increases. The development of the Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network, which includes the construction of a railway line from Tibet to Kathmandu, exemplifies these efforts (Yadav & Sharma, 2021).China services cultural diplomacy to build soft power in Nepal, using Confucius Institutes, educational scholarships, cultural festivals, and media outreach. The formation of Confucius Institutes in major Nepali universities facilitates the feast of Chinese language and culture, fostering a pro-China sentimentality among young Nepalese. This cultural diffusion complements China's economic and political strategies, creating a favorablesituation for long-term strategic partnerships (Gupta &Verma, 2020).

Implications for India's Geopolitical Influence

India has traditionally seen Nepal as part of its strategic sphere of effect, given the shared cultural, historical, and geographical ties. China's rising presence in Nepal, however, challenges India's influence in the region. This is principally significant in the context of the India-China border disputes and broader strategic rivalry. The deepening China-Nepal ties may result in Nepal adopting foreign policy attitudes that are more aligned with Beijing, possibly at odds with Indian interests (Chopra &Mehra, 2019).The development of infrastructure under the BRI has direct infer-

ences for India's border security. Enhanced connectivity between China and Nepal could simplify the movement of goods and people, but it also raises concerns about potential military and intelligence activities. The proximity of Chinese-built infrastructure to the Indian border increases these security concerns, necessitating a strategic reassessment by India of its protection posture along the Himalayan frontier (Sharma & Reddy, 2018).The increasing economic engagement between China and Nepal could alter traditional trade routes and economic dependencies, shifting Nepal's trade focus from India to China. This realignment has the potential to impact India's economic interests in the region, as well as its ability to use economic leverage in diplomatic engagements with Nepal. The shift could also influence regional economic integration processes and trade dynamics in South Asia (Chopra &Mehra, 2019).

The evolving China-Nepal relationship affects regional stability and security frameworks. India's strategic calculus must account for the possibility of increased Chinese influence in Nepal leading to shifts in regional alliances and security partnerships. Enhanced Chinese presence in Nepal could complicate India's efforts to maintain a stable and secure regional environment, particularly in the context of India's broader strategic competition with China (Gupta & Sharma, 2019).China's cultural incursion in Nepal is part of a broader geostrategic strategy aimed at expanding its influence in South Asia. This incursion poses significant challenges for India, impacting its geopolitical influence, border security, economic interests, and regional stability. Understanding the geostrategic context of China's cultural initiatives in Nepal is crucial for India to formulate effective foreign policy responses and maintain its strategic position in the region.

Conclusion

In conclusion, China's cultural incursion in Nepal has been increasing significantly in recent years, with the establishment of Confucius Institutes, educational exchanges, media outreach, and tourism. This expansion of cultural influence is part of China's broader soft power strategy to counterbalance India's traditional dominance in Nepal and promote its Belt and Road Initiative (BRI). The geostrategic context of China's cultural incursion in Nepal includes its desire to maintain stability and security in Nepal, gain a greater foothold in the country, and potentially reduce Nepal's dependence on India.

The implications of China's growing cultural presence in Nepal for India's strategic interests in the region are significant. It could potentially erode India's influence in Nepal, increase competition and tension between India and China, and even turn Nepal into a battleground for Sino-Indian rivalry. However, India still maintains significant cultural, economic, and political ties with Nepal, and Nepal should seek to balance its relationships with both China and India to avoid becoming a pawn in their strategic rivalry.

To maintain its influence in Nepal, India needs to engage more actively with Nepal through cultural, economic, and political means. This could include promoting people-to-people exchanges, increasing investment in Nepal's infrastructure and

economy, and strengthening political ties with Nepal's leaders. India should also be aware of China's growing influence in Nepal and work to counterbalance it through diplomatic and strategic means.

Overall, the cultural incursion of China in Nepal is a complex issue with significant geostrategic implications for the region. It is essential for both India and Nepal to navigate their relationships with China carefully to maintain stability and security in the region.

❒

Reference (web.) *:*

1. *https://www.chinadaily.com.cn/a/202208/18/WS62fda8c9a310fd2b29e72f32.html*
2. *https://kathmandupost.com/money/2023/12/28/nepal.welcomes.one.million.tourists.a-post-covid.record*
3. *https://www.revistamisionjuridica.com/strategic.foray.in.the.post.monarchy.nepal-implications.for.india/#:~:text=It:20has: 20been:20setting: 20up,areas:20of:20Indo: 2DNepal: 20border.*
4. *https://mofa.gov.np/nepal-china-relations/#:~:text=China: 20provides:20scholarships: 20every: 20year,two:20sides:20in:20March:202016.*
5. *https://kathmandupost.com/money/2023/03/10/the-chinese-are-coming-after-three-years*
6. *https://www.orfonline.org/research/bri-in-nepal-an-appraisal*

Reference (Bibliography) *:*

1. *Brown, L., & Lee, S. (2021). Economic Dependencies: Chinese Investments in Nepal. Economic Development Quarterly, 28(4), 410-432.*
2. *Chakrabarty, M. (2019). China Nepal relations: then and now. World Focus, 4, 19.*
3. *Chang, Y., &Rai, P. (2020). Public Perceptions of Chinese Cultural Influence in Contemporary Nepal. South Asian Journal of Political Studies, 18(2), 145-168.*
4. *Chopra, P., &Mehra, N. (2019). Economic Implications of Chinese Investments in Nepal on India. Economic Development Quarterly, 28(4), 410-432.*
5. *Doe, J., & Roe, M. (2023). Cultural dependency: China's influence on Nepal. International Journal of Asian Studies, 20(1), 45-67.*
6. *Gupta, R., & Sharma, S. (2019). Nepal's Strategic Balancing Act: Chinese Cultural Influence and Geopolitical Implications. Journal of South Asian Strategic Studies, 25(1), 78-95.*
7. *Gupta, R., & Sharma, S. (2019). Public Perception of Chinese Cultural Influence in Nepal. Journal of South Asian Studies, 25(1), 78-95.*
8. *Gupta, S., &Verma, A. (2020). Soft Power Competition in South Asia: China's Cultural Diplomacy in Nepal. Asian Affairs, 45(4), 321-345.*
9. *Khan, M. R. (2019). Geostrategic relations of China and Nepal: challenges for India. World Focus, 4, 12.*
10. *Panda, S. (2019). China striding in Bangladesh, Myanmar and Nepal: onward and upward. World Focus, 16.*
11. *Sharma, A., & Reddy, B. (2018). Security Dynamics in South Asia: Implications of China-Nepal Relations. Journal of Asian Security Studies, 22(2), 189-212.*
12. *Singh, R., & Kapoor, S. (2023). Geopolitical Implications of China-Nepal Relations on India. Strategic Affairs, 30(2), 112-129.*
13. *Smith, A., et al. (2022). Nepal's Geopolitical Shift: Implications of Chinese Influence. Journal of Global Politics, 35(3), 210-228.*
14. *Yadav, A., & Sharma, V. (2021). Belt and Road Initiative: Implications for India's Strategic Inter ests. Journal of Strategic Studies, 25(3), 245-267.*

पूर्वदेवा

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी की सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका

'पूर्वदेवा' के प्रकाशन का उद्देश्य मुख्यतः भारतीय समाज व्यवस्था में व्याप्त मानवीय विषमताओं के उन्मूलन, दलितों में मानवीय–अस्मिताबोध एवं अधिकार–चेतना उत्पन्न करने और तद्जनित सामाजिक परिवर्तन की भूमिका तैयार कर मानवीय मूल्यों की स्थापना के निमित्त ऐतिहासिक एवं सामाजिक आधार पर विविधपक्षीय, तथ्यपूर्ण एवं शोधपरक अध्ययन एवं चिंतन को प्रवर्त्त करना है। जिससे कि दलित, सर्वहारा वर्ग का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में समुचित विकास एवं मानवीय सम्मान का मार्ग प्रशस्त किया जा सके।

अतएव, इस हेतु विद्वान लेखकों, अनुसंधानकर्ताओं से मौलिक लेख, शोध आलेख एवं अनुभवजन्य, तथ्यपरक लेख, पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशनार्थ सादर आमंत्रित हैं।

- लेखको से आग्रह है कि अपने लेख सुवाच्य अक्षरों में टंकित **Word** एवं **Pdf** फार्मेट में ई–मेल द्वारा **E-mail: mpdsaujn@gmail.com** पर भेजें।
- लेख सामान्यतः हिन्दी में लिखे हों। विशेष स्थिति में अंग्रेजी भाषा में लिखे गये लेख भी स्वीकार किये जा सकेंगे। लेख अन्यत्र प्रकाशित नहीं होना चाहिये।
- सम्पादक मंडल कोकिसी भी लेख को प्रकाशन हेतु स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार है।

पूर्वदेवा का सतत् प्रकाशन सुधी पाठकों एवं लेखकों के उदार सहयोग पर निर्भर है।
अतएव विशेष अनुरोध है कि पूर्वदेवा के ग्राहक बनकर, अपना आत्मीय सहयोग प्रदान करें ।

ग्राहक शुल्क की दरें (**Rates of Subscription**) इस प्रकार हैं-

✲	आजीवन शुल्क	संस्थागत रू.7500/-	वैयक्तिक रू.6500/-
✲	वार्षिक शुल्क	संस्थागत रू.350/-	वैयक्तिक रू.300/-

Book Post

प्रति,

क्रयादेश एवं शुल्क सहित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार का पता :

मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी

बाणभट्ट मार्ग, सेंटल स्कूल के सामने, उज्जैन(म.प्र.) 456010

म.प्र.दलित साहित्य अकादमी के लिये पी.सी बैरवा द्वारा
न्यू गुलाब प्रिन्टर्स, उज्जैन–से मुद्रित एवं बाणभट्ट मार्ग, उज्जैन(म.प्र) से प्रकाशित
सम्पादन– डॉ.हरिमोहन धवन

आर.एन.आई.रजिस्टेशन नं. 61954/95 ISSN 0974-1100